दशम माला, खंड 16, अंक 10

सोमवार, 7 दिसम्बर, 1992
16 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....64.....
Date.....9-2-94.....

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 7 दिसम्बर, 1992 / 16 अग्रहायण, 1914 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
24	नीचे से 5	"श्रीमती भावना विलखिया" के स्थान पर "श्रीमती भावना विखलिया" पढ़िए।
33	2 (विवरण में)	"ऋप" के स्थान पर "ऋण" पढ़िए।
77	15	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ग)" पढ़िए।
	19	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िए।
	22	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िए।
83	2	शीर्षक में "कार्यलि" के स्थान पर "कार्यालय" पढ़िए।
84	नीचे से 11	"712.00" के स्थान पर "172.00" पढ़िए।
87	4	शीर्षक में "भारतीय पर्यटन पर टी.वी. की फिल्में" के स्थान पर "भारतीय पर्यटन पर स्टार टी.वी. की फिल्में" पढ़िए।
87	नीचे से 7	राज्यमंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" पढ़िए।
143	14	"श्रीमतो" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िए।
153	नीचे से 10	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ख)" पढ़िए।
180	7	प्रश्न संख्या "2179" के स्थान पर "2197" पढ़िए।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध
185	3	प्रश्न संख्या "2203" के स्थान पर "2202" पढ़िए।
210	9	प्रश्न संख्या "223" के स्थान पर "2235" पढ़िए।
213	अंतिम पंक्ति	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ख)" पढ़िए।
253	18	"5232" के स्थान पर "2232" पढ़िए।
293	अंतिम पंक्ति	"4·50" के स्थान पर "4·30" पढ़िए।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलि
हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाए

विषय-सूची

दशम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 10, सोमवार, 7 दिसम्बर, 1992/16 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
अयोध्या की घटनाओं के बारे में	... ...	1—2
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	2—228
तारांकित प्रश्न संख्या : 181 से 200		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2089 से 2279 और 2281 से 2320		
अयोध्या की घटनाओं की बारे में—जारी	... ...	288—294

किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 7 दिसम्बर, 1992/16 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अयोध्या की घटनाओं के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम विश्व हिन्दू परिषद पर प्रतिबंध चाहते हैं । (**व्यवधान**) श्री आडवाणी को इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० थामस (मुवत्तपुजा) भा० ज० पा० पर प्रतिबंध लगना चाहिए (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आडवाणी जी को गिरफ्तार किया जाये । (**व्यवधान**)

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : होम मिनिस्टर इस्तीफा दें । इसमें कांग्रेस की मिली-भगत थी । यह सरकार विफल हो गई है —(**व्यवधान**)—प्रधान मंत्री इस्तीफा दें । (**व्यवधान**)

श्री सूरज मंडल (गौड्डा) : बी० जे० पी० पर बैन लगाया जाए । (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आडवाणी जी इस्तीफा दें (**व्यवधान**)

11.01 म०पू०

इस समय श्री इब्राहिम सुलेमान सेट और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

*181. **श्री रामपाल सिंह** :

श्री हरीकेवल प्रसाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संचार सेवा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान देश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित एक्सचेंजों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे में से कोई कटौती की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के दौरान 16.44 लाख लाइनों की सकल क्षमता को चालू करने की योजना है, जिसमें से 15.65 लाख लाइनें मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार सहित विविध प्रकार एवं आकारों के इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए मकान

*182. **श्री खेलन राम जांगड़े** :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार वास्तव में कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मकान बनाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एक डाक विभाग में कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण का अनुमोदन प्रत्येक वर्ष के आधार पर की गई मांग तथा वित्तीय प्रतिबन्धों के अध्ययन द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण के लिए अनुमोदित क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार थी :—

1989-90	1603
1990-91	808
1991-92	250

(दो) दूरसंचार विभाग में क्वार्टरों के निर्माण के लिए वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। आठवी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ तक 12.5 प्रतिशत अनुपात स्टाफ संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना था।

(ख) (एक) **डाक विभाग** : उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्मित क्वार्टरों की राज्यवार वास्त- संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) (दो) **दूरसंचार विभाग**

ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) (एक) **डाक विभाग** : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है। ये क्वार्टर विभिन्न श्रेणियों के हैं जो विभिन्न सर्किलों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार होंगे।

(ग) दो) **दूरसंचार विभाग** :

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लगभग 15,000 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए अलग-अलग क्षेत्रीय एकक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं।

विवरण-I

डाक विभाग के लिए निर्मित क्वार्टरों की संख्या

क्र०सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	—	8
2.	असम	9	—	—
3.	बिहार	1	11	—

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	—	—	—
5.	गुजरात	1	12	16
6.	हरियाणा	3	13	4
7.	हिमाचल प्रदेश	4	8	12
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
9.	कर्नाटक	42	1	1
10.	केरल	11	—	3
11.	मध्य प्रदेश	62	16	10
12.	महाराष्ट्र	68	12	16
13.	उत्तर पूर्व	34	—	—
14.	उड़ीसा	30	3	75
15.	पंजाब	—	8	—
16.	राजस्थान	55	—	26
17.	तमिलनाडु	33	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	30	48	24
19.	पश्चिम बंगाल	4	12	32
	कुल :	395	144	227

विवरण-II

क्रम०सं०	सर्किल का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग के लिए निर्मित क्वार्टरों की संख्या		
		1989-90	90-91	91-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	6	—
2.	असम	8	11	49

1	2	3	4	5
3.	बिहार	57	48	19
4.	गुजरात	24	48	31
5.	हरियाणा	9	6	64
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	36
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	10
8.	कर्नाटक	111	—	46
9.	केरल	108	155	318
10.	मध्य प्रदेश	116	93	133
11.	महाराष्ट्र	98	134	116
12.	उत्तर-पूर्व	45	16	21
13.	उड़ीसा	30	51	27
14.	पंजाब	17	30	27
15.	राजस्थान	52	97	99
16.	तमिलनाडू	80	27	94
17.	उत्तर प्रदेश	45	81	48
18.	पश्चिम बंगाल	419	113	37
19.	मुख्य महाप्रबंधक टेलीफोन्स, मद्रास	—	46	96
20.	मुख्य महाप्रबंधक टेलीफोन्स, कलकत्ता	108	605	26
21.	मुख्य महाप्रबंधक, ए०एल०टी०टी०सी०, गाजियाबाद	—	—	—
22.	तकनीकी विकास सर्किल, जबलपुर	—	—	7
23.	मुख्य महाप्रबंधक, एन०टी०आर० नई दिल्ली	—	—	14
24.	म०टे०नि०लि०, नई दिल्ली	—	—	—
25.	म०टे०नि०लि०,बम्बई	—	—	—
	कुल :	927	1567	1318

विद्युत क्षेत्र

[अनुवाद]

*183. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री चित्त बसु :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश कि विद्युत सम्बन्धी मांग को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री कल्पनाथ राय**) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के दौरान 30537.7 मे०वा० के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। विद्युत उत्पादन क्षमता में उक्त वृद्धि के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होगी। तथापि, योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1996-97 में ऊर्जा की कमी 9% और व्यस्ततमकालीन कमी 20.7% रहेगी।

(ख) इस समय, विद्युत की पर्याप्त मात्रा में मांग है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत की मांग लगभग 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उपर्युक्त मात्रा में क्षमता संवर्धन को व्यवहार्य पाया गया है।

(ग) सरकार द्वारा उपलब्ध ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करने हेतु व्यापक ऊर्जा संरक्षण एवं मांग प्रबन्धन कार्यक्रम के साथ-साथ विद्यमान क्षमता के बेहतर समुपयोजन और नई विद्युत उत्पादन क्षमता के तेजी से सृजन सम्बन्धी विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं :— विद्यमान संयंत्रों के संयंत्र भार गुणक (पी० एल० एफ०) में वृद्धि करने हेतु क्षमता सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, प्रणाली सुधार स्कीमों के माध्यम से पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना और अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाकर सार्वजनिक क्षेत्र की सहायता करना।

पवन हंस लिमिटेड

*184. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस लिमिटेड घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे वाणिज्यिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या उपाये किए गये हैं अथवा किये

जाएंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां

(ख) औ (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

नए दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

[हिन्दी]

*185. **प्रो० प्रेम धूमल** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1992 के बाद देश में खोले गए दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जो तकनीकी रूप से तैयार हो चुके हैं किन्तु जिन्होंने अभी कार्य करना आरंभ नहीं किया है; और

(ग) इनके कब तक चालू होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जून, 1992 से निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :—

दूरदर्शन

1. **स्टूडियो केन्द्र**

भोपाल

भुवनेश्वर

अगरतला

2. **कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र**

पांडिचेरी

3. **उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**

बरेली

4. **अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**

पुरी

मदुरम

वल्लभ नगर

करनपुर

रायसिंह नगर

कोन्टाई

कोटपुतली

येल्लांदु

5. अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

किलोत्रन

सांकू

दरास

आकाशवाणी

6. 2 × 3 कि०वा० एफ० एम० ट्रांसमीटरों सहित स्थानीय रेडियो स्टेशन और

बहु-उद्देशीय स्टूडियो

पूर्णिया

बेलोनिया

कैलाशहर

बालाघाट

हाफलांग

हजारीबाग

चाईबासा

यवतमाल

सतारा

चन्द्रपुर

7. बहु-उद्देशीय स्टूडियो सहित 2 × 5 कि० वा० एफ० एम० के रिले केन्द्र

कतौली

8. 2 × 3 कि० वा०एफ० एम० ट्रांसमीटर सहित नए रेडियो स्टेशन और

बहु-उद्देशीय स्टूडियो

चुरू

(ख) तकनीकी रूप से तैयार आकाशवाणी स्टेशन :—

झालावाड़, ओबरा, झांसी, गुना, रायचूर बरेली, जसलमेर फैजाबाद, धुले, नासिक, सागर, मरकरा, मरकापुरम, और हमीरपुर ।

(ग) झालावाड़, औबरा, झांसी, गुना, रायचुर और बरेली के रेडियो स्टेशन निकट भविष्य में शुरू किए जाएंगे। जैसलमेर, फैजाबाद, धुले, नासिक, सागर, मरकारा, मरकापुरम और हमीरपुर के रेडियो स्टेशनों को तभी शुरू किया जा सकता है जब उनके प्रचालन और अनुरक्षण के लिए न्यूनतम आवश्यक स्टाफ उपलब्ध हो जाएगा।

विदेशी पर्यटक

*186. **श्री यशवंत राव पाटिल :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष-यात्रा आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विदेशी पर्यटकों के लिए यात्रा आरक्षण सुविधाएं एयरलाइनों और इंडियन रेलवे द्वारा कम्प्यूटर नेटवर्क तथा जनरल सेल्स एजेन्टों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, केवल विदेशी पर्यटकों के प्रयोग के लिए इंडियन एयरलाइन्स और रेलवे में विशेष काउंटरों पर विशेष कोटे उपलब्ध हैं।

सिंचाई प्रणालियां

[अनुवाद]

*187. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई प्रणालियों की कार्य कुशलता अधिकतम स्तर तक बढ़ाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सिंचाई क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सिंचाई क्षेत्र से प्राप्त वित्तीय लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कमान क्षेत्र में उचित जल प्रबन्ध को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय जल नीति से भिन्न सिंचाई प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अपनाने के वास्ते कदम उठाए गए हैं। नीति का उद्देश्य जल के इष्टतम उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली के उपयुक्त प्रबंध पर और प्रचालन के अनुश्रवण, संयुक्त उपयोग, जल निकास,

किसानों की भागीदारी, अनुरक्षण अनुदान, जल दरें, प्रशिक्षण आदि के संबंध में दिशा-निर्देशों पर होगा।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान वृहद, मध्यम तथा सिंचाई स्कीमों पर 17534 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

(घ) और (ङ) सिंचाई परियोजनाओं से आर्थिक आय का मूल्यांकन पेय, म्युनिसिपल तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्रदान करने एवं जल विद्युत उत्पादन करने के अतिरिक्त ऐसी परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा अन्य सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास के अनुसार प्राप्त लाभों के आधार पर किया जाता है और केवल उगाहे गए जल प्रभार के रूप में प्राप्त राजस्व के आधार पर नहीं।

खानों से खनिज निकालना

[हिन्दी]

*188. **श्री लाल बहादुर रावल :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 से आज तक पता लगाई गई विभिन्न खनिज धातु वाली खानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से ऐसी कितनी खानें हैं जिनमें से खनिज धातुएं निकाली जा रही हैं तथा उनकी मात्रा कितनी है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खनिजों का गवेषण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अनेक स्तर होते हैं और कई वर्ष चलते हैं। उसके बाद किसी खास खनिज के उत्पादन के लिए वास्तविक विकास होता है। किसी खान का विकास गवेषण के अन्तिम परिणामों पर आधारित तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययनों के परिणामों पर निर्भर करता है। किसी खनिज के गवेषण, उसकी खान का विकास और वास्तविक खनन के विभिन्न स्तरों के बीच हमेशा समय अन्तराल होता है। धात्विक खनिजों का उत्पादन करने वाली खानों की संख्या और वर्ष 1990-91 और 1991-92 में उनके मूल्य की राज्यवार तुलनात्मक स्थिति विवरण-I में दर्शाई गई है। विभिन्न धात्विक खनिजों की खानों की संख्या और खनिजों की मात्रा की तुलनात्मक स्थिति विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण I

भारत में खानों की संख्या और खनिज उत्पादन का मूल्य

राज्यवार (केवल धात्विक खनिज)

राज्य	1990-91	*000 रुपयों में	1991-92	*000 रुपयों में
	खानों की सं०	उत्पादन का मूल्य	खानों की सं०	उत्पादन का मूल्य
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	41	3,[illegible],009	38	15,53,48

1	2	3	4	5
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3. असम	—	—	—	—
4. बिहार	75	15,60,816	73	103,51,42
5. गोवा	67	8,140,74	70	88,95,32
6. गुजरात	94	5,8,544	88	6,08,70
7. हरियाणा	1	1,84	1	6,27
8. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
9. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
10. कर्नाटक	151	222,28,12	155	229,02,22
11. केरल	—	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	86	223,04,04	94	252,90,77
13. महाराष्ट्र	25	25,09,23	24	24,64,06
14. मणिपुर	1	67	1	60,64
15. मेघालय	—	—	—	—
16. उड़ीसा	145	259,11,92	143	320,34,67
17. पंजाब	—	—	—	—
18. राजस्थान	21	180,81,32	17	241,62,30
19. सिक्किम	1	51,76	1	62,60
20. तमिलनाडु	6	87,48	4	66,82
21. उत्तर प्रदेश	—	—	—	—
22. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—
23. दिल्ली	—	—	—	—
	714	11,88,40,81	709	13,64,88,97

विवरण-2

खानों की संख्या/उत्पादन (मात्रा) का तुलनात्मक विवरण

धात्विक खनिज

क्रमांक	खनिज	यूनिट	1990-91		1991-92	
			मात्रा	खानों की सं०	मात्रा	खानों की सं०
1.	बाक्साइट	टन	4970269	206	4611515	206
2.	क्रोमाइट	टन	929001	21	1064646	22
3.	तांबा अयस्क	टन	5249180	14	5199428	14
4.	सोना	कि०ग्रा०	2208	6	2006	7
5.	लौह अयस्क	हजार टन	9600178	279	107782	266
6.	सीसा सान्द्र	टन	43852	6	51796	7
7.	मैंग्नीज अयस्क	टन	577009	178	1467261	183
8.	टंगस्टन सान्द्र	कि०ग्रा०	20072	2	7755	8
9.	टिन सान्द्र	कि०ग्रा०	174123	2	114260	2
10.	चांदी	कि०ग्रा०	34983	—	37756	—
11.	जस्ता सान्द्र	*टन	136716	—	252326	—
				714		709

डाकघर

[अनुवाद]

*189. श्री राम नाईक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े नगरों में नए डाकघर खोलने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) मुम्बई में वर्तमान डाकघरों की संख्या कितनी है और प्रत्येक द्वारा औसतन कितनी जनसंख्या की सेवा की जाती है;

(ग) क्या जगह की अनुपलब्धता के कारण मुंबई में और डाकघर नहीं खोले जा रहे है; और

(घ) मुम्बई अपेक्षित संख्या में डाकघर खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

* इसमें तांबा अयस्क/सीसा सान्द्र शामिल है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड निम्नलिखित हैं :

जब कोई नया डाकघर खोला जाता है तो वह आत्म-निर्भर होना चाहिए और पहली वार्षिक पुनरीक्षा के समय उससे 5 प्रतिशत का लाभ अवश्य होना चाहिए। 20 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों के मामले में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 किलोमीटर निर्धारित की गई है तथा अन्य शहरों और कस्बों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 2 किलोमीटर होनी चाहिए।

(ख) इस समय बम्बई में 273 डाकघर हैं और 1991 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक डाकघर औसतन 36,000 लोगों को सेवा प्रदान करता है।

(ग) जी हां, लोखंडवाला काम्प्लेक्स अंधेरी में एक डाकघर 18-12-90 को और दूसरा डाकघर कुरार गांव मलाड़ में खोलने के लिए 15-11-84 को मन्जूर किया गया था परन्तु स्थान उपलब्ध न होने की वजह से इन्हें अभी खोला नहीं जा सका है।

(घ) वार्षिक योजनाओं में आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तरोत्तर डाकघर खोले जाते हैं। 1991-92 के दौरान मांडुप ईस्ट में 8-12-91 को एक डाकघर और इस वर्ष 14-10-92 को चीता कैम्प में एक डाकघर खोला गया है। बम्बई में 1992-93 के दौरान छः विभागीय उप डाकघर खोले जाने की संभावना है।

मैट्रो चैनल

*190. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो चैनल के संबंध में कोई आचार-सहिता बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आचार-संहिता नहीं है, तथापि लाइसेंस धारियों के लिए पात्रता मापदण्ड तथा कार्यक्रमों के लिए मार्गनिर्देश हैं, जिन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. लाइसेंसधारियों के लिए पात्रता मापदण्ड

इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक निर्माताओं के लिए यह जरूरी है कि वे निम्नलिखित मापदण्डों को पूरा करते हों;

(क) भारत का नागरिक हो, (व्यक्तियों के लिए) / कंपनियों, जिनमें भारतीय शेयर होल्डरों का बहुमत हो/भागीदारी फर्म जिनके समस्त भागीदार भारत के नागरिक हों।

(ख) दिवालिया घोषित न किया गया हो या किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध न ठहराया गया हो;

(ग) वित्तीय स्थिति का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने के लिए लिखित में इच्छा की पुष्टि करनी चाहिए;

(ङ) लिखित रूप में यह आश्वासन देना चाहिए कि लाइसेंस में निर्दिष्ट सभी शर्तों अथवा परिषद अथवा सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अनुवर्ती निदेश का पालन करेगा;

*(च) समाचारों से सम्बद्ध कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले आवेदक का उस चैनल द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र में कोई समाचार पत्र/पत्रिका नहीं होनी चाहिए जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया हो;

(छ) आवेदक का टेलीविजन/रेडियो कार्यक्रम, फीचर फिल्मों, विडियो फिल्मों, वीडियो पत्रिकाओं, वृत्तचित्रों आदि का निर्माण करने का प्रमाणित रिकार्ड होना चाहिए।

2. कार्यक्रमों के लिए मार्गनिर्देश :

(1) कार्यक्रमों द्वारा आकाशवाणी प्रसारण संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित की मनाही की गई है :

(1) मित्र देशों की आलोचना;

(2) धर्म अथवा समुदायों पर आक्षेप;

(3) अश्लील या मानहानिकारक बातें;

(4) जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता हो अथवा जिससे कानून और व्यवस्था न बनाई रखी जा सकती हो;

(5) ऐसी कोई बात जिससे न्यायालय की अवमानना हो;

(6) जिसमें राष्ट्रपति तथा न्यायाधिकारी की न्यायनिष्ठा की निन्दा की गई हो;

(7) राष्ट्र की एकता पर प्रभाव डालने वाली कोई बात; और

(8) किसी व्यक्ति के नाम से आलोचना।

(2) लाइसेंसधारी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लागू विज्ञापन संहिता का और उनमें भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों का पूरा-पूरा पालन करेगा।

(3) ये कार्यक्रम चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 5 (ख) और सरकार द्वारा समय-समय पर फिल्म प्रमाणीकरण के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी मार्गनिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप होंगे।

(4) इन कार्यक्रमों द्वारा कापीराइट के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

(5) चैनल द्वारा अपने प्रसारण समय का कम से कम 20 प्रतिशत ऐसे कार्यक्रम प्रसारित

* टिप्पणी : सार्वजनिक सूचना संख्या 8-1-92 पी०बी०सी० तारीख 27-10-92 के तहत इसे हटा दिया गया है।

किए जाएंगे जो परिषद की दृष्टि में समाज सापेक्ष और विकास प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) चैनल द्वारा राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे जिनके लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निवेश दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश शामिल होंगे।

(7) चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का उपयोग किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में नहीं किया जाएगा।

(8) चुनाव के दौरान चैनल द्वारा राजनीतिक पार्टियों द्वारा अथवा उनके बारे में प्रसारणों में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का पालन किया जाएगा।

(9) किसी विवाद के मामले में कार्यक्रमों में सभी दृष्टिकोणों को उचित और निष्पक्ष रीति से प्रस्तुत किया जाएगा।

विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

*191. **श्री ललित उरांव :**

श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 30 नवम्बर, 1992 की तिथि को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिन ताप, पन और लघु पनविद्युत संयंत्रों का निर्माण किया गया है उनके नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक संयंत्र पर कुल कितनी-कितनी लागत आयी है;

(ग) ऐसे विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक संयंत्र पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है;

(ङ) विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य से कितने-कितने प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में 30-11-92 तक देश में क्षमता संवर्धन से सम्बन्धित लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
1989-90	4892·4	4687·7
1990-91	4212·0	2776·5

1	2	3
1991-92	3810·8	3026·5
1992-93	4458·02	1516·0

विभिन्न ताप विद्युत एवं जल विद्युत परियोजनाओं में सृजित क्षमता का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्यों से 97 परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत किए जाने में लगने वाला समय, राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और निम्नलिखित जैसी विभिन्न सम्बन्धित केन्द्रीय एजेंसियों/मन्त्रालयों द्वारा स्वीकृतियां प्रदान किए जाने पर निर्भर करेगा—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी—वार्षिक स्वीकृति, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय और कोयला मन्त्रालय से इंधन लिंकेज सुनिश्चित करने के बारे में, भूतल परिवहन मन्त्रालय एवं रेल मन्त्रालय से इंधन की ढुलाई एवं इस सम्बन्ध में नियन्त्रण के बारे में, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे में और वित्त मन्त्रालय तथा योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी अनुमोदन 25 करोड़ रुपये से कम लागत वाली मिनी जल विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (30-11-92 तक) के दौरान जोड़ी गई अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता।

क० ताप विद्युत

वर्ष 1989-90

क्र० सं०	परियोजना का नाम तथा क्षमता (मे० वा०)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष के दौरान चालू की गई क्षमता (मे०वा०)	कुल परियोजना लागत (लाख रु० में)	परियोजना के लिए 8वीं योजना में अनुज्ञासित परिव्यय (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1.	राजघाट प्रतिस्थापन-1 (2×67·5)	दिल्ली	67.5	23777	1807
2.	पम्पोर स्टेज-1 (3×25)	जे० एंड के०	50	6010	400
3.	कोटा (2×210)	राजस्थान	210	48000	3945
4.	बन्ता (3×88+1×49	राजस्थान	237	40952	3044
5.	टांडा (4×110)	उ० प्र०	110	47591	6656

1	2	3	4	5	6
	6. रिहन्द (2×500)	उ० प्र०	500	242082	15616
	7. औरैया (4×112+1× 102 एसटी)	उ० प्र०	438	69292	6435
	8. गांधी नगर (1×200)	गुजरात	210	31694	शून्य
	9. कच्छ लिग्नाइट (2×70)	गुजरात	70	25300	200
	10. विन्ध्याचल (6×210)	म० प्र०	420	158098	9406
	11. खापरखेड़ा (2×240)	महाराष्ट्र	210	73000	2000
	12. ट्राम्बे (1×500)	महाराष्ट्र	500	39315	एन० ए०
	13. रामगुंडम (3×500)	आ० प्र०	500	176470	7069
	14. विजयवाड़ा (2×210)	आ० प्र०	420	53900	350
	15. मेत्तूर (2×210)	तमिलनाडु	216	36170	912.76
	16. बारामुरा (जीटी 1×6.5	त्रिपुरा	6 5	1480	शून्य
	17. रोखियां जीटी-8	त्रिपुरा	8·0	3579	शून्य
	जोड़ ताप विद्युत :		4167·0		
	(ख) जल विद्युत		वर्ष 1989-90		
	1. माही चरण-2 90	राजस्थान	45	20200	100
	2. डब्ल्यू वाई सी सोंपान 16	हरियाणा	8	11721	144
	3. कडाना पी एस एस 120	गुजरात	60	12926	2857
	4. खड़कवासला 16	महाराष्ट्र	16	2133	60
	5. नागार्जुन सागर आर बी सी 60	ए० पी०	30	5588	67
	6. वाराही 239	कर्नाटक	115	24500	750

1	2	3	4	5	6
7.	लोवर भवानी 8	टी० एन०	4	2080	79
8.	वैगही बांध टी० 6	टी० एन०	6	1408	30
9.	पंचेत हिल विस्तार 40	डी० वी० सी०	40	6292	1835
10.	अपर कोलाब चरण-1 240	उड़ीसा	80	20401	—
11.	रेंगाली विस्तार 150	उड़ीसा	100	7100	1310
12.	तागो 45	अरू० प्र०	1·5	1065	49
		जल विद्युत जोड़	505.5		
जोड़ ताप विद्युत एवं जल विद्युत			=	4672·5 मेगावाट	
(ग) मिनी हाइड्रा				4·4 मेगावाट	
(घ) अपराम्परिक स्रोत				10·8 मेगावाट	
कुल जोड़ (ग) से (घ)				4687.7 मेगावाट	
(अ) (ताप विद्युत			वर्ष 1990-91		
1.	औरेया एसटी-2 4×112 जीटी+ 2×102 एस टी	यू० पी०	102	63292	6435
2.	कच्छ लिगनाइट 2×70	गुजरात	70	25300	200
3.	वातवा जीटी-1 (2×33 जीटी+ 33 एस टी	गुजरात	33	एन०ए०	एन०ए०/निजी क्षेत्र
4.	विन्ध्याचल 6×210	एम० पी०	210	158098	9406

1	2	3	4	5	6
5.	चन्दपुर 2×500	महाराट्र	500	998842	3500
6.	विजेशवरम 2×33 जीटी+ 1×33 एसटी	ए० पी०	66	13400	शून्य
7.	रायचुर 1×210	कर्नाटक	210	28400	2483
8.	नवेली 4×210	टी०एन०	210	136324	19382
9.	तुटीकोरिन 2×210	टी० एन०	210	70724	14442.54
10.	दक्षिण विद्युत उत्पादन केन्द्र (सी०ई०एस०सी०) 2×67·5	प० बंगाल	67·5	25433	शून्य
11.	कोलघाट 3×210	प० बंगाल	210	41808	शून्य
12.	कालघाट 3×210	प० बंगाल	210	99723	8472
13.	बोकारो "ख"-2 2×210	बिहार	210	39134	8464
14.	रोखिया जी० टी० 2×8	त्रिपुरा	8	3579	शून्य
15.	डी० जी० सेट इम्फाल 2×1	मणिपुर	2	106	10
16.	छताम में डी०जी० सेट 5×2·5	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	12·5	2140·	216
	योग ताप विद्युत		2331·0		
(ख)	जल विद्युत		1990-91		
1.	बनसागर टोन्स 315	राजस्थान	210	57802	14762

1	2	3	4	5	6
2.	काणेहर 4	महाराष्ट्र	4	637	50
3.	काडना 120	गुजरात	60	12926	2857
4.	भातसा 15	महाराष्ट्र	15	1442	50
5.	वाराही 239	कर्नाटक	115	24500	750
6.	लोअर भवानी 8	तमिलनाडु	4	2080	79
7.	हिराकुण्ड चरण-3	उड़ीसा	37.5	3618	—
	योग जल विद्युत		445.5		
	योग ताप विद्युत एवं जल विद्युत		2776·5		
क्र०	ताप विद्युत	वर्ष 1991-92			
1.	रोपड़ 2 × 210 मे० वा०	पंजाब	210	60000	15,926
2.	एबसीटीपीपी 4 × 210 मे० वा०	उ०प्र०	210	157917	62904
3.	दादरी जीटी 4 × 131 मे०वा० एसटी 2 × 146·5 मे०वा०	उ०प्र०	262	97920	54388
4.	गांधी नगर 1 × 210 मे०वा०	गुजरात	210	21100	700
5.	वातवा जीटी-2 × 33 मे०वा० एसटी-1 × 33 मे०वा०	गुजरात	66	एट०एन०	एन०ए०
6.	उत्राण जीटी-3 × 33 मे०वा० एसटी-1 × 33 मे०वा०	गुजरात	66	22704	4500

1	2	3	4	5	6
7.	कवास जीटी-4 × 106 मे०वा० एसटी-2 × 110 मे०वा०	गुजरात	106	149451	46100
8.	चन्द्रपुर 2 × 500 मे०वा०	महाराष्ट्र	500	98842	3500
9.	विजेश्वरम जीटी-2 × 33 मे०वा० एसटी-1 × 33 मे०वा०	आन्ध्रप्रदेश	33	13400	शून्य
10.	नरीमन जीटी-2 × 5 मे० वा०	तमिलनाडु	10	3373	200
11.	नैवेली 4 × 210 मे०वा०	तमिलनाडु	210	136324	19382
12.	तूतीकोरिन 2 × 210 मे०वा०	तमिलनाडु	210	70724	14442·54
13.	दक्षिणी जेनेरेटर 2 × 67.5 मे०वा०	प० बंगाल	67·5	25433	शून्य
14.	कहलगांव एसटीपीएस-1 4 × 210 मे०वा०	बिहार	210	185519	48987
	जोड़ ताप विद्युत=:		2370·5 मे० वा०		

ख० जल विद्युत — वर्ष 1991-92

1.	यूबीडीसी-2 45 मे० वा०	पंजाब	30	9992	1831
2.	बंगदोल 6 मे० वा०	राजस्थान	6	1784	466
3.	टनकपुर 120 मे० वा०	उ०प्र०/एनएचपीसी	120	40088	1570
4.	खारा 72 मे० वा०	उ० प्र०	72	21808	19
5.	बाणसागर टौन्स 405 मे०वा०	म० प्र०	105	57802	114762

1	2	3	4	5	6
6.	सूरतगढ़ 4 मे० वा०	राजस्थान	4	एन० ए०	एन० ए०
7.	बिरासंगपुर 20 मे० वा०	म०प्र०	20	2420	448
8.	नागार्जुनसागर एलबीसी-60 मे०वा०	वा० प्र०	60	5588	233
9.	घाटप्रभा 32 मे० वा०	कर्नाट.	16	3680	259
10.	टागो 4.5 मे० वा०	अरुणाचल प्रदेश	3·0	1065	49
		जल विद्युत जोड़=	436·0		
	ताप विद्युत और जल विद्युत का जोड़		2806·5		
	(ग) न्यूक्लीय		220.0		
	कुल जोड़ (क) से (ग) :		3026.5		
			वर्ष 1992-93		
(क)	ताप विद्युत		(30-11-92 तक)		
1.	दादरी जोटी-4×131 मे०वा० एसटी-2×146.5 मे०वा०	उ०प्र०	262	97920	54388
2.	कवास जीटी-4×106 मे०वा० एसटी-2×110 मे०वा०	गुजरात	318	149451	46100
3.	नैवेली 4×210 मे०वा०	तमिलनाडु	210	136324	19382

1	2	3	4	5	6
4.	फरक्का 2 × 500 मे०वा०	प० बंगाल	500	195425	31903
		ताप विद्युत जोड़ : 1290 मे० वा०			
(ख)	जल विद्युत	वर्ष 1992-93 (30-11-92 तक)			
1.	उमीयात उमट्रू 60 मेगावाट	मेघालय	60	11476	1437
2.	अपर कौलाब 80 मेगावाट	उड़ीसा	80	284	186
3.	रेंगाली विस्तार 150 मेगावाट	उड़ीसा	50	7100	1310
4.	शिवपुर 18 मेगावाट	कर्नाटक	18	3060	निजी क्षेत्र
5.	घाटप्रभा 32 मेगावाट	कर्नाटक	16	3680	259
6.	अपर रोगनीचू 8 मेगावाट	सिक्किम	2	2832	388
		जल विद्युत योग 226			
		ताप विद्युत एवं जल विद्युत योग 1516			

इस्पात का मूल्य

[अनुवाद]

*192. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

श्री शरद यादव :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के बाद सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात एककों में अनबिका स्टाक एकत्र हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समय और नियंत्रण हटाने से पहले एकत्र

स्टाक का अनुमानित मूल्य कितना-कितना रहा तथा प्रति माह अनुमानतः कितना ब्याज दिया जा रहा है;

(ग) इस सम्बन्ध में कौन-से कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) इस समय तथा नियंत्रण हटाने से पहले इस्पात की विभिन्न मदों का मूल्य क्या-क्या रहा; और

(ङ) स्वदेशी तथा विदेशी बाजारों में इस्पात की विभिन्न मदों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस्पात संयंत्रों के पास लोहे और इस्पात मदों के स्टाक का संचयन अनेक घटकों पर निर्भर करता है जैसे कि उत्पाद की समग्र मांग और मौसमी उतार-चढ़ाव, मुद्रा बाजार की स्थिति तथा बाजार का दबाव सरकारी खर्च का स्तर, उत्पादन तथा आयात आदि का स्तर, आदि । इन घटकों पर निर्भरता के कारण इस्पात संयंत्रों का स्टाक समय-समय पर घटता-बढ़ता रहता है ।

(ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा स्टाक को कम करने के लिए किये गये अथवा प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं :—

(i) विभिन्न उत्पादों की बाजार में मांग और विपणन क्षमता को मद्देनजर रखते हुए उत्पाद-मिक्स पर पुनः कार्य संचालन;

(ii) ग्राहकों से सम्बन्ध सुधारना;

(iii) उपभोक्ताओं को ऋण सुविधाओं का चयनात्मक विस्तार;

(iv) निर्यात बढ़ाने के लिए सम्भावनाओं का पता लगाना;

(v) वितरण संजाल का विस्तार/सुदृढ़ करना ।

(ङ) स्वदेशी बाजार की तुलना में अन्य देशों में मूल्यों के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दूरदर्शन ट्रांसमिशन के संबंध में भारत-ईरान समझौता

[हिन्दी]

*193. **श्री रतिलाल वर्मा** :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो और टेलीविजन सम्बन्धी ट्रांसमिशन के बारे में चर्चा करने के लिए किसी ईरानी शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) ईरान इस्लामिक गणराज्य प्रसारण के एक ईरानी शिष्टमंडल ने दोनों देशों के बीच रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग पर विचार करने के लिए अक्तूबर, 1992 में भारत का दौरा किया था। एक समझौता ज्ञापन पर 21 अक्तूबर, 1992 को हस्ताक्षर किये गये थे तथा इस समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य प्रसारण के बीच रेडियो और टेलीविजन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

महत्वपूर्ण उपबन्ध :—

1. फारसी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों और फिल्मों के वीडियो तथा आडियो टेपों का आदान-प्रदान।
2. तकनीकी क्षेत्रों में व्यावसायिक सूचना तथा सहयोग का आदान-प्रदान।
3. रेडियो और टेलीविजन से सम्बन्धित क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक-दूसरे से परामर्श।
4. दोनों देशों के राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर रेडियो और टेलीविजन पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करना।
5. फोटो समाचारों और टी० वी० कार्यक्रमों का आदान-प्रदान।
6. दोनों पक्ष अपने देश की प्रणाली व्यवस्था के माध्यमों को क्षीण करने के उद्देश्य से किए गए प्रतिकूल प्रचार-प्रसार विशेषकर सरकारी मीडिया द्वारा और नकारात्मक रिपोर्टों का खण्डन करने में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।

यू० एन० आई० के पत्रकारों की मांगें

*194. **श्री राम विलास पासवान** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एन० आई० के पत्रकारों ने हाल ही में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) यू०एन० आई० में हड़ताल थी। प्राप्त सूचना के अनुसार हड़ताल का कारण उनके मुख्य लेखाकार की सेवाओं को समाप्त करना था। नीति सम्बन्धी मामला होने के कारण सरकार समाचार एजेंसियों के इस प्रकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती।

विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा भारतीय फिल्मों का प्रसारण

[अनुवाद]

*195. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क प्रदर्शन-अधिकार खरीद कर भारतीय फिल्में दिखा रहे हैं और इस प्रकार दूरदर्शन से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन एजेंसियों की कुल कितनी फिल्में और दूरदर्शन द्वारा तैयार किये गये अन्य कार्यक्रम बेचे गये तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में और भारतीय मुद्रा में कितनी आय हुई और इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान फिल्मों तथा अन्य दूरदर्शन कार्यक्रमों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा/रुपये व्यय किये गये; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय टी० वी० नेटवर्कों पर टेलीकास्ट भारतीय फिल्मों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह सूचना नहीं रखी जाती।

(ग) फिल्मों तथा अन्य टी० वी० कार्यक्रमों को निर्यात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, फिल्मों तथा टी० वी० कार्यक्रमों के आयात को सरकार की निर्यात तथा आयात नीति द्वारा विनियमित किया जाता है।

दिल्ली और कलकत्ता के लिए विमान सेवाएं

[हिन्दी]

*196. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से आज तक दिल्ली तथा कलकत्ता हवाई अड्डों पर कितनी बार घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में बाधा आई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जनवरी, 1992 से अवरुद्ध उड़ानों की कुल संख्या

	दिल्ली	कलकत्ता
एअर इंडिया (2 नवम्बर, 1992 तक)	26	11
इंडियन एअरलाइंस (जनवरी, 92 तक)	2406	2873
वायुदूत (अक्तूबर, 1992 तक)	378	566

(ख) उड़ानें मुख्य रूप से, तकनीकी, वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कारणों तथा खराब मौसम बम्ब की धमकी, पक्षियों के टकराने, धावन-पथ की मरम्मत आदि जैसे कारणों से अवरुद्ध हुईं।

(ग) उड़ानों में व्यवधान को रोकने के लिए, समय पर उड़ानों की कड़ी निगरानी रख ा, बार-बार होने वाली खराबी को ठीक करना, समयावलियों को युक्ति-संगत बनाना, पर्याप्त कल-पुर्जों का रख-रखाव आदि जैसे उपाय किये गये हैं।

दिल्ली में बिजली की चोरी

[अनुवाद]

*197. **श्री जीवन शर्मा :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए बिजली की चोरी रोक पाना सम्भव नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले छः महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सहित विभिन्न एजेंसियों, जिनसे उसने बिजली खरीदी है को करोड़ों रुपये देय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस धनराशि की अदायगी करने तथा बिजली की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिजली की चोरी के विरुद्ध अभियान एक सतत् प्रक्रिया है। मई—अक्तूबर, 1992 के दौरान डेसू द्वारा 14,235 मामलों की जांच की गई थी और विद्युत की चोरी तथा बिजली के उपभोग के सन्दर्भ में दुरुपयोग/अन्य उल्लंघनों से सम्बन्धित 9968 मामलों का पता लगाया गया था। इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा 156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) और (घ) विद्युत सप्लाई के सन्दर्भ में 30-11-92 की स्थिति के अनुसार, डेसू की ओर विभिन्न एजेंसियों की लगभग निम्नलिखित राशियां (प्रभारों सहित) बकाया है :—

(करोड़ रुपये में)

1.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बी० टी० पी० एस०)	: 2255
2.	नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०)	: 115
3.	नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन० एच० पी० सी०)	13
4.	अन्य (भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड आदि)	: 34

(ङ) डेसू बिद्युत की खरीद, विशेषरूप से वी० टी० पी० एस० से प्राप्त की गई विद्युत का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसे आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त टैरिफ, निवेश सम्बन्धी लागत में वृद्धि एवं अन्य प्रचालनात्मक खर्चों के कारण अत्यधिक राजस्व सम्बन्धी कमी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली प्रशासन/डेसू को बकाया राशियों का भुगतान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाए जाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। डेसू द्वारा बिजली की चोरी को रोकने हेतु छापों में तेजी लाई गई है जिससे भारतीय बिजली अधिनियम के अन्तर्गत एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है

बिहार में पर्यटन स्थल

[हिन्दी]

*198. श्री साईमन मरान्डी :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान राजमहल, डमतार मथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से वर्ष 1991-92 और 1992-93 में परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं परन्तु कोई भी प्रस्ताव राजमहल और डमतार के विकास से सम्बन्धित नहीं है।

प्राप्त प्रस्ताव पर्यटक सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के बारे में हैं। जैसे पर्यटक आवास मुहैया कराना, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, जन सुविधाएं, साहसिक क्रीड़ा उपकरण जुटाना, मेलों, उत्सवों तथा प्रचार आदि के लिए सहायता देना। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान 12 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और वर्ष 1992-93 के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के लिए 15.6 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन

*199. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और अब तक राज्यवार प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन निदेशों का ईमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) जी, हां । समय-समय पर दूरसंचार/टेलीफोन के सभी महाप्रबन्धकों को इस मंत्रालय के अनुदेश जारी किये जाते रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिना बारी के मंजूर किये गये टेलीफोनों को अधिक-से-अधिक 30 दिन की अवधि के भीतर संस्थापित कर दिया जाए बशर्ते कि ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो और विभागीय औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया हो ।

(घ) और (ङ) कुल मिलाकर क्षेत्रीय एककों द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है परन्तु ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें अलग-अलग कारणों से इस समय-सीमा से अधिक समय लग जाता है ।

विवरण

वर्ष 1990, 1991 और 1992 (30-11-92 तक) के दौरान बिना बारी प्राथमिकता के आधार पर संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र० सं०	दूरसंचार सर्किल का नाम	मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या		
		1990	1991	1992 (30-11-92 तक)
1	2	3	4	5
1.	असम	55	226	291
2.	आंध्र प्रदेश	328	1616	2978
3.	बिहार	112	448	288
4.	गुजरात	82	631	410
5.	हरियाणा	215	2046	705
6.	हिमाचल प्रदेश	24	51	48
7.	जम्मू और कश्मीर	58	143	428
8.	कर्नाटक	97	1019	985

1	2	3	4	5
9.	केरल	794	573	899
10.	मध्य प्रदेश	263	650	706
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	456	928	803
12.	उत्तर-पूर्व सर्किल*	32	145	78
13.	उड़ीसा	65	107	103
14.	पंजाब	641	1473	1018
15.	राजस्थान	335	1414	2378
16.	तमिलनाडु	398	944	1145
17.	उत्तर प्रदेश	2713	3304	2231
18.	पश्चिम बंगाल	185	438	424
19.	म०टे०नि०लि० बम्बई	302	1184	535
20.	म०टे०नि०लि० नई दिल्ली	7743	12587	7624
	कुल :	14898	29932	24077

भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच शृंखला का दूरदर्शन से प्रसारण

*200. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

श्री रवि राय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट टैस्ट मैचों की शृंखला दूरदर्शन द्वारा भारत में न दिखाये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मैच के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे दिखाये जाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैचों को प्रसारित करने के लिए पर्याप्त इन्तजाम किए हैं। यद्यपि सभी एक-दिवसीय मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, लेकिन सभी

*इसमें अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के राज्य शामिल हैं।

टैस्ट मैचों के प्रत्येक दिन के खेल के 30 मिनट के मुख्य अंश उसी दिन शाम को दिखाए जाएंगे तथा अगले दिन उन्हें पुनः प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एक-दिवसीय मैच के 40 मिनट के मुख्य अंशों को मैच के अगले दिन प्रसारित किया जाएगा। 13 से 17 नवम्बर, 1992 तथा 26 से 30 नवम्बर, 1992 तक खेले गए पहले तथा दूसरे टैस्ट मैच के मुख्य अंशों का प्रसारण पहले ही किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत वित्तीय निगम द्वारा विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण

2089. **श्री राम पाल सिंह :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत वित्तीय निगम द्वारा विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) इस निगम द्वारा 30 नवम्बर, 1992 तक देश में वित्त पोषित की गई और स्वीकृति प्रदान की गई विद्युत परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) विद्युत वित्तीय निगम द्वारा शेष विशेषतः उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजनाओं को कब से धनराशि प्रदान जी जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पी० एफ० सी० द्वारा निम्नवत मानडण्ड अपनाए गए हैं :—

(1) पी० एफ० सी० संतुष्टि हेतु समयबद्ध रूप से प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्यवाही योजना (ओ० ई० ए० पी०) तैयार करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड (एस० ई० बी०) और राज्य विद्युत उत्पादन निगम (एस० जी० सी०) द्वारा ऋण सहायता के लिए अनुरोध किया जाना।

(2) निम्न मानदण्डों की पूर्ति के लिए परियोजनाओं हेतु पी० एफ० सी० ऋण प्रदान करता है :—

(क) आर्थिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण हो और लाभांश की दर 12% से कम न हो;

(ख) तकनीकी दृष्टि उपयुक्त;

(ग) प्रस्तावित तकनीकी समाधानों की लागत न्यूनतम होनी चाहिए,

(घ) विद्यमान विस्तार योजनाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

(ङ) प्रस्तावित समाधान जो कि अधिक युक्ति युक्त हो, भारत सरकार अथवा राज्य के पर्यावरणीय एवं इसको प्रभावित करने वाले मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए,

(च) राज्य और संघ एजेन्सियों द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की स्वीकृतियां स्कीम के लिए प्राप्त की जानी चाहिए।

वित्तपोषण के लिए जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ये निम्नवत है :—

(क) ताप विद्युत एवं जल विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

(ख) प्रणाली सुधार

(ग) पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का विस्तार और

(घ) निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पूरा करना ।

पी० एफ० सी० केवल ऐसे राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहागता प्रदान करता है जिसकी राज्य सरकारें इस बात की पुष्टि करती हैं कि विद्युत (प्रदान अधिनियम) में निहित सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण की अपेक्षा राज्य बिजली बोर्ड के अधिशेष राजस्व से पी० एफ० सी० ऋण की राशि को वसूल किए जाने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

30 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार निगम द्वारा वित्तपोषित और स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

पी० एफ० सी० द्वारा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। यदि सम्बन्धित ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है और वित्त पोषण के लिये पी० एफ० सी० द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति भी की जाती है तो ऋण सम्बन्धी प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाती है और शीघ्र अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

जहां तक यू० पी० एस० बी० का सम्बन्ध है, पी० एफ० सी० द्वारा यू० पी० एस० ई० बी० के नये ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने से पूर्व इसे निम्न शर्तों की पूर्ति करनी होगी ।

(1) पी० एफ० सी० की संतुष्टि के लिये यू० पी० एस० ई० बी० का प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्यवाही योजना को अन्तिम रूप देना होगा ।

(2) पी० एफ० सी० को गारण्टी सम्बन्धी प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में गारण्टी की राशि को बढ़ाकर अथवा अपनी डैण्ट सर्विस कवरेज रेशों में सुधार करके अपनी क्रियाकलापों में विस्तार करने के लिए यू० पी० एस० ई० बी० को आवश्यक कदम उठाने होंगे ।

3. यू० पी० एस० ई० बी० का पी० एफ० सी० के ऋण को सम्मत पद्धति के अनुसार भुगतान करते रहने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	ऋण प्राप्तकर्ता	स्वरूप	परियोजना
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	ए० पी० एस० ई० बी०	टी०एच०जी०	विजयवाड़ा -चरण-2
2.		—वही—	ट्रांसमिशन	पालांचा रामागुण्डम
3.		—वही—	एस० आई०	400 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
4.		—वही—	आर०एम० 7सी०	कोथागुडम सातवीं योजना सी०एल०ए०
5.		—वही—	ट्रांसमीशन	विशाखापत्तनम
6.		—वही—	ट्रांसमीशन	220 के०वी० कुड्डापाह.
7.		—वही—	ट्रांसमशिन	रामागुण्डम निजामाबाद
8.		—वही—	टी०एच०जी०	विजयवाड़ा चरण-2
9.		—वही—	—वही—	विजयवाड़ा चरण-2
10.		—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० विजयवाड़ा से
11.		—वही—	ट्रांसमिशन	लांगर हाउस
12.		—वही—	—वही—	मिरयालगुडा 100
13.		—वही—	—वही—	श्रीसेल्म-ओंगल

1	2	3	4	5
14.		ए०पी०एस०ई०बी०	टी०एच०जी०	विजयवाड़ा चरण-2
15.		—वही—	ट्रांसमिशन	कुरनूल-समाया
16.		—वही—	—वही—	100 एम०वी०ए० 220/132 के०वी
17.		—वही—	यू० डी०	हैदराबाद
18.		—वही—	टी०एच०जी०	विज्जेश्वरम जी०टी०
19.		—वही—	ट्रांसमिशन	सिक्स 132/33 के०वी० एस/एस
20.		—वही—	ट्रांसमिशन	200 के०वी० एवं 132 के०वी० वी०टी०पी०एस-गुन्टूर -चिलाकालूरिपेट लाइन
21.		—वही—	टी०एच०जी०	रायलसीमा टी०पी०पी० (सीएफस एशिया विकास बैंक के ऋण)
22.		—वही—	आर०एस-7एस	कोठागुडम सातवीं योजना एस०पी०
23.		—वही—	यू०डी०	ऊर्जा लेखा परीक्षा
24.		—वही—	एच०वाई०जी०	अपर सिलेर (एम०जा० मे०वा०)
25.		—वही—	ट्रांसमिशन	220/132 के०वी० एस/एस, काली किरी
26.		—वही—	यू०डी०	विजय नगरम
27.		—वही—	यू०डी०	गुन्टूर
28.		—वही—	यू०डी०	इलुरू
29.		—वही—	ट्रांसमिशन	3 नम्बर 132 के०वी नए उपकेन्द्र
30.		—वही—	—वही—	7 नम्बर की विस्तार 132 के०वी० वर्तमान उपकेन्द्र

1	2	3	4	5
31.		ए०पी०एस०ई०बी०	यू०डी०	विजयवाड़ा
32.		—वही—	यू०डी०	परोद्दाटुर
33.		—वही—	यू०डी०	भिमावराम
34.		—वही—	ट्रांसमिशन	ट्रांसफार्मर की विस्तार, 132/33 के०वी०क्षमता की 3 उपकेन्द्रों में एस०/एस०
35.		—वही—	—वही—	ट्रांसफार्मर की विस्तार, युद्दू मालम में क्षमताएं कुरनूल
36.		—वही—	—वही—	220/132 के०वी० 1 × 100 एम०वी०एस०एस०/एस, पेनुदरथी
37.		—वही—	टी०एच०जी०	विजयवाड़ा टी० पी० एस० चरण-3
38.		—वही—	ट्रांसमिशन	वी०टी०पी०एस० चरण-3 से पावर एवेक्युएशन हेतु पारेषण प्रणाली
39.		—वही—	—वही—	कोठागुडम आठवीं योजना
40.		—वही—	—वही—	ई०एच०वी० उपकेन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
41.		—वही—	यू०डी०	कुडापाहा
42.		—वही—	आर०एम०-8	नैल्लौर आठवीं योजना
43.		—वही—	ट्रांसमिशन	वी०एच०एफ संचार प्रणाली
44.		—वही—	यू०डी०	महबूबनगर
45.		—वही—	यू०डी०	करीम नगर
46.		—वही—	एस०आई०	600 एम०वी०ए०आर० 33के०वी०कैपेसिटर बैंक्स

1	2	3	4	5
47.		ए०पी०एस०ई०बी०	ट्रांसमिशन	4 नम्बर 200 के०वी० एवं 2 नम्बर 132 के०वी० उपकेन्द्रों का विकास
48.		—वही—	ट्रांसमिशन	14 नम्बर 132 के०वी० एस/एस का विस्तार
49.		—वही—	यू०डी०	हैदराबाद फेज-2
50.		—वही—	ट्रांसमिशन	आन्ध्र प्रदेश विद्युत प्रणाली में विद्यमान पी०एल०सी०सी० उपकरण का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण
51.		—वही—	ट्रांसमिशन	220/132 के०वी० सिंगल सर्किट महबूब नगर और कलावकुर्थी एवं पारेषण लाइन की स्थापना
52.		—वही—	ट्रांसमिशन	तदेपल्ली-ओनगोल 132 के०वी०सिंगल सर्किट लाइन के पुनर्निर्माण द्वारा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
53.		—वही—	टी० एच० जी०	विजयवाड़ा ता०वि०के० चरण-3(2×210 मेगावाट
54.	1. अरूणाचल प्रदेश	ए०आर०पी०	एच०वाई०जी०	टागो माइक्रो एच०ई०पी०
55.	1. असम	ए०एस०ई०बी०	ट्रांसमिशन	असम में पारेषण कार्य
57	1. बिहार	बी०एच०पी०सी०	एच०वाई० जी०	पूर्वी गण्डक
57.	2.	—वही—	एच०वाई०जी०	सोन कैनाल
58.	3.	बी०एस०ई०बी०	आर०एस० 7सी०	कारबोगांगिया
59.	4.	—वही—	आर०एस० 7सी०	बरौनी
60.	5.	—वही—	ट्रांसमिशन	हाथीवाह, 400 के०वी० बिहारशरीफ-बेगुसराय लाइन में प्रचालन में है ।

1	2	3	4	5
61.	6.	बी०एस०ई०बी०	आर०एम० 7सी०	पतरातु
62.	7.	—वही—	यू०डी०	राची विद्युत सप्लाई का नवीकरण व रि-वेंपिंग
63.	8.	—वही—	ट्रांसमिशन	220के०वी० डी०सी० बेगुसराय-पुर्णिया लाइन तथा एस/एस बेगुसराय में
64.	9.	—वही—	ट्रांसमिशन	132 के०वी० पुर्णिया-कटिहार लाइन तथा कटिहार में एस०/एस०
65.	10.	—वही—	आर०एम०-7एस	बरौनी सातवीं योजना (एस०पी०)
66.	11.	—वही—	ट्रांसमिशन	132 के०वी० सुल्तानगंज
67.	12.	—वही—	एस०आई०	135 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
68.	13.	—वही—	आर०एम०-7 एस०	पतरात सातवीं योजना (एस०पी०)
69.	14.	टी०वी०एन०एल०	टी०एच०जी०	तेनुघाट टी०पी०एस० (2 × 210मेगावाट)
70.	15.	—वही—	टी०एच०जी०	तेनुघाटी टी०पी०एस० (2 × 210 मेगावाट)
71.	16.	—वही—	टी०एच०जी०	तेनुघाट टी०पी०एस० (2 × 210मेगावाट)
72.	17.	—वही—	टी०एच०जी०	तेनुघाट चरण-I
73.	18. गुजरात	जी०ई०बी०	आर०एम० 7सी०	धुवरण 7वीं योजना सी०ए०एल०
74.	2.	—वही—	आर०एम०-7सी०	उकई सातवीं योजना सी०ए०एल०
75.	3.	—वही—	आर०एम०-7सी	गांधीनगर सातवीं योजना सी०एल०ए०
76.	4.	—वही—	एस०आई०	300 एम०वी०ए०आर कैपेसिटर्स
77.	5.	—वही—	यू०डी०	बड़ौदा

1	2	3	4	5
78.	6.	जी०ई०वी०	टी०एच०जी०	गांधीनगर टी०पी०एस० चरण-2 यूनिट-3
79.	7.	—वही—	ट्रांसमिशन	हिम्मतनगर में 220 के०वी० एस०/एस०
80.	8.	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० कोदीनार लाइन
81.	9.	—वही—	टी०एच०जी०	कच्छ लिग्नाइट यूनिट 1 एवं 2
82.	10.	—वही—	एस०आई०	150 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
83.	11.	—वही—	ट्रांसमिशन	वालिया में 132 के०वी० एस०/एस०
84.	12.	—वही—	ट्रांसमिशन	भिलाद में 220/66के०वी० एस०/एस० तथा सम्बद्ध लाइनें
85.	13.	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० लिम्बडी-धारंगधारा लाइन तथा धारंग धारा में 220के०वी० एस०/एस०
86.	14.	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० जेरदा एस०/एस० तथा 220 के०वी० पालमपुर-जेरदा लाइन
87.	15.	—वही—	टी०एच०जी०	गांधीनगर टी०पी०एस० यूनिट-4
88.	16.	—वही—	टी०एच०जी०	उतराण गैस टर्बाइन संयंत्र
89.	17.	—वही—	ट्रांसमिशन	400के०वी० असोज-लिम्बड़ी-जैतपुर लाइन एवं लिम्बड़ी में एस०/एसे०
90.	18.	—वही—	आर०एम०-7 एस०	उकई सातवीं योजना एस०पी०
91.	19.	—वही—	आर०एम०-7 एस०	धुवरण 7वीं योजना एस०पी०
92.	20.	—वही—	यू०डी०	बलसाद
93.	21.	जी०ई०वी०	यू०डी०	महुआ टाउन

1	2	3	4	5
94.	22.	जी०ई०बी०	आर०एम०-8	नकोबोरी आठवीं योजना
95.	23.	—वही—	—वही—	गांधीनगर आठवीं योजना
96.	24.	—वही—	टी०एच०जी०	सिक्का 1×120 मेगावाट
97.	25.	—वही—	—वही—	उतराण पावर
98.	26.	—वही—	आर०एम०-8	ध्रुवरण टी०पी०एस० आठवीं योजना
99.	27.	—वही—	यू०डी०	पोरबन्दर
100.	28.	—वही—	—वही—	नाडियाड
101.	29.	—वही—	एस०आई०	500 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स बैंक की स्थापना
102.	1. हिमाचल प्रदेश	एच०पी०ए०ई०बी०	आर०यु०	गिरि एच०ई०पी०आर० एण्ड यू
103.	2.	—वही—	एच०बाई०जी०	गज एच०ई०पी०
104.	3.	—वही—	—वही—	बनेर एच०ई०पी०
105.	4.	—वही—	एस०आई०	36 एम०वी०ए०आर०
106.	5.	—वही—	यू० डी०	शिमला
107.	6.	हिमाचल प्रदेश सरकार	आर०यू०	भाखड़ा, दाहिना किनारा एच०ई०पी० 5×120 मे०वा०
108.	7.	एच०पी०एस०ई०बी०	ट्रांसमिशन	132 के०वी०डी०सी० जैसौर-बेहरा लाइन
109.	8.	—वही—	—वही—	132 के०बी०एस०सी० कुनिहार शिमला लाइन
110.	9.	—वही—	—वही—	132 के०वी०एस०सी० गिरि-पोंटा लाइन
111.	10.	—वही—	एच०वाई०जी०	बनेर एच०ई० परियोजना (3×4 मे०वा०)
112.	11.	—वही—	—वही—	गाज एच०ई० परियोजना (3×3.5 मे०वा०)

	2	3	4	5
113.	12.	एच०एस०ई०बी०	आर०यू०	भाभा जल विद्युत केन्द्र की मरम्मत तथा देखरेख
114.	1. हरियाणा	—वही—	टी०एच०जी०	पानीपत चरण-3 यूनिट-4 एवं 5
115.	2.	—वही—	ट्रांस	समापुर—पलवल
116.	3.	—वही—	आर०एम०-7सी०	फरीदाबाद सातवीं योजना सी०एल०ए०
117.	4.	—वही—	—वही—	पानीपत सातवीं योजना सी०एल०ए०
118.	5.	—वही—	एस०आई०	300 एम०वी०ए०आर०
119.	6.	—वही—	टी०एच०जी०	पानीपत चरण-3 यूनिट 4 एवं 5
120.	7.	—वही—	एस०आई०	165 एम०वी०ए०आर०
121.	8.	—वही—	यू०डी०	करनाल
122.	9.	—वही—	—वही—	जगाधरी
123.	10.	—वही—	—वही—	रोहतक
124.	11.	—वही—	—वही—	अम्बाला कैंट
125.	12.	—वही—	—वही—	यमुनानगर
126.	13.	—वही—	ट्रांसमिशन	सिरसा तथा नरवाना में 220/132 के०वी०एस०/एस० (बढ़ती हुई क्षमता)
127.	14.	—वही—	यू०डी०	गुड़गांव
128.	15.	—वही—	आर०एम०-7 एस०	फरीदाबाद सातवीं योजना एस०पी०
129.	16.	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी०डी०/सी० कैथल शाहाबाद लाइन तथा शाहबाद में एस/एस

1	2	3	4	5
130.	17.	एच०एस०ई०बी०	ट्रांसमिशन	220 के०वी०पी०टी०पी०एस० रोहतक, पी०टी०पी०एस० सोनीपत लाइन तथा रोहतक और सोनीपत में एस/एस
131.	18.	—वही—	एस०आई०	45 एम०वी०ए०आर०
132.	19.	—वही—	आर०एम०-8	पानीपत आठवीं योजना
133.	20.	—वही—	यू०डी०	अम्बाला सिटी
134.	21.	हरियाणा सरकार	आर०यू०	भाखड़ा दाहिना किनारा एच०ई०पी० (5×120 मे०वा०
135.	1. जम्मू एवं कश्मीर	जे० एण्ड के०	टी०एच०जी०	एम्पोर गैस टर्बाइन संयंत्र
136.	1. कर्नाटक	के०ई०बी०	ट्रांसमिशन	हन्तागली-शिमोगा
137.	2.	—वही—	एस०आई०	110 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स बैंक
138.	3.	—वही—	ट्रांसमिशन	शिवासुन्दरम
139.	4.	—वही—	टी०एच०जी०	येलाहांका टी०पी०पी० (फ्रांसीसी ऋण)
140.	5.	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी०डी०/सी० तालागुपा-कोटागुनूर-शिमोगा लाइन
141	6.	—वही—	यू०डी०	बंगलौर सिटी (शहरी वितरण)
142.	7.	—वही—	एस०आई०	255 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
143.	8.	—वही—	ट्रांसमिशन	बंगलौर स्थित भार प्रेषण केन्द्र का आधुनिकीकरण
144.	9	के० ई० बी०	यू० डी०	97.5 एम०वी०ए०आर०, 11 के०वी० सेट कैपेसिटर बैंक 39 संख्याओं में, कर्नाटक में एस०/एस०
145.	10	के० ई० बी०	ट्रांसमिशन	बेलगांव में 220/110/11 के०वी० एस०/एस० के ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि

1	2	3	4	5
146.	11	के० ई० बी०	ट्रांसमिशन	1×16 एम०वी०ए० की स्थापना, रानेबेनूर एस०/एस० में 110/11 के०वी० ट्रांसफार्मर
147.	12	के० ई० बी०	ट्रांसमिशन	66/11 के०वी० के नये एस०/एस० तथा सम्बद्ध लाइनों की स्थापना
148.	13	के०पी०सी०एल०	एच०वाई०जी०	वराही एच०ई०पी०
149.	14	—वही—	टी०एच०जी०	रायचूर टी०पी०एस०
150.	15	—वही—	टी०एच०जी०	रायचूर टी०पी०एस०
151.	16	—वही—	एच०वाई०जी०	घाटप्रभा एच०ई०पी०
152.	17	—वही—	,,	वराही एच०ई०पी०
153.	18	—वही—	,,	मालापुर मिनी एच०ई०पी०
154.	19	—वही—	टी०एच०जी०	रायचूर टी०पी०एस०
155.	1 केरल	के०एस०ई०बी०	एच०वाई०जी०	पोरिंगलकुथु
156.	2	—वही—	एस०आई०	50 एम०वी०ए०आर० 11 के०वी० कैपेसिटर
157.	3	—वही—	यू०डी०	कोल्लाम
158.	4	—वही—	,,	अल्लापुझा
159.	5	—वही—	,,	थाल्लासेरी
160.	6	—वही—	,,	पल्लाकाड
161.	7	—वही—	ट्रांसमिशन	110 के०वी० सस्थामकोट्टा, कायमकुलम, कुमाराकोम तथा सम्बद्ध लाइनें

1	2	3	4	5
162.	8	के०एस०ई०बी०	यू०डी०	कोटायम
163.	9	—वही—	एच०वाई०जी०	पोरिंगलकुथु एच०ई०पी०
164.	1 मणिपुर	मानी	ट्रांसमिशन	मणिपुर में 132 के०वी० रिंगमेन पारेषण प्रणाली
165.	2	मानी	यू० डी०	इम्फाल
166.	1 मिजोरम	निजो	ट्रांसमिशन	पारेषण कार्य
167.	1 मध्यप्रदेश	एम०पी०ई०बी०	,,	रायचूर-कोरबा
168.	2	—वही—	आर०एम०-7 सी०	अमरकंटक
169.	3	—वही—	,,	कोरबा
170.	4	—वही—	,,	सतपुरा
171.	5	—वही—	एस०आई०	86.4 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
172.	6	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० बिना—दमोह लाइन तथा एस०/एस०
173.	7	—वही—	,,	एटारसी—सतना
174.	8	—वही—	,,	टोंस एच०ई०पी० से विद्युत का निष्क्रमण हेतु लाइन
175.	9	—वही—	टी०एच०जी०	पेंच 1 एवं 2 (2×210 मे० वा०)
176.	10	—वही—	,,	संजय गांधी 3 तथा 4 (2×210 मे०वा०)
177.	11	—वही—	,,	संजय गांधी 3 तथा 4 (2×210 मे०वा०)
178.	12	—वही—	ट्रांसमिशन	400 के०वी० एटारसी भोपाल लाइन तथा सम्बद्ध कार्य
179.	13	—वही—	एच०वाई०जी०	हंसदेव बांगों एच०ई०पी०
180.	14	—वही—	टी०एच०जी०	पेंच 1 तथा 2 (2×210 मेगावाट)

1	2	3	4	5
181.	15	एम०पी०ई०बी०	यू०डी०	भोपाल शहर
182.	16	—वही—	एस०आई०	220 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
183.	17	—वही—	टी०एच०जी०	संजय गांधी 3 तथा 4 (2×210 मेगावाट)
184.	18	—वही—	ट्रांसमिशन	400 के०वी० इन्दौर—नागदा लाइन तथा सम्बद्ध कार्य
185.	19	—वही—	यू०डी०	रतलाम शहर
186.	20	—वही—	एच०वाई०जी०	बापसागर टोन्स एच०ई०पी०
187.	21	—वही—	टी०एच०जी०	संजय गांधी 1 तथा 2 (2×210 मेगावाट)
188.	22	—वही—	ट्रांसमिशन	महेन्द्रगढ़ टी०ए०पी० लाइन
189.	23	—वही—	टी०एच०जी०	संजय गांधी 1 तथा 2 (2×210 मेगावाट)
190.	24	—वही—	ट्रांसमिशन	132 के०वी० का रयसेन में एस०/एस० तथा सम्बद्ध कार्य
191.	25	—वही—	,,	पीठमपुर में 220 के०वी० का एस०/एस० तथा सम्बद्ध कार्य
192	26	—वही—	ट्रांसमिशन	देवास में 220 के०वी० का एस०/एस० तथा इन्दौर—देवास लाइन
193.	27	—वही—	ट्रांसमिशन	नीमच, सरनी, पिपरिया में 20 एम०वी०ए०, 132/33 के०वी० का ट्रांसफार्मर
194.	28	—वहीं—	आर०एम०-7 सी	अमरकंटक सातवीं योजना (सी०एल०ए०)
195.	29	—वही—	ंसमिशन	नीमच में 220 के०वी० का एस०/एस० तथा नागदा नीमच लाइन
196.	30	—वही—	ट्रांसमिशन	उज्जैन में 220/132 के०वी० के ट्रांसफार्मर

1	2	3	4	5
197.	31	एम०पी०ई०बी०	यू०डी०	बुरहानपुर
198.	32	—वही—	ट्रांसमिशन	220/132 के०वी० में रतलाम में 160 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर
199.	33	—वही—	एच०वाई०जी०	बिरसिंहपुर एच०ई०पी० (1 × 20 मेगावाट)
200.	34	—वही—	एस०आई०	185 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
201.	35	—वही—	ट्रांसमिशन	इन्दौर—धार लाइन से 132 के०वी० लीलो तथा 132 के०वी० घटाबिलोद
202.	36	—वही—	आर०एम०एम० एस०सी०	अमरकंटक—बैग फिल्टर
203.	37	—वही—	ट्रांसमिशन	धामनोद में 132 के०वी० का एस०/एस० तथा 132 के०वी० डी०सी०डी०एस०, टी०ए०पी० लाइन
204.	38	—वही—	यू०डी०	रीवां
205.	39	—वही—	,,	सागर
206.	40	—वही—	ट्रांसमिशन	मुलताई में 132 के०वी० एस०/एस० तथा सम्बद्ध लाइनें
207.	41	—वही—	आर०एम०-7 एस०	कोरबा सातवीं योजना (एस०पी०)
208.	42	—वही—	यू०डी०	ग्वालियर
209.	43	—वही—	,,	खरगांव
210.	44	—वही—	आर०एम०-7 एस०	अमरकंटक सातवीं योजना (एस०पी०)
211.	45	—वही—	ट्रांसमिशन	400 के०वी० भोपाल—बिना लाइन तथा बिना में एस०/एस०
212.	46	—वही—	यू०डी०	ऊर्जा लेखा परीक्षा तथा भार सर्वेक्षण

1	2	3	4	5
213.	47	एम०पी०ई०बी०	यू०डी०	भिण्ड
214.	48	—वही—	,,	शिवपुरी
215.	49	—वही—	,,	छतरपुर
216.	50	—वही—	,,	यू०डी०के लिए 69 एम०वी०ए०आर० के शंट कैपेसिटर
217.	51	—वही—	,,	राजनंद गांव
218.	52	—वही—	,,	एटारसी
219.	53	—वही—	,,	मीटरों का प्रतिस्थापन
220.	54	—वही—	,,	रायगढ़
221.	55	—वही—	टी०एच०जी०	संजय गांधी टी०पी०एस०
222.	56	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० औरैया—मालनपुर लाइन तथा मेहान में स्विचिंग एस०/एस०
223.	57	—वही—	ट्रांसमिशन	एच०टी० उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन
224.	58	—वही—	यू०डी०	महु
225.	59	—वही—	,,	छिन्दवाड़ा
226.	60	—वही—	,,	जगदलपुर
227.	61	—वही—	,,	नीमच
228.	62	—वही—	ट्रांसमिशन	भोपाल में 400/220 के०वी०, 315 एम०वी०ए० के ट्रांसफार्मर
229.	63	—वही—	ट्रांसमिशन	बरवानी तथा निमरानी में 132/33 के०वी० के एस०/एस०

1	2	3	4	5
230.	64	एम०पी०ई०बी०	टी०एच०जी०	विरसिंहपुर चरण-I (2×210 मेगावाट)
231.	65	—वही—	आर०एम०-8	कोरबा पूर्वी टी०पी०एस० आठवीं योजना आर० तथा एम०
232.	66	—वही—	आर०एम०-8	सतपुरा टी०पी०एस० आठवीं योजना
233.	67	—वही—	एस०आई०	एटारसी--बरूवाह 220 के०वी० इ/सी लाइन पर क्रमबद्ध प्रतिपूर्ति
234.	68	—वही—	एस०आई०	255 एम० वी०ए०आर०, 33 के०वी० कैपेसिटर बैंकों की स्थापना
235.	1	महाराष्ट्र एम०एस०ई०बी०	टी०एच०जी०	खापरखेड़ा टी०पी०एस० (2×210 मेगावाट)
236.	2	—वही—	आर०एम०-7 सी	नासिक
237.	3	—वही—	आर०एम०-7 सी	कोराड़ी
238.	4	—वही—	,,	पारस
239.	5	—वही—	आर०एम०-7 सी	भुसावल
240.	6	—वही—	टी०एच०जी०	खापरखेड़ा टी०पी०एस० (2×210 मेगावाट)
241.	7	—वही—	एस०आई०	512 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर बैंक
242.	8	—वही—	टी०एच०जी०	खापरखेड़ा टी०पी०एस० (2×210 मेगावाट)
243.	9	—वही—	ट्रांससिशन	400 के०वी० चन्द्रपुर—पारली लाइन
244.	10	—वही—	टी०एच०जी०	खापरखेड़ा टी०पी०एस० (2×210 मेगावाट)
245.	11	—वही—	,,	खापरखेड़ा टी पी एस (2×210 मेगावाट)
246.	12	—वही—	ट्रांसमिशन	400 के०वी० पारली—चन्द्रपुर लाइन

1	2	3	4	5
247.	13	एम०एस०ई०बी०	आर०एम०-7 सी	कोराड़ी
248.	14	—वही—	एस०आई०	220 के०वी० कराड़—मिराज लाइन पर 30.66 एम०वी०ए०आर० सीरीज प्रतिस्थापन
249.	15	—वही—	यू०डी०	सतारा शहर
250.	16	—वही—	एस०आई०	546 एम०वीए०आर० कैपेसिटर्स
251.	17	—वही—	ट्रांसमिशन	एस०/एस० में अभिवृद्धि
252.	18	—वही—	,,	भण्डारा—गोंदिया
253.	19	—वही—	यू०डी०	कोना शहर
254.	20	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० तथा 132 के०वी० एस०/एस०
255.	21	—वही—	टी०एच०जी०	चन्द्रपुर यूनिट 5 एवं 6
256.	22	—वही—	आर०एम०-8	पारस आठवीं योजना
257.	23	—वही—	,,	पारली आठवीं योजना
258.	24	—वही—	,,	भुसावल टी०पी०एस० आठवीं योजना
259.	25	—वही—	,,	कोराड़ी आठवीं योजना
260.	26	—वही—	,,	नासिक आठवीं योजना
261.	27	—वही—	,,	चन्द्रपुर आठवीं योजना
262.	28	—वही—	टी०एच०जी०	चन्द्रपुर 500 मेगावाट
263.	1	नागालैण्ड नागा	ट्रांसमिशन	मोकोकचोंग
264.	2	नागा	,,	नागिनी मोरा—टी०ए०जैड०

1	2	3	4	5
265.	3	नागा	ट्रांसमिशन	तुली—[illegible]यिनी मोरा
266.	4	—वही—	,,	मोकोकचोंग—कुमेहू
267.	5	—वही—	,,	मालुरी—बोखा
268.	1 उड़ीसा	ओ०पी०जी०सी०	टी०एच०जी०	इब घाटी टी०पी०एस० (ओ०पी०जी०सी०)
269.	2	—वही—	,,	इब टी०पी०एस० परियोजना
270.	3	ओ०एस०ई०बी०	ट्रांसमिशन	मंजानगर—दुबरी लाइन तथा दुबरी में एस०/एस०
271.	4	—वही—	,,	इन्द्रावती एच०ई०पी० के सहयोग से उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम
272.	5	—वही—	आर०एम०-7 सी	तलचेर टी०पी०एस० आर०एम० चरण-1 (सी०एल०ए०)
273.	6	—वही—	एस०ओ०ई०	88-89 की अवस्थाओं के लिए 60 एम०वी०ए०आर० के कैपेसिटर
274.	7	—वही—	,,	89-90 की अवस्थाओं के लिए 100 एम०वी०ए०आर० के कैपेसिटर
275.	8	—वही—	ट्रांसमिशन	6 ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि
276.	9	—वही—	,,	220 के०वी० दुबरी—भद्रक—बालासोड लाइन तथा भद्रक, बालासौर में एस०/एस०
277.	10	—वही—	,,	इन्द्रावती एच०ई०पी० से सम्बद्ध उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम
278.	11	—वही—	,,	5 ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि

1	2	3	4	5
279.	12	ओ०एस०ई०बी०	आर०एम०-7 सी	तलचेर टी०पी०एस०आर० एण्ड एम० चरण)-1 सी०एल०ए०)
280.	13	—वही—	यू०डी०	भुवनेश्वर
281.	14	—वही—	,,	कटक
282.	15	—वही—	आर०यू०	चिपलीमा एच०ई०पी०
283.	16	—वही—	यू०डी०	पुरी
284.	17	—वही—	आर०एम०-7 एस	तलचेर टी०पी०एस०आर० एण्ड एम० चरण-1 (एस०पी०)
285.	18	—वही—	ट्रांसमिशन	तलचेर टी०पी०एस० में ट्रांसफोर्मेशन क्षमता में वृद्धि
286.	19	—वही—	,,	भुवनेश्वर एस०एल०डी०सी० में अन्तरिम वृद्धि
287.	20	—वही—	यू०डी०	ऊर्जा लेखा परीक्षा तथा भार सर्वेक्षण
288.	21	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० द्वितीय सर्किट भांजानगर—चांका लाइन
289.	22	—वही—	,,	132/33 के०वी० 1 × 12.5 एम०वी०ए० लिलो तथा कामाख्यांनगर तथा जयपोर में एस०/एस०
290.	23	—वही—	,,	एन०टी०पी०सी० की बिसरा एस०/एस० तथा ओ०एस० ई०बी० के तारकेरा एस०/एस० के बीच 220 के०वी० डी०/सी० अन्त: सम्बन्ध
291.	24	—वही—	,,	बृजराजनगर में 220/232 के०वी० एस०/एस
292.	25	—वही—	आर०एम०-8	तलचेर पी०टी०एस० चरण-2 आठवीं योजना आर एंड एम
293	26	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० इब—बलराज नगर डी०/सी० लाइन

1	2	3	4	5
294.	1 पंजाब	पा० एस० ई० बी०	यू डी	बटाला
295.	2	—वही—	,,	अमृतसर
296.	3	—वही—	,,	तरनतारन
297.	4	—वही—	,,	लुधियाना
298.	5	—वही—	टी०एच जी	रोपड़ चरण-3
299.	6	—वही—	आर यू	यू०बी०डी०सी०-1
300.	7	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० बटाला—फतेहगढ़ लाइन तथा एस०/एस०
301.	8	—वही—	,,	220 के०वी० मोगा—फिरोजपुर लाइन तथा एस०/एस
302.	9	—वही—	,,	रोपड़ में ट्रांसफोरमेंशन कार्य
303.	10	—वही—	,,	तरनतारन में ट्रांसफोरमेशन कार्य
304.	11	—वही—	एच वाई जी	यू०बी०डी०सी०-2
305.	12	—वही—	टी एच जी	रोपड़ चरण-3
306.	1 राजस्थान	आर एस ई बी	ट्रांसमिशन	खेतड़ी—रतनगढ़
307.	2	—वही—	टी एच जी	कोटा टी०पी०एस
308.	3	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० अन्ता—कोटा डी०/सी० लाइन
309.	4	—वही—	एस०आई०	199 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर
310.	5	—वही—	टी०एच०जी०	कोटा टी०पी०एस०
311.	6	—वही—	टांसमिशन	220 के०वी० कोटा—बीवार—जोधपुर डी०सी० लाइन

1	2	3	4	5
312.	7	—वही—	ट्रांसमिशन	132/33 के०वी० लाइन तथा रानीवाडा में एस०/एस०
313.	8	—वही—	,,	132 के०वी० लाइन तथा गुहाना में एस०/एस०
314.	9	—वही—	एस०आई०	98 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर
315.	10	—वही—	ट्रांसमिशन	सूरतगढ़ में 320 के०वी० रतनगढ़—सूरतगढ़ लाइन तथा एस०/एस०
316.	11	—वही—	आर०एम०-8	कोटा टी०पी०एस० आठवीं योजना आर० एण्ड एम०
317.	12	—वही—	ट्रांसमिशन	हीरापुर में 250 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर
318.	13	राजस्थान सरकार	आर०यू०	भाखड़ा वाहिना किनारा एच०ई०पी० (5×120 मेगावाट)
319.	1 सिक्किम	सिक्किम	एच०वाई०जी०	ऊपरी सोंगनिचू
320.	2	—वही—	,,	नियोंगचू मिनी एच०ई०पी०
321.	3	—वही—	,,	नियोंगचू मिनी एच०ई०पी०
322.	4	—वही—	,,	ऊपरी रोंगनिचू
323.	5	—वही—	,,	नियोंगचू एच०ई०पी०
324.	6	—वही—	,,	ऊपरी रोंगनिचू एच०ई०पी०
325.	1 तमिलनाडु	टी०एन०ई०बी०	टी०एच०जी०	मैत्तूर चरण-2 यूनिट-3 एवं 4 (2×210 मेगावाट)
326.	2	—वही—	आर०एम०-7 सी	तूतीकोरिन
327.	3	—वही—	,,	एन्नौर (2×60+3×110 मेगावाट)
328.	4	—वही—	एस०आई०	44 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स

1	2	3	4	5
329.	5	टी०एन०ई०बी०	टी०एच०जी०	मैत्तूर चरण-2 यूनिट 3 व 4 (2×210 मेगावाट)
330.	6	—वही—	ट्रांसमिशन	तूतीकोरिन टी०पी०एस० विद्युत निष्कासन प्रणाली
331.	7	—वही—	टी०एच०जी०	तूतीकोरिन चरण-2 यूनिट 4 व 5 (2×210 मेगावाट)
332.	8	—वही—	ट्रांसमिशन	श्री पेरम्बदूर में 400 के०वी० का एस०/एस०
333.	9	—वही—	ट्रांसमिशन	श्री पेरम्बदूर एस०/एस० में ट्रांसफार्मर
334.	10	—वही—	आर०एम०यू०एस०सी०	एन्नोर आग से क्षतिग्रस्त
335.	11	—वही—	टी०एच०जी०	मैत्तूर चरण-2 यूनिट 3 व 4 (2×210 मेगावाट)
336.	12	—वही—	,,	तूतीकोरिन चरण-2 यूनिट 4 व 5 (2×210 मेगावाट)
337.	13	—वही—	ट्रांसमिशन	330/210/11 के०वी० आरासूर एस०/एस०
338.	14	—वही—	एस०आई०	31ए म०वी०ए०आर० कैपेसिटर्स
339.	15	—वही—	ट्रांसमिशन	अथुर में 230/110 के०वी० एस०/एस० तथा सम्बद्ध लाइनें
340.	16	—वही—	टी०एच०जी०	तूतीकोरिन चरण-2 यूनिट 4 व 5 (2×210 मेगावाट)
341.	17	—वही—	यू०डी०	कुम्बाकोनम
342.	18	—वही—	ट्रांसमिशन	230/110 के०वी० सत्तूर एस०/एस० तथा 110 के०वी० लाइनें
343.	19	—वही—	यू०डी०	तू ीकोरिन
344.	20	—वही—	ट्रांसमिशन	मदुरै में 230 के०वी० का स्विचिंग स्टेशन
345.	21	—वही—	आर०यू०	मोयार एच०ई०पी०

1	2	3	4	5
146.	22	टी०एन०ई०बी०	ट्रांसमिशन	पुआलपुर में 1.2 किलोमीटर एम०पी०यू०आर० लाइन के साथ 110/11 के०वी० एस०/एस०
147.	23	—वही—	ट्रांसमिशन	उडमलपेट में 230 के०वी० का एस०/एस०
348.	24	—वही—	यू०डी०	सालेम
349.	25	—वही—	,,	तिरूनेवेली
350.	26	—वही—	,,	एरोडे
351.	27	—वही—	ट्रांसमिशन	उत्तरी मद्रास टी०पी०एस० विद्युत निष्क्रमण प्रणाली
352.	28	—वही—	टी०एच०जी०	नारीमानम गैस टर्बाइन संयंत्र (2 × 5 मेगावाट)
353.	29	—वही—	टी०एच०जी०	उत्तरी मद्रास टी०पी०पी० (ए०डी०बी० का सी०एफ०एस० ऋण)
354.	30	—वही—	यू०डी०	मद्रास
355.	31	—वही—	आर०यू०	कुण्डा
356.	32	—वही—	आर० एम०-7 एस	एन्नौर सातवीं योजना एस०/टी०
357.	33	—वही—	टी०एच०जी०	मैत्तूर चरण-2
358.	34	—वही—	ट्रांसमिशन	करियाकुड़ी एस०/एस० का विस्तार
359.	35	—वही—	,,	श्री पेरम्बदूर में 400 के०वी० 220 एम०वी० ए० ट्रांसफार्मर को अतिरिक्त भार
360.	36	—वही—	,,	73 एस०/एस० में पी०एल०सी०सी० उपस्कर
361.	37	—वही—	टी०एच०जी०	तूतीकोरिन टी०पी०एस०

1	2	3	4	5
362.	38	टी०एन०ई०बी०	यू०डी०	तिरूचेनगोडे
363.	39	—वही—	,,	यू०डी० के लिए 144 एम०वी०ए०आर० का शंट कैपेसिटर
364.	40	—वही—	आर० एम०-8	तूतीकोरिन आठवीं योजना आर० एण्ड एम०
365.	41	—वही—	ट्रांसमिशन	श्री पेरम्बदूर में 400 के०वी० के एस०/एस० के लिए दूसरा 315 एच०बी०ए० का ट्रांसफार्मर
366.	42	—वही—	यू०डी०	तिरूपुर
367.	43	—वही—	आर०यू०	सोलेयार एच०ई०पी० (2×35 मेगावाट)
368.	44	—वही—	ट्रांसमिशन	230 के०वी० तिरूचि स्विचिंग स्टेशन
369.	45	—वही—	,,	सलेम 400 के०वी० एस०/एस० में 400/110 के०वी० चरण की स्थापना
370.	46	—वही—	यू०डी०	नागपट्टनम
371.	47	—वही—	आर०एम०-8	एन्नौर आठवीं योजना
372.	48	—वही—	यू०डी०	यू०डी० के लिए 55.8 एम०वी०ए०आर० का शंट कैपेसिटर
373.	1 त्रिपुरा	त्रिपुरा	एच०वाई०जी०	गुपटी
374.	1 उत्तर प्रदेश	यू०पी०आर०वी०यू०एन०	टी०एच०जी०	ऊंचाहार-1
375.	2	—वही—	,,	ऊंचाहार-1
376.	3	यू०पी०एस०ई०बी०	ट्रांसमिशन	132 के० वी० मेरठ, गाजियाबाद, मेडिकल कालेज, मेरठ तथा लखोटी (अनुपूरक ऋण)

1	2	3	4	5
377.	4	यू० पी० एस० ई० बी०	ट्रांसमिशन	मोहमदाबाद, कुण्डेशर में 132 के०वी० पारेषण कार्य (अनुपूरक ऋण)
378.	5	—वही—	,,	132 के०वी० गोमती नगर चिनहट एस०जी०पी०जी०आई० (उत्तरेतिया) लखनऊ (अनुपूरण ऋण)
379.	6	—वही—	,,	220 के०वी० मुरादाबाद सी०बी० गंज
380.	7	—वही—	टी०एच०जी०	टाण्डा टी०पी०एस०
381.	8	—वही—	आर०एम०-7 सी	हरदुआगंज (सी०एल०ए०) चरण-1
382.	9	—वही—	,,	ओबरा (सी०एल०ए०) चरण-1
383.	10	—वही—	,,	पनकी (सी०एल०ए०) चरण-1
384.	11	—वही—	एस०आई०	88-89 की दशाओं के लिए 300 एम०वी०ए०आर० के कैपेसिटर
385.	12	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० [illegible]—सहारनपुर—शामली
386.	13	—वही—	,,	220 के०वी० एन०ए०पी०पी०—[illegible]
387.	14	—वही—	टी०एच०जी०	टाण्डा टी०पी०एस०
388.	15	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० [illegible]—[illegible]
389.	16	—वही—	एस०आई०	88-89 की दशाओं के लिए 250 एम०वी०ए०आर० के कैपेसिटर
390.	17	—वही—	टी०एच०जी०	अनपारा टी०पी०एस०

1	2	3	4	5
391.	18	यू०पी०एस०ई०बी०	ट्रांसमिशन	132/33 के०वी० मऊ
392.	19	—वही—	,,	पूर्वी उत्तर प्रदेश के गौरीगंज, शंकरगढ़ में 132 के०वी० के पारेषण कार्य
393.	20	—वही—	टी०एच०जी०	अनपारा टी०पी०एस०
394.	21	—वही—	ट्रांसमिशन	132 के०वी० गोमती नगर चिनहट, शंकरगढ़ एस०जी०पी० जी०आई० (उत्तरेतिया) लखनऊ
395.	22	—वही—	,,	पोटद्वारावाद, कुण्डेशर में 132 के०वी० पारेषण कार्य
396.	23	—वही—	,,	232 के०वी० मेरठ रोड, गाजियाबाद, मेडिकल कालेज, मेरठ तथा लखोटी
397.	24	—वही—	,,	132 के०वी० बस्ती दमोरियागंज
398.	25	—वही—	,,	पूर्वी उत्तर प्रदेश के गौरीगंज, शंकरगढ़ में 132 के०वी० पारेषण कार्य (अनुपूरक ऋण)
399.	26	—वही—	,,	132 के०वी० बिन्दल
400.	27	—वही—	,,	गाजीपुर में क्षमता वृद्धि
401.	28	—वहीं—	टी०एच०जी०	अनपारा टी०पी०एस०
402.	29	—वही—	ट्रांसमिशन	सैयदपुर में क्षमता अभिवृद्धि
403.	30	—वही—	टी०एच०जी०	टाण्डा टी०पी०एस०
404.	31	—वही—	ट्रांसमिशन	440 के०वी०/220 के०वी० प्रणाली पर पारेषण कार्य
405.	32	—वही—	यू०डी०	वाराणसी

1	2	3	4	5
406.	33	यू०पी०एस०ई०बी०	यू०डी०	मउनाथभंजन
407.	34	—वही—	एस०आई०	89-90 की अवस्थाओं के लिए 500 एम०वी०ए०आर० के कैपेसिटर
408.	35	—वही—	ट्रांसमिशन	220 के०वी० सीबी गंज—बदायूं
409.	36	—वही—	यू०डी०	कानपुर
410.	37	—वही—	ट्रांसमिशन	132 के०वी० एस०/एस० भोपा रोड में तथा सम्बद्ध लाइनें
411.	38	—वही—	,,	132 के०वी० ज्वालापुर—चिल्ला लाइन
412.	39	—वही—	आर०एम०-7 सी	पनकी (सी०एल०ए०) चरण-1
413.	40	—वही—	ट्रांसमिशन	श्रीनगर (गढ़वाल) में 132 के०वी० कुा एस०/एस०
414.	41	—वही—	,,	220 के०वी० खुर्जा—जहांगीराबाद लाइन
415.	42	—वही—	टी०एच०जी०	टाण्डा टी०पी०एस०
416.	43	—वही—	ट्रांसमिशन	132 के०वी० आजमगढ़—कोयलसा लाइन
417.	44	—वही—	आर०यू०	तिलोठ
418.	45	—वही—	,,	चिल्ला
419.	46	—वही—	,,	पयरी
420.	47	—वही—	यू०डी०	फतेहपुर
421.	48	—वही—	,,	बहराइच
422.	49	—वही—	टी०एच०जी०	अनपारा टी०पी०एस०

1	2	3	4	5
423.	50	यू०पी०एस०ई०बी०	यू०डी०	गोरखपुर
424.	51	—वही—	"	बरेली
425.	52	—वही—	"	इलाहाबाद
426.	53	—वही—	ट्रांसमिशन	66 के०वी० एस०/एस, श्रीनगर—जोसीमठ लाइन
427.	54	—वही—	"	अनुपूरक ऋण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 400 के०वी० तथा 220 के०वी० पारेषण कार्य
428.	1 पश्चिम बंगाल	डब्ल्यू०बी०पी०डी०एल०	टी०एच०जी०	कोलाघाट टी०पी०एस० चरण-1
429.	2	—वही—	"	कोलाघाट टी०पी०एस० चरण-2
430.	3	—वही—	"	कोलाघाट टी०पी०एस० चरण-1
431.	4	—वही—	"	कोलाघाट टी०पी०एस० चरण 2
432.	5	—वही—	"	कोलाघाट टी०पी०एस० चरण-2
433.	6	—वही—	"	कोलाघाट टी०पी०एस० चरण-2
434.	7	—वही—	आर०एम०-8	कोलाघाट टी०पी०एस० 8वीं योजना नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
435.	8	—वही—	आर०एम०-7 सी	बन्डल आर० एवं एम० फेज-1 (सी०एल०ए०)
436.	9	—वही—	आर०एम०-7 सी	संथाडीह आर० एवं एम० फेज-1 (सी० एल०ए०)
437.	10	—वही—	ट्रांस	बहरामपुर पावर सिस्टम स्टन्थनिंग
.438	11	—वही—	ट्रांस	हावड़ा उप केन्द्र में ट्रांसफारमर

1	2	3	4	5
439	12	डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी०	ट्रांस	आदीसपुती ग्राम ट्रांसफारमर क्षमता अभिवृद्धि
440.	13	—वही—	ट्रांस	सतगच्छियां पावर सिस्टम स्टेन्थिग
441.	14	—वही—	ट्रांस	400 के०वी० एस०/सी के०टी०पी० दुर्गापुर लाइन
442.	15	—वही—	ट्रांस	220 के०वी० के०टीपी० एस—हल्दिया लाइन एवं हल्दिया में उप केन्द्र
443.	16	—वही—	ट्रांस	220/132 के०वी० रिसरा स्थित उप केन्द्र
444.	17	—वही—	आर०एम०/7 एस०	बुन्देल आर० एवं एम० फेज-1 (एम०पी०)
445.	18	—वही—	ट्रांस	132 के०वी० माल्दा—डलखाला लाइन
446.	19	—वही—	ट्रांस	132 के०वी० जीरात—बारासात लाइन एवं बारासात स्थित उप केन्द्र
447.	20	डी०पी०एल०	आर०एम०-7 सी	डी०पी०एल० दुर्गापुर (सी०एल०ए०)
448.	21	टी०पी०एल०	आर०एम०एम०एस०सी०	डी०पी०एल० प्रतिस्थापन जी०टी०

ऊपर निर्दिष्ट संक्षिप्त रूपों का विवरण :—

कोड	नाम
टी० एच० जी०	ताप विद्युत उत्पादन
एच० वाई० जी०	जल विद्युत उत्पादन
ट्रांस	पारेषण एवं वितरण
एस० आई०	प्रणाली सुधार (कैपेसिटर्स)
यू० डी०	शहरी वितरण
आर० यू०	जल विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण एवं क्षमता संवर्धन
आर० एम०-7 सी	ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (7वीं योजना सी० एल० ए०)
आर० एम०-7 एस	ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (7वीं योजना एस० पी०)
आर० एम०-8	ताप विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (8वीं योजना)
आर०एम०एम०एस०मी०	ताप विद्युत संयंत्रों का नबीकरण एवं आधुनिकीकरण (विविध)

ब्रह्मपुरम में डीजल विद्युत केन्द्र

[अनुवाद]

2090. **श्री पी० सी० थामस** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में ब्रह्मपुरम में मंजूर डीजल विद्युत उत्पादन घर की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए निधि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) स (ग) केरल में ब्रह्मपुरम में 296.8 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर एक डीजल आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (5 × 20 मे०वा०) की स्थापना किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को केरल राज्य बिजली बोर्ड से तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने हेतु फरवरी, 1992 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस स्कीम को के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई क्योंकि केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निवेश/स्वीकृतियों को सुनिश्चित नहीं किया गया है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपेक्षित निधियों की व्यवस्था किए जाने तथा के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी -आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात ही इसे स्वीकृति दी जा सकेगी।

भारत तथा नेपाल के बीच विचार-विमर्श

2091. **श्री सूर्यनरायण यादव** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोसी नदी के पानी को नेपाल की ओर ले जाने के मामले पर नेपाल की सरकार से विचार-विमर्श किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, भारत और नेपाल सप्त-कोसी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा अन्वेषण करने के लिए सहमत हो गए हैं।

कलकत्ता में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

2092. **डा० असीम बाला** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन एक्सचेंजों को कब तक स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) कलकत्ता में सत्रह स्थानीय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान।

दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

2093. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के नेशनल हुक अप पर संस्कृत में समाचार बुलेटिन और अन्य कार्यक्रमों को प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन कार्यक्रमों को प्रसारित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) ट्रांसमिशन समय एवं संसाधन के कमी के कारण फिलहाल दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार बुलेटिन प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विजयवाड़ा में टी० वी० स्टुडियो

2094. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टी० वी० स्टुडियो का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है;

(ख) इसकी अनुमानित लागत क्या है और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) टी० वी० स्टुडियो की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) व्यावसायिक ग्रेड रंगीन उपकरण सहित सुसज्जित तकनीकी क्षेत्र सम्बद्ध एक स्टूडियो युक्त दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र को विजयवाड़ा में स्थापित किए जाने की परिकल्पना है । प्रस्तावित स्टूडियो केन्द्र के लिए स्थान ले लिया गया हैं तथा उपकरण, जिसकी प्राप्ति में काफी समय लगता है, की आपूर्ति के लिए निर्माताओं को भी आर्डर दे दिए गए हैं । सरकार द्वारा परियोजना के लिए औपचारिक अनुमोदन करने के बाद इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने में लगभग चार वर्ष का समय लग जाता है ।

नागपुर-बम्बई-दिल्ली दूरदर्शन से माइक्रोवेव सम्पर्क

[हिन्दी]

2095. **श्री तेज सिंह राव भोंसले :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर और बम्बई-दिल्ली दूरदर्शन के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करके विदर्भ के समाचार बम्बई-दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) विदर्भ क्षेत्र से सम्बन्धित समाचारों और दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को क्षेत्रीय टी०वी० सेवा के तहत दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा पहले से प्रसारित किया जा रहा है जिनको उपग्रह माध्यम से राज्य के सभी टी० वी० ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है। इसके अलावा विदर्भ क्षेत्र से सम्बन्धित राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को भी राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाता है।

दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर को माइक्रोवेव लिंकेज के माध्यम से दिल्ली अथवा बम्बई से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल के डाक कार्यालयों में तार सेवा, बचत बैंक और पी० सी० ओ० सुविधाएं प्रदान करना

[अनुवाद]

2096. **श्री सुखेन्दु खां** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के गांवों में ऐसे कितने डाक कार्यालय मौजूद हैं जहां पर पी० सी० ओ० तार सेवा और बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी डाक कार्यालयों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) पश्चिम बंगाल के गांवों में ऐसे डाकघरों की संख्या नीचे दी गई है जिनमें पी०सी०ओ०, तार और बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं :

पीसीओ और तार सेवा	= 1868
बचत बैंक	=7417

(ख) से (घ) यद्यपि, पश्चिम बंगाल के सभी ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में निकट भविष्य में या तो डाकघरों या पंचायत कार्यालयों, परचून की दुकान आदि के माध्यम से पी० सी० ओ० सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है, परन्तु इन कार्यालयों/दुकानों आदि के माध्यम से तार सुविधा उपलब्ध कराना जनता की मांग पर निर्भर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के शेष 173 डाकघरों में बचत बैंक सुविधाएं प्रदान करना जनता की मांग पर निर्भर करता है।

टेलीविजन के लिए बहु-भाषायी ध्वनि

2097. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन टेलीविजन के लिए बहु भाषायी आवाज की परियोजना शुरू कर रहा है ताकि हिन्दी अथवा अंग्रेजी न समझ सकने वाले काफी तादाद में ग्रामीण श्रोताओं को मदद मिल सके,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक कार्य शुरू कर देने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) और (ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग (डी० ओ० ई०) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) के सहयोग से सामान्य तस्वीर सहित बहुभाषायी आवाज/उप शीर्षक प्रदान करने वली एक परियोजना, जो स्थापना के लिए परिकल्पित है इस समय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अनुसन्धान एवं विकास (आर० एंड डी०) विंग में योजना अवस्था में है।

(ग) सामान्यत: सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करने के बाद इस प्रकार की अनुसंधान एवं विकास परियोजना के पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का समय लग जाता है।

महाराष्ट्र में डाक वितरण व्यवस्था

2098. **श्री राम चन्द्र मरोतराव घंगारे :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर डाक वितरण व्यवस्था खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्थानों पर डाक सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। तथापि डाक वितरण में यदाकदा विलम्ब हो जाता है।

(ख) कभी-कभार होने वाला यह विलंब एयरलाइंस/रेल आदि जैसी परिवहन सेवाओं के कारण पारगमन में विलंब, अस्पष्ट पता, पिन कोड का प्रयोग न करने आदि की वजह से होता है।

(ग) फील्ड और मुख्यालयों दोनों स्तरों पर निरंतर मानीटरिंग की जाती है तथा परिवहन एजेंसियों के साथ समन्वय रखा जाता है। दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

विद्युत उत्पादक यूनिटों के नवीकरण के लिए विदेशी सहायता

2099. **श्री हाराधन राय :**

श्री जायनल अबेदिन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किसी विदेशी फर्म ने हमारे देश में विद्युत उत्पादक यूनिटों का नवीकरण करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के नवीकरण के लिए पांच विदेशी फर्मों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और जल विद्युत केन्द्रों के लिए तीन विदेशी फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस मामले में कार्यवाही किया जाना सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारियों/राज्य बिजली बोर्डों पर निर्भर करता है।

विवरण

विद्युत उत्पादन यूनिटों के नवीकरण के लिए जिन विदेशी फर्मों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनकी सूची

क्र० सं०	विदेशी फर्मों का नाम	उस यूनिट का नाम जिसका नवीकरण किया जाना है
	ताप विद्युत उत्पादन यूनिट	
1.	मै० हाईटैक लि०, जापान	कोठागुडम "ए"
2.	मै० आई० एच० आई०, जापान	कोठागुडम "ए"
3.	एशिया ब्राउन बोवेरी, जर्मनी (ए० बी० बी०)	[illegible]
4.	सीमेन एनर्जी, जर्मनी	दुर्गापुर
5.	टैक्नोप्रो मैक्सोपोर्ट आफ एशिया (टी० पी० ई०)	नैवेली
	जल-विद्युत उत्पादन यूनिट	
6.	ए० बी० बी० पावर जनरेशन बाडेन, स्विट्जरलैंड	नेरियामंगलम
7.	हाउडो वेवे, स्विट्ज	नेरियामंगलम और पोरिंगलकुथु
8.	जनरल इलैक्ट्रिकल कम्पनी कनाडा,	सबरीगिरी

मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम के लिए अतिरिक्त पारेषण लाइन

2100. **श्री एन० जे० राठवा :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम के [illegible] में विद्युत सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से अतिरिक्त पारेषण लाइनों पर कार्य आरम्भ करने का है; और

(ख) इस सम्बन्ध में योजना को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दक्षिण असम, मिजोरम और त्रिपुरा में केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन 132 के० वी० कार्यों का विस्तार किये जाने के लिये एक परियोजना स्कीम (60.88 करोड़ रुपए) को हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) ने स्कीम का तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया है और कुछ शर्तें भी रखी हैं।

फरक्का ताप विद्युत परियोजना

2101. **श्री जायनल अबेदिन** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का ताप विद्युत परियोजना की अब तक कितनी यूनिटों की शुरुआत की गई है, और उनकी विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है;

(ख) कितनी यूनिटों का निर्माण करना अभी बाकी है;

(ग) इसके अन्तिम चरणों में काम पूरा होने के बाद कितनी विद्युत का उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) क्या इस परियोजना की अन्तिम यूनिट के निर्माण के सम्बन्ध में कोई अनिश्चितता आ गई है जैसा कि मूल योजना में व्यवस्था की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी०पी०सी०) की फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना की 200-200 मे० वा० की तीन यूनिटें चालू कर दी गई हैं।

(ख) 500 मे० वा० की पहली यूनिट को सितम्बर, 1992 में परीक्षण-समकालित किया गया है।

(ग) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना की ईष्टतम विद्युत उत्पादन क्षमता 2100 मे० वा० होगी।

(घ) से (च) इस परियोजना के चरण-3 (500 मे० वा०), जिसे सितम्बर, 1989 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, का कार्य वित्त पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही आरम्भ किया जा सकेगा। विश्व बेंक के समयबद्ध ऋण (टाइम स्लाइस लोन) के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की सूची में इसे भी शामिल किया गया है।

सिंचाई योजना के सम्बन्ध में लागत मूल्यांकन

2102. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु योजनाओं की तुलना में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में कोई लागत-लाभ सम्बन्धी मूल्यांकन कराया गया है; और

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वृहद अथवा मध्यम सिंचाई स्कीम के लागत-लाभ विश्लेषण की तुलना लघु सिंचाई स्कीम से नहीं की जा सकती है क्योंकि किसी विशेष स्थल पर निर्मित की जाने वाली परियोजना की व्याप्ति और आकार उस क्षेत्र की स्थलाकृति, जल उपलब्धता, जल वैज्ञानिक एवं जल-भू-वैज्ञानिक विशेषताओं तथा सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र द्वारा विनियमित होते हैं। ये तीन प्रकार प्रतियोगी नहीं हैं किन्तु ये किसी क्षेत्र में इष्टतम जल संसाधन विकास प्राप्त करने के लिए पूरक होते हैं।

जहां तक कि बृहद/मध्यम/लघु स्कीम के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के सृजन की प्रति हेक्टेयर लागत का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि लघु सिंचाई स्कीमें ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। इसके कारण ये हैं कि छोटी स्कीमें क्षेत्र विशेष के लिए होती हैं तथा पर्यावरण सुरक्षा उपायों, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, जल ग्रहण उपचार, जल निकास सुविधाओं, व्यापक वितरण नेटवर्क तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यों की लागत महत्वपूर्ण रूप से लघु स्कीमों की समग्र लागत में नहीं जोड़ी जाती है। इसके अतिरिक्त वृहद/मध्यम परियोजना की उपयोगिता की अवधि लघु स्कीमों से अधिक होती है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

2103. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंज ठीक से काम कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान चालू किए जाने वाले नये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। परन्तु कई बार लम्बे समय तक बिजली की सप्लाई न होने के कारण एक्सचेंजों के कार्यकरण में रुकावट उत्पन्न हो जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 में प्रस्तावित नए एक्सचेंजों के नाम

1		2	
1. दमोह		27. निपानिया	जिला भोपाल
2. मानेगांव		28. पिगरिया	
3. नन्दी	जिला—बालाघाट	29. पर्वतिया	
4. कांजल		30. गांस	
5. नेत्रा		31. भाण्डा	
6. लिंगा		32. टोटप	जिला छतरपुर
7. मानेगांव		33. गौरिहार	
8. अमोटा		34. सतई	
9. अतूरमगांव		35. सिरस	
10. बनियागांव	जिला—बस्तर	36. बक्सगांव	
11.		37. झिलमिल	जिला छिन्दवाड़ा
12. बाड़सूर		38. खापरखेड़ा	
13. झांसी		39. बड़छिछोली	
14. गडीरास		40. बोरगांव	
15. किलेवाल		41. गोम्मीवाड़ा	
16. कूकनार		42. संग्रामपुर	जिला दमोह
17. भकड़ी		43. तेजगढ़	
18. बोरदेही		44. जझरपुर	जिला दतिया
19. चोपना		45. पटाडी	
20. पकाखेडा	जिला बैतूल	46. विक्रमपुर	जिला देवास
21. बिसनूर		47. मानकुण्ड	
22. पंखा		48. छोबराधिरा	
23. जम्बाड़ा		49. जिनवानी	
24. बाल्डी		50. कूवासारी	जिला धार
25. थाना		51. एकलटूना	
26. बंग्रासिया		52. खेराडे	

1		2	
53. मोरगांव		82. तेंचो	
54. सागावाड		83. धानपुरी	
55. बडोदिया		84 घाना	
56. देशवाला		85. बर्गीनगर	
57. बलोदा		86. सियोनीतोला	जिला जबलपुर
58. अण्डा		87. सुरतलई	
59. दघी	जिला दुर्ग	88. सहसान	
60. कपासी		89. चरगांव	
61. पटई		90. विजकरछोगढ़	
62. रावती	जिला ग्वालियर	91. जोहिला	
63. सुकरबेडी		92. चाका	
64. भागवाडा		93. बघेरा	
65. पावरखेज		94. कुन्दनपुर	जिला झबुआ
66. कोठारा	जिला होशंगाबाद	95. काठियावाडा	
67. लारकुई		96. तारखेडी	
68. बायन		97. बरलेढ	
69. बदतुर		98. बरजार	
70. पुरेंत		99. उदयगढ़	
71. तायांव		100. खड़ी	जिला खण्डवा
72. ताजपुरा		101. खार	
73. अटूटाहेडा	जिला इंदौर	102. बगमार	
74. आगरा		103. मिरपुर	
75. पाडलिया		104. देवतरी	
76. गेरोटा		105. खालसी	
77. रंगतासा		106. धूलकोट	
78. सानदोड		107. तलकपुरा	जिला खरगौन
79. भोरासली		108. बामण्डी	
80. मैण्ड		109. सिखेड़ा	
81. नगोडा		110. लपेनाइ	

1		2	
111. कोइता		140. लटगांव	
112. धारवाड		141. नोनी	
113. चचोरिया		142. नयाखेडा	
114. भानीमाना		143. निवारी	
115. खुरण्धुरा		144. झामर	
116. मोएडा		145. छुटामुण्डा	जिला रायगढ़
117. गुलाटी		146. जमगांव	
118. गनपुर		147. नवापाडन	
119. टोंकी		148. कोपिर	
120. कटारगांव		149. कापू	
121. हटनावाड		150. कस्तूरा	
122. मिर्जापुर		151. राजपुर	
123. घूघारी	जिला मण्डला	152. बिलासपुर	
124. खतिया		153. सिलतारा	जिला रायपुर
125. मानिकपुर		154. लिमतारा	
126. बिछिया		155. सान्दी	
127. नाओली	जिला मंदसौर	156. पाडूका	
128. बोर्दा		157. हिर्मी	
129. एरा		158. भगलोड	
130. लोआरी		159. सेमरा	
131. धमसारा		160. [illegible]ईगढ़	
132. सिमनीहारा		161. जमगांव	
133. बडिया-आमरा		162. खट्टी	
134. [illegible]वाटी		163. नोनियाबरेली	जिला रायसेन
135. पिपलियाहारी		164. डिघवान	
136. बडलई		165. बगसपुर	
137. सिरखेडी		166. नकतारा	
138. डाबर		167. सुल्तानगंज	
139. पलोहा	जिला नरसिंहपुर	168. हरदोड	

1		2	
169. पिपलिया रसोदा	जिला राजगढ़	197. आरी	जिला सिवसी
170. बाखेड		198. लखनवाडा	
171. बेसना		199. फूलारा	
172. लाखनवास		200. नगनदेवरी	
173. लिमचौहान		201. बाम्होरी	
174. बोडला	जिला राजनंदगांव	202. सुनवारा	
175. घुमका		203. अखरार	जिला शाहयंज
176. मोहरा		204. घुंघुटी	
177. नवांगांव		205. घावला	
178. बरबोडना	जिला रतलाम	206. नेहली-सिका	
179. पचेवा		207. बवारीखेडा	जिला शाजापुर
180. भण्डावल		208. अपलईकलां	
181. माण्डवी		209. देबाली-खटसूर	
182. कुन्दनपुर		210. सुडवास	
183. खज्रीदेवरा		211. बिजनियाखेडी	
184. मैयादान	जिला सरगुजा	212. धाराखेडी	
185. घौरपुर		213. मोलटा	
186. बडराफनगर		214. कानाथार	जिला शिण्ड
187. रामनगर		215. बिल्लोवा	
188. उलझावन	जिला सहोर	216. लहरोली	
189 खजूरीकलां		217. भरोली	
190. खण्डवा		218. देहगांव	
191. सेमारी-दागी		219. सिरसोड	जिला शिवपुरी
192. ब्रिजेशनगर		220. भाडी खेडा	
193. हिटजखेडी		221. भामगढ़	
194. दोण्डी		222. बिरा	
195. गुण्डिया वर्मा		223. कुलहोली	जिला मुरैना
196. खजूरिया कसिम		224. बुधेरा	

1		2	
225.	बाडपुरा	251.	करतला
226.	दाराकलां	252.	ठूमन
227.	सोंठवा	253.	रामपुर
228.	राघापुरा	254.	पिंजाडा
229.	धारनौडा जिला गुना	255.	जयजयपुर
230.	झगर	256.	बिर्रा
231	उमरी	257.	नवगार
232.	गडोली	258.	जर्वे
233.	बहादुरपुर	259.	चांदखेड़ी जिला उज्जैन
234.	सिहवान जिलां सीधी	260.	जवासिया
235.	सोहावल	261.	इंदौर
236.	टीकरी	262.	रूनखेडा
237.	पलेरा जिला टीकमगढ़	263.	गुनावाड
238.	जिरन-खास	264.	बनवाना
239.	पटेला	265.	बेरछा
240.	लखराम	266.	बालाबरखेडा जिला विदिशा
241.	कूकटूर	267.	सिहोदा
242.	सिवनी	268.	देव खजूरी
243.	मर्नी जिला बिलासपुर	269.	हैदरगढ़
244.	कोटमी	270.	विल्लौरी
245.	घुटकू	271.	वर्धा
246.	दनिया	272.	टियोज
247.	चिलहाटी	273.	उदयपुर
248.	कोटमी-सुनार	274.	मसूदपुर
249.	चेतमा	275.	घटेरा
250.	पोण्डरी	276.	आनन्दपुर

असम में डाक घर भवन

[अनुवाद]

2104. **श्री प्रबीन डेका :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय कितने डाक घरों के पास विभाग के भवन नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कुछ नए भवनों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा और वर्ष 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) :(क) यह संख्या 440 है।

(ख) जी हां।

(ग) उन डाकघरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिनके लिए सरकार ने विभागीय भवन बनाने की मंजूरी दे दी है। डाकघर-भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 1992-93 के लिए 26 लाख रु० आवंटित किए गए हैं।

विवरण

असम सर्किल के उन डाकघरों की सूची जिनके लिए भवन बनाने की मंजूरी दी गई है।

1. गुवाहाटी विश्वविद्यालय डाकघर
2. पुराना तितवार डाकघर
3. तिंगखोंग डाकघर
4. हावराघाट डाकघर
5. कृष्णई डाकघर
6. लहोल डाकघर
7. बाड़भाता डाकघर
8. देरवाई डाकघर
9. पाठशाला डाकघर
10. नगरबेरा डाकघर
11. माईवोंग डाकघर
12. सिलिकरी डाकघर
13. जोनई डाकघर

14. वाड़पाथर डाकघर

15. पर्वतपुर डाकघर

16. मुकम जं० डाकघर

17. कामपुर डाकघर

18. रत्नपुर रोड डाकघर

19. कलाईगांव डाकघर

20. अगिया डाकघर

"गोदावरी डेल्टा सिस्टम" का आधुनिकीकरण

2105. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गोदावरी डेल्टा सिस्टम" के आधुनिकीकरण हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और केन्द्रीय जल आयोग को सौंप दी गई थी; और

(ख) स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गोदावरी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 226 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए फरवरी, 1991 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। जांच के समय इसमें सिंचाई, फसल और जलविज्ञान आयोजना, भूजल का संयुक्त प्रयोग और जलनिकास घटक आदि जैसे मूल आयोजना पहलुओं में कमी पाई गई थी। इस रिपोर्ट में नहर के आधुनिकीकरण/पक्का करने के औचित्य पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं डाला गया था। अतः परियोजना रिपोर्ट जून, 1991 में राज्य सरकार को इस टिप्पणी के साथ लौटा दी गयी कि यदि वह आवश्यक समझती है तो कमियों को दूर करके संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(ख) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों कीं टिप्पणियों को अनुपालना करती है तथा पर्यावरण व वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय के क्रमशः पर्यावरण व वन तथा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करती है।

कलकत्ता की टेलीफोन डायरेक्टरी

2106. **श्री सोमनाथ चटर्जी** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन विभाग की टेलीफोन डायरेक्टरी अन्तिम बार कब प्रकाशित हुई थी;

(ख) इसका अगला संस्करण कब तक प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) डायरेक्टरी के प्रकाशन में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) कलकत्ता टेलीफोन्स की डायरेक्टरी पिछली बार सितम्बर, 1989 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी का अगला संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।

(ग) कलकत्ता टेलीफोन्स की डायरेक्टरी ठेकेदार द्वारा काम पूरा न करने के कारण समय पर प्रकाशित नहीं की जा सकी।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन

2107. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की जिला-वार संख्या 31 अक्तूबर, 1992 तक कितनी थी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : पश्चिम बंगाल में 31 अक्तूबर, 1992 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में

क्रम सं०	जिले का नाम	टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति (31-10-92 को)
1	2	3
1.	24 परगना (उत्तर)	721
2.	24 परगना (दक्षिण)	242
3.	बांकुरा	518
4.	बुर्दवान	4173
5.	बीरभूम	875
6.	कूचबिहार	421
7.	दार्जिलिंग	3446
8.	हुगली	430
9.	हावड़ा	66
10.	जलपाईगुड़ी	713
11.	मालदा	570

1	2	4
12.	मिदनापुर	1640
13.	मुर्शीदाबाद	490
14.	नादिया	739
15.	पुरूलिया	204
16.	उत्तर दिनाजपुर	884
17.	दक्षिण दिन्नाजपुर	239
	योग	16151

पूर्वोत्तर राज्यों में इलैक्ट्रानिक डाक सेवा हेतु भू-केन्द्र

2108. **श्री उद्धव बर्मन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में इलैक्ट्रानिक डाक सेवा हेतु भू-केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थल सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सरकार का प्रस्ताव भू-केन्द्रों के बीच मनीआर्डर पारेषण के लिए उपग्रह का इस्तेमाल करने का विचार है।

(ग) शिलांग, एजवाल, अगरतला, कोहिमा और उत्तरी लखीमपुर में माइक्रो भू-केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ताकि उपग्रह द्वारा मनीआर्डर प्राप्त किए और भेजे जा सकें। यह देश में शुरू में स्थापित किए जाने वाले 75 माइक्रो भू-केन्द्रों के नेटवर्क का ही एक भाग होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भुवनेश्वर में प्रैस सूचना कार्यालय

2109. **श्री अनादिचरण दास :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रैस सूचना कार्यालय का कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक खोलने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास):(क)और (ख)भुवनेश्वर में एक शाखा कार्यालय की स्थापना करना आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्कीम में शामिल है। तथापि, इसका कार्यान्वयन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पन बिजली परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

2110. **डा० कृपासिंधु भोई** :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया जा रहा है और ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) उन जल-विद्युत परियोजनाओं जिनके बारे में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो रही है

(आंकड़े अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र०सं०	परियोजना एवं राज्य का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	ऋण की राशि
1.	नाथपा झाकरी, हिमाचल प्रदेश	1500	43 .0
2.	श्रीनगर, उत्तर प्रदेश*	330	223:9
3.	सरदार सरोवर, गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश	1450	300.0
4.	कोयना, चरण-4, महाराष्ट्र	1000	230.0
5.	कालीनदी, चरण-2, कर्नाटक	270	197.2
6.	शारावती टेल रेस, कर्नाटक	240	130.0
7.	लोअर पेरियार, केरल	180	176.0
8.	अपर इन्द्रावती, उड़ीसा	600	**ऋण: 156.4
			+क्रेडिट : 156 एम०एस०डी०आर०

* ऋण 28-8-92 से स्थगित कर दिया गया है।

** ऋण 15-12-91 को समाप्त।

उड़ीसा में रत्नागिरी में पर्यटन सुविधाएं

2111. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में, विशेषकर रत्नागिरी में पर्यटन को प्रोत्साहन देने और पर्यटकों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1992-93 के दौरान राज्य को इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है/प्रदान की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां । वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं :—

1. रत्नागिरी में मार्गस्थ सुविधाएं
2. पुरी में यात्री निवास
3. पिपली और साखी गोपाल में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
4. पुरी में यात्रिका
5. बाली यात्रा, कोणर्क नृत्य उत्सव और बाग उत्सव (राजरानी उत्सव) के लिए प्रचार सहायता ।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य के लिए निर्धारित 172.30 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता में से 30.05 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

2112. **प्रो० सुशांत चक्रवर्ती** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है और विश्व में इस समय सबसे अधिक और सब से कम बिजली की प्रति व्यक्ति खपत करने वाले दस देश कौन-कौन से हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : वर्ष 1991-92 के दौरान देश में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 269.95 किलोवाट आवर (अनन्तिम) थी । बिजली की सबसे अधिक खपत वाले 10 देश तथा सबसे कम खपत वाले 10 देशों की सूची 1990 में उपलब्ध । तथा यह संलग्न विवरण-I और -II में दी गई है ।

विवरण-I

वर्ष 1990 के दौरान बिजली की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति खपत करने वाले दस देश ।

क्र०सं०	देश का नाम	(किलोवाट घंटा में)
1.	नार्वे	25083
2.	कनाडा	18149
3.	स्वीडन	17130
4.	लक्समबर्ग	14054
5.	फिनलैंड	13118
6.	यू० एस० ए०	12170
7.	आस्ट्रेलिया	9161
8.	स्विटजरलैण्ड	8097
9.	जर्मनी (एफ०आर०)	7420
10.	जर्मनी (डी० आर०)	7280

स्रोत : एनर्जी स्टेटिस्टिक ईयर बुक-1990-संयुक्त राष्ट्र संघ ।

विवरण-II

वर्ष 1990 के दौरान बिजली की सबसे कम प्रतिव्यक्ति खपत करने वाले दस देश

क्र०सं०	देश का नाम	(किलोवाट घंटा में)
1.	कम्बोडिया	8
2.	चाड	14
3.	इथियोपिया	18
4.	मालै	23
5.	उगाण्डा	26
6.	नेपाल	40
7.	सूडान	53
8.	म्यांमार	62
9.	अफगानिस्तान	68
10.	बंगलादेश	70

स्रोत : एनर्जी स्टेटिस्टिक ईयर बुक-1990-संयुक्त राष्ट्र संघ ।

सिंचाई परियोजनाओं में सुधार

2113. **श्रीमती विमल कुमारी भंडारी :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई "डिलीवरी" प्रणाली में आमूलचूल सुधार करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कोई परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में कुछ राज्यों को सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें राज्यों को सम्मिलित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं,

(ङ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना में सिक्किम को भी सम्मिलित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) वितरण प्रणाली के सुधार और मरम्मत के लिए तथा विद्यमान सतही नहरों (ज्यादातर वृहद व मध्यम) की संशोधित प्रचालनात्मक योजनाओं के माध्यम से बेहतर प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए आई० डी० ए० क्रेडिट सं० 1770 आई० एन० के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से एक राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना संचालित की जा रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल परियोजना के वित्त पोषण के लिए 12-5-1987 को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ विकास क्रैडिट करार पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक ने 93.2 मिलियन एस० डी० आर० (1986 के मूल्य स्तर पर 114 मिलियन अमेरिकी डालर तथा भारतीय 148.2 करोड़ रुपये के समतुल्य) की क्रेडिट सहायता दी है। इस परियोजना के लिए 1986-87 से 1992-93 तक की 7 वर्षों की अवधि में ऋण दिए जाने की आशा है और क्रेडिट समाप्त होने की तारीख मार्च, 1994 है। इस परियोजना का उद्देश्य एक विश्वसनीय, भविष्य सूचक व समान सिंचाई सेवा के माध्यम से विद्यमान सिंचाई परियोजना में उत्पादकता और कृषि आय बढ़ाना है।

(ग) प्रारम्भिक अवस्था पर केवल तीन राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, व तमिलनाडु ने ही इस कार्यक्रम में भाग लिया है तथापि, धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना से होने वाले लाभ महसूस किए। परिणामस्वरूप 6 अन्य राज्य नामशः बिहार, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश भी इस कार्यक्रम में शामिल हो गए।

(घ) राज्यों को पहले अपनी पुरानी विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं (ज्यादातर वृहद व मध्यम) की प्रणालियों की कमियों का पता लगाना है और अपने प्रस्तावों की सारी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करनी है। 1986-87 के मूल्य स्तर पर प्रति हेक्टेयर लागत 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित है।

(ङ) सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव शामिल करने के लिए नहीं भेजा है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते ।

जम्मू और कश्मीर में चूना-पत्थर के भंडार

2114. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में चूना-पत्थर के विशाल भंडार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां कितने भंडार होने का अनुमान है;

(ग) सरकार ने इनकी खुदाई के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इनकी खुदाई पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के अनुसार, कश्मीर क्षेत्र के चूना-पत्थर निक्षेपों का अनुमान लगभग 3 बिलियन टन लगाया गया है । इन निक्षेपों में सीमेंट ग्रेड और साथ ही रासायनिक दोनों ग्रेड उपलब्ध हैं ।

(ग) राज्य में सीमेंट ग्रेड के सन्पन्न चूना-पत्थर निक्षेपों के आधार पर विशाल और लघु क्षमता के अनेक सीमेंट प्लांट स्थापित किये गए हैं । राज्य में रासायनिक ग्रेड चूना-पत्थर के निक्षेपों के आधार पर कुछ लघु और मध्यम आकार के कैल्शियम कार्बाइड प्लांट भी स्थापित किए गए हैं ।

(घ) इन निक्षेपों के विदोहन के लिए खनन के आकार, स्थान, भूवैज्ञानिक स्थिति, उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं के अनुसार खान मुहाने पर चूना-पत्थर की निष्कर्षण लागत 50 रु० से 75 रु० प्रतिटन तक अलग-अलग होती है ।

दिल्ली और पटना के बीच विमान सेवा

[हिन्दी]

2115. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पटना के बीच पहले की तरह ही प्रातःकालीन और सायंकालीन विमान सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री जगेश्वर सिंघिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शरद ऋतु के दौरान बहुत सवेरे पटना और मार्ग के अन्य स्टेशनों पर प्रतिकूल मौसम होने से विलम्ब और उड़ान रद्द करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है । शरद ऋतु में इस व्यवधान को न्यूनतम करने और पूरे वर्ष में समय की एकरूपता को बनाए रखने के लिए, इंडियन एयरलाइंस को

इस समय दिल्ली और पटना के बीच बहुत सवेरे कोई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है ।

विदेश स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय

[अनुवाद]

2116. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों के लिये अपने कार्य क्षेत्र से पर्यटक भेजने सम्बन्धी देश-वार वार्षिक लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उन कार्यालयों के कार्य क्षेत्र का लक्ष्य और उपलब्धि कितनी थी, जिन्होंने एक वर्ष में 10,000 से अधिक पर्यटक भेजे हैं; और

(ग) चालू वर्ष के लिए ऐसे प्रत्येक कार्यालय का लक्ष्य कितना रखा गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । तथापि, विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों से यह आशा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पर्यटक भेजने का प्रयास करेंगे ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन देशों से जहां भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय स्थित हैं पर्यटक आगमन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

पर्यटक आगमन

देश	1989	1990	1991
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	30,433	30,076	22,700
कनाड़ा	40,306	41,046	36'142
फ्रांस	78,501	79,496	69,346
हालैंड	22,716	24,353	19,845
इटली	50,751	49,194	41,129
जापान	58,707	59,122	46,655
मलेशिया	33,120	34,278	30,617
सिंगापुर	29,377	32,570	28,363
स्पेन	20,016	18,567	13,644
स्वीडन	12,781	13,281	10,591
स्विटजरलैंड	32,034	32,431	29,247
थाइलैंड	10,576	11,877	11,354
यू.ए.ई.	31,471	27,477	28,860
बहरीन	13,574	12,637	11,386

1	2	3	4
यू० के०	229,496	235,151	212,052
अमरीका	134,314	125,300	117,322
जर्मनी	78,812	71,374	72,019

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन और अमरीका द्वारा विद्युत क्षेत्र में पूंजीनिवेश

2117. **श्री प्रफुल पटेल :**

श्री धर्म भिक्षम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरिका और ब्रिटेन ने भारत में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजना स्थलों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की क्षमता और अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) भारत में विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए यू० एस० ए० (अमरीका) और यू० के० (ब्रिटेन) की निजी फर्मों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की सूची निम्नवत है :—

क्र०सं०	परियोजना/राज्य का नाम	क्षमता (मे०वा०)	अनुमोदित लागत (करोड़ रु०)	कम्पनी/देश का नाम
1	2	3	4	5
1.	जेगुरप्रा०सी०सी०जी०टी०/ आंध्र प्रदेश	712.00 (गैस)	515.00	जी०वी०के० इंडस्ट्रीज यू०एस०ए०
2.	ए०एल०सी० का जीरो यूनिट ता०वि०के० तामिलनाडु	210.00 (लिग्नाइट)	750.00 (दिसम्बर,91)	एस०टी० पावर सिस्टम इन्क यू०एस०ए०
3.	विशाखापत्तनम/ आंध्र प्रदेश	1000.00 (कोयला)	3000.00 (जुलाई,92)	अशोक लेलैण्ड/निक्सन एनर्जी (यू०एस०ए०)/ए० पी०एस०ई०बी०
4.	काकीनाडा/ आंध्र प्रदेश	200.00 (सी०सी०जी०टी)	500.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिस, यू०एस०ए०
5.	दभोल एस०एन०जी० टी०पी०एस०/महाराष्ट्र	2550.00 (गैस)	6000.00 (जून,92)	एनरान पावर डैवलपमैंट कौर० पोरेशन (यू०एस०ए०)

1	2	3	4	5
6.	दुबूरी टी०पी०एस०/ उड़ीसा	500.00 (कोयला)	1548.00 (जनवरी,92)	उ०-पूर्वी एनर्जी सर्विसेज इन्क०, यू०एस०ए०/कलिंगा पावर कौरपो०
7.	मंगलौर/कर्नाटक	500.00 (कोयला)	1000.00	कौन्जेन्ट्रिक्स इन्क० (यू०एस०ए०)
8.	हिसार 1 व 2/ हरियाणा	500.00 (2×250)	1000.00	कौन्जैन्ट्रिक्स इन्क० (यू०एस०ए०)
9.	बंगलौर/कर्नाटक	500.00 (कोयला)	1000.00	—वही—
10.	घानकुनी/पश्चिम बंगाल	20.00 (गैस)	40.00 (जून,92)	स्पैक्ट्रम टैक्नोलौजिस (यू०एस०ए०)
11.	गंधार/गुजरात	615.00 (गैस)	573.73	गुजरात पावर कारपोरेशन लि०और टोरेंट एक्सपोर्ट लि० यू०एस०ए०
12.	इंडेली/कर्नाटक	60.00 (जलविद्युत)	125.00	कैथनैस इन्ट० पावर कौरपोरेशन, यू०एस०ए०
13.	बेडवी/कर्नाटक	210.00 (जलविद्युत)	350.00	—वही—
14.	अलमती डैम कर्नाटक	270.00 (जलविद्युत)	312.00	एशिया पावर कौरपोरेशन लि० (टापको) (यू०एस०ए०) और कर्नाटक पावर कारपोरेशन
15.	हासपैट/कर्नाटक	500.00 (कोयला)	1350.00	डाक इंटरकौन्टिनैन्टल लि० यू०एस०ए०
16.	रायचूर चरण-5/कर्नाटक	500.00 (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इन्ट०, इन्क० उ०-पूर्वी एनर्जी (यू०एस०ए०) कर्नाटक पावर कौरपोरेशन
17.	मैसूर/कर्नाटक	1000.00 (कोयला)	3000.00	पब्लिक पावर इन्ट०, इन्क० उ०-पूर्वी एनर्जी (यू०एस०ए०)
यू०के०				
1.	धारवार/कर्नाटक	300.00 (कोयला)	600.00	चालैस होल्डिंग लि० (यू०के०)

अतिरिक्त स्थानीय काल शुरू करने के पश्चात अर्जित राजस्व

2118. **श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पांच मिनट की अवधि के पश्चात एक और अतिरिक्त टेलीफोन काल शुरू करने से क्या सरकार को टेलीफोन उपभोक्ताओं से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के शुरू करने के पश्चात पिछले छः माह के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 5 मिनट की अवधि की शुरूआत करने के बाद अतिरिक्त टेलीफोन कालों को अनन्य रूप से मीटर में दर्ज करना मौजूदा प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है क्योंकि मीटर में दर्ज की गई स्थानीय कालों में 5 मिनट की अवधि से कम की कालें और एस० टी० डी० आई० एस० डी० कालें शामिल होंगी।

स्थानीय कालों में पांच मिनट की अवधि के बाद दूसरी काल दर्ज किए जाने की शुरूआत का उद्देश्य उपभोक्ता को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क के परियात को कम करना है।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना

[हिन्दी]

2119. **श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री राम पूजन पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान देश में कितने दूरदर्शन स्टुडियो का शिलान्यास किया गया ;

(ख) इन स्टूडियो की स्थापना के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) अब तक इलाहाबाद में निर्माण कार्य शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विजयवाड़ा, इलाहाबाद और हिसार में क्रमशः 7 जनवरी, 1990, 7 जुलाई, 1990 और 12 फरवरी, 1991 को दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्रों की स्थापना का शिलान्यास किया गया।

(ख) यद्यपि जहां विजयवाड़ा और इलाहाबाद को उनकी सांस्कृतिक महत्ता के आधार पर दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र की स्थापना के लिए चुना गया है वहां प्रत्येक राज्य में उसकी भाषा में निर्मित प्राथमिक (क्षेत्रीय) दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के दूरदर्शन के दीर्घावधि उद्देश्य के अनुसरण में हरियाणा के हिसार में पूर्ण सुसज्जित टी० वी० स्टुडियो की स्थापना की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) इलाहाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की स्कीम को अन्तिम रूप देने में

समय-समय पर देश में स्टुडियो सुविधाओं के और विस्तार के प्रश्न की पुनरीक्षा की जानी अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को अनुमोदित किए जाने के बाद ही इलाहाबाद में दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र की स्थापना से सम्बन्धित सिविल कार्यों को हाथ में लिया जाएगा।

भारतीय पर्यटन पर टी० वी० की फिल्में

2120. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम एशिया और अन्य देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन पर बनी कुछ फिल्मों का स्टार टी० वी० पर प्रदर्शन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार पश्चिम एशिया के अतिरिक्त किन-किन देशों से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित फिल्में स्टार टी० वी० के विभिन्न चैनलों से मुफ्त प्रसारित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

2121. **श्री० आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त स्थाई समिति को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई समिति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों के टेलीफोन बिल

2122. **श्री वी० धनंजय कुमार :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के लिए टेलीफोन कालों की कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों के आवासों और कार्यालयों के टेलीफोन बिलों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) दूरसंचार विभाग ने मंत्रियों द्वारा की जाने वाली टेलीफोन कालों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोसी नहर सिंचाई परियोजना के लिए सहायता

[हिन्दी]

2123. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी जिले में कोसी पश्चिमी नहर की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता क्या है और कमला नदी की मुख्य नहर पूर्वी तथा पश्चिमी नहरों नहरों की खुदाई के सम्बन्ध में क्या स्थिति है और कमला नदी के आर-पार साइफन के निर्माण की स्थिति का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संघ सरकार ने बिहार सरकार द्वारा मूलतः किए गए अनुरोध के अनुसार वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 20 करोड़ रु० से अधिक कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार के मधुबनी जिले के अन्तर्गत पश्चिमी कोसी नहर की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 1,08,901 हेक्टेयर है। विभिन्न संरचनाओं पर मिट्टी कार्य की सूचित प्रगति (30-6-92 की स्थिति के अनुसार) इस प्रकार है :

क्र०सं०	संरचना का नाम	लम्बाई कि० मी०	प्रगति
1.	पश्चिम कोसी मुख्य नहर	56.50	40 कि० मी० में 100% संरचनाओं के लिए गेप्स को छोड़ते हुए
2.	झांझरपुर शाखानहर	41.68	71%
3.	उग्रनाथ शाखानहर	36.50	22% आर०डी० से 2—11.3
4.	साकरी शाखाहनर	44.30	50%
5.	काकरघाटी शाखानहर	इस पर कार्य रोक दिया गया	फेस—III का हिस्सा होने के कारण
6.	सहारघाट शदखानहर	सूचित नहीं किया गया	69%
7.	कमला साईफोन	फरवरी 1992 में कार्य शुरू किया गया 47 मीटर की लम्बाई में शुरू किया गया।	

(ख) और (ग) योजना आयोग के कार्यदल ने वर्ष 1992-93 के लिए पश्चिम कोसी नहर के वास्ते 30 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है जबकी राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया था ।

बिजली उत्पादक सेटों का आयात

[अनुवाद]

2124. **श्री विजय एन० पाटिल :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादक सेटों का, क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बिजली उत्पादक सेटों के आयात पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय जल ग्रिड कार्यक्रम

[हिन्दी]

2125. **श्री छीतूभाई गामीत :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल ग्रिड कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किया जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जल संसाधनों के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के वास्ते अधिक जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल के अंतरण हेतु प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों के बीच अलग अलग अन्तर-सम्पर्कों की परिकल्पना की गयी है ।

(ग) इन प्रस्तावों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की । कुल 36 जल अन्तरण सम्पर्कों में से, प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 17 और हिमालयी घटक के अन्तर्गत 19 को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा अभिज्ञात किया गया है । प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 9 सम्पर्कों के कार्यात्मक अध्ययन पूरे हो गए हैं, शेष सम्पर्कों के अध्ययन आठवीं योजना में शामिल किए गए हैं । प्रायद्वीपीय घटक के 9 सम्पर्कों तथा हिमालयी घटकों

के 3 सम्पर्कों के अन्वेषण भी इस अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

दिल्ली में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

2126. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गैस पर आधारित 600 मेगावाट विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुछ निजी कम्पनियों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) डेसू द्वारा किए गए मुक्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुए 16 प्रस्तावों का मूल्यांकन किए जाने के आधार पर निम्नलिखित 6 पार्टियों को सूचीबद्ध किया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया हैं कि बवाना गैस-आधारित विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करें :—

1. रियांस इण्डस्ट्रीज लि०
2. आर० पी० गोयन्का
3. स्ट्रा प्रोडक्ट्स
4. वेम आर्गेनिक्स
5. एनटीपीसी तथा आसया ब्राउन बावेरी
6. नार्दर्न इन्जीनियरिंग इन्क० यू० एस० ए०

विदेशी पर्यटकों द्वारा अजन्ता और एलौरा का भ्रमण

[हिन्दी]

2127. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 92 में आज तक कितने विदेशी पर्यटकों ने अजन्ता और एलौरा का भ्रमण किया;

(ख) पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अजन्ता और एलौरा के निकटवर्ती क्षेत्र के विकास करने हेतु उक्त अवधि में कितनी राशि का नियतन किया गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) औरंगाबाद में एक स्वागत केन्द्र के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान 16.95 लाख रु० मंजूर किए गए और अजन्ता और एलौरा पर प्रचार समग्री तैयार करने के लिये 2.98 लाख रु० की राशि अवमुक्त की गई।

जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष की सहायता से रु० 81.71 करोड़ की कुल लागत से अजन्ता और एलौरा के संरक्षण और विकास के लिये एक परियोजना हाल ही में स्वीकृत की गई है।

एयर इन्डिया और इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा एयरहोस्टेज (परिचारिकाओं) और पायलटों की भर्ती

[अनुवाद]

2128. **डा० (श्रीमती) के० एस० सोंदरम :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स में भर्ती किये गये पायलटों एवं परिचारिकाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1992 में आज तक पायलट और परिचारिका के पदों पर कितने उम्मीदवार चुने गये ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में डाक सामग्री का वितरण

2129. **श्री सुव्रत मुखर्जी :**

डा० असीम बाला :

श्री सैयद मसूदल हुसैन :

डा० रामचन्द्र डोम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के रायगंज, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर जिलों में डाक सामग्री के वितरण में विलम्ब की घटनाओं में वृद्धि हुई है और क्या वहां इनका अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 1991 और 1992 के दौरान आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में डाक सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) डाक वस्तुओं के वितरण में देरी या कमी के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई। तथापि रुपये के उत्कीर्ण-लिफाफे की कमी ध्यान में आई है।

(ख) उत्कीर्ण-लिफाफों की कमी का कारण इन्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा इसकी अपर्याप्त सप्लाई है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सर्किल में निम्नलिखित संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1990-91	1666
1991-92	1324
1-4-92 से 31-10-92	669

(घ) पश्चिम बंगाल में सेवाओं में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) डाक पारेषण व वितरण की निरंतर मानीटरिंग ।

(ii) ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के साथ निकट समन्वय ।

(iii) उत्कीर्ण लिफाफों की पर्याप्त सप्लाई हेतु इन्डिया सिक्योरिटी प्रेस के साथ उच्चतम स्तर पर मामला उठाया गया है ।

(iv) जिन डाकघरों/सर्किलों की जरूरत कम होती है, उनसे स्टाक मांग कर तात्कालीन कमी को पूरा किया जाता है ।

राज्यों में टेलीफोन के अधिक राशि के बिल बनाना

[हिन्दी]

2130. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन के अधिक राशि के बिल आने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) भविष्य में ऐसी शिकायतें न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाऐ जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) (एक) पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोनों के अधिक राशि के बिल के सम्बन्ध में संचार मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों की कुल सं० 6,71,6?8 है ।

(दो) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं ।

(ख) भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें न हों इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(एक) गलत मीटरिंग की किसी भी सम्भावना से बचने के लिए मीटर सर्किटों सहित एक्सचेंज उपस्करों की नियमित जांच की जाती है।

(दो) मीटर कक्षों में ताले लगाए गए हैं और मुख्य विवरण फ्रेम (एम० डी० एफ०) कक्षों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

(तीन) सभी प्रमुख विन्दुओं जैसे वितरण बिन्दु में ताले लगाए गए हैं जहां से जानबूझकर शरारत करने अथवा टेलीफोन लाइनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना रहती है।

(चार) उन सभी उपभोक्ताओं का निर्धारण करना जिनके प्राक्षेक टेलीफोन मीटरों की रीडिंग में अकस्मात वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की वृद्धि का पता चलते ही टेलीफोन लाइनों को पर्यवेक्षणाधीन रखा जाता है। इस उद्देश्य से मल्टी-लाइन-आब्जरवेशन-उपस्कर नामक विशेष उपस्कर का इस्तेमाल किया जाता है।

(पांच) जिन ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उन्हें डायनामिक एस० टी० डी० नियंत्रण सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके जरिए वे अपने टेलीफोन में सुलभ एस० टी० डी०/आई० एस० डी० सेवाओं को बन्द अथवा खोल सकते हैं और इस प्रकार वे अपने टेलीफोनों को दूसरों के प्रयोग से बचा सकते हैं और अपने टेलींफोन पर कारगर ढ़ंग से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें एस० टी० डी०/आई० एस० डी० कालों के विस्तार बिल भेजे जाते हैं।

(छः) कुछ नान-डिजिटल एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं को विस्तृत बिल भेजने के लिए आटोमेटिक मेसेज एकाउन्टिंग (ए० एम० ए०) उपस्कर भी संस्थापित किए जा रहे हैं।

(सात) लिपिकीय अशुद्धियों से बचने के लिए सभी मेट्रो जिलों में बिल बनाने के कार्य को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है और अब यह कार्य अन्य महत्वपूर्ण शहरों एवं कस्बों में किया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31,335
2.	असम	10,602
3.	बिहार	24,366

1	2	3
4.	गुजरात	44,448
5.	हरियाणा	25,282
6.	हिमाचल प्रदेश	4,401
7.	जम्मू और कश्मीर	9,130
8.	कर्नाटक	34,592
9.	केरल	36,634
10.	मध्य प्रदेश	30,831
11.	महाराष्ट्र	1,09,427
12.	गोवा	3,111
13.	अरूणाचल प्रदेश	178
14.	मणीपुर	203
15.	मिजोरम	163
16.	मेघालय	1,032
17.	नागालैंड	513
18	त्रिपूरा	654
19.	उड़ीसा	12,712
20.	पंजाब	37,579
21.	चंडीगढ़ संघ क्षेत्र	6,928
22.	राजस्थान	11,564
23.	तमिलनाडु	44,906
24.	पांडीचेरी	1,159
25.	उत्तर प्रदेश	88,035
26.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित	53,811
27.	दिल्ली	48,062
	जोड़ :	6,71,658

केरल में पजासी परियोजना के लिए जापानी सहायता

[अनुवाद]

2131. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल में जापान की सहायता से पजासी पर्यटन विकास परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू करने की संभावना है और यह कब तक पूरं हो जाएगी; और

(घ) इस पर कितनी राशि के व्यय होने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बारक घाटी में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

2132. **श्री द्वारका नाथ दास :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारक घाटी में गैस पर आधारित एक विद्युत परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ कियां जायेगा तथा इसके कब पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विद्युत पारेषण और वितरण से नियंत्रण हटाना

2133. **श्री चंदूलाल चन्द्राकर :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी उद्यमियों के माध्यम से विद्युत पारेषण और वितरण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ क्षेत्र में कोई नया विद्युत पारेषण और वितरण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सरकार द्वार निर्धारित सामान्य नीति के अन्तर्गत विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) छतीसगढ़ क्षेत्र में कई ई० एच० वी० उपकेन्द्रों का निर्माण किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें ये शामिल हैं—

1. सिलतारा और बरसर में 400 के० वी० उपकेन्द्र
2. उरला में 220 के० वी० उपकेन्द्र
3. रायगढ़ में 220 के० वी० उपकेन्द्र
4. कनेरगढ़, ओगरगढ़, कबारधी, मोदी सीमेंट, बी० बाजार, अमेदी, चिलहोंटी, पथलगांव, अम्बिकापुर तथा सरायपल्ली में 132 के० वी० उपकेन्द्र।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

2134. **श्री ए० चार्ल्स :**

श्री रमेश चेन्नीतला :

श्री के० वी० थामस :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-10-92 की स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची के जिला-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. अल्लेप्पी	—	14828
2. कालीकट	—	24903
3. कन्नानौर	—	23013
4. एर्नाकूलम	—	41129
5. इडूक्की	—	7072
6. कसारागोड	—	13582
7. कोट्टायम	—	24254
8. कालापुरम	—	22680
9. पालघाट	—	12357

10. पतनभतिट्टा	—	12589
11. क्वीलान	—	16 30
12. त्रिचूर	—	31875
13. त्रिवेन्द्रम	—	24726
14. वेनड	—	4890
15. संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	—	541
16. संघ राज्य क्षेत्र पाणिचेरी (माहे)	—	1331

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 80,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर और संसाधन उपलब्ध हों। शेष आवेदकों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया है :—

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

—बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची को दो वर्ष तक सीमित करना।

ऊर्जा संरक्षण

2135. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई उपाय किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक के किये गये उपायों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान कितनी ऊर्जा की बचत होने की आशा है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री **कल्पनाथ राय**) : (क) और (ख) निदर्शन परियोजनाओं, आंशिक आर्थिक सहायता ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य, कृषि क्षेत्र की पम्प सुधार स्कीमें, उद्योगों की ऊर्जा संवर्धन स्कीमों के वित्त पोषण हेतु आई० डी० बी० आई० के माध्यम से विशेष ऋण स्कीमें लागू करना और सर्वव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य समुदायों (टारगेट ग्रुप्स) को जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने समेत सरकार ने अनेक ऊर्जा संवर्धन उपायों की शुरूआत की है। उपायों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं आदि द्वारा ऊर्जा संवर्धन उपस्कर के लिए निवेश को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। औद्योगिक यूनिटों द्वारा ऊर्जा दक्ष कार्य निष्पादन में सुधार किए जाने को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्कारों की भी शुरूआत की गई है।

(ग) हाल ही के वर्षों में जिन विभिन्न संवर्धन संबंधी उपायों की शुरूआत की गई है इनके परिणामस्वरूप संवर्धन की मात्रा का पता लगाना अभी समयानुसार शीघ्रता का द्योतक होगा। कुछ समय पश्चात् इसके लाभों का अनुमान लगाया जाना अधिक संतोषप्रद हो सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2136. **डा० परशुराम गंगवार :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से प्रत्येक राज्य में वर्षवार और जिलावार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा इनकी विद्युतीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में सभी गांवों का विद्युतीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने हेतु लोगों के अंशदान के लिए बांड जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री कल्पनाथ राय**) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आबंटित की गई निधियों समेत सातवीं योजनावधि के दौरान जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया उनके बारे में वर्षवार और राज्यवार संख्या सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 50,000 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की परिकल्पना की गई है इनमें 10,000 ऐसे गांव भी शामिल हैं जिनका विद्युतीकरण अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से किया जाना है। देश में सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता तथा विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यों को हाथ में लिए जाने के लिए राज्यों की उत्सुकता पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) ग्राम विद्युतीकरण निगम का, अपने योजनागत परिव्यय की पूर्ति के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान करमुक्त बाण्ड और सरकारी गारण्टी वाले बाण्ड जारी करके 105 करोड़ रु० जुटाए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्ड की सूचना के अनुसार सातवीं योजनावधि के दौरान जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया इनके बारे में वर्षवार एवं राज्यवार ब्यौरा तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य	198 -86		1986-87	
		विद्युतीकरण किए गए गांव	आबंटित की गई निधियां (लाख रु०)	विद्युतीकरण किए गए गांव	आबंटित की गई निधियां (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	804	3667	905	4648
2.	अरुणाचल प्रदेश	0		0	
3.	असम	1620	2128	1468	1335
4.	बिहार	2117	1866	3120	3016
5.	गोवा	0		0	
6.	गुजरात	799	1928	595	1711
7.	हरियाणा	0	852	0	1444
8.	हिमाचल प्रदेश	701	974	825	1244
9.	जम्मू एवं कश्मीर	89	314	117	472
10.	कर्नाटक	913	2030	1225	2249
11.	केरल	0	901	0	1101
12.	मध्य प्रदेश	3279	4823	3709	6288
13.	महाराष्ट्र	501	2825	502	2334
14.	मणिपुर	35	51	78	252
15.	मेघालय	59	4	76	262
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	65	354	85	296

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	1108	1396	1363	1617
19.	पंजाब	0	1844	0	2223
20.	राजस्थान	1127	1168	1126	1802
21.	सिक्किम	32	387	26	304
22.	तमिलनाडु	0	1776	4	1867
23.	त्रिपुरा	150	284	159	279
24.	उत्तर प्रदेश	3878	2783	3564	6518
25.	पश्चिमी बंगाल	1318	665	1342	2736
26.	अन्य कार्यक्रम		*		*
कुल योग		18595	53032	20289	43998

		1987-88		1988-89	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1076	6122	1250	4160
2.	अरुणाचल प्रदेश	71	201	95	218
3.	असम	1190	1306	1375	1771
4.	बिहार	2307	3010	2708	4206
5.	गोवा	0		0	
6.	गुजरात	410	2900	25	3579
7.	हरियाणा	0	2144	0	1749
8.	हिमाचल प्रदेश	634	1410	46	1118
9.	जम्मू एवं कश्मीर	101	697	59	781
10.	कर्नाटक	746	3014	313	907
11.	केरल	0	1050	0	1306
12.	मध्य प्रदेश	3929	7629	4337	9259
13.	महाराष्ट्र	787	7102	1050	6380
14.	मणिपुर	98	308	112	387

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	225	736	315	780
16.	मिजोरम	49	0	55	506
17.	नांगालैंड	170	646	25	465
18.	उड़ीसा	1516	2137	134	2958
19.	पंजाब	0	2351	0	2418
20.	राजस्थान	1097	2777	1442	350
21.	सिक्किम	40	343	31	188
22.	तमिलनाडु	0	3064	0	3162
23.	त्रिपुरा	155	369	125	319
24.	उत्तर प्रदेश	4185	6989	2488	1745
25.	पश्चिमी बंगाल	1573	3595	1649	866
26.	अन्य कार्यक्रम		*		
	कुल योग	20359	60559	18536	15696

*राज्यवार आबंटन में शामिल ।

		1989-90		1990-92	
1.	आन्ध्र प्रदेश	391	4576	4426*	23773
2.	अरुणाचल प्रदेश	160	757	326	1176
3.	असम	611	1490	5959	8081
4.	बिहार	2318	4552	12570	16650
5.	गोवा	0		0	
6.	गुजरात	0	3569	1829*	13487
7.	हरियाणा	0	2286	0*	8475
8.	हिमाचल प्रदेश	0	976	2206*	5722
9.	जम्मू एवं कश्मीर	43	729	409	2993
10.	कर्नाटक	0	3234	3190*	1163

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	0	1671	0*	6029
12.	मध्य प्रदेश	406	11729	19319	39719
13.	महाराष्ट्र	0	6851	2840*	25492
14.	मणिपुर	172	913	493	191
15.	मेघालय	233	777	908	2566
16.	मिजोरम	95	379	199	585
17.	नागालैण्ड	2	346	343	2067
18.	उड़ीसा	865	26 9	6103	10727
19.	पंजाब	0	2505	0*	11341
20.	राजस्थान	1923	4894	6715	14942
21.	सिक्किम	30	300	159	1522
22.	तमिलनाडु	0	3919	4*	13778
23.	त्रिपुरा	174	634	763	1885
24.	उत्तर प्रदेश	1832	8794	15947	36829
25.	पश्चिम बंगाल	1500	2978	7382	14880
26.	अन्य कार्यक्रम		**		**
	कुल योग	14414	71278	92193	274563

* 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार ऐसे राज्य जिनके 100 गांवों का विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है।

** राज्यवार आबंटन में शामिल।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2137. **श्री के० प्रधानी :**

डा० कृपासिन्धु भोई :

कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्य कितने चरणों में आरम्भ किये जाने

की सम्भावना है;

(ख) इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए कितनी विदेशी सहायता/ऋण उपलब्ध है;

(ग) आधुनिकीकरण के पहले चरण में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए क्रेडिटनस्टाल्ट फर वियेडेरोफबौ (के० एफ० डब्ल्यू०) जर्मनी से 2600 लाख डी० एम०, रूस के मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी० पी० ई०) से 238.9 लाख अमरीकन डालर का सप्लायर क्रेडिट और फ्रांस से 665 लाख फ्रेंच फ्रैंक के ऋण की परिकल्पना की गई है।

(ग) चरण-I के सभी 9 स्वदेशी पैकेजों के आर्डर दिए गए हैं और समय अनुसूची के अनुसार प्रगति हो रही है। संचयी आधार पर, उत्खनन का 85% कंकरीट बिछाने का, 93% स्ट्रकचरल फैब्रिकेशन का 69%, अवसंरचना स्थापना का 38%, उपस्कर आपूर्ति का 82% तथा उपस्कर स्थापना का 45% कार्य अक्तूबर, 1992 तक पूरा हो गया है। आधुनिकीकरण के चरण-I में अक्तूबर 1992 तक 306.72 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(घ) समग्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम दिसम्बर, 1995 तक पूरा करने की समय अनुसूची है और कुल संस्वीकृत लागत 3954 करोड़ रुपये है।

बाक्साइट का खनन

2138. **श्री रामकृष्ण कोतासा :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में के० डी० डेटान में बाक्साइट के खनन और प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सी-डाट एक्सचेंज

[हिन्दी]

2139. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन स्थानों पर सी-डाट 512 बोर्ड/एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान राज्य में इस प्रकार के बोर्ड/एक्सचेंज लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बोर्डों/एक्सचेंजों के कब तक लगाए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) बिहार के जिन स्थानों पर सी-डाट 512 बोर्ड/एक्सचेंज काम कर रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

1. सुपौल
2. जमशेदपुर
3. मोतीहारी
4. छपरा
5. गया
6. दरभंगा।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 1993-94 के दौरान स्थापित किए जाने वाले सी-डाट 512 बोर्डों/एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	जिला	सी-डाट 512 एक्सचेंजों/बोर्डों की संख्या	स्थापित किए जाने का सम्भावित समय
1	2	3	4
1.	गिरिडीह	1	अप्रैल, 1993 तक
2.	देवघर	1	—वही—
3.	डालटनगंज	1	मई 1993 तक
4.	मुंगेर	1	—वही—
5.	कटिहार	1	मई 1993 तक
6.	हजारीबाग	1	जून 1993 तक
7.	अररिया	1	—वही—
8.	किशनगंज		—वही—
9.	गोपालगंज	1	अगस्त 1993 तक
10.	भागलपुर	1	—वही—

1	2	3	4
11.	नवादा	1	अक्तूबर 1993 तक
12.	औरंगाबाद	1	—वही—

बेडथी पनबिजली परियोजना

[अनुवाद]

2140. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**

श्री वी० कृष्णा राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेडथी पन बिजली परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किसी अमरीकी कम्पनी को आमन्त्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) कर्नाटक की बेडथी जल विद्युत परियोजना जिसे गंगवाली चरण-I भी कहते हैं, को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20-2-79 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय कुछ सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए थे जिन्हें परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अभी सुनिश्चित किया जाना है। इस बीच, परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य प्राधिकारियों को संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। राज्य प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को संशोधित रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

(ग) से (ङ) इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कैथनेस इन्टरनेशनल पावर कारपोरेशन (यू० एस० ए०) और कर्नाटक सरकार के बीच अगस्त, 1992 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना को वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृत किए जाने और पर्यावरणीय स्वीकृति का पुनर्मूल्यांकन किए जाने के बाद परियोजना का क्रियान्वयन आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

टिहरी बांध परियोजना

[हिन्दी]

2141. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० महादोपक सिंह शाक्य :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :
श्री राजवीर सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना को पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस बीच स्वीकृति द दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर वर्ष 1991-92 के दौरान और 30 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) क्या रूस ने इस परियोजना का वित्त-पोषण करने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रूस से इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मिलने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) टिहरी परियोजना को कुछेक शर्तों के अधीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1990 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

(ख) पुनर्वास सम्बन्धी कार्य तथा अन्य अवसंरचनात्मक क्रियाकलाप आयोजना के अनुसार प्रगति पर हैं। सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही बांध स्थल पर निर्माण कार्य पुनः आरम्भ किया जाएगा।

(ग) इस परियोजना पर 1991-92 के दौरान 78.99 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई थी और 30 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार 747.28 करोड़ रुपया (अनन्तिम) की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) टिहरी बांध परियोजना के क्रियान्वयन में रूसियों ने रुचि प्रकट की है। तथापि वित्तपोषण पैकेज समेत कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दूरदर्शन चैनल में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

[अनुवाद]

2142. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री गुरूदास कामत :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी का एफ० एम० बैण्ड और दूरदर्शन का मेट्रो चैनल का अधिकार गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में दूरदर्शन के मैट्रो चैनलों और आकाशवाणी के एफ० एम० चैनलों पर निजी निर्माताओं को समय आबंटन किया जाए। योजना का सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में दूरदर्शन के महानगर चैनलों तथा आकाशवाणी के एफ० एम० चैनलों पर समय आबंटन करने की योजना

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(क) इस योजना का नाम दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानगर चैनलों पर समय का आबंटन करने की योजना है।

(ख) यह तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

2. **परिभाषाएं**

जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में—

(1) चैनल से अभिप्रेत दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के महानगरों में टी० वी० अथवा एफ० एम० रेडियो चैनल से है।

(2) राष्ट्रपति से अभिप्रेत भारत का राष्ट्रपति है।

(3) सरकार से अभिप्रेत केन्द्रीय सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है।

(4) परिषद से अभिप्रेत भारतीय प्रसारण परिषद से है।

(5) अध्यक्ष से अभिप्रेत भारतीय प्रसारण परिषद का अध्यक्ष है।

(6) सदस्य से अभिप्रेत प्रसारण परिषद का सदस्य है।

3. ****प्रसारण परिषद**

एक प्रसारण परिषद होगी जिसका एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष कोई विख्यात और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अन्य सदस्यों में *दूरदर्शन/आकाशवाणी के महानिदेशक और दूरदर्शन/आकाशवाणी के मुख्य इंजीनियर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगे। अन्य सदस्य

*टिप्पणी : जब दूरदर्शन से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श होगा तो दूरदर्शन के महानिदेशक और मुख्य इंजीनियर सदस्य होंगे। इसी तरह जब आकाशवाणी से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श होगा तो आकाशवाणी के महानिदेशक और मुख्य इंजीनियर सदस्य होंगे।

**सार्वजनिक सूचना संख्या 8/1/92-पी० बी० सी० ता० 6-11-92 के तहत इस समिति को "भारतीय समय आबंटन समिति" के रूप में पुनः नामित किया गया है।

प्रतिष्ठित एवं विख्यात मीडिया कर्मी, लेखक और नाट्यकार, अभिनेता और फिल्म कर्मी होंगे जिन्हें इलैक्ट्रानिक मीडिया की जानकारी और विशेषज्ञता प्राप्त हो ।

4. **परिषद का कार्यकाल**

परिषद का कार्यकाल उसकी स्थापना की तारीख से तीन वर्ष अथवा नई परिषद की नियुक्ति तक होगा । अध्यक्ष तथा सदस्यों की रिक्तियां परिषद की शेष अवधि के कार्यकाल के लिए ही भरी जाएंगी ।

5. **सदस्यों की शर्तें**

अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्च शक्ति प्राप्त समितियों के सदस्यों पर लागू यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

6. (1) **परिषद के कार्य**

परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी :

(क) टेलीविजन/रेडियो चैनल पर समय आबंटित करने के प्रयोजन से, परिषद सार्वजनिक सूचना जारी कर व्यक्तियों से, जो भारत के नागरिक होंगे/कंपनियों से जिनमें भारतीय शेयरहोल्डरों का बहुमत होगा/भागीदारी फर्मों से, जिनके समस्त भागीदार भारत के नागरिक होंगे, आवेदन आमंत्रित करेगी ।

(ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन के चैनलों पर कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस जारी करेगी और उपयुक्त समय का आबंटन करेगी ।

(ग) लाइसेंसधारी द्वारा टेलीकास्ट/प्रसारित कार्यक्रम की समीक्षा करेगी ।

(घ) लाइसेंसों के आस्थगन और रद्दकरण पर विचार करेगी, निर्णय लेगी और कार्यवाही करेगी ।

(ङ) चैनलों पर कार्यक्रमों के लिए गुणवत्ता के आयाम तय करेगी ।

(च) इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों द्वारा टेलीकास्ट/प्रसारित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में शिकायतें/कठिनाईयों को दूर करने के लिए मंच प्रस्तुत करेगी ।

6. (2) **सरकार द्वारा निर्देश**

इस योजना के लिए सरकार को समय-समय पर निर्देश जारी करने और मार्गनिर्देश निर्धारित करने का अधिकार होगा और परिषद ऐसे निर्देशों और मार्गनिर्देशों के लिए जिम्मेदार होगी ।

7. **लाइसेंसधारियों के लिए पात्रता मापदण्ड**

इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक निर्माताओं के लिए यह जरूरी है कि वे निम्नलिखित मापदण्डों को पूरा करते हों, :

(क) भारत का नागरिक हो, (व्यक्तियों के लिए)/कंपनियों, जिनमें भारतीय शेयर होल्डरों का बहुमत हो/भागीदारी फर्में जिनके समस्त भागीदार भारत के नागरिक हों ।

(ख) दिवालिया घोषित न किया गया हो या किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध न ठहराया गया हो;

(ग) वित्तीय स्थिति का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने के लिए लिखित में इच्छा की पुष्टि करनी चाहिए;

(ङ) लिखित रूप में यह आश्वासन देना चाहिए कि लाइसेंस में निर्दिष्ट सभी शर्तों अथवा परिषद अथवा सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अनुवर्ती निर्देश का पालन करेगा;

*(च) समाचारों से सम्बद्ध कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले आवेदक का उस चैनल द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र में कोई समाचार पत्र/पत्रिका नहीं होनी चाहिए जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया हो।

(छ) आवेदक का टेलीविजन/रेडियो कार्यक्रम, फीचर फिल्मों, वीडियो फिल्मों, वीडियो पत्रिकाओं, वृत्तचित्रों आदि का निर्माण करने का प्रमाणित रिकार्ड होना चाहिए।

8. **लाइसेंस के लिए आवेदन**

परिषद समय के उचित अन्तराल के बाद सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दूसरे चैनल पर समय के आबंटन की इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित करेगी। ऐसे आवेदकों को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1000/-रुपये की रकम अदा करनी होगी।

9. **समय का आबंटन**

केन्द्रीय परिषद को इस योजना के प्रयोजन के लिए चैनल पर समय की उपलब्धता के बारे में बताएगी। परिषद सफल आवेदकों को सम्बद्ध चैनलों पर उपयुक्त समय का आबंटन करेगी। परिषद आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित तकनीकी आयाम के अनुपालन की निगरानी करेगी।

10. इस योजना के अन्तर्गत प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले मार्गनिर्देश :

(1) कार्यक्रमों द्वारा आकाशवाणी प्रसारण संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित को मनाही की गई है :

(क) मित्र देशों की आलोचना;

(ख) धर्म अथवा समुदायों पर आक्षेप;

(ग) अश्लील या मानहानिकारक बातें;

(घ) जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता हो अथवा जिससे कानून और व्यवस्था न बनाई रखी

(* टिप्पणी : सार्वजनिक सूचना संख्या 8/1/92-पी० बी० सी० तारीख 27-10-92 के तहत इसे हटा दिया गया है।)

जा सकती हो;

(ङ) ऐसी कोई बात जिससे न्यायालय की अवमानना हो;

(च) जिसमें राष्ट्रपति तथा न्यायाधिकारी की न्यायनिष्ठा की निन्दा की गई हो;

(छ) राष्ट्र की एकता पर प्रभाव डालने वाली कोई बात; और

(ज़) किसी व्यक्ति के नाम से आलोचना।

(2) लाइसेंसधारी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लागू विज्ञापन संहिता का और उनमें भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों का पूरा-पूरा पालन करेगा।

(3) ये कार्यक्रम चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (ख) और सरकार द्वारा समय-समय पर फिल्म प्रमाणीकरण के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी मार्गनिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप होंगे।

(4) इन कार्यक्रमों द्वारा कापीराइट के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

(5) चैनल द्वारा अपने प्रसारण समय का कम-से-कम 20 प्रतिशत ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे जो परिषद की दृष्टि में समाज सापेक्ष और विकास प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) चैनल द्वारा राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे जिनके लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निदेश दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम सन्देश शामिल होंगे।

(7) चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का उपयोग किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में नहीं किया जाएगा।

(8) चुनाव के दौरान चैनल द्वारा राजनीतिक पार्टियों द्वारा अथवा उनके बारे में प्रसारणों में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का पालन किया जाएगा।

(9) किसी विवाद के मामले में कार्यक्रमों में सभी दृष्टिकोणों को उचित और निष्पक्ष रीति से प्रस्तुत किया जाएगा।

11. **गुणवत्ता क्रम (क्वालिटी रेटिंग)**

परिषद उसके द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के आयामों के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करेगी। जिन लाइसेंसधारियों के कार्यक्रम विषयवस्तु और तकनीकी आयामों के, अर्थात दोनों दृष्टियों से न्यूनतम सीमा से कम पाए जाएंगे उन्हें लिखित रूप से अपने कार्यक्रमों में आवश्यक रूप से सुधार करने के लिए लिखित रूप में कहा जाएगा। लाइसेंसधारियों के लाइसेंसों के नवीकरण पर विचार करते समय उनके कार्यक्रमों की गुणवत्ता का पूर्व रिकार्ड अनिवार्य मापदण्ड होगा। परिषद कार्यक्रम की गुणवत्ता के मूल्यांकन के परिणाम समय-समय पर प्रकाशित भी करेगी।

12. **शिकायतों को दूर करना**

इस योजना के अंतर्गत किसी लाइसेंसधारी द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम विशेष के खिलाफ

किसी व्यक्ति अथवा संस्था से लिखित शिकायत प्राप्त होने पर परिषद लाइसेंसधारी के परामर्श से, यदि ऐसा करना जरूरी हो, जांच करेगी और यदि शिकायत सिद्ध हो जाती हो तो उचित उपचारात्मक कार्रवाई करेगी। परिषद लाइसेंसधारी को उसके निष्कर्ष प्रसारित करने का निदेश दे सकती है और यदि आवश्यक हो तो लाइसेंस स्थगित करने/रद्द करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।

13. लाइसेंस का स्थगन/रद्दकरण अनिवार्य न समझा जाय तब तक लाइसेंसधारी को कार्यक्रम की मार्गनिर्देशों/लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा और उसे स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस स्पष्टीकरण पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा और निर्णय की सूचना लाइसेंसधारी को दे दी जाएगी।

14. **लाइसेंस का नवीकरण**

इस योजना के अंतर्गत जारी किसी लाइसेंस के नवीकरण पर निर्णय लेने के लिए लाइसेंस में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से 6 महीने पूर्व परिषद कार्रवाई शुरू कर देगी। परिषद इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्णय लेगी :

(क) वर्तमान लाइसेंस की अवधि के दौरान लाइसेंसधारी का कार्य निष्पादन

(ख) लाइसेंसधारी द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का गुणवत्ता क्रम

(ग) अन्य कम्पनियों से समान प्रकरण/विषय पर प्राप्त प्रस्ताव

(घ) किसी एक समय में चैनल के कार्यक्रम सम्बन्धी समूची आवश्यकता को देखते हुए किसी विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता।

15. **सरकार द्वारा चैनलों का नियंत्रण**

युद्ध अथवा दैवी आपदा की स्थिति में सरकार, लोकहित में, आदेश के जरिए, इस योजना के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों के अधीन सभी प्रसारणों का तथा/अथवा प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है।

16. **लाइसेंस शुल्क**

लाइसेंसधारियों द्वारा देय लाइसेंस राशि का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

17. **संदेहों को दूर करना**

इस स्कीम के किसी प्रावधान के अर्थात निर्णय के बारे में सन्देह होने पर मामले को निर्णय के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

गुजरात में बिजली उत्पादन क्षमता

2143. **श्री काशीराम राणा :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में गुजरात की बिजली उत्पादन क्षमता में कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ख) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए कोयले पर आधारित नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गुजरात में विद्युत उत्पादन क्षमता में 1885 मे० वा० के लगभग कमी होने की प्रत्याशा की गई है। नौवीं योजना के दौरान प्रत्याशित विद्युत उत्पादन क्षमता का पता नौवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही लग पाएगा।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों के अनुसार, गुजरात राज्य में किसी भी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—विद्यमान संयंत्रों से ईष्टतम विद्युत उत्पादन करना, विद्युत का अन्त:राज्यीय आधार पर अन्तरण करना, केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से सहायता प्रदान करना, ऊर्जा संवर्धन तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना।

मुख्य डाक कार्यालयों को निकासी गृह में बदलना

2144. **प्रो० रीता वर्मा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उन मुख्य डाक कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें स्थानीय निकासी गृह में बदला गया है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में निकासी गृह में बदले जाने वाले मुख्य डाक कार्यालयों के क्या नाम हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) देश को 19 डाक सर्किलों में बांटा गया है। जिन प्रधान डाकघरों को लोकल क्लीयरिंग हाउसेज की पूर्ण इकाई के रूप में सूचीबद्ध किया गया है उनकी सर्किलवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जिन प्रधान डाकघरों को 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है, उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	डाक सर्किल का नाम	लोकल क्लीयरिंग हाउसेज के सदस्य के रूप में पंजीकृत एच० पी० ओ० के नाम
1	2	3
1.	केरल	1. अलूर
		2. अलापुझा

1	2	3
		3. अलवे
		4. वड़ागारा
		5. कालीकट
		6 कन्नानूर
		7. चेंगन्नूर
		8. चंगनचेरी
		9. इर्नाकुलम
		10. इरिनजलकुडा
		11. कनहनगढ़
		12. करूणागापल्ली
		13. कसरगोड
		14. कयमकूलम
		15. कोट्टरकारा
		16. कोट्टायम
		17. कोची
		18. मलप्पुरम
		19. मंजेरी
		20. मवेलीकरा
		21. कुन्नालूर
		22 चेरताला
		23. नेय्यारट्टीनकारा
		24. ओट्टापलम
		25. पलई
		26. तोडुपुझा
		27. पथनमथिट्टा
		28. कुन्नमकुलम
		29. किलंडी
		30. किलोन
		31. वड़ाकवेरी त्रिचूर

1	2	3
		32. तेल्लीचेरी
		33. तिरूर
		34. तिरूवल्ला
		35. त्रिचुर
		36. त्रिवेन्द्रम जी० पी० ओ०
		37. वैकोम
		38. पालघाट
		39. मुक्ट्टुपुझा
		40. पेरूमुवुर
2.	मध्य प्रदेश	1. रायपुर
		2. नीमुच
		3. मंदसौर
		4. रतलाम
		5. उज्जैन
		6. बिलासपुर
		7. गोरवा
		8. दुर्ग
		9. जबलपुर
		10. रीवा
		11. लसकर
3.	राजस्थान	1. अजमेर
		2. बांसवाड़ा
		3. ब्यावर
		4. भीलवाड़ा
		5. बीकानेर
		6. चित्तौड़गढ़
		7. जयपुर जी० पी० ओ०
		8. जोधपुर
		9. कोटा

1	2	3
		10. नागौर
		11. झुन्झुनू
		12. श्रीगंगानगर
		13. उदयपुर
		14. नसीराबाद
	गुजरात	1. अहमदाबाद जी० पी० ओ०
		2. अमरेली
		3. वरदौली
		4. विलीमोरा
		5. भड़ौच
		6. भावनगर
		7. गोदरा
		8. गोंडल
		9. नादियाड
		10. नरसारी
		11. पालनपुर
		12. सूरत
		13. बड़ौदरा
		14. वलसाड
5.	हिमाचल प्रदेश	1. बिलासपुर
		2. धर्मशाला
		3. हमीरपुर
		4. कांगड़ा
		5. मंडी
		6. शिमला
6.	महाराष्ट्र	1. अकोला
		2. अमरावती
		3. चन्द्रपुर

1	2	3
		4. भंडारा
		5. गोंडिया
		6. खम्बगांव
		7. नागपुर
		8. वर्धा
		9. औरंगाबाद
		10. बीड
		11. जलगांव
		12. नांदेड़
		13. धुलिया
		14. अहमदनगर
		15. जलना
		16. चालीसगांव
		17. परभनी
		18. नासिक रोड एच०ओ०
		19. नासिक एच०ओ०
		20. थाणे
		21. कल्याण
		22. बम्बई जी०पी०ओ०
		23. पुणे
		24. पंधरपुर
		25. शोलापुर
		26. पणजी
		27. मरगांव
		28. सांगली
		29. इचलकरंजी
		30. यवतमल
7.	उड़ीसा	1. बालासोर

1	2	3
		2. वरीपाड़ा
		3. भुवनेश्वर जी०पी०ओ०
8.	पंजाब	1. अमृतसर
		2. चंडीगढ़
		3. दसुया
		4. फिरोजपुर
		5. होशियारपुर
		6. जालन्धर सिटी
		7. लुधियाना
		8. पटियाला
		9. फगवाड़ा
		10. रोपड़ा
9.	तमिलनाडु	1. अम्बासमुद्रम
		2. अरकोनम
		3. भवानी
		4. बोदिनयकुनूर
		5. कोयम्बटूर
		6 कुन्नूर
		7. कुड्डालूर
		8. डिंडीगुल
		9. इरोड़
		10. गुड्डियातम
		11. करईकुडी
		12. करूर
		13. कांचीपुरम
		14. कोविलपट्टी
		15. मद्रास जी०पी०ओ०
		16. मदुरई

1.	2	3
		17. मेईलादुतुरई
		18. मिट्टूपलयम
		19. नागरकोयल
		20. नमक्कल
		21. पेरियाकुल्लम
		22. पोल्लाची
		23. पांडिचेरी
		24. राजपलियम
		25. सलेम
		26. सिरकाली
		27. पलनी
		28. शिवकाशी
		29. थंजावूर
		30. तिरूचेंगोडू
		31. तिरुचिरापल्ली
		32. तिरूनेलवेली
		33. तिरूपत्तूर
		34. तिरूपुर
		35. टूटीकोरन
		36. उद्गमंडलम
		37. वेल्लौर
		38. विलूपुरम
		39. तिरूद्धनगर
10.	हरियाणा	1. अम्बाला कैंट
		2. अम्बाला सिटी
		3. भिवानी
		4. फरीदाबाद
		5. गुड़गांव

1	2	3
		6. हिसार
		7. करनाल
		8. कुरुक्षेत्र
		9. पानीपत
		10. रोहतक
		11. सिरसा
		12. सोनीपत
11.	पश्चिम बंगाल	1. आसनसोल
		2. बंकुरा
		3. वर्धमान
		4. दुर्गापुर
		5. कलकत्ता जी०पी०ओ०
		6. चिंसुरा
		7. जलपाईगुड़ी
		8. मिदनापुर
		9. रानीगंज
		10. सिलीगुड़ी
12.	असम	1. धुबरी
		2. डिब्रूगढ़
		3. गुवाहाटी जी०पी०ओ०
		4. जोरहाट
		5. करीमगंज
		6. नवगांव
		7. सिवसागर
		8. सिल्चर
		9. तेजपुर
13.	उत्तर पूर्व	1. शिलांग (मेघालय)
		2. इम्फाल (मणिपुर)

1	2	3
14.	दिल्ली	1. नई दिल्ली
15.	कर्नाटक	1. बेलगांव
		2. बिदर
		3. बीजापुर
		4. धारवाड़
		5. गडग
		6. हुबली
		7. करवार
		8. कुमसा
		9. गुलबर्ग
		10. बंगलौर जी०पी०ओ०
		11. मैसूर
		12. मंगलूर
		13. पत्तूर
		14. शिमोगा
		15. चित्रदुर्ग
		16. दावनगेरे
		17. चिकमंगलूर
		18. हसन
		19. मांदीकेरी
		20. मंडया
		21. तुमकर
		22. सिरसी
16.	बिहार	1. भागलपुर
		2. बोकारो स्टील सिटी
		3. छपरा
		4. धनबाद
		5. गया

1	2	3
		6. हजारीबाग
		7. जमशेदपुर
		8. मुंगेर
		9. मुजफ्फरपुर
		10. पटना जी०पो०ओ०
		11. रांची
17.	आंध्र प्रदेश	1. अनंतपुर
		2. गुड्डाफ
		3. धर्मविरम
		4. एलूरू
		5. गुंटाकल
		6. हिन्दुपुर
		7. हैदराबाद जी०पी०ओ०
		8. काकीनाडा
		9. करीमनगर
		10. कुर्नूल
		11. महबूब नगर
		12. मछलीपटनम
		13. नलगोंडा
		14. नरसरावपेट
		15. श्रीकाकुलम
		16. तिरुपति
		17. विजयवाड़ा
		18. विशाखापटनम
		19. विजयनगरम
		20. वारंगल
18.	उत्तर प्रदेश	1. आगरा
		2. आगरा फोर्ट

1	2	3
		3. इलाहाबाद
		4. इलाहाबाद कचहरी
		5. आजमगढ़
		6. बांदा
		7. अलीगढ़
		8. बदायूं
		9. बारबंकी
		10. देहरादून
		11. देहरादून कैंट
		12. देवरिया
		13. इटावा
		14. फैजाबाद
		15. गोरखपुर
		16. कुनराघाट
		17. गोंडा
		18. गाजियाबाद
		19. जौनपुर
		20. कानपुर
		21. कानपुर कैंट
		22. नवाबगंज (कानपुर)
		23. खीरी
		24. लखनऊ जी०पी०ओ०
		25. लखनऊ चौक
		26. मेरठ
		27. मेरठ सिटी
		28. मुरादाबाद

1	2	3
		29. शामली
		30. सीतापुर
		31. वाराणसी
		32. वाराणसी कैंट
		33. रुड़की
		34. हापुड़
		35. उन्नाव
		36. बरेली
		37. मथुरा
		38. बलिया
		39. बुलंदशहर
		40. हल्द्वानी
		41. झांसी
		42. पीलीभीत
		43. रायबरेली
		44. शाहजहांपुर
		45. बिजनौर
		46. मुजफ्फरपुर
		47. सहारनपुर
		48. नैनीताल
19.	जम्मू एवं कश्मीर	1. श्रीनगर जी०पी०ओ०

विवरण-II

लोकल क्लीयरिंग हाउसेज के सदस्य के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावि हैड पोस्ट ऑफिस के नाम

क्र० सं०	डाक सर्किल का नाम	1992-93 के दौरान	1993-94 के दौरान
1	2	3	4
1.	केरल	1. चलकुडी	1. कंजीरापल्ली

1	2	3	4
		2. पोन्नानी	2. कट्टाप्पना
		3. अट्टींगल	3. अलातुर 4. कलपेट्टा 5. तालीपरम्बा
2.	मध्य प्रदेश	शून्य	1. सागर कैंट
3.	राजस्थान	1. अलवर 2. भरतपुर	1. डूंगरपुर 2. रतनगढ़ 3. बूंदी 4. पाली 5. हनुमानगढ़ जंक्शन
4.	गुजरात	1. भुज 2. जामनगर 3. राजकोट	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	1. सोलन	शून्य
6.	महाराष्ट्र	1. कोल्हापुर 2. सतारा 3. कराड 4 चिपतुन 5. रतनगिरि	शून्य
7.	उड़ीसा	1. भद्रक 2. राउरकेला	शून्य
8.	पंजाब	1. जगरांव 2. राजपुरा 3. भटिंडा 4. फरीदकोट	1. संगरूर 2. गुरुदासपुर 3. खन्ना
9.	तमिलनाडु	1. अतुर 2. धारापुरम 3. धर्मपुरी 4. कृष्णगिरि 5. उडुमलपेट 6. तिरुवन्नमली	1. अरनी 2. टिंडीवनम
10.	हरियाणा	शून्य	शून्य

1	2	3	4
11.	पश्चिम बंगाल	1. सिक्किम 2. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
12.	असम	1. तिनसुखिया	शून्य
13.	उत्तर-पूर्व	1. कोहिमा (नागालैंड) 2. आईजाल (त्रिपुरा) 3. अगरतला (त्रिपुरा)	शून्य
14.	दिल्ली	शून्य	शून्य
15.	कर्नाटक	शून्य	1. बीलेरी 2. रायचूर 3. सलिया 4. करकला 5. कोलार
16.	बिहार	1. औरंगाबाद 2. आरा 3. बेगूसराय 4. दुमका 5. डाल्टनगंज 6. गिरीडीह 7. हाजीपुर 8. लहरिया सराय 9. पुर्णिया 10. सासाराम 11. समस्तीपुर	1. बक्सर 2. बांकीपुर 3. बिहारशरीफ 4. देवगढ़ 5. बेतिया 6. बांका 7. चाइबासा 8. दरभंगा 9. गुमला 10. गोपालगंज 11. हिनू 12. कटिहार 13. मोतीहारी 14. मधुबनी 15. मरहौरा 16. नवादा 17. रामगढ़ कैंट 18. सीतामढ़ी 19. सिदान 20. सहरसा

1	2	3	4
17.	आंध्र प्रदेश	1. चित्तूर 2. नानदियाल	1. अदोनी 2. बोद्दतपुर 3. नदानापल्ली
18.	उत्तर प्रदेश	1. अल्मोड़ा 2. बस्ती 3. बहराईच 4. फिरोजाबाद 5. हरदोई 6. खुर्जा 7. मैनपुरी 8. मिर्जापुर 9. प्रतापगढ़ 10. रामपुर 11. सुलतानपुर	शून्य
19.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य

मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डाक तार घर

[हिन्दी]

2145. **श्री योगानन्द सरस्वती** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन और डाकघरों की सुविधाओं वाले ग्राम पंचायतों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत को डाकघर और टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) उनमें से उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां डाक से तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा के विस्तार की योजना क्या है; और

(घ) राज्य के मुख्यालय शहरों में तीव्र डाक सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिलेवार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 30 नवम्बर, 1992 तक टेलीफोन सुविधा वाले पंचायत ग्रामों की संख्या 8844 है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पंचायत ग्रामों में 30-11-1992 को डाकघरों की संख्या : 9500 है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) (i) सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में 31 मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार की है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ii) नए डाकघर निकटवर्ती डाकघर से दूरी, सेवित आबादी और नए डाकघर पर आने वाली लागत पर होने वाली आमदनी की शर्तें तथा उपलब्ध निधि को देखते हुए खोले जाते हैं। अतः प्रत्येक पंचायत ग्रामों में डाकघर कब तक खोले जा सकते हैं, यह समय निश्चित नहीं किया जा सकता।

(ग) 1782. अलग से कोई विस्तार योजना नहीं है। तार सुविधा अपेक्षित परियात की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है।

(घ) राज्य के किसी शहर/कस्बे में द्रुत डाक सेवा की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है और इस पर यातायात वाणिज्यिक तथा बाजार की उपलब्धता को देखते हुए विचार किया जाता है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में 30-11-92 को जिन पंचायत ग्रामो में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध थी उनके जिलेवार ब्यौरे

क्र० सं०	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा सहित पंचायत ग्रामों कीकुल सं०	क्र० सं०	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा सहित पंचायत ग्रामों की कुल सं०
1	2	3	1	2	3
1.	बालाघाट	181	17	इन्दौर	147
2.	बस्तर	402	18.	जबलपुर	302
3.	बेतूल	146	19.	झाबुआ	130
4.	भिंड	130	20.	खंडुआ	208
5.	भोपाल	83	21.	खरगौन	305
6.	बिलासपुर	433	22.	मांडला	153
7.	छत्तरपुर	166	23.	मंदसौर	264
8.	छिंदवाड़ा	243	24.	मुरैना	241
9.	दामोह	135	25.	नरसिंहपुर	159
10.	दतिया	99	26.	पन्ना	55
11.	देवास	145	27.	रायगढ़	317
12.	धार	206	28.	रायपुर	524
13.	दुर्ग	162	29.	रायसेन	192
14.	गुना	182	30.	राजघढ़	131
15.	ग्वालियर	195	31.	राजनांदगांव	163
16.	होशंगाबाद	193	32.	रतलाम	157

1	2	3	1	2	3
33.	रीवा	156	41.	शिवपुरी	138
34.	सागर	279	42.	सिधी	121
35.	सरगूजा	143	43.	टीकमगढ़	141
36.	सतना	180	44.	उज्जैन	237
37.	सिहोर	194	45.	विदिशा	150
38.	सिवनी	154			
39.	शहडोल	161		योग	8844
40.	शाजापुर	241			

विवरण-II

मध्य प्रदेश में 30-11-92 को जिन पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध थी उनके जिलेवार ब्यौरे

क्र० सं०	जिले का नाम	सं०	क्र०सं०	जिले का नाम	सं०
1.	बालाघाट	212	24.	खंडवा	198
2.	मांडला	187	25.	खरगौन	269
3.	सिवनी	170	26.	मंदसौर	270
4.	भोपाल	58	27.	मोरेना	239
5.	बिलासपुर	545	28.	भिंड	234
6.	छत्तरपुर	180	29.	रायगढ़	371
7.	पन्ना	120	30.	अबम्किापुर	270
8.	टिकमगढ़	157	31.	रायपुर	517
9.	छिंदवाड़ा	246	32.	रतलाम	139
10.	बेतुल	201	33.	झबूआ	125
11.	दुर्ग	255	34.	रीवा	286
12.	राजनम्दगांव	183	35.	सतना	239
13.	होशंगाबाद	197	36.	सागर	170
14.	नरसिंहपुर	150	37.	दामोह	162
15.	गुना	154	38.	सिहोर	147
16.	शिवपुरी	194	39.	राजगढ़	151
17.	ग्वालियर	20	40.	शहडोल	240
18.	दतिया	220	41.	सिधी	162
19.	इन्दौर	109	42.	उज्जैन	156
20.	देवास	155	43.	शाजापुर	150
21.	धार	180	44.	विदिशा	140
22.	जबलपुर	286	45.	रायसेन	184
23.	जगदलपुर	502			

विशेष निगमित डाक घर

[अनुवाद]

2146. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "पब्लिक इश्यू मेल" के संचालन हेतु विशेष निगमित डाक घर स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष निगमित डाकघर कहां तक उपयोगी होंगे; और

(घ) इन पर कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। चुने हुए केन्द्रों पर ऐसे विशेष डाकघर खोले गए हैं तथा आवश्यकतानुसार और केन्द्रों में भी ऐसे डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) ऐसे डाकघर खोलने का राज्यवार कोई कार्यक्रम नहीं है। डाक सर्किल जरूरत के अनुसार ऐसे डाकघरों की योजना बनायेंगे और उन्हें खोलेंगे।

(ग) ये विशेष डाकघर त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत केवल एकमुश्त रूप में संस्थाओं से डाक लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सामान्य डाकघर, ऐसी डाक निपटाने के लिए पूरी तरह से साधन सम्पन्न नहीं होते और इसलिए ये विशेष डाकघर उपयोगी हैं।

(घ) ऐसे डाकघरों पर होने वाले व्यय का कोई आकलन या पृथक लेखा-जोखा नहीं है : कर्मचारी अन्य डाकघरों से लेकर इन डाकघरों में तैनात किए जाते हैं। इसमें केवल डाकघर के स्थान जैसे अन्य खर्च ही शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

[हिन्दी]

2147. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**

श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय दूरदर्शन केन्द्रों और रिले केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पहुंचते हैं;

(ग) क्या किसी नए दूरदर्शन केन्द्र अथवा रिले केन्द्र की स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भोपाल दूरदर्शन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इनके विस्तार के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भोपाल में एक पूर्ण सुसज्जित टी० वी० स्टडियो केन्द्र के अलावा मध्य प्रदेश में इस समय विभिन्न शक्तियों के 54 टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) मध्य प्रदेश के सभी 45 जिले इस समय दूरदर्शन सेवा से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कवर हो रहे हैं। इस समय राज्य का अनुमानित 52.2% क्षेत्र दूरदर्शन सेवा से कवर हो रहा है जिसमें किनारे के वे सेवा क्षेत्र शामिल हैं, जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाने अपेक्षित होते हैं।

(ग) और (घ) रायपुर में कार्यक्रम जेनेरेशन सुविधा (पी० जी० एफ०) जिसकी अपेक्षित जनशक्ति के उपलब्ध हो जाने पर चालू हो जाने की उम्मीद है, के अलावा दो अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर अर्थात् दतिया और जावरा में एक-एक, तथा पर्सिया में एक अति अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीठर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। राज्य में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करने के अनुक्रम में, दो उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर अर्थात् अम्बिकापुर और गुना में एक-एक तथा चार अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर अर्थात् अलीराजपुर, सिरोंज, गदरवाड़ा तथा कुकड़ेश्वर में एक-एक, साधनों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं के अधीन स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं।

(ङ) इस समय, पूर्ण सुसज्जित टी० वी० स्टूडियो सुविधाओं सहित भोपाल में एक मुख्य शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर कार्यरत है। स्टूडियो सुविधाओं में व्यावसायिक ग्रेड रंगीन उपकरण से सुसज्जित सम्बद्ध तकनीकी क्षेत्रों सहित एक मुख्य स्टूडियो तथा एक लघु निरंतरता (कन्टिन्यूटी) स्टूडियो है। एक रंगीन ओ० बी० (बाह्य प्रसारण) वैन तथा ई० एन० जी० (इलैक्ट्रानिक न्यूज गैदरिंग) उपकरण भी प्रदान कर दिए गए हैं। राज्य में उपग्रह से प्राप्त क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा शुरू करने की परिकल्पना है, जिसके लिए भोपाल में एक उपग्रह अर्थ स्टेशन, कार्यान्वयन की अन्तिम अवस्था में है।

"सोसल आडिट पेनल"

[अनुवाद]

2148. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री शरत् चन्द्र पटनायक :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे :
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा मार्च 1992 में गठित "सोसल आडिट पैनल" ने कोई अंतरिम रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी, हां। सामाजिक परीक्षण पैनल ने दिनांक 5-7-92 और 16-10-92 को दो कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। पहली कार्रवाई रिपोर्ट में डाक और दूरसंचार दोनों विभागों के लिए सिफारिशें निहित हैं। दूसरी कार्रवाई रिपोर्ट में केवल दूरसंचार विभाग के लिए सिफारिशें की गई हैं।

डाक विभाग

पहली कार्रवाई रिपोर्ट में सामाजिक परीक्षण पैनल ने डाक विभाग के लिए 38 सिफारिशें की हैं जिसमें तारीख की मुहर (डेट स्टैंपिंग) की गुणवत्ता में सुधार करना, बड़ी मात्रा में डाक भेजने वालों (बल्क मेलर्स) के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग को बढ़ावा देना, नागर विमानन/रेलवे जैसे परिवहन मंत्रालयों के साथ अधिकाधिक अन्तर मंत्रालयों पारस्परिक कार्रवाई है टैरिफों की आवधिक पुनरीक्षा, पावतियों (ए० डी०) के वितरण का बेहतर प्रतिशत सुनिश्चित करना, पोस्टकार्डों की दर में वृद्धि, सूचना प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार और डाक-सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए उच्चतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना शामिल है।

सिफारिशों की जांच कर ली गई है तथा उनके कार्यान्वयन की रूपात्मकता (मोडेलिटीज) का चयन कर लिया गया है।

दूरसंचार विभाग

पैनल द्वारा दूरसंचार विभाग के लिए की गई मुख्य सिफारिशों में ये सिफारिशें शामिल हैं :— सार्वजनिक टेलीफोन घरों की उदार व्यवस्था, निशुल्क डायरेक्टरी पूछताछ सेवा, कम्प्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ, उपभोक्ता का अपना निजी टेलीफोन उपकरण, खराब टेलीफोनों को शीघ्रता-पूर्वक ठीक करना, प्रपत्रों का संशोधन, टेलीफोन के बिल तैयार करना और राजस्व की वसूली, टेलीफोन के कार्य न करने पर प्रभारों में छूट, उपभोक्ताओं के साथ बेहतर सम्पर्क, लाइनों के संतुलन को दूर करने के उपाय, उपभोक्ताओं द्वारा निजी टर्मिनल उपस्कर रखना, निगरानी (वाच-डाग) पैनलों का गठन, टेलीफोन डायरेक्टरियों का समय पर प्रकाशन, टेलीफोन उपभोक्ताओं और बिना बारी के कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची, महानगर टेलीफोन निगम लि० के दर्जे के सम्बन्ध में निर्णय।

इन सिफारिशों की जांच कर ली गई है तथा उनके समुचित कार्यान्वयन के लिए बहुलकर्ताओं का चयन कर लिया गया है।

दीव में पर्यटन स्थल

[हिन्दी]

2149. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के विचार से संघ शासित क्षेत्र दीव में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार दीव संघ राज्य क्षेत्र में विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिए हर सम्भव सहायता करेगी । नागाओं समुद्र तट, दीव में तम्बू आवास के एक प्रस्ताव के लिए 28.50 लाख रु० स्वीकृत किए गए हैं और 22.00 लाख रु० अवमुक्त किए गए हैं ।

(घ) पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का स्थान-वार अनुमान नहीं लगाया जाता ।

भूमिगत जल के लिए विदेशी सहायता

[अनुवाद]

2150. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिगत जल संसाधनों के लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोई विदेशी तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए चयनित राज्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(ख) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	सहायता देने वाली एजेंसी	मुद्रा	प्राप्त की गयी सहायता			
					1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1.	बिहार सार्वजनिक नलकूप	बिहार	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	2.843	3.256	0 989	शून्य
2.	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	22.273	20374	परियोजना 31-3-91 को पूरी हो गयी है।	
3.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	2.616	6.452	15.448	शून्य
4.	उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	उत्तर प्रदेश	नीदरलैंड	डच गील्डर	33.96	9.236	20.460	शून्य

(मार्च, 1990 तक)

उपर्युक्त के अतिरिक्त केन्द्र भूजल बोर्ड को "भूजल समुपयोजन परियोजना" के वास्ते वर्ष 1990—92 के दौरान जापानी अनुदान सहायता के फेस-एक तथा फेस-दो के अंतर्गत 7.39 करोड़ रुपए तथा 7.23 करोड़ रुपए की राशि के उपस्कर प्राप्त हुए हैं।

यू० एस० ए० आई० डी० से सहायता प्राप्त "जल संसाधन प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण परियोजना" के अंतर्गत वर्ष 1991 से 1993 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में केन्द्र/ राज्य सरकार के 33 अधिकारियों को भूजल पर उन्नत प्रशिक्षण दिया गया।

भूजल प्रबन्ध फेस-दो पर भारत नीदरलैंड प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान भूजल पर पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारत में चार और नीदरलैंड में एक) आयोजित किए गए जिनमें केन्द्र/राज्य सरकार के 94 अधिकारियों ने भाग लिया। इस समय केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तीन अधिकारी दीर्घावधि आधार पर नीदरलैंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के विमान का गायब होना

[हिन्दी]

2151. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के सिचिलियन प्रशिक्षण विमान के गायब होने की कोई घटना सरकार की जानकारी में आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) दिनांक 29-10-1992 को बंगलूर से त्रिवेन्द्रम की क्षेत्रीय उड़ान कर रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकादमी के टीवी-20 विमान वी० टी०-ई० एम० डी० का, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से लगभग 2500 फुट की ऊंचाई और 26 नाटिकल मील की दूरी पर त्रिवेन्द्रम हवाई यातायात नियंत्रण टावर से संपर्क टूट गया था । गहन छानबीन के बावजूद विमान के मलबे का अभी तक पता नहीं चला । खोज जारी है । घटना की जांच के लिए नागर विमानन के महानिदेशक ने एक दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्ति की है ।

उड़ीसा में तारघर

2152. **श्री श्रीकान्त जेना :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में नये तारघर खोलने तथा विद्यमान तारघरों का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, ।

(ख) विवरण निम्नानुसार हैं—

(1) उड़ीसा में, कोरापुर, रायगदा (कारापुर) और भद्रक में तीन नए तार घर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(2) उड़ीसा में मौजूदा तार-घरों के आधुनिकीकरण की योजना निम्नलिखित रूप से बनाई गई हैं—

(i) कम्प्यूटर आधारित तार प्रणालियों को जोड़कर, जिससे तारों का मैनुअल पुनर्परिषण समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार अपेक्षाकृत शीघ्र वितरण किया जा सकेगा, एक प्रणाली भुवनेश्वर में संस्थापित की जाएगी तथा दूसरी प्रणाली कटक में पहले से ही कार्य कर रही है ।

(ii) प्रलेख पारेषण (डाकूमैंट ट्रांसमीशन फैक्स) सुविधा की शुरूआत करके ।

(iii) मार्स उपकरणों को बदल कर इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड की व्यवस्था करके ।

ईटानगर में उच्च शक्ति प्राप्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

2153. **श्री लाईता उम्ब्रे** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्टूडियो सुविधा सहित उच्च-शक्ति प्राप्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य में बहुत कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सिरिल्ला व्यास) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक उच्च शक्ति (1 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर पहले से ही कार्यरत है । सम्बद्ध तकनीकी तथा अन्य सुविधाओं से सुसज्जित लगभग 108 वर्ग मीटर क्षेत्र के स्टूडियो वाली एक टी० वी० स्टूडियो केन्द्र परियोजना इस समय ईटानगर में कार्यान्वयनाधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) अरुणाचल प्रदेश में इस समय 16 अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर कार्यरत हैं । इनमें से कुछ ट्रांसमीटरों द्वारा विभिन्न कारणों से असंतोषजनक सेवा प्रदान करने की सूचना मिली है । चूंकि, ये ट्रांसमीटर उपेक्षित स्थिति में कार्यरत है, इसलिए इनकी मानिटरिंग और तुलनात्मक रूप से कम समय में इनकी खराबियों को दूर करने के लिए रिमोट मानिटरिंग तथा नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना है । तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

देश में जल का पूरा उपयोग

[हिन्दी]

2154. **श्री राम लखन सिंह यादव** :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कुल सिंचित प्रतिशत क्षेत्र सिंचित था;

(ख) आठवीं योजना अवधि में कितने प्रतिशत क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में लाने की योजना है;

(ग) क्या देश में सृजित की गई सिंचाई क्षमता का अधिकांशत: पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका पूरा उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) क्षमता का सृजन और इसका उपयोग एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सिंचाई शुरू करने तथा इसके पूर्ण उपयोग के बीच कुछ वर्षों के अन्तर से बचा नहीं जा सकता क्योंकि सिंचित कृषि के लिए फील्ड चैनलों के निर्माण और भूमि तैयार करने हेतु कृषकों को समय लगता है। वर्षा पोषित कृषि से सिंचित कृषि शुरू करने में भी कृषि तकनीकों में मुख्य परिवर्तन करना पड़ता है, जिनमें सिद्धहस्त होने में कृषकों को समय लगता है।

इस अन्तर को कम करने के लिए वर्ष 1974-75 से केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहले से ही क्रियान्वित किया गया है। अन्य उपचारात्मक उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया अधिक क्षेत्र, पुरानी स्कीमों की वास्तविक क्षमता का पुनर्मूल्यांकन, सूचित किए गए एकीकृत आंकड़े तथा वार्षिक निष्पादन पुनरीक्षा के मुकाबले जल एवं फसल लेखाकरण पर बल देना शामिल है।

विवरण

क्र० संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवी योजना के अंत तक चरम सिंचाई क्षमता के मुकाबले सृजित सिंचाई क्षमता का प्रतिशत	आठवीं योजना के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता का लक्ष्य (हजार हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	62.9	919.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	21.5	20.00
3.	असम	25.5	300.00
4.	बिहार	57.8	2147.00
5.	गोवा	36.8	40.20
6.	गुजरात	64.2	628.00
7.	हरियाणा	77.1	396.00
8.	हिमाचल प्रदेश	40.2	27.64

1	2	3	4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	64.3	60.50
10.	कर्नाटक	57.9	621.00
11.	केरल	42.0	248.00
12.	मध्य प्रदेश	41.1	950.00
13.	महाराष्ट्र	60.0	800.00
14.	मणिपुर	44.1	69.16
15.	मेघालय	33.7	15.88
16.	मिजोरम	13.6	6.00
17.	नागालैंड	78.4	13.00
18.	उड़ीसा	42.6	484.00
19.	पंजाब	85.4	252.42
20.	राजस्थान	81.1	588.61
21.	सिक्किम	48.5	5.00
22.	तमिलनाडु	92.2	120.30
23.	त्रिपुरा	38.4	40.20
24.	उत्तर प्रदेश	90.7	6415.00
25.	पश्चिम बंगाल	63.3	620.53
	कुल राज्य	67.4	15787.44
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	47.5	11.21
	जोड़	67.4	15798.65

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया राशि

[अनुवाद]

2155. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक विद्युत बोर्ड द्वारा प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को इस समय कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों को राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राज्य बिजली बोर्डों की ओर विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों की निम्नानुसार राशि बकाया है :—

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	देय राशि (करोड़ रुपये में)
एन० टी० पी० सी०	सिक्किम	0.09
डी० वी० सी०	बिहार	0.0937
	उड़ीसा	0.56

(ख) राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया देय वसूल किए जाने योग्य राशि की मात्रा उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि से काफी अधिक है। इसलिए विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशियों को वसूल किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार के विशेष कदम उठाए जाने की परिकल्पना नहीं की जा रही है।

गुजरात में होटल, मोटल तथा यात्री निवासों का निर्माण

2156. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में गुजरात केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से निर्मित होटल, मोटल और यात्री निवासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक होटल, मोटल और यात्री निवास बनाने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) होटलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में पर्यटन विभाग की कोई स्कीम नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग को गुजरात राज्य सरकार से यात्री निवासों या मोटलों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष के दौरान द्वारका में एक यात्री निवास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को सूचीबद्ध कर दिया गया है। तथापि, गुजरात राज्य सरकार से

विस्तृत अनुमानों सहित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उस्मानाबाद के लिए आकाशवाणी केन्द्र

2157. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानाबाद के लिए आकाशवाणी केन्द्र तैयार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है; और

(ग) इसे चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं। सिविल कार्य और तकनीकी उपकरणों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उस्मानाबाद में स्थानीय रेडियो स्टेशन तकनीकी रूप से 1993 तक तैयार हो जाने की परिकल्पना है और उसके बाद इसे तभी चालू किया जा सकेगा जब वहां पर इसके परिचालन एवं रखरखाव के लिए न्यूनतम आवश्यक स्टाफ की तैनाती हो जाएगी।

(ग) इस कार्य को पूरा होने में देरी का मुख्य कारण, आकाशवाणी के स्थल का देरी से दिया जाना है।

सरकारी विज्ञापनों पर खर्च

2158. **श्री अनन्तराव देशमुख** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ सालों से सरकारी विज्ञापनों पर होने वाले वार्षिक खर्च में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट नीति बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जैसा कि पिछले तीन वर्षों के निम्नलिखित व्यय के आंकड़ों से प्रकट होता है :—

1989-90	1064.50 लाख
1990-91	2085.22 लाख
1991-92	1422.56 लाख

(ख) और (ग) विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय के पास पहले से ही विज्ञापनों को जारी करने हेतु साफ एवं सुस्पष्ट नीति है। विज्ञापनों को ग्राहक मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं

के अनुसार तथा उपलब्ध नीति के आधार पर जारी किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में विद्युत संकट

2159. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में निरंतर विद्युत संकट के क्या कारण हैं जिसके फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति में अक्सर कटौती होती है;

(ख) पिछले छ. महीनों के दौरान विद्युत आपूर्ति में कटौती से राजधानी में औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक उत्पादन में कितनी हानि हुई है; और

(ग) राजधानी में निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए कौन से तात्कालिक तथा दीर्घावधिक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली में बिजली सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। अप्रैल—अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान 6168 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता की तुलना में 6124 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी। 0.7% न्यूनतम कमी थी जिसे उपयुक्त भार प्रबन्धन तथा उद्योगों में व्यस्ततमकालीन भार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाकर पूरा किया गया। निम्न वोल्टता तथा निम्न बारम्बारता की दशाओं से उत्तरी ग्रिड के प्रणाली पैरामीटरों की सुरक्षा करने के लिए कुछेक अवसरों पर बिजली की कटौती करना आवश्यक हो जाता है। बिजली की कटौती के कारण विशेषतौर पर औद्योगिक उत्पादन में हुई हानियों, यदि हो, को इंगित कर पाना सम्भव नहीं है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले कई अन्य कारण हैं।

(ग) बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की गई आयोजनाओं में डेसू की विद्यमान गैस टर्बाइनों में 3 × 34.07 मेगावाट की अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिटें स्थापित किया जाना, 600/900 मेगावाट गैस-आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाना, उत्तरी ग्रिड से अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने के लिए दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० की पारेषण रिंग स्थापित करना तथा पारेषण तथा वितरण प्रणाली को विभिन्न वोल्टता स्तरों पर सशक्त करना शामिल है। दादरी में स्थापित की जा रही 840 मेगावाट राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना से भी दिल्ली को 90% बिजली का हिस्सा मिलेगा।

रिहन्द-2 विद्युत परियोजना

2160. **श्री रूप चन्द पाल :**

श्री अनिल बसु :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **विद्युत** मंत्री दिनांक 4 मई, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के सन्दर्भ

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द विद्युत परियोजना चरण-दो के लिए वैकल्पिक वित्तीय प्रबन्ध कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०) की रिहन्द विद्युत परियोजना चरण-2 को उन परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें समयबद्ध खण्ड अवधारणा (टाइम स्लाइस कानसेप्ट) के अन्तर्गत विश्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना है। इस सन्दर्भ में विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श जारी हैं।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक सेवाओं का निजीकरण

2161. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक सेवाओं का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोकिंग कोल का आयात

2162. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी ने सभी समेकित इस्पात संयंत्रों के लिए कम राख वाले कोकिंग कोल के आयात हेतु एक केनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सरकार से कोई पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भी "सेल" को कोकिंग कोल के आयात हेतु वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सरकार को "टिस्को" से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोककर कोयले का आयात करने के लिए विश्व बैंक से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को सीधे वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सेल द्वारा कोककर कोयले के आयात के लिए प्रतिपूर्ति दावे हेतु विश्व बैंक की त्वरित संवितरण व्यवस्था से 1000 लाख अमरीकी डालर की राशि उपलब्ध कराना सम्भव होगा। दिसम्बर, 1991 में सेल ने 10 लाख टन कोक-कर कोयले का आयात करने के लिए वित्त मंत्रालय से 750 लाख अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त की थी।

टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने के नियम

[हिन्दी]

2163. **श्री महेश कनोडिया** :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करने के क्या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गुजरात में इनके प्रकाशन के सम्बन्ध में नियमों और मानदंडों का पालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अंग्रेजी में टेलीफोन डायरेक्टरी वर्ष में एक बार गौण स्विचन क्षेत्र (एस० एस० ए०) वार प्रकाशित की जाती है। जब हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन की उचित मांग होती है। सामान्यतया टेलीफोन डायरेक्टरी की कुल मांग का लगभग 15 प्रतिशत डायरेक्टरी हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती हैं।

(ख) और (ग) गुजरात में टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन के बारे में नियमों और मानकों का अनुपालन किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में निविदाओं को अन्तिम रूप देने, ठेके सौंपने में की जाने वाली कार्रवाई में कठिनाइयां होने और ठेकेदारों की ओर से विलम्ब किए जाने के कारण डायरेक्टरी के प्रकाशन में विलम्ब हुआ है।

निजी उद्यमियों द्वारा विद्युत क्षेत्र में निवेश

[अनुवाद]

2164. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अब तक किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का निजी उद्यमियों द्वारा पूंजी निवेश करने को आकर्षित करने हेतु और अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है ?

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र निवेशकों को दिए गए प्रोत्साहन के फलस्वरूप, 41,764.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर निजी क्षेत्र में 17,402.5 मे० वा० क्षमता स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित नीति को सुगम्य बगाया गया है ।

टेलीग्राफिक मनीआर्डर के कमीशन प्रभार में वृद्धि

[हिन्दी]

2165. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने अन्तरदेशीय मनीआर्डर/टेलीग्राफिक मनीआर्डर के कमीशन प्रभार में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनसाधारण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनीआर्डर के कमीशन प्रभार में कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अन्तर्देशीय मनीआर्डर/टेलीग्राफिक मनीआर्डर के लिए कमीशन की मौजूदा दरें 11 जून, 1990 से प्रभावी हैं और इसके उपरान्त इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2166. **डा० सुधीर राय :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्च, 1993 को चालू करने की अनुमोदित समय-सूची से 16 पैकेजों (6 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 10 स्वदेशी टर्नकी पैकेजों) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें से 14 पैकेजों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं और शेष 2 स्वदेशी पैकेजों के लिए आर्डर दिए जाने हैं। परियोजना के आर्डर दिए गए पैकेजों में स्थल कार्य अग्रिम चरण में है। दो टर्नकी पैकेज पूर्णरूपेण चालू कर लिए गए हैं और 5 पैकेजों की आंशिक सुविधाएं पूरी हो गई हैं।

(ख) दो धमन भट्टियां जिन्हें दिसम्बर, 1994 में पूरी कर लिए जाने की सम्भावना है, को छोड़कर आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य के दिसम्बर, 1993 में पूरा हो जाने की आशा है।

आठवीं योजना में बिहार में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

2167. **श्री हरि किशोर सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार में कितने डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का विचार है; और

(ख) राज्य में अभी तक खोले गए डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० रंगय्या नायडू) : (क) **डाकघर**—आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 500 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। राज्यों को लक्ष्य वार्षिक आधार पर आबंटित किए जाते हैं। बिहार में, वर्ष 1992-93 के दौरान 70 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 8 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

टेलीफोन एक्सचेंज—योजना अवधि के लिए एक्सचेंजों की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि टेक्नालाजी, मांग की अनिश्चितता आदि से एक्सचेंजों की संख्या प्रभावित होती है। तथापि, 8वीं योजना (1992—97) में बिहार की एक्सचेंज क्षमता में लगभग 1,27,000 लाइन जोड़ने का विचार है।

(ख) **डाकघर**—1992-93 में बिहार में अब तक 5 शाखा डाकघर और 2 विभागीय उप-

डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई है।

टेलीफोन एक्सचेंज—31-10-1992 की स्थिति के अनुसार 525 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं जिनमें 1-4-92 के बाद खोले गए 10 एक्सचेंज भी शामिल हैं।

बाढ़ नियंत्रण उपाय

[अनुवाद]

2168. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान और दिसम्बर, 1992 तक बाढ़ नियंत्रण उपायों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार देश में बाढ़ नियंत्रण हेतु किसी व्यापक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान 245.72 करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है। दिसम्बर, 1992 तक हुए व्यय के आंकड़े नहीं निकाले जा सकते हैं।

(ख) और (ग) देश में 32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, जिसे बाढ़ों से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा, प्रदान की जा सकती है, में से मार्च, 1991 तक किए गए चालू उपायों से 14 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है।

स्टार टी० वी० और विदेशी टी० वी० के कार्यक्रमों को सेन्सर करना

2169. **श्री राम कापसे** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रसारित किए जा रहे स्टार टी० वी० और विदेशी टी० वी० के कार्यक्रमों को सेंसर करने के उपयुक्त उपायों पर विचार करने के लिए समितियां गठित की थीं;

(ख) उन समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) में घाटा

2170. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) में घाटे अप्रैल, 1992 से 30 प्रतिशत की सीमा से भी अधिक हो गयी है जैसा कि दिनांक 14 सितम्बर, 1992 के दैनिक समाचार पत्र "दि स्टेट्समैन" में छपा था;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो सालों में प्रत्येक साल के दौरान इसी अवधि में इनके तुलनात्मक आंकड़े देते हुए इसके कारण बताएं;

(ग) दिल्ली में उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ और कितनी मिलियन यूनिटों के बिल बनाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम में संशोधन करना

2171. **श्री जी० माडेगौडा :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अधिनियम में जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) क्या जल विवाद न्यायाधिकरण के वर्तमान अधिनियम में उचित निर्णय लेने हेतु समुचित मार्गनिदेश नहीं दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में अधिकरण के लिए कोई दिशा-निर्देश हों ।

तमिलनाडु में कन्याकुमारी, महाबलिपुरम और रामेश्वरम का विकास

2172. **श्री बापू हरि चौरे :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कन्याकुमारी, महाबलिपुरम और रामेश्वरम के विकास हेतु तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में पर्यटन विकास हेतु कुल कितनी राशि आबंटित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तमिलनाडु सरकार से

कन्याकुमारी, महाबलीपुरम और रामेश्वरम में पर्यटन के विकास के लिए चौदह प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) सभी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं।

(ग) देश में पर्यटन का विकास करने हेतु वर्ष 1992-93 के लिए 35.30 करोड़ रुपए का बजट है।

केरल में पर्यटन का विकास

2173. **श्री रमेश चेन्नितला :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य को कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की है/प्रदान की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) हाल ही में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को केरल सरकार से 1992-93 के दौरान राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. एल्लेप्पी में नेहरू स्मारक मण्डप
2. गुरुवयूर में यात्री निवास
3. मालमपुझा में कुटीरें

(घ) केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रत्येक परियोजना के आधार पर उसके गुण-दोष पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती है।

गुजरात में कोयला आधारित संयंत्रों को निजी क्षेत्र को सौंपना

2174. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जस्वाणी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कुछ कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को निजी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्युत केन्द्रों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विदेशी डाकघर

2175. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को वाराणसी उत्तर प्रदेश में विदेशी डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी हां। वाराणसी में विदेशी डाकघर खोलने के प्रस्ताव की पहले जांच की गई थी, किन्तु कम परियात और प्रणालीगत समस्याओं के कारण उक्त डाकघर नहीं खोला जा सका। हाल ही में, इस मामले की पुनः जांच की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि वाराणसी में बाबतपुर कार्गो काम्प्लेक्स उपडाकघर में एक एक्सटेंशन एक्सपोर्ट विंडो खोली जाए जो विदेशों को भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं की बुकिंग की सुविधा के साथ-साथ सीमा शुल्क सम्बन्धी जांच की सुविधा प्रदान करेगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं।

मयूर विहार फेस-दो विद्युत संयंत्र

2176. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मयूर विहार फेस-दो 66 के० वी० ए० उप केन्द्र पूर्णतः चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या "डेसू" ने अक्टूबर, 1992 तक चिल्ला गांव के निकट 66 के० वी० ए० ग्रिड उपकेन्द्र में सभी नियन्त्रण और रिले पैनल के संस्थापन का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समाचार अपार्टमेंट्स सहित ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को कब से नए ग्रिड उप-केन्द्र से सीधी बिजली की आपूर्ति की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) मयूर विहार में 66 के० वी० उप-केन्द्र आंशिक रूप से प्रचालन में है और यह इस क्षेत्र की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। डेसू द्वारा चिल्ला गांव में स्थित 66 के० वी० ग्रिड उप-केन्द्र को चालू करने हेतु आवश्यक उपस्कर की व्यवस्था की जा रही है। समाचार अपार्टमेंट्स सहित सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को नए ग्रिड उप-केन्द्र से सीधे सप्लाई मार्च, 1993 तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है।

दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना

2177. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की कम्पनियों ने 390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना पर कार्य बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना पर फिलहाल कुल कितनी कम्पनियां कार्य कर रहीं हैं;

(घ) उनको दिए गए ठेके का मूल्य कितना है;

(ङ) क्या इन कम्पनियों ने ठेके में अनुबद्ध शर्तों का पालन किया है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क 390 मे० वा० क्षमता की दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन० एच० पी० सी०) ने जिस फ्रांसीसी कन्सोरटियम को सौंपा था उसने 24-8-1992 को परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों को स्थगित कर दिया। तथापि, डिजाइनिंग तथा इंजीनियरिंग कार्य तथा स्थायी उपस्करों का उत्पादन/सप्लाई सम्बन्धी वे कार्य जो कि परियोजना क्षेत्र से बाहर किए जा रहे हैं, अनवरत रूप से चल रहे हैं। फ्रांसीसी कन्सोरटियम ने अभी हाल ही में सरकार को सूचित किया था कि उनके द्वारा परियोजना स्थल पर पुनः कार्य आरम्भ किया जा रहा है और सुरंग खोदन मशीन का मरम्मत कार्य सबसे पहले हाथ में लिया जाएगा। उक्त मरम्मत कार्य पूरे हो चुके हैं और परियोजना के ढांचे से सम्बन्धित कार्य अभी आरम्भ किया गया है।

ख) फ्रांसीसी व्यापार संघ द्वारा यह कहा जाता रहा है कि परियोजना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ग) परियोजना में कार्यरत फ्रांसीसी व्यापार संघ में पांच विभिन्न कम्पनियां शामिल हैं।

(घ) उक्त संविदा, 24-10-88 की स्थिति के अनुसार लागू विनिमय दर पर लगभग 785 करोड़ रु० के बराबर मूल मूल्य के लिए थी। इसके अलावा, संविदा में समान विनियम दर पर लगभग 61 करोड़ रु० के आकस्मिक व्यय की भी परिकल्पना की गई थी।

(ङ) एन० एच० पी० सी० का यह मत है कि फ्रांसीसी व्यापार संघ द्वारा परियोजना स्थल पर कार्य स्थगित किया जाना, संविदा की शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप नहीं है।

(च) फ्रांसीसी व्यापार संघ द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार

द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं –परियोजना स्थल पर सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा करने और इस सम्बन्ध में फ्रांसीसी व्यापार संघ को आश्वस्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा परियोजना स्थल का दौरा करना, परियोजना स्थल के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करना तथा एन० एच० पी० सी० एवं फ्रांसीसी व्यापार संघ के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक स्थानीय सुरक्षा समिति का गठन करना ताकि सुरक्षा व्यवस्था की सतत रूप से मानीटरिंग की जा सके और परियोजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं के मामले में जहां आवश्यक हों, उचित कदम उठाए जा सकें।

(छ) चूंकि फ्रांसीसी व्यापार संघ द्वारा हाल ही में कार्य आरम्भ करने सम्बन्धी अपनी इच्छा व्यक्त की गई है और उनके द्वारा सुरंग छेदन मशीन का मरम्मत कार्य आरम्भ करने सम्बन्धी कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई है, अतः फिलहाल परियोजना को पूरा करने सम्बन्धी कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट विमानपत्तनों का विस्तार

2178. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री पी० सी० थामस :

श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट विमानपत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन विमानपत्तनों के लिए कितनी अतिरिक्त उड़ानें शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) **त्रिवेन्द्रम**—भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विस्तार प्रयोजन के लिए मौजूदा धावनपथ के दक्षिणी-पश्चिमी छोर पर 140 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए केरल राज्य सरकार से अनुरोध किया है। वर्ष 1991-92 के दौरान सुरक्षा लाज और अन्तर्देशीय प्रस्थान को पहले से ही वातानुकूलित किया गया है और उसका विस्तार कर दिया गया है। आगमन हाल को वातानुकूलित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की धावनपथ प्रकाश प्रणाली में सुधार करने, मुख्य धावनपथ की पटरियों को सुदृढ़ करने और निर्मित करने तथा टर्मिनल-1 में संवर्धन/परिवर्तन करने की योजनाएं हैं।

कोचीन—राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास घन की अत्यधिक कमी होने के कारण इस हवाई अड्डे का उन्नयन करने की उनकी कोई योजना नहीं है।

कालीकट—राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 615 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक अलग से नए टर्मिनल के निर्माण की योजना है, जो आने वाले 250 यात्रियों के लिए उपयुक्त होगा। मार्च, 1993 के अन्त तक निर्माण कार्य के शुरू होने की आशा है।

(ख) इस समय त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट से सेवा में वृद्धि करने की इंडियन एयर-

लाइन्स की कोई योजना नहीं है ।

विदेशी टी० वी० नेटवर्क में हिन्दी कार्यक्रम

2179. **श्री ताराचन्द खन्डेलवाल** :

क्या **सूचना और** प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1992 की हिन्दुस्तान टाइम्स में "जी० टी० वी० टु० बीम हिन्दी फेयर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या कई विदेशी टी० वी० नेटवर्क ने भारत में केवल हिन्दी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, हां । तथापि, विदेशी उपग्रह के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम केवल उन्हीं दर्शकों को उपलब्ध होते हैं जिन्होंने संगत डिश एन्टीना लगवाया होता है । अपने दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम फारमेट में गुणात्मक सुधार लाने के बारे में निरन्तर प्रयास किए जाते हैं ।

राज्य बिजली बोर्ड के बकाया को कम करना

2180. **श्री संदीपान भगवान थोरात** :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1992 तक प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की ओर एन० टी० पी० सी०, एन० एच० पी० सी० तथा अन्य विद्युत निगमों की कितनी बकाया राशि है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा देय राशि को कम करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय बकाया राशियां निम्नवत हैं :—

निगम का नाम	रा० वि० बोर्ड का नाम	देय राशि (करोड़ रु० में)
एन० टी० पी० सी०	सिक्किम	0.89
डी० वी० सी०	बिहार	0.0937
	उड़ीसा	0.56

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न प्रभारों सहित विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एन० टी० पी० सी० को कुल देय राशि 2400 करोड़ रुपये से अधिक है। एन० टी० पी० सी० के विस्तार के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाए जाने की कमी के द्वारा बकाया राशियों के कारण इसकी परिसमापन की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है। अपितु इसकी विद्यमान परियोजनाओं के प्रचालन पर भी इसका अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा है।

उड़ीसा में सिंचाई विकास

2181. **श्री के० पी० सिंह देव** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार/नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में सिंचाई की वृद्धि दर को त्वरित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हीराकुंड वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण, नराज बराज (पुराने ढांचे का प्रतिस्थापन) और जोकाडिया सिंचाई (वार्षिक सिंचाई 47320 हेक्टेयर तक बढ़ाना) नामक तीन परियोजनाएं क्रमशः दिसम्बर, 1984, अगस्त, 1989, और अगस्त, 1989 में केन्द्र में प्राप्त हुई थीं। उनकी अनुमानित लागत क्रमशः 32.6 करोड़, 124.18 करोड़ और 27.40 करोड़ रुपए थी। जांच के पश्चात् यह देखा गया कि जोकाड़िया सिंचाई परियोजना का कमान क्षेत्र रेंगाली सिंचाई परियोजना के कमान से अतिव्याप्त हो रहा था। हीराकुंड वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव संशोधन हेतु अप्रैल, 1989 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया था, नराज बराज पर राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

(ग) आठवीं योजना में उड़ीसा में वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास कार्यों के लिए योजना आयोग द्वारा लगभग 3037 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए रक्षित संयंत्र

[हिन्दी]

2182. **श्री राम बदन :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भिलाई इस्पात संयंत्र को आंतरिक विद्युत खपत की पूर्ति के लिए एक रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का भिलाई इस्पात संयंत्र की विद्युत सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए भिलाई में संयुक्त क्षेत्र में एक विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापित करने का विचार है। हाल ही में दो समझौते ज्ञापन, एक स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन० टी० पी० सी०) के बीच तथा दूसरा "सेल" तथा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एम० पी० ई० बी०) के बीच किए गए हैं और संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी में पूंजी निवेश के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

(ग) निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव को अभी ठोस रूप दिया जाना है।

वाणिज्यिक प्रयोग हेतु सैटेलाइट फोन

[अनुवाद]

2183. **श्री जे० चोक्का राव** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्टरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट आर्गेनाइजेशन" ने ब्रीफ केस सैटेलाइट फोन विकसित किए हैं और इन्हें चालू वर्ष के अन्त तक वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का देश में इस प्रकार के फोन शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो कहां ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह संगठन (इनमार्सेट) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1993 के दौरान "ब्रीफ केस" टाइप उपग्रह टेलीफोन टर्मिनल वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना है।

( ) भारत में इस सेवा को शुरू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दूरदर्शन पर कृषकों के लिए कार्यक्रम

[हिन्दी]

2184 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने कृषि पर कोई वृत्तचित्र तैयार करके प्रसारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वृत्तचित्रों सहित, दूरदर्शन केन्द्रों ने विभिन्न फारमैटों में कृषि कार्यक्रमों को टेलीकास्ट किया।

(ख) ऐसे ब्यौरे केन्द्रीय रूप से संकलित करके नहीं रखे जाते।

हिमाचल प्रदेश में माइक्रोवेव टावर्स

2185. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में माइक्रोवेव टावर्स की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया गया था और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अब तक 29 टावरों की योजना बनाई जा चुकी है और इनमें से 19 टावरों का कार्य पिछले कई वर्षों में पहले ही पूरा हो चुका है तथा 10 और पर कार्य चल रहा है (सूची संलग्न विवरण में दी गई है)।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां टावरों का संस्थापना कार्य पहले ही पूरा हो चुका है

1.	शिमला	11.	सोलन (छत पर लगा ढांचा)
2.	कसौली	12.	मंडी
3.	चाइल	13.	देवगा
4.	निहरी	14.	बिलासपुर
5.	डलहौजी	15.	धर्मशाला
6.	चम्बा	16.	हमीरपुर
7.	स्वारघाट	17.	ऊना (छत पर लगा ढांचा)
8.	मरवनि	18.	चूनाघाई
9.	नाहन (छत पर लगा ढांचा)	19.	पालमपुर
10.	थानेदार		

उन स्थानों के नाम जहां टावरों का संस्थापना कार्य किया जा रहा है।

1. चाइल (दूसरा टावर)
2. सोलन
3. पौंटा साहिब
4. सराण (सिरमौर)

5. नाहन

6. ऊना

7. महमूर

8. कांगड़ा

9. सुरानी

10. बिलासपुर

[अनुवाद]

सातवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई तथा भूमि जल के लिए धनराशि

2186. **श्री राम सिंह काश्यप :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान भूमि जल के उपयोग सहित लघु सिंचाई के लिए राज्य-वार योजना परिव्यय तथा संस्थागत वित्त की राशि क्या है;

(ख) राज्य-वार कितनी वास्तविक राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1992-93 के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1992-93 के दौरान भूजल संहित लघु सिंचाई के वास्ते राज्यवार योजनागत परिव्यय/व्यय तथा संस्थागत वित्त संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लघु सिंचाई पर योजनागत परिव्यय/व्यय तथा संस्थागत वित्त

(करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	सातवीं योजना के दौरान		वर्ष 1992-93 के दौरान	
		योजनागत परिव्यय	योजनागत व्यय	संस्थागत वित्त	योजनागत परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	147.40	176.04	404.76	41.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	23.00	23.32	—	11.40
3.	असम	160.00	162.53	36.68	53.05

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	260.00	284.03	127.01	172.48
5.	गोवा	8.80	8.80	0.05	2.61
6.	गुजरात	134.55	109.78	163.13	53.02
7.	हरियाणा	14.17	9.33	111.51	1.30
8.	हिमाचल प्रदेश	54.00	59.98	0.29	26.75
9.	जम्मू व कश्मीर	42.00	62.69	0.10	17.26
10.	कर्नाटक	151.00	172.70	295.82	45.87
11.	केरल	50.00	44.63	93.0	20.00
12.	मध्य प्रदेश	433.60	330.19	301.37	152.50
13.	महाराष्ट्र	250.00	399.36	532.66	128.50
14.	मणिपुर	10.00	8.71	—	5.50
15.	मेघालय	9.70	10.14	—	6.80
16.	मिजोरम	7.00	6.84	—	2.54
17.	नागालैंड	15.00	14.42	—	3.45
18.	उड़ीसा	110.00	182.95	35.20	64.35
19.	पंजाब	46.22	34.96	154.06	22.97
20.	राजस्थान	47.88	55.85	128.15	30.15
21.	सिक्किम	10.00	8.82	—	2.00
22.	तमिलनाडू	85.00	100.28	174.31	45.00
23.	त्रिपुरा	15.00	20.55	—	9.00
24.	उत्तर प्रदेश	512.00	589.21	423.26	56.36
25.	पश्चिम बंगाल	68.00	86.82	76.07	57.39
	कुल राज्य	2664.32	2962.93	3057.51	1031.64
	कुल संघ राज्य	15.67	15.35	3.44	5.85
	कुल राज्य/ संघ राज्य	2679.99	2978.28	3060.95	1037.50

दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम

[हिन्दी]

2187. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम को बन्द कर दिया गया और उसके कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या भाटी खान को भी बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप बेकार हुए श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) भाटी खानें बन्द कर दी गई हैं।

(ग) भाटी खानों में कार्य म:, 1990 में दुर्घटना के बाद रोक दिया गया था। बाद में इस त्र को दिल्ली प्रशासन द्वारा वन्य प्राणी शरण-थल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, इस खान में लगभग 2000 मजदूर काम कर रहे थे औ उनमें से अनेक को दिल्ली सीमा के पार हरियाणा स्थित खानों में रोजगार मिलने की संभावना है।

बंगलौर में इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग फैक्टरी

[अनुवाद]

2188. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज :**

क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से बंगलौर में नई प्रौद्योगिकी "ओ० सी० बी० 283" के अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग फैक्टरी की दूसरी यूनिट स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। कर्नाटक सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि आई० टी० आई० के बंगलौर मनकापुर और पालघाट स्थित कारखानों में ओ० सी० बी०—283 प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उपस्कर बनाने की क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

शोलापुर के लिए बोइंग सेवा

2189. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर से अन्य स्थानों के बीच विमान सेवा की अर्थक्षमता का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शोलापुर के लिए बोइंग सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सोलापुर हवाई अड्डा बोइंग परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है ।

सीतामढ़ी में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलना

[हिन्दी]

2190. **श्री नवल किशोर राय** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार में सीतामढ़ी जिले की पूरी जनसंख्या वर्तमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर से दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदला जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सीतामढ़ी में यू० एच० एफ० बैंड में परिचालित अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर जो अपने कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक टी० वी० सेवा प्रदान कर रहा है, के अलावा सीतामढ़ी जिले के भाग मुजफ्फरपुर में कार्यरत उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में भी आते हैं । फिलहाल, सीतामढ़ी के मौजूदा अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार में फालतू पानी का उपयोग

2191. **श्री रामदेव राम** :

श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य के मलामऊ डिवीजन के अन्तर्गत औरंगा, अमानत और कन्हर जलाशय योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार की नदियों के फालतू पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान को मोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो उत्तरी बिहार की किन-किन नदियों का पानी मोड़ने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) औरंगा जलाशय स्कीम, आठवीं योजना में शामिल एक अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजना है। इस परियोजना की नवीनतम लागत 257 करोड़ रुपए है और इसकी चरम सिंचाई क्षमता लगभग 53400 हेक्टेयर है। मार्च, 1992 तक इस स्कीम पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना के लिए आठवीं योजना परिव्यय .0 करोड़ रुपए हैं। अमानत और कन्हर जलाशय स्कीमों की संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण उनका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। इन दो नई योजनाओं के लिए आठवीं योजना में कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने पर जोर दिया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकार ने दामोदर बेसिन में तिलैया जलाशय घाघर नदी में जल व्यपवर्तित करने के लिए एक परियोजना तैयार की है ताकि गया और नवादा जिलों में लगभग 32000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सके।

(ङ) और (च) जल संसाधनों के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अन्तरण के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों के बीच अलग अलग अन्तर-सम्पर्कों की परिकल्पना की गयी है। इन प्रस्तावों को सुनिश्चित (फर्म-अप) करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का वर्तमान अधिदेश, प्रायद्वीपीय नदी घटक से संबंधित है। हिमालयी घटक के प्रारम्भ से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के उद्देश्यों में संशोधन की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोनों का खराब होना

2192. **श्री विश्वेश्वर भगत** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः माह से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े टेलीफोन तथा सार्वजनिक टेलीफोनों की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) सरकार ने उन्हें ठीक करने के लिए क्या कार्रवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 0.66%

(ख) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) नंगी तारों को इंसुलेटिड तारों से बदला जा रहा है।

(ii) तारों की बार-बार चोरी होती है और तारों की चोरी के लिए सुभेद्य क्षेत्रों (थेफ्ट प्रोन

एरियाज) में सार्वजनिक टेलीफोन "मल्टी एक्सेस रेडियो रिले सिस्टम" पर प्रदान किए जा रहे हैं।

(iii) एम० ए० आर० आर० प्रणालियों पर अधिकाधिक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा रहे हैं।

(iv) सिगनल चैनल वी० एच० एफ० प्रणालियां भी पुरःस्थापित की जी रही हैं।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2193. **श्री थाइल जान अंजलोज :**

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और उनका आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) केरल में 92-93 के दौरान 280 टेलीफोन एक्सचेंजों की आधुनिक बनाने और 103 का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिनमें से अब तक 46 एक्सचेंजों को पहले ही आधुनिकीकरण किया जा चुका है और 23 का विस्तार किया जा चुका है। 92-93 की बाकी अवधि के दौरान, शेष 234 एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण और 80 का विस्तार किया जाएगा। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

केरल में 92-93 के दौरान जिन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना है उनका जिलावार ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या	विस्तार हेतु प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	त्रिवेन्द्रम	6	5
2.	किलोन	22	11
3.	पटनमथिट्टा	25	5

1	2	3	4
4.	अल्लेप्पी	15	7
5.	कोट्टायम	20	9
6.	एर्नाकुलम	22	10
7.	इडुकी	24	8
8.	त्रिचूर	18	8
9.	पालघाट	17	12
10.	मलापुरम	24	9
11.	कालीकट	22	4
12.	वयनाड	12	6
13.	कन्नानूर	32	9
14.	कासरगोड	21	3
		जोड़ 280	103

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कार्यालय

2194. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस स्थान पर खोलने का विचार है;

(ग) इसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित किया जाना अभी आवश्यक नहीं समझा गया है ।

महानगर टेलीफोन निगम लि० में चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का चयन

2195. **श्री अम्मा जोशी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि० के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ग) इन पदों के लिए पात्रता मानदण्ड क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लि० के वरिष्ठतम अधिकारी को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बतौर नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से अल्प अवधि उपाय के रूप में की गई है।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन किए जाने की संभावना है। अतः फिलहाल यह उचित समझा गया कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महानगर टेलीफोन निगम लि० के पद के लिए अल्पावधिक व्यवस्था कर ली जाए।

(ग) इस पद के उम्मीदवार को दूरसंचार सेवाओं के प्रबन्ध का व्यापक अनुभव होना चाहिए। इसकी अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष है लेकिन विशेष मामले में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड/मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति के विवेक पर इसमें छूट दी जा सकती है।

दिल्ली में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

2196. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान दिल्ली में किन-किन स्थानों को एस० टी० डी० सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) एस० टी० डी० लाइनों के कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जिन स्थानों पर 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) मार्च, 1993 तक इन लाइनों के चालू हो जाने की संभावना है।

विवरण

जिन स्थानों को 1992-93 के दौरान एस०टी०डी० के जरिए दिल्ली से जोड़ने का प्रस्ताव है उनके नामों की सूची

आन्ध्र प्रदेश सर्किल	अनंतवरम
अब्दुल्लापुर	अंगारा
अचंता	आत्माकुर (टी०एच०क्यू)
अद्दांवी	आत्माकुर
अल्लागड्डा	अदनोगड्डा

आंध्र प्रदेश

बंगनापल्ली
बेतमचेरला
बुचीरेड्डीपालम
सीमेंट नगर
चेवेटला
चिलमकुर
चितारवानी
चोट्टुप्पल
कोल्लालामामीदाडेंड
डेल्टा गन्नावरम
देवरायमजल
धारूर
डुंडोगल
एडलापल्ली
एन्नाराम
गंडापल्ली
हीरामण्डलम
हुजीराबाद
जमालमडुगु
जनगांव
जोगीपेट
काडोरा
कैकालुरु
कालीडिंडी
कल्लुरू
कल्यानदुर्ग
कस्यानीखानी
कंडुकुर
कनेकल
करमचेड
काजीपल्ली
किरलामपुडी
किसान नगर
कोडावलूर
कोडुमुरू
कोइलाकुंटा
कोंदरूपाडु
कोतूर
कुलाकाचेरला
के० टाडेप ली
मदनापल्ली
महमदाबाद
महेशवरम
मकथल
मंगलागुडम
मानुगुरु
मियापुर
मोहिनाबाद
मोमिनपेट
मुक्कामाला
नाकरकल
नक्कापल्ले
नरसन्नापेट
नरसारावपेट
नारायनपेट
नरपल्ली
नरसोपश्नम
नशीराबाद
नेडुनूर
नेलकोंडापल्ली
निडादावोल
ओंकोल्लु
पग्गापेटा
पकाला
पालामनार
पालम
पल्लादीगुंटा
पामिदी
पारगी
पेसुगोंडा
पोडापाडु

आंध्र प्रदेश सर्किल

पुंगानूर
रागुंठपल्ली
राजम
रामगुंडम
रामकृष्णपुरा
रामगिरि
रायादुर्ग
रुद्रावरम
सदाशिवपेट
सालुरू
शमीरपेट
शार
श्रीसिल्ला
सूर्यपेट
एस० जे० मुडी
टाडा
तल्लादा
तल्लारेवू
तन्दूर
तुमाकुंटा
उन्दी
उन्दराजावरम
उन्दराजावरम
उप्पुगडुरू
उरवाकोंडा
वनपार्टी
वेलंगी
बेलुरती
येदलापाडु
येरूपालेम
जहीराबाद

असम सर्किल

बोकाखात
विश्वानाथ भारली
गागो रोड
मनिमानी
रंगापारा
तीताबोर
उदरबन्द
घींग
कोरचोंग
पुरानीगुडम
देमो
कुवारीताल
पालानघाट
देवन
अरुनाचल
द्वारबन्ध
बसकंडी
देरगांव
नाकाधारी
चापार
बैंटामारी
कुंभा
बिलासोपारा
अभयपुरी
हटियांगमारी
मनकाचर
कमलावारी
सोनारी
लाला
लखीपुर
डूमडूमा

बिहार सर्किल

अमरपुर
बख्तियारपुर
बाराजामदा
बरसोई
चक्करपुर

बिहार सर्किल

दियानारा
हिल्सा
जापला
काको
केरमा
लहीसराय
मशीरथी
पालाजोरी
पोरी
राजरप्पा
शेरघाटी
उडाकिशनगंज
अरवाल
बानीपुर
बरहरवा
बिक्रम
दलसिंहसराय
दुआमरांव
इश्रीबाजार
झाझा
कटोरिया
कोघास
सटेहर
नौगाचीहा
पतरातू
राजौली
रोसेरा
सिमदेगा
वैशाली
बाघा
बंजारी
बढ़ा
बिक्रमगंज
डाउदनगर

घाटशिला
जयनगर
झारमुंडी
कटरस
कुजू
महलगांव
नावमुंडी
फूलपरस
राजमहल
शेखपुरा
सुगौली

गुजरात सर्किल

बाबरा
भिलोदा
चोरीला
धनेरा
धरोल
इदार
काडीदारा
खेरल्लू
कोटड़ा सेगानी
लूनावाड़ा
मगरोल
पलसाना
थारसा
बालासिनोर
वागरा
बोरसाड
दामोह
धरमपुर
गनदेवी
जम्बूसर
कामरेज
किम
सखतार

गुजरात सर्किल

मानवदर
मियागाम (करजन)
पटरी
उमरेठ
वालोद
भिलाद (श्रीगाम)
चानसमा
घंघुका
धारी
हरीज
जानदान
खेडब्रह्मा
कोसाम्बा
लाठी
मांडवी
मुली
शाहरा
ऊना
विसवदार

जम्मू और काश्मीर

साम्बा
रियासी
पुलवामा
बिशना
रामबन
हीरा नगर
बदगाम

हिमाचल प्रदेश

बंगाना
नादौन
रेनुका (सांगरा)
कंडाघाट
बैजनाथ
पालमपुर
सरकाघाट
थ्योग
जोगिंदर नगर
पाचाद
अरकी

हरियाणा

पेहवा
हथीन
सैंफीदौन
लोहारू
मेहम
रानिया
थानेसर
पटोदी
घुला (चेका)
गन्नौर
चरखी दादरी
बवानीखेड़ा
तोहाना
कुंडली
बावल
कोसली
नारनौंद
रतियां
झज्जर
नूह

कर्नाटक सर्किल

हरपनाहल्ली
नारयुंड
रोन
चित्तापुर
नेवरगी
के० आर० नगर

कर्नाटक सर्किल

गुंडलुपेट
होन्नावर
होन्नाली
होसादुर्गा
एच० बी० हल्ली
हीरेकेरूर
मुंदरगी
अफजलपुर
मधील
सी० आर० नगर
एच० डी० कोटे
जोइडा
कुनीगल
मोलकलमुरू
बी० बागेवाडी
शीराहट्टी
आलन्द
हुनगुंड
येलबुर
वेलूर
चन्नागिरि
गुब्बी
देवनाहल्ली

केरल सर्किल

अन्नामनाडा
अरक्कुन्नम
आर्यनन्द
अथादली
अयूर
चायान्नूर
चम्रूर
चेलक्करा
चेगालम
चेपरा
चिरायिंकिल
चोम्बाला
एडाक्काड
एडाप्पल
एलम्बूर
एंगनडीयूर
इरिक्कर
इरिट्टि
कल्लाम्बलम
कल्पाकनचेरी
कांजीरामकुलम
कन्नारा
कप्पाड
करीमकुनम
करूकाचल
करताकम्पल
कट्टानम
कट्टापाना
केचरी
किदनगर
कोडाकीरा
कोडुवल्ली
कोल्लाकडाव
कोल्लापल्ली
कोल्लेनगोड
कोनगाड
कोराट्टी
कोट्टियाम
कुलासेरी
कुम्बाला
कुमिली
कुन्नाथानम
कुन्नीकोड
कुषियाथोड
कुप्पुपरम्बा
कुट्टीपुरम

केरल सर्किल

मल्लापल्ली
मनन्थावाडी
मणिमाला
मारंगातुपल्ली
मारनचेरी
मत्तूल
मावूर
माभूवन्नूर
मेलाडी
मलूकावूमाटम
मेवलूर
मोनकाम्ब
मुरिजाकल
मुथुकुलम
मुट्टम
ऊन्नूकल
पाडींजारंगाडी
पल्लोक्करा
पन्नूर
पारासाला
पारावूर
पट्टाम्बी
पाक्षायन्नूर
पेरडाला
पेरिंग्मथूर
पेरला
पिन्नकानाडू
पूवार
पूवापल्ली
पुलिकुन्नू
पुन्नयारकुलम
पुथूर
राजापुरम
श्रीकांतपुरम

सुल्तान्स बैटरी
तालायोलापरंबा
तामरासेरी
तोरथला
तिरूनवाया
थूवाकुन्नू
तिरवाम्बाड़ी
त्रिकारीपुर
उदमा
उझावर
वडसिरोकरा
वल्लुवामबाराम
वनियामकुलम
वाझीथाला
वेलनचिरंगरा
वेल्लानाड
वेल्लाराडा
वेंगूर
वेंजारामूडू
विकूरा
व्यथीरी

मध्य प्रदेश

खजूरी
अशोनगर
जशपुरनगर
मनासा
धम्मूद
शुजलपुर मंडी
खुर्सिया
नवापाराजिम
सैलाना
हरसूद
अमरवाडा
चुरहट
ब्यारा

मध्य प्रदेश

करेली

गदरवारा

खुरई

महासामुंड

कोरबा

सैंधवा

परसिया

मोहना

पायलगांव

नायरी

मनेरी

चौराई

बरासियोनी

बिल्ला

पिपरिया

सिंगे

सरायपल्ली

खजुराहो

खाचरोड

खुमारी

बरवानी

सिहोरा

हरदा

बारनगर

खैरूगेश

पचमढ़ी

सौसार

फतेहाबाद

पंढरना

सांवर

सोनकूच

महाराष्ट्र सर्किल

अमलनेर

बासमत नगर

चन्नपुर एम०आई०डी०सी०

दापोली

गांधीगलाज

हिंगनघाट

कंकावाली

करंजा

किर्लोस्करवादी

महाद

बागासोपरा

निफाद

पैथान

परोला

सैलू

सावंतवाडी

शिरडी

श्रीगोंडा

वैजापुर

वालिब

अम्बेजोगाई

बूटी-बोरी

चिक्काली

देगलौर

गोकुलशिरगांव

हिंगोली

कन्नाड

खेड

कोलाद

मनसार

नांदुरा

ओमेरगा

पालघर

रामटेक

साकोली

सेलोद

सिन्नार
तिरोडा
वेंगुरला
वरूद
आमगांव
चादवाड
चिपलून
धामनगांव रेलवे
गारेगांव
कागल
कापसी
किनवात
लोटे
मोहोल
नेवासा
पचौरा
परली वैलनाथ
रोहा
सताना
शेगांव
उद्गीर
वीटा

उत्तर-पूर्व

राइंग
दिरांग
लायतकौर
डौकी
मौगंप
पारेन
छुछुयाइमलांग
अकुलोटो
खोवाई
बिशलगढ़
टेंगा
मोरे
नांमपोह
महेन्द्रगंज
चम्पाई
तुली
इम्पुर
छांगटोगिया
बेलेनिया
रूपा
बागमारा
खेलिया हरियाट
बैरानीहाट
कोलसिब
घासपानी
अलिछान
कमलपुर
साबरूम

उड़ीसा सर्किल

औल
कन्दरपुर
केंसिगा
नवापाड़ा
सालेभाटा
लाठीकाटा
भटिली
पैकमाल
छेन्दीपाड़ा
करान्जिया
सुरूदा
सुनगुदा
पट्टापुर
कोटाला
रेंगलई
किरीबरू हिल टाप

कुकुदाखंडी
गोंडोला
टिकावती
खजूरियापाड़ा
कुदार
जामूटिना
रायरमपुर
दासपल्ला
गाबाकुंडा
बा'राम्बा
रघुनाथपुर
महाकलपाड़ा
टिगरिया
जयपटना
हरिशंकर रोड
नारला रोड
बागदेही
बिलिया पाड़ा
घाट गांव
हाटादिही
जोशीपुर
मोहना
गोप
ककटपुर
बहादझला
आई०एन०एस० छिलका
निश्चितकोयली
बालीकुवा
खरियार रोड
बगमुंडा
तुसरा
पुरूनापानी
कादोबहल
पदियाबहल
भुबन
बंसुदेवपुर
पुरुषोत्तमपुर
काटीकाटा
पुडामारा
कांटामल
सातूपल्ली
जामसोला
पदमापुर (जी०एम०)
आर० सुमंदी
रायकिया
छायताना
तेनसा
देवगढ़
अथमल्लिक
सतशाखा
इन्दुपुर
खुन्तुनी
कौखिया
जरका
सिंघपुर
बेलपोड़ा
रूपरा रोड
सिंहापल्ली
मेलछामुंडा
गोंदिया
जोरांदा
नागरम
बुगुदा
बासुनी
राजसुनखेला
सारनकुल
बी० टी० पुर
गनिया
बहूग्राम
ब्रहानीपाल

उड़ीसा सर्किल

राजखयार
लोयसिंगा
बोनई
अहाबीरा
सुहेला
सहसपुर
परजन्ज
रानीताल
कुसुपुर
मद्दा
सेरगढ़
कुजांग
बोलानी
रसगोविंदपुर
भंजबिहार
जी० उदयगिरी
पुराना कटक
बीसमित्रपुर
बिसरा
बीरामहाराजपुर
खन्दापाड़ा
नाछुनी
कौपल
किशोर नगर
पानीकोयली
छतिया
बीरीकटक
बिनका
उत्केला
सियाल खंडेइटा
बीजेपुर
हरिचन्दनपुर
केसादुशपाल
रूपसा
खालीकोट
बालाकाटी
नयाहाट
ओडागांव
फिरंगिया

पंजाब सर्किल

धारीवाल
मालौट
मानसा
बटाला
मलेरकोटला
तलवंडी साबू
बालाछोर
मोरिंडा
दिना नगर
मंडी गोविन्दगढ़
डेराबस्सी
कुशली
आनन्दपुर साहिब
सरहिन्द
अजनाला
अमलोह
गढ़ शकर
दोराहा
बस्सी पठाना

पश्चिमी बंगाल

कोन्टाई
खटरा
दिनहाट
सोरेंग
इस्लामपुर
गोगांव
मथाभांगा
जांगीपुर
सोरीछा

पश्चिमी बंगाल

बानरहाट
कन्डी
रानाघाट
कोवांगला
कटवा
अरामबाग
झारग्राम
मेखलीगंज
लालबाग
काकटुइप
मिलकी
तमलुक
पकयाग
कालना
छुंगटुंग
घटाल
तूफानगन्ह
रामपुरहाट
मुथबेरला बिष
पानागढ़ बाजार
पान सुकुरा

राजस्थान सर्किल

केकड़ी
नसीराबाद
सरवर
बान्सुर
लक्ष्मनगढ़
थानागाजी
बागीडोरा
गाही
घाटोल
कुशलगढ़
किशनगंज
मंगरोल
आसिद
बानेस
झाजपुर
कोटरी
मन्डल
मंडलगढ़
रायपुर
शाहपुर
साहारा
कोलायट
लूनकरन सार
नोखा
आरोह
राजगढ़ (चूरू)
रतनगढ़
सरदार शहर
डूंगरगढ़
सुजानगढ़
तारानगर
बसेरी
राजाखेरा
आसपुर
सागवाड़ा
सिमलवाड़ा
शाहबाद
छिपा बासेद
गुधामोलानी
शही
पाछपाडरा
सिबान
बैतू
डींग
कमन
कुम्हेर
नागर

राजस्थान सर्किल

रूपबास
वेयर
भिनमाल
ओसिअन
अतरू
पिपलदा
डिडवाना
लाडनु
देसूरी
रायपुर
भीम
रेलमगरा
गंगापुर सिटी
खंडार
समोत्रा
फतेहपुर
पिंडवाडा
भदरा
पदमपुर
रावतसर
श्रीविजयनगर
घरसाना
तोडारायसिंह
झाडोल
मारली
वल्लभगढ़
गंगापुर (भीलवाड़ा)
नवलगढ़
केसरीपाल
नैनवा
बड़ी सादड़ी
बेगुन
भालेसर
छोटी सादड़ी
डूनगेर
गंगराय
कापासान
निम्बाहेड़ा
प्रतापगढ़
रसमी
पहाड़ी
रानीवास
शेरगढ़
छाबसा
रामगंज मंडी
डेगाना
नावा
जैतरान
सोजात
देवगढ़
बामणवास
हिन्डोन
महुआ
डोडाभीम
लक्षमणगढ़
देओघर
करणपुर
पिलीबंगा
सादुलपुर
सूरतगढ़
देवली
धारियाबाद
खैरवाड़ा
नडबाय
वलोतरा
सांभर झील
फालना
बस्सी
छाकसू

राजस्थान सर्किल

छोमू
दूदू
फागी
फुलेरा
अ लेरा
गंगधार
खानपुर
पछपहाड़
पिरावा
अहोर
सांचोर
भोपालगढ़
डिगोड
संगोड
जायल
प्रबारसर
मारवाड जंक्शन
अमेट
कुम्भलगढ़
बोनली
करौली
नडाती
डाटा रामगढ़
श्रीमाधोपुर
अनुपगढ़
नोहार
रायसिंह नगर
सग्राय
टिबी
मालपुरा
गोगुंदा
कोतरा
सरडा
भवानीमंडी
श्रीमहावीरजी
नेवाय
बिलारा
कनोटा
वनस्थली
मेडतासिटी
तलेरा
बिरवा
माऊंट आबु
पौटा
बसवा
मनोहरपुरा
संथाल
सिकन्दरा
बिस्सऊ
सिकराई
बारी
पुष्कर
तिगारा
हुरदा (स्थानीय गुलाबपुरा)
अगार
डबोक
राजगढ़ (अलवर)
चिराना
खेतड़ी कोपर
ऋषभदेव
लालसोट
गनेरा
सुन्दरपुरा
पापरडा
मेड
भिंडरेज
निमराना
विरतनगर

राजस्थान सर्किल

बयाना
सलुम्बर
झालरापाटन
शेओगंज (स्थानीय सुमेरपुर)
खानछोड़
जवाजा
लचरोल
उदयपुरवाटी
खेतड़ी टाउन
गुलाबपुर
झांदीकुई
नरेडा
राजमोटा
नागल राजावाटन
मंडवाडी
चौहटान
हिंडाली
जम्बरामगढ़
हनुमानगढ़ जंक्शन
बाली
उनियारा

तमिलनाडु सर्किल

अलनगुडी
अम्मापेटाइ
अन्नूर
अरियालुर
औंदीपट्टी
अव्युदियारकोइल
बूथापंडी
चेनंगम
चिरानमदेवी
चेत्तीनडा
चेरम्यूर
कोवाचेल
देन्कानीकोट्टा
गंटरवाकोट्टीय
गिंगी
गुडालूर (निलगिरी)
गुडीयाथम
डोरस
इलियानगुडी
पेनाग्राम
पेरावुरानी
पोलूर
पोन्नामरावथी
पोरायार
संथानकुलम
सिवागिरी
श्रीवायकुण्डम
तिरूचुल्ली
तिरूमायम
तिरूपत्तुर (के०के०डी०)
तिरूपत्तुर (एन०ए०)
तिरूथूरायपूंडी
तिरूवाडानाई
तिरूवेथीपुरम
तिसायानविल्लीई
तिट्टागूडी
उथामपलायम
उथानगराई
बार्गीटमनगरम
बारगुर
भावानीसागर
चिन्नामनूर
चित्तर
चरिस्तामनगरम
डी० जी० पौडूर
ईराल
इरावानचैरी
गोमांगलम

तमिलनाडु सर्किल

गुडालूर (एम० ए०)
हिगमवायूसे
आइडापाडी
इलूप्पूर
जोलारपेट
केडावाम
कालूगोंडापल्ली
कालूगुमालाई
काकरीगिरी
जयमकोंडान
कमूथई
कच्चूमन्नारकोइल
किरानूर
केलाकराय
कोडावासल
कोटागिरी
लागगुडी
मनामाडुराय
मुडूकुलथूर
नानीइम
नाथम
नवालूर
नेय्यूर
निडामंगलम
नीलाकोटई
ओमालूर
ओराथामड
ओड्डापिडाराम
पलाकोडे
पल्लीपेट
शोलिंगर
सिरूमुंगई
तिरूपायथानगुडी
तित्ताचेरी
वेसूर (मलयम)
बेलकान्नी
वालजाबाद
उथिरामोरूर
उथूकोट्टाय
वाडीपट्टी
वालंगगायमन
वालापाडी
वेडारानयम
वेडासांडूर
विलाथिकुलम
वांडीवाश
पत्तूकोट्टाय
मनडाययूर
राधापुरम
कुड्डालोर
आदिरामपत्तीनम
अलंगासमूदराम
अनामल्लाई
अन्थियूर
अराचलूर
अथीपेडू
अत्तायामपट्टी
अय्यामपेट
सिंगमपुनेरी
स्वामीमलाई
तिरूपुनानम
टी० एन० पलायम
वासुदेवनालूर
वेम्बाडीथालम
कूथानालूर
कावारापेट्टीय
कावेरीपट्टनम
किरूमाम्क्कम
कोराडाचेरी
मालायंदीपथ्थिनम

तमिलनाडु सर्किल

मंडापम
मुक्कूडाल
मुथ्थीम
नासियानूर
नाटचेयारकोइल
नवालूरकुटापट्टू
नवेली-II
पेडलूर
पसूर
पेरनामपेट
पेटईवैथलाई
पुडुकोडई
पुडूवायल
पुंगालूर
पुंजयपुलीयामपट्टी
सम्बनारकोइल
सिंगापेरूपलकोइल
तिरूकाटूपल्ली
लिरूवेलंगडू
बालीपुराथनपलायम
वीरापंडी
वी० वेलोडे

उत्तर प्रदेश

अकबरपुर
अलीगंज
अमरोहा
अनूपशहर
ओनला
अवाली
बाबेरू
बागेश्वर
बहेरी
बंसी
मिकियासायन
भिंगा
भोगांव
बीकापुर
बिडकी
बिसलपुर
बिसौली
बिसवा
बुढाना
चाकीया
चकरात
चंदौसी
चरखंडी
चौरी चौरा
छिबरामऊ
चूनार
कर्नलगंज
दालमऊ
दातागंज
देवप्रयाग
धामपुर
धारचूला
डीडीहाट
दुमरियागंज
हुंडा
ऐतमादपुर
फरीदपुर
फतेहपुर
गंगुलीहाट
गारौथा
गढ़मुक्तेश्वर
घाटमपुर
ज्ञानपुर
हैदरगढ़
हल्दवानी
हरिया
हाटा
इग्लास

उत्तर प्रदेश

जलालाबाद
जलालपुर
जलेसर
जानसठ
जसराना
कायमगंज
कैराना
केशरीगंज
कर्णप्रयाग
करहाल
कार्वी
केराकट
खैर
खलिलाबाद
खातिमा
खेरागढ़
कोटद्वार
कुलपहाड
कुंडा
लहरपुर
लक्सर
लालगंज (कटरा)
लैंसडाऊन
मछलीशहर
मरीहन
मठ
मऊ
मौरनीपुर
भवाना
महोबा
मेहरौनी
मिलक
मिशरोख
मोहम्मदाबाद (जी०ओ०एच०एन०)
मोहम्मदाबाद (जी०जेड०पी०)
मोहम्मदी
मोथ
नगीना
नजीबाबाद
नकुड
नानपांडा
नरैनी
नरेन्द्रनगर
नवाबगंज
निघासन
पटियाली
पाती
पुवायन
पुरनपुर
रामस्नेहघाट
रुद्रप्रयाग
सादाबाद
साफीपुर
शाहाबाद
सैहसबान
सैयदपुर
सलोन
संभल
शाहबाद
शाहगंज
सिधौली
सिकन्दराबाद
सितारगंज
स्वार
तलबेहाट
टांडा
ठाकुरद्वारा
तिलहार
तिलोई
तुलसीपुर
अतरौली
जमनीया

उत्तर प्रदेश	चम्पावत
बेहट	धनौरा
बिलारी	हसनपुर
बिलासपुर	महाराजगंज

संचार सेवाओं का विस्तार

[अनुवाद]

2179. **श्री आनन्द अहिरवार :**

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचार सेवाओं में विस्तार करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की जायेगी तथा कितने विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया जाएगा;

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु किन्हीं वरीयता क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार संबंधी ब्यौरे

—स्थानीय स्विचन क्षमता की 93 लाख लाइनों की निवल वृद्धि

—75 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों की निबल वृद्धि

—31200 टेलेक्स लाइनों की वृद्धि

—सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना

—सभी एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करना

—डायरेक्टरी पूछ-ताछ, मैनुअल ट्रंक सेवा, बिल प्रणाली एवं दोष मरम्मत सेवा जैसी

—ग्राहक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।

मुख्यत: फ्रेंचाइज आधार पर कम से कम उन सभी कस्बों में निम्नलिखित मूल्य वर्धित सेवाएं

प्रदान किए जाने की योजना है जिनकी आबादी 5 लाख या इससे अधिक हैं :

—सेल्यूलर मोबाइल सेवा

—वायस-मेल सेवा

—इलेक्ट्रानिक मेल सेवा

—आडियो कानफ्रेंसिक सेवा

—वीडियो कानफ्रेंसिंग सेवा

—रेडियो पेजिंग

—वीडियोटेक्स

(ग) प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों, मांग की अनिश्चितताओं आदि को ध्यान में रखते हुए 8वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि एक्सचेंज क्षमता की लगभग 93 लाख लाइनों के यूनिट-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। संलग्न अनुबंध में आधुनिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आधुनिकतम उपस्कर द्वारा बदले जाने के लिए प्रस्तावित लगभग 17 लाख लाइनों की मौजूदा क्षमता का यूनिट वार ब्यौरा भी दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) मार्च, 1994 तक सभी मैनुअल एक्सचेंजों के स्थान पर पूर्णतः आटोमेटिक नेटवर्क तैयार करने को प्राथमिकता दी गई है।

(च) योजना आयोग ने 23,946 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया है और साथ ही प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित योजना के वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य नए उपायों के जरिए निधि की व्यवस्था करने के निदेश दिए हैं। वास्तविक लक्ष्य पूरे करने के लिए 40,555 करोड़ रु० की निधि की आवश्यकता होगी।

विवरण

1992—97 के दौरान प्रस्तावित टेलीफोनों को चालू करने के कार्यक्रम के सर्किल वार ब्यौरे

क्रम सं०	सर्किल का नाम	क्षमता		
		निवल	प्रतिस्थापन/ आटोमेटिक बनाना	टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6482284	161800	514300
2.	असम	74547	27825	59100

1	2	3	4	5
3.	बिहार	127368	57268	101000
4.	गुजरात (दादर नगर हवेल दमन एवं दिव सहित)	794.586	170770	630400
5.	हरियाणा	290612	51884	230600
6.	हिमाचल प्रदेश	71110	25410	56400
7.	जम्मू एवं कश्मीर	53214	89410	43300
8.	कर्नाटक	599556	145916	475700
9.	केरल	492341	104215	390600
10.	मध्य प्रदेश	402767	93125	319800
11.	महाराष्ट्र (गोवा और म० टे० नि० लि० बंबई सहित)	2030556	238670	1670700
12.	उत्तर पूर्व	31615	15445	25100
13.	उड़ीसा	61574	24402	48900
14.	पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	499997	92675	386700
15.	राजस्थान	417947	103361	331600
16.	तमिलनाडु (पाणिचेरी और मद्रास सहित)	777358	143130	634200
17.	उत्तर प्रदेश	530707	134609	421000
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार और कलकत्ता सहित)	220015	93785	181800
19.	दिल्ली	1141800	31300	970000
	कुल	9271974	1724700	7500000

उत्तर प्रदेश में थाक में टी० वी० टावर

[हिन्दी]

2198. **डा० जी० एल० कनोजिया :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में धारू जनजातिय क्षेत्र में टी० वी० टावर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) लखीमपुर में वर्तमान अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर को बदलकर एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना की परिकल्पना है। इस ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर आशा की जाती है कि खेरी (लखीमपुर) का पूरा जिला टी० वी० कवरेज के अंतर्गत आ जाएगा। तथापि इस परियोजना का लागू किया जाना संसाधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर ही निर्भर करेगा।

राजस्थान में टेलीविजन सेवाएं

2199. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के साथ पाकिस्तानी सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में दूरदर्शन कार्यक्रम की सेवा ों में सुधार की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित राजस्थान के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा प्रदान करने की दृष्टि से दो उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर अर्थात बाड़मेर और जैसलमेर में एक-एक, इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, गंगानगर जिले के सीमावर्ती जिले के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के लिए दो अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर भी अर्थात भद्रा तथा रावतसर में एक-एक, लगाए जा रहे हैं / लगाए जाने की परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त साधनों तथा परस्पर प्राथमिकताओं के अधीन अनूपगढ़ (गंगानगर जिला) में भी एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की परिकल्पना है।

राज्य के सभी उच्च शक्ति/अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों को उपग्रह लिंकेज जिसके लिए जयपुर में उपग्रह अर्थ स्टेशन कार्यान्वयन की अंतिम अवस्था में है, के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर के साथ जोड़ने की भी परिकल्पना है।

बिभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों तथा दर्शकों के सर्वेक्षण के आधार पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा विषय-वस्तु में सुधार करने का दूरदर्शन का निरंतर प्रयास रहता है।

त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन का विस्तार

[अनुवाद]

2200. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के विस्तार के लिए 1993-94 के दौरान कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विकास के लिए अनुपेक्षित क्षेत्रों का पता लगा लिया है और स्थानीय जनता के पुनर्वास की लागत का आकलन किया है तथा विस्थापितों की संख्या का अनुमान लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक त्रिवेन्द्रम में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्णाण पर कितनी राशि व्यय की गयी; और

(ङ) निर्धारित अवधि में विमानपत्तन के विस्तार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 14.12 करोड़ रुपए।

(ख) और (ग) मौजूदा धावनपथ के दक्षिणी पश्चिम की ओर टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 140 एफड़ भूमि और धावनपथ के विस्तार के लिए 110 एकड़ भूमि का पता लगाया गया है। भूमि के अर्जन और स्थानीय लोगों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण ने केरल राज्य सरकार से सिफारिश की है। इन लागतों का जायजा नहीं लिया गया है।

(घ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के विस्तार पर मार्च, 1992 तक 4.07 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ङ) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के विकास और विस्तार के लिये धावनपथ का विस्तार और नए टर्मिनल कम्पलैक्स का विकास, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो काम्पलेक्स का सुधार अन्तर्देशीय आगमन हाल और सुरक्षा स्थान का वातानुकूलन और धावनपथ प्रकाश प्रणाली में सुधार, एप्रोच प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अर्जन हेतु 1.82 करोड़ रुपए की राशि केरल सरकार के पास जमा कर दी गई है।

महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटक

2201. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :**

श्री हरिसिंह चावड़ा

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में कितने विदेशी पर्यटक आए; और

(ख) इस अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1989,1990 और 1991 में क्रमश: 4801, 3274 और 2802 विदेशी पर्यटक गुजरात आए। महाराष्ट्र के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का अनुमान राज्य-वार नहीं लगाया गया है।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948

[हिन्दी]

2203. श्री शिबू सोरेन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने केन्द्र सरकार से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को पर्यटक मानचित्र में शामिल किया जाना

2203. श्री राम सागर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई० टी० बी० बर्लिन, 1992 में भाग लेने वाले प्रतिरूप के लिए प्रकाशित पर्यटन मानचित्र में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :(क) और (ख) पर्यटन विभाग ने आई० टी० बी० बर्लिन के लिए कोई मानचित्र तैयार नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2204. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कार्यरत स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की जिलावार क्षमता कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1370.

(ख) जानकारी को अद्यतन किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र का विनियंत्रण

[अनुवाद]

2205. **श्री मनोरंजन भक्त :**

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन का विकेन्द्रीकरण, ट्रांसमिशन का केन्द्रीकरण तथा वितरण का विकेन्द्रीकरण करने हेतु विश्व बैंक से कोई सुझाव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत में विद्युत क्षेत्र की संरचना में सुधार किया जाना सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। विभिन्न उपाय जिनको अपनाए जाने की आवश्यकता है इनके बारे में विश्व बैंक द्वारा समय-समय पर टीका-टिप्पणी की गई है, जिसने विगत में भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा की गई शुरूआत और केन्द्रीय पारेषण निगम अर्थात् पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि० की स्थापना किए जाने के कदम का बैंक ने समर्थन किया है।

कोंकण क्षेत्र के किसानों और मछुवारों के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम

2206. **श्री सुधीर सावंत :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के किसानों और मछुआरों के लिए कार्यक्रमों के प्रसारण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के किसानों तथा मछुआरों आदि जैसे भिन्न-भिन्न वर्गों के दर्शकों के लिए दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा अपनी क्षेत्रीय सेवा में तथा दूरदर्शन केन्द्र, पणजी द्वारा विभिन्न फोरमेटों में कार्यक्रम पहले से ही प्रसारित किए जा रहे हैं।

बिहार में बक्सर में कम शक्ति का टी० वी० टावर

[हिन्दी]

2207. **श्री तेज नारायण सिंह :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बक्सर में कम प्रसारण क्षमता का टी० वी० टावर लगाए जाने के कारण उस क्षेत्र के लोग पटना से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार तथा अन्य कार्यक्रमों को नहीं देख पाते;

(ख) क्या सरकार का उक्त केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। कार्यक्रमों के रिले के लिए बक्सर का अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर उपग्रह के जरिए दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से जुड़ा हुआ है न कि दूरदर्शन केन्द्र पटना से।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों को विज्ञापन देना

2208. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से प्रकाशित किन-किन पंजीकृत समाचार-पत्रों को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से नियमित रूप से विज्ञापन प्राप्त होता है;

(ख) क्या इन लघु समाचार पत्रों को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से विज्ञापन प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों तथा भुगतान की गई धन-राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से प्रकाशित पंजीकृत समाचार पत्रों के नाम, जिन्हें वर्ष 1992-93 के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में सूचाबद्ध किया गया है; संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन सरकारी विज्ञापन नीति निर्देशक सिद्धान्तों में दिए गए मानकों के अनुसार जारी करता है। इन मानकों, प्रचार अपेक्षाओं तथा बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य यह रहता है कि विज्ञापनों के जारी करने में संतुलत रहे क्योंकि सरकारी विज्ञापनों को जारी करने का सम्बन्ध विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से है, इसलिए छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन प्राप्त करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिए गए विज्ञापनों और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या	स्थान (स्टेंडर्ड कालम सेंटीमीटर)	राशि (रुपयों में)
1989-90	46	82,213	8,63,334
1990-91	58	69,447	10,19,072
1991-92	60	65,304	13,57,743

विवरण

(1992-93) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रकाशित समाचारपत्रों की सूची जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में सूचीबद्ध हैं

क्र० सं०	प्रकाशन का नाम	स्थान
	2	3
1.	आज की सुबह हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
2.	अंतर ज्वाला हिन्दी साप्ताहिक	दुगड्डा (गढ़वाल)
3.	दुखते स्वर हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
4.	देव भूमि हिन्दी साप्ताहिक	चमोली
5.	दून दर्पण हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
6.	दून मेल हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
7.	दून पोस्ट हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
8.	दून वाणी हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
9.	दून भूमि हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
10.	गढ़वाल टाइम्स हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
11.	घाटी का भारत हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
12.	घाटी के गरजते स्वर हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
13.	हिमाचल टाइम्स अंग्रेजी दैनिक	देहरादून
14.	हिमाचल टाइम्स हिन्दी दैनिक	देहरादून
15.	जन लहर हिन्दी दैनिक	देहरादून

1	2	3
16.	लोकतन्त्र हिन्दी साप्ताहिक	काशीपुर
17.	नैनीताल समाचार हिन्दी पाक्षिक	नैनीताल
18.	पर्वतीय दर्शन टाइम्स हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
19.	प्रधान टाइम्स हिन्दी दैनिक	ऋषिकेश
20.	समृद्धि भारत हिन्दी साप्ताहिक	कोटद्वार
21.	सपना सुहर्वण हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
22.	सत्यपथ हिन्दी साप्ताहिक	कोटद्वार
23.	शांति एवं एकता दर्शन हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
24.	सीमांत प्रहरी हिन्दी साप्ताहिक	मसूरी
25.	सीमांत वार्ता हिन्दी दैनिक	पौड़ी
26.	शिखर संदेश हिन्दी पाक्षिक	देहरादून
27.	सोशल विकास हिन्दी पाक्षिक	देहरादून
28.	तरुण हिंद हिन्दी साप्ताहिक	ऋषिकेश
29.	दि फ्रंटियर मेल अंग्रेजी साप्ताहिक	देहरादून
30.	उदय भारत हिन्दी दैनिक	देहरादून
31.	उत्तर उजाला हिन्दी दैनिक	हल्द्वानी
32.	उत्तरांचल हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
33.	उत्तरांचल वाणी हिन्दी दैनिक	ऋषिकेश
34.	उत्तरी मानसरोवर हिन्दी साप्ताहिक	चमोली
35.	वनगार्ड अंग्रेजी दैनिक	देहरादून
36.	वाणी प्रवाह हिन्दी दैनिक	काशीपुर
37.	युगवाणी हिन्दी साप्ताहिक	देहरादून
38.	पौड़ी टाइम्स हिन्दी साप्ताहिक	पौड़ी
39.	साप्ताहिक गढ़वाल मंडल	पौड़ी

भारतीय पर्यटन वित्त निगम

[अनुवाद]

2209. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने कर्ज के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की;

(ख) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए कर्ज दिए गये; और

(ग) चालू वर्ष में निगम के पास वितरित करने के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पर्यटन वित्त निगम द्वारा ऋण के रूप में वितरित की गई कुल राशि के आंकड़े निम्नानुसार हैं—

(लाख रु० में)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	1989-90	1990-91	1991-92
रुपयों में ऋण	1276	3871	4759
पट्टे पर	—	36	25
इक्विटी	—	16	44
	1276	3923	4820

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए यह ऋण वितरित किया गया उनका ब्यौरा निम्नानुसार हैं—

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	1989-90	1990-91	1991-92
होटल	978	3675	4518
मनोरंजन पार्क	180	216	300
कार रेंटल	86	32	—
अन्य	32	—	10
	1276	3923	4828

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय पर्यटन वित्त निगम के पास 60 करोड़ रुपए के संसाधन होने के अनुमान हैं।

मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों को दूरदर्शन नेटवर्क में शामिल करना

[हिन्दी]

2210. **कुमारी विमला वर्मा** :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के आदिवासी क्षेत्रों विशेषत: मध्य प्रदेश के सिवनी, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों को दूरदर्शन नेटवर्क में शामिल करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन का हमेशा यह प्रयास रहता है कि प्राथमिकता के आधार पर मध्य प्रदेश सहित देश के आदिवासी क्षेत्रों को दूरदर्शन सेवा प्रदान की जाए।

इस समय, जबलपुर में कार्य कर रहे एक उच्च शक्ति (1 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर के अलावा भी जबलपुर, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में क्रमश: तीन अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं और वे अपने कवरेज क्षेत्रों में संतोषजनक टी० वी० सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। 1993-94 के दौरान जबलपुर के टी० वी० ट्रांसमीटर की शक्ति को 1 कि० वा० से 10 कि० वा० तक बढ़ाने से इन जिलों में टी० वी० कवरेज में अधिक सुधार होने की आशा है। नरसिंहपुर जिले में टी० वी० सेवा में और अधिक सुधार करने की दृष्टि से, गदरवारा में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की भी परिकल्पना है जो संसाधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

अन्तर्राज्यीय नदी परियोजना के लिए वित्तपोषण करने वाली केन्द्रीय एजेंसी

[अनुवाद]

2211. **डा० विश्वनाथम केनिथी** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की सभी स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण करने वाली केन्द्रीय एजेंसी के गठन की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस एजेंसी के कब तक गठित हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, देश में राष्ट्रीय महत्व की कुछ सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया। संसाधनों की कमी के कारण, योजना आयोग प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका तथा उसने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय

परियोजनाओं के वित्त पोषण के मामले पर पहले राज्यों के साथ चर्चा कर ली जानी चाहिए क्योंकि सिंचाई क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर राष्ट्रीय संसाधन उपलब्धता उसके द्वारा परिवर्तित नहीं की जा रही है ।

राजमुन्द्री हवाई अड्डे का विकास

2212. **डा० के० वी० आर० चौधरी :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राजमुन्द्री विमानपत्तन के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) निधियों की कठिनाई और सीमित वाणिज्यिक सम्भावना के कारण राजमुन्द्री हवाई अड्डे के लिए प्रचालन करने हेतु इंडियन एयरलाइंस से मांग की कमी के कारण राजमुन्द्री हवाई अड्डे के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य

[हिन्दी]

2213. **श्री छेदी पासवान :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान प्रदान किए जाने वाले नए टेलीफोन कनेक्शनों का निर्धारित लक्ष्य 1991-92 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार पिछले वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और लक्ष्य पूर्ति किस हद तक हुई थी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। 1991-92 के दौरान 7 लाख टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि 92-93 के दौरान 8.5 लाख कनैक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	91-92 के दौरान सीधी एक्सचेंज लाइनों का कार्य निष्पादन	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	37771	39651
2.	असम	16299	8 04
3.	बिहार	22747	22914
4.	गुजरात (द्वीप, दमन, दादरा और नागर हवेली सहित)	45323	45963
5.	हरियाणा	17371	15947
6.	हिमाचल प्रदेश	8283	7022
7.	जम्मू और कश्मीर	3987	3006
8.	कर्नाटक	32309	42790
9.	केरल	40445	45344
10.	मध्य प्रदेश	59088	68296
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	112221	159478
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	8679	5501
13.	उड़ीसा	9589	12860
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	25458	25533
15.	राजस्थान	36797	29012
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरि सहित)	34138	38104
17.	उत्तर प्रदेश	68932	61082
18.	पश्चिमी बंगाल (सिक्किम सहित)	50725	20093
19.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	70169	84710
	जोड़	700331	735410

इंदिरा सागर बांध की सिंचाई क्षमता

[अनुवाद]

2214. **कुमारी पुष्पादेवी सिंह** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खंडवा के निकट पुनासा स्थित इंदिरा सागर बांध के पूरा होने पर कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाने की आशा है;

(ख) खंडवा के निकट इस बांध परियोजना के निर्माण को पूरा करने हेतु क्या तिथि निश्चित की गई है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया था;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(घ) इस परियोजना के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश में खण्डवा के निकट पुनासा इंदिरा सागर बांध के पूर्ण होने पर 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किए जाने की आशा है ।

(ख) 1993.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना को सन् 2000 तक पूरी किये जाने की प्रत्याशा है ।

(ग) सितम्बर, 199 तक इस परियोजना पर 252.338 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं ।

(घ) मुख्य बांध की नींव खुदाई और विद्युत घर की खुदाई शुरू हो गई है तथा कोफर बांध एवं व्यपवर्तन सुरंग पर निर्माण कार्य प्रगति पर है । हैड रेस एवं टेल रेस चैनलों का कार्य भी दे दिया गया है ।

तिरूवनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र में आधुनिक उपस्कर

2215. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तिरूवनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र में आधुनिक उपस्कर उपलब्ध कराना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस केन्द्र का स्तर बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) हालांकि प्रौद्योगिकी विकास एक सतत् प्रक्रिया है फिर भी दूरदर्शन का अपने केन्द्रों को उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत आधुनिक उपकरण से सुसज्जित करने का सतत् प्रयास रहता है । इन विचारों को ध्यान

में रखते हुए दूरदर्शन केन्द्र तिरूवनन्तपुरम को व्यावसायिक ग्रेड रंगीन उपकरण तथा बाह्य कवरेज के लिए रंगीन ओ० बी० वैन प्रदान की गई है। इसके अलावा मौजूदा इलैक्ट्रानिक न्यूज गेदरिंग (ई० एन० जी०) यूनिटों के स्थान पर तीन आधुनिक बेटा कैम-कोरडर्स भी केन्द्र को प्रदान करने का विचार है।

(ग) केरल सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बक्रेश्वर ताप विद्युत संयंत्र

2216. **श्री अमर राय प्रधान :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान अथवा चीन पश्चिम बंगाल स्थित बक्रेश्वर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस करार की शर्तें क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना पर खर्च की गई राशि

2217. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इन परियोजनाओं का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 19.67 लाख रुपये।

(ख) परियोजना नाम	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
महानदी डेल्टा प्रणाली चरण-I	10222	3.06
महानदी डेल्टा चरण-II	34525	10.36
सलान्दी सिंचाई प्रणाली	10000	2.99

1	2	3
ऋषिकुल्या सिंचाई प्रणाली	12610	3.78
देरजंग सिंचाई प्रणाली	5951	1.78
मलिया सिंचाई प्रणाली	8445	2.53
धनेई सिंचाई प्रणाली	3831	1.15
हीराकुंड वितरण प्रणाली (सारांश रिपोर्ट पर आधारित)	24125	7.24

(ग) राज्य सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

वायुदूत का संचालन

[हिन्दी]

2218. **श्रीमती केसरबाई सोनजी क्षीरसागर** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को अपने कर्मचारियों की हड़ताल के कारण घाटा हो रहा है;

(ख) उड़ानों को रद्द करने अथवा विलम्ब से उड़ान भरने के कारण कितनी धनराशि की हानि हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वायुदूत की उड़ानों में विलम्ब की बढ़ती हुई घटनाओं और इसकी उड़ानें रद्द होने की दृष्टि से वायुदूत की वित्तीय स्थिति क्या है;

(घ) वायुदूत की मुम्बई-नान्देड़ सेवा को बरास्ता औरंगाबाद के स्थान पर बरास्ता पूना चलाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत छः महीनों के दौरान वायुदूत की मुम्बई-नान्देड़ उड़ानें कितनी बार रद्द की गयीं और इसका क्या परिणाम हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विमान चालकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आंदोलन/हड़ताल के कारण इंडियन एयरलाइंस को हुई हानि इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये)
1990-91	(0.57)
1991-92	(4.91)
(1992-93 (अक्तूबर, 1992 तक)	(5.71)*

*इसमें विमान यातायात नियंत्रकों द्वारा प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त ईंधन जलने की लागत पर 3.60 करोड़ रुपये शामिल हैं।

एयर इंडिया की सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) अलाभकारी परिचालनों, विमानों के पुराने बेड़े, अतिरिक्त मानवशक्ति, उड़ानों के विलम्ब/रद्द करने आदि के कारण गत तीन वर्षों के दौरान वायुदूत को हुई हानि इस प्रकार है :—

1989-90	—	35.82 करोड़ रुपये
1990-91	—	37.08 करोड़ रुपये
1991-92	—	30.59 करोड़ रुपये

(घ) वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कारण इस उड़ान को पुणे से होकर प्रचालित करने के पक्ष में है।

(ङ) मुख्य रूप से परिचालनात्मक कारणों से गत 6 महीनों के दौरान बम्बई-पुणे-नान्देड़ के मार्ग पर वायुदूत की उड़ान 16 बार रद्द की गई थी।

केरल में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

2219. **श्री के० मुरलीधरन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 में केरल में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिला-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी सलाहकार समिति

[हिन्दी]

2220. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की किन-किन सिफारिशों पर उनके मन्त्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग में विचार किया गया है तथा उन्हें लागू किया गया है;

(ख) कौन-कौन सी सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की जा सकी हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष सिफारिशें कब तक लागू की जायेंगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशें, जो क्रियान्वित हो सकी हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) क्रियान्वित नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा, उनके कारणों एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सम्भावित समय सहित संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

विवरण-I

जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशें जो क्रियान्वित की जा चुकी हैं

सिफारिश

1. मंत्रालय के नये संगठनों इत्यादि के नाम मूलत: हिन्दी में ही रखे जाना ।
2. अनुवाद पर निर्भर न रहकर सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में ही करना ।
3. कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सारा कामकाज हिन्दी में ही किए जाने की अपेक्षा करना ।
4. सभी संविदाएं और करार अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में जारी करना ।
5. प्रगति रिपोर्ट समय पर मंगाने के लिए कार्रवाई करना ।
6. हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाना ।
7. धारा 3 (3) और नियम-5 का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना ।
8. हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण, एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर शीघ्र पूरा किया जाना ।
9. हिन्दी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएं ।
10. तकनीकी मामलों में भी हिन्दी का प्रयोग शुरू करना ।
11. हिन्दी पत्राचार बढ़ाना ।

विवरण-II

जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों की सिफारिशें, जो क्रियान्वित नहीं की जा सकीं

सिफारिश	क्रियान्वित न किए जाने का कारण
1. यदि किन्हीं कारणवश नये टाइपराइटर नहीं खरीदे जा सकते हैं तो कम से कम कुछ अंग्रेजी टाइपराइटरों के कुंजी-पटल बदलवाकर इसे हिन्दी टाइपराइटरों में बदल दिए जाएं ।	भारत सरकार के किफायत बरतने के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है लेकिन बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इसे शीघ्र क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।
2. "अनुवाद" तथा "कार्यान्वयन व प्रबोधन" के लिए अलग-अलग स्टाफ की व्यवस्था ।	इस सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों व विभागों से आवश्यक सूचना मंगा ली गई है तथा मामले पर आगे विचार किया जा रहा है । तथापि, भारत सरकार के किफायत बरतने के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में काफी समय लग सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश में रेनिगुंटा में डीजल आधारित विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

2221. **डा० रवि मल्लू :**

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रेनिगुंटा में एक डीजल आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (ए० पी० एस० ई० बी०) ने जिला चित्तूर के रानीगुण्टा में एल० एस० एच० एस०/एफ० ओ० पर आधारित विद्युत परियोजना (100 मेगावाट) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ईंधन लिंकेज की उपलब्धता के अभाव में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) द्वारा इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सका। ए०पी०एस०ई०बी० को ईंधन लिंकेज सुनिश्चित किए जाने के बाद स्कीम को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

2222. **श्री सुखेन्दु खां** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कितने पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है;

(ख) जून, 1991 से आज तक की अवधि में कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को चालू किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि में कितने गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था की गई ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 281

(ख) 157

(ग) 107

लौह अयस्क पिंड

2223. **श्री हाराधन राय** :

श्री पूर्णचन्द्र मलिक :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात उद्योग द्वारा लौह अयस्क पिंडों का कुल कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या पिंडों की सप्लाई में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या पिंडों की कमी के कारण बिक्री योग्य इस्पात में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) लौह अयस्क पैलेटों का उपयोग देश में गैस पर आधारित संयंत्रों पर स्पंज लौह उद्योग द्वारा स्पंज लोहे/ तप्त ब्रिक्वेटिड लोहे के उत्पादन में किया जाता है । मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड के गैस पर आधारित संयंत्र को इस समय पैलेटों का एकमात्र उपभोक्ता है, मैं पैलेटों की खपत वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 6 लाख टन बताई गई है ।

(ख) स्पंज लोह उद्योग के लिए पैलेटों की कमी की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेनिगुन्टा हवाई अड्डे का विस्तार

2224. **श्री एन० जे० राठवा** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुमाला-तिरुपति विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रेनिगुन्टा हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की हैं;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि के व्यय होने का अनुमान है और शेष धनराशि किस प्रकार जुटाई जाएगी ।

(घ) रेनिगुंटा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) तिरुमाला-तिरुपति देवास्थानम ट्रस्ट राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 6 करोड़ रुपए की राशि देने के लिए महमत हुआ है बशर्ते आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार का अनुसमर्थन प्राप्त हो । धावनपथ के उन्नयन और तकनीकी भवन के निर्माण के लिए कुल अनुमानित व्यय 10.96 करोड़ रुपए है । राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चरणबद्ध तरीके से 4.96 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जाएगी ।

(घ) चूंकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तिरुमाला-तिरुपति देवास्थानम ट्रस्ट के साथ ऋण समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, अतः यह बताना असामयिक होगा कि कब तक विस्तार का काम पूरा हो जाएगा ।

बाल फिल्म सोसायटी

2225. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल फिल्म सोसायटी देशभर में बाल फिल्म शो आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां पर बाल फिल्म सोसायटी ने विगत दो वर्षों के दौरान फिल्म शो आयोजित किए; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान फिल्म शो मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए :

दिल्ली, रिहन्दरंगा, गुडीयाडा, करीमनगर, चित्तौड़, बांकुरा, हावड़ा, राउरकेला, बम्बई, वर्धा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, ग्वालियर, शिवपुरी, दुर्ग, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, मदेरा, गुलबर्गा, बीदर, हैदराबाद, अनंतपुर, कुडप्पा, रांची, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली नागपुर भरूच, त्रिचूर, कालीकट, मैसूर, हसन ।

(ग) ये फिल्म-शो मुख्य रूप से जिला/स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं, जो बाल फिल्मों के प्रदर्शन के लिए निःशुल्क अथवा मामूली किराये पर थियेटर उपलब्ध कराते हैं ।

मध्य प्रदेश में वरीयता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

2226. **श्री शिवराज चौहान :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल सहित मध्य प्रदेश में वरीयता के आधार पर स्वीकृत किए गए टेलीफोन कनेक्शनों में से इस समय कनेक्शन हेतु लंबित आवेदनों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार कितने आवेदन निपटाए गए हैं; और

(घ) शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दे दी गई है ।

(ख) से (घ) जिन टेलीफोनों को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, उनके जिला-वार ब्यौरे तथा इन टेलीफोनों को प्रदान न किए जाने के कारण संलग्न विवरण-II में दिए

गए हैं । कुछ मामलों में ये टेलीफोन विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने और कुछ अन्य मामलों में एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध होने पर संस्थापित कर दिए जाएंगे ।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में प्राथमिकता आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदनों की जिला-वार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	लंबित मामलों की संख्या	क्र० सं०	जिले का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1.	बालाघाट	5	25.	नरसिंहपुर	1
2.	बस्तर	—	26.	पन्ना	—
3.	बेतुल	1	27.	रायगढ़	—
4.	भिंड	—	28.	रायपुर	3
5.	भोपाल	49	29.	रायसेन	—
6.	बिलासपुर	1	30.	राजगढ़	—
7.	छतरपुर	1	31.	राजनंदगांव	—
8.	छिंदवाड़ा	1	32.	रतलाम	7
9.	दमोह	—	33.	रीवा	11
10.	दतिया	—	34.	सागर	7
11.	देवास	2	35.	सरगुजा	—
12.	धार	3	36.	सतना	—
13.	दुर्ग	3	37.	सिहोर	—
14.	गुना	—	38.	सिवनी	—
15.	ग्वालियर	9	39	शहडोल	—
16.	होशंगाबाद	3	40.	सीधी	—
17.	इंदौर	56	41.	शाजापुर	—
18.	जबलपुर	20	42.	शिवपुरी	2
19.	झाबुआ	—	43.	टीकमगढ़	—
20.	खंडवा	1	44.	उज्जैन	—
21.	खरगौन	1	45.	विदिशा	3
22.	मांडला	—			
23.	मंदसौर	6		जोड़ :	206
24.	मुरैना	10			

विवरण-II

लम्बित टेलीफोन कनेक्शन प्रदान न किए जाने के जिला-वार कारण

क्र०सं०	जिले का नाम	कनेक्शन प्रदान न करने के कारण
1	2	3
1.	बालाघाट	क्षमता नहीं है। मार्च, 93 तक प्रदान कर दिए जाएंगे।
2.	बस्तर	शून्य
3.	बेतुल	पार्टी द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। पार्टी द्वारा आवेदन करने के तत्काल बाद प्रदान कर दिया जाएगा।
4.	भिंड	शून्य
5.	भोपाल	32 मामले पार्टियों से विवरण प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े हैं। 17 मामले रोक दिए गए हैं क्योंकि धोखा-धड़ी का सन्देह होने के कारण उनकी जांच की जा रही है।
6.	बिलासपुर	भुगतान नहीं किया गया। मांग-पत्र जारी किए गए। भुगतान प्राप्त होने पर तत्काल प्रदान कर दिए जाएंगे।
7.	छतरपुर	मामले पर सर्किल कार्यालय के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। शहर परिवर्तन की पुष्टि के बाद प्रदान कर दिए जाएंगे।
8.	छिंदवाड़ा	तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। मार्च, 93 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।
9.	दमोह	शून्य
10.	दतिया	शून्य
11.	देवास	1. भुगतान सम्बन्धी विवरण प्राप्त होने के तत्कात बाद प्रदान कर दिए जाएंगे। 2. क्षिप्रा में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के बाद।

1	2	3
12.	धार	तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। मार्च, 93 तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है।
13.	दुर्ग	अभी हाल में प्राप्त हुआ है। इसे 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रदान कर दिया जाएगा।
14.	गुना	शून्य
15.	ग्वालियर	पार्टियों से विवरण प्राप्त होने हैं। भुगतान सम्बन्धी विवरण प्राप्त होने पर कर दिए जाएंगे।
16.	होशंगाबाद	1. 15 दिनों की अवधि के भीतर। 2. मार्च, 93 लंबी दूरी के कनेक्शन के लिए पार्टी ने आवेदन नहीं किया है। मार्च, 93 तक एक तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।
17.	इंदौर	प्रतीक्षा सूची के विवरण प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रदान कर दिए जाएंगे और कुछ मामलों में पतों के परिवर्तन की पुष्टि करने के बाद।
18.	जबलपुर	14 मामलों का निपटान रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी विवरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। कटनी के 6 मामले क्षमता उपलब्ध न होने के कारण लम्बित पड़े हैं। मार्च, 93
19.	झाबुआ	शून्य
20.	खंडवा	लम्बी दूरी का कनेक्शन, दूरी 18 किमी० । पार्टी ने लम्बी दूरी के प्रभारों के लिए आवेदन नहीं किया है।
21.	खरगोन	भुगतान विवरणों को प्राप्ति के तत्काल बाद।
22.	मंडला	शून्य

1	2	3
23.	मंदसौर	1-12-92 को प्राप्त हुए मामलों में टेलीफोन 15-12-92 तक प्रदान कर दिए जाएंगे ।
24.	मुरैना	उपभोक्ताओं के कारण ।
		उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर लेने के तत्काल बाद प्रदान कर दिए जाएंगे ।
25.	नरसिंहपुर	15 दिनों की अवधि के भीतर प्रदान कर दिए जाएंगे ।
26.	पन्ना	दिसम्बर, 92 में प्राप्त हुआ ।
27.	रायगढ़	शून्य
28.	रायपुर	पते में परिवर्तन की पुष्टि के कारण लम्बित ।
		पुष्टि होने के तत्काल बाद प्रदान कर दिया जाएगा ।
29.	रायसेन	शून्य
30.	राजगढ़	शून्य
31.	राजनन्दगांव	शून्य
32.	रतलाम	भुगतान करने के 15 दिनों के भीतर कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे ।
33.	रीवा	5—तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है ।
		मार्च, 93 तक
		6—पार्टियों का पता नहीं ।
34.	सागर	6—पार्टियों से विवरण आने बाकी हैं ।
		1—तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं ।
		6—विवरण प्राप्त होने के बाद प्रदान किए जाएंगे ।
35.	सरगुजा	शून्य
36.	सतना	शून्य
37.	सिहोर	शून्य
38.	सिवनी	शून्य

1	2	3
39.	शहडोल	शून्य
40.	शाजापुर	शून्य
41.	शिवपुरी	भुगतान सम्बन्धी विवरण प्राप्त न होने के कारण लम्बित। भुगतान विवरणों की प्राप्ति के तत्काल बाद प्रदान कर दिए जाएंगे।
42.	सीधी	शून्य
43.	टीकमगढ़	शून्य
44.	उज्जैन	शून्य
45.	विदिशा	क्षमता पूरी है। मार्च, 93 तक प्रदान कर दिए जाएंगे।

असम में लाज, होटल और यात्री निवासों का निर्माण

[अनुवाद]

2227 **श्री प्रबीन डेका** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1992-93 के दौरान असम सरकार से राज्य में पर्यटक लाज, होटल और यात्री निवासों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य को वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और वर्ष 1992-93 में कितनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) हाल ही में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को असम सरकार से 1992-93 के दौरान राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—

1. कामाख्या के तीर्थ कुटीरें
2. कलैन में मार्गस्थ सुविधाएं
3. बर्दलोनी पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटक विहार स्थल
4. तेजपुर/रामनगर/नाजिरा/तिनसुखिया में हैंग-ग्लाइडिंग सहित जल-क्रीडाएं

5. चरैदेव में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन

6. प्रचार और एक शिल्प ग्राम की स्थापना करने के लिए सहायता

केन्द्र सरकार ने 1991-92 के दौरान पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 82.47 लाख रुपये अवमुक्त किए हैं और 1992-93 के दौरान अब तक 14.00 लाख रुपये अवमुक्त किए हैं ।

हिन्दुजा ग्रुप द्वारा आन्ध्र प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना लगाना

2228. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित हिन्दुजा ग्रुप ने आन्ध्र प्रदेश में तापीय विद्युत परियोजना लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कहां लगायी जायेगी;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) मिशन एनर्जी कम्पनी (यू० एस० ए०) के एक कन्सोर्टियम तथा अशोक लेलैण्ड लि० (भारत) ने जिला विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम ताप विद्युत संयंत्र (1000 मे० वा०) स्थापित किए जाने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कन्सोर्टियम द्वारा परियोजना को स्थापित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच करने की अवधि को 31-1-92 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अनुमानित लागत तथा पूरा करने की तिथि इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही अभिज्ञात हो पाएगी।

डा० अम्बेडकर पर फिल्म

2229. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

श्री राम नाईक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का विचार डा० भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव अभी किस चरण में है; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थाई समिति ने इस प्रयोजनार्थ किस निर्माता का चयन किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार के कल्याण मंत्रालय में देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में डा० भीमराव अम्बेडकर पर एक फीचर

फिल्म निर्मित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कार्यकारी निर्माता के रूप में इस परियोजना को कार्यान्वित करेगा। इस फिल्म के निर्देशक तथा पटकथा लेखक की नियुक्ति को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की धनराशि

2230. **श्री राम नाईक :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 में 30 सितम्बर, 1992 तक महानगर टेलीफोन निगम में मुम्बई में विज्ञापनों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम, मुम्बई के कार्यालयों/अधिकारियों के चैम्बरों के नवीकरण पर कुल कितना खर्च किया ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) महोदय, महानगर टेलीफोन निगम लि०, बम्बई द्वारा 1991-92 के दौरान और अप्रैल, 92 से 30 सितम्बर, 1992 तक विज्ञापन पर कुल क्रमशः 1,54,99,436 रुपये और 1,01,07,431 रुपए खर्च किए गए हैं।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई द्वारा 1991-92 के दौरान और अप्रैल, 92 से सितम्बर, 1992 तक कार्यालयों/कक्षों के नवीकरण पर कुल क्रमशः 5, 96, 429 रुपये और 1,53,413 रुपये खर्च किए गए हैं।

राजस्थान में पर्यटकों के लिए होटल

2231. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए होटलों के निर्माण सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति

[हिन्दी]

2232. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार को केन्द्रीय ग्रिड से सूखे के दौरान रियायती दर पर बिजली देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की मात्रा कितनी होगी और यह कितने समय तक दी जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास इस समय बिहार को सूखे की अवधि के दौरान केन्द्रीय ग्रिड से रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में लाम्बा लाइन हवाई पट्टी का विस्तार

[अनुवाद]

2233. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लाम्बा लाइन हवाई पट्टी के विस्तार पर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कालीकट से शारजाह के लिए उड़ान आरम्भ करने पर खर्च

2234. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एयर लाइंस ने कालीकट से शारजाह को नई सेवा आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ान की उद्घाटन तिथि क्या है;

(ग) सरकार तथा एयरलाइंस के आमंत्रित यात्रियों के सहित इस उड़ान में भाड़ा देने वाले तथा न देने वाले यात्रियों की संख्या अलग-अलग क्या है;

(घ) भारत के विभिन्न स्थानों से कालीकट तथा भारत व विदेशों में आमंत्रितों की उड़ान पर और आतिथ्य पर कुल कितना खर्चा आया; और

(ङ) उनकी कालीकट से शारजाह तक बिना भाड़ा उड़ान से कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां । उद्घाटन उड़ान की तारीख 15-2-1992 थी ।

(ग) उड़ान में 43 भाड़ा देने वाले और 65 भाड़ा न देने वाले यात्री (छः इंडियन एयर-लाइंस कर्मचारी सहित) थे ।

(घ) उद्घाटन उड़ान पर आमंत्रित मेहमानों के आतिथ्य पर भारतीय मुद्रा में लगभग 15,000/- रुपये और विदेशी मुद्रा में लगभग 3.15 लाख रुपए खर्च हुए। विभिन्न स्थानों से कालीकट में आमंत्रित व्यक्तियों की आन्तरिक यात्रा पर लगभग 1.85 लाख रुपये खर्च हुए।

(ङ) उद्घाटन उड़ानों पर विशिष्ट मेहमानों को ले जाने के लिए एयरलाइनों की यह एक सामान्य परिपाटी है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संस्था के संकल्प में इसके लिए व्यवस्था है, और ऐसा समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार के लाभ की दृष्टि से किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरलाइंस पर इस कारण हुए घाटे का दायित्व नहीं डाला जा सकता।

हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार और विकास

223 . **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार एवं विकास करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना में सम्मिलित किए जाने वाले हवाई अड्डों के नाम क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आठवीं पंचवर्षीय योजना के आकार को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए ब्यौरे निश्चित नहीं किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में टैक्स भवन में लगी आग

[हिन्दी]

2236. **श्री भगवान शंकर रावत** :

श्री स्वामी सुरेशानन्द :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर-अक्तूबर, 1992 में आगरा में टैक्स भवन में स्थित टेलीकाम कार्यालय में लगी आग से अनुमानत: कितना नुक्सान हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस प्रकार के अग्निकांड की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) करीब 1.20 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों की हानि हुई है—जैसे मुख्य वितरण फ्रेम, केबिल और कम्प्यूटर उपस्कर।

एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी । तीन व्यक्तियों को गम्भीर तथा चार को मामूली चोटें आईं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मुख्य महाप्रबन्धक, तकनीकी और विकास सर्किल, निदेशक (सतर्कता) उत्तर प्रदेश दूर-संचार सर्किल, लखनऊ तथा उपायुक्त, आगरा द्वारा की जा रही विस्तृत जांच अभी चल रही है तथा इन यूनिटों से अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है ।

(घ) सभी यूनिटों को पुनः यह अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे अग्नि शमन उपकरणों का ठीक प्रकार से अनुरक्षण करने और अग्नि ड्रिल अभ्यासों आदि के बारे में आदेशों का कड़ाई से पालन करें ।

बैल्थारा रोड (बलिया) ताप विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

2237. **श्री राजवीर सिह :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1990-91 में बैल्थारा रोड (बलिया) ताप विद्युत परियोजना की पुनरीक्षित योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास इसके अनुमोदन हेतु भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति, वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला लिंकेज की स्वीकृति तथा साथ ही रेल मंत्रालय द्वारा कोयला और तेल ढुलाई को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश में जिला बलिया में 3 × 250 मेगावाट क्षमता की बेलथारा रोड ताप विद्युत परियोजना को राज्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू० पी० एस० ई० बी०) से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) को संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट नवम्बर, 1991 में प्राप्त हुई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपेक्षित स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने तथा प्राप्त की जा रही लिंकेज सम्बन्धी स्वीकृति के अभाव में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने के लिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

गांवों में विद्युतीकरण

[हिन्दी]

2238. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा-

निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को इन दिशानिर्देशों के अनुसार लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, एक राज्य स्तर का कार्यक्रम है जिसे राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के विद्युत विभागों द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष योजना आयोग द्वारा किया जाता है जोकि राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर आधारित होता है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

2239. **श्री खेलन राम जांगड़े** :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में विस्तार/आधुनिकीकरण के निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

—मार्च, 1994 तक सभी मैनुअल एक्सचेंजों को बदलना ताकि पूर्ण रूप से स्वचालित नेटवर्क प्राप्त किया जा सके।

—जिन स्विचों का कार्य-काल समाप्त हो चुका है, उन्हें बदलना।

—छोटे आकार के इलेक्ट्रोमैकेनिकल एम० ए० एक्स०-III एक्सचेंजों और लाइन फाइंडर टाइप (एम० ए० एक्स०-II) को बदलना।

मध्य प्रदेश के लिए तदनुसार विस्तार/आधुनिकीकरण योजनाएं बनाई जा रहीं हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान लगभग 50,000 नये, टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

फ्लाइट सिम्यूलेटर

[अनुवाद]

2240. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस ने दो फ्लाइट सिम्यूलेटर (उड्डयन अनुरूपक) खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) क्या खरीदने से पूर्व इनकी जांच की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयर लाइंस ने 32.56 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से दृश्य साधनों सहित दो एयरबस ए-320 सिम्यूलेटरों की खरीद की है।

(ग) और (घ) सिम्यूलेटर तत्काल उपलब्ध नहीं होते। इनका निर्माण ग्राहक द्वारा बताई गई विशिष्टताओं के आधार पर किया जाता है। एयरबस-320 के पहले सिम्यूलेटर का पूर्ण परीक्षण विनिर्माण संयंत्र पर किया गया तथा स्थापना के बाद केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन, हैदराबाद में किया गया था। जहां तक दूसरे सिम्यूलेटर का सम्बन्ध है, विनिर्माता के परिसर से इसका प्रेषण, स्थापना के बाद इसके पूर्ण परीक्षण और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन, हैदराबाद में इसकी स्वीकार्यता की शर्त के अधीन किया गया था। हैदराबाद में इसकी स्थापना सम्बन्धी कार्य चल रहा है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा इसका अन्तिम भुगतान इसके परीक्षण, संतोषजनक कार्य-निष्पादन और एयरलाइन्स द्वारा इसकी स्वीकार्यता के बाद किया जाएगा।

इंडियन एयरलाइंस में जम्बो जैट्स

2241. **श्री यशवन्तराव पाटिल :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के लिए जम्बो जैट खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षु पायलेटों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान

2242. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 26 मई को नागर विमानन नियमों का उल्लंघन करके दो प्रशिक्षु पायलेटों द्वारा हैदराबाद/बंगलौर सैक्टर में ए-320 विमान (आई० सी० 915) उड़ाने की घटना से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कोई जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) दिनांक 26-5-92 को अनुसूचित ए-320 उड़ान आई० सी० 915 का प्रचालन एक कर्मीदल द्वारा किया गया था जिसमें एक परीक्षक था, जो पायलेट इन कमांड था और रूट चैक के अन्तर्गत एक अनुदेशक उसका कौन पायलेट था।

बंगलूर से उड़ान के तत्काल बाद चेतावनी आई कि "लैंडिंग गियर बन्द नहीं है" कर्मीदल ने उड़ान हैदराबाद के लिए जारी रखी। जांच से पता चला कि लैंडिंग गियर का इन-रिट्रैक्शन दरवाजे के साथ लगी चटकनी के निष्क्रिय हो जाने के कारण हुआ। यह उड़ान प्रचालन मैनुअल के अनुरूप नहीं थी।

इस घटना की जांच पूरी किये जाने तक परीक्षक और अनुदेशक पायलेट को परीक्षक/अनुदेशक पायलेट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है। दोनों पायलेटों के खिलाफ अन्तिम कार्रवाई के लिए विनियामक प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा है।

विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

2243. **श्री ललित उरांव :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान तथा 30-11-92 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में विद्युत का पृथक-पृथक कितना उत्पादन किया गया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान प्राप्त मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार कुल कितने कार्य-दिवस लगे ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान बेची गई बिजली के सन्दर्भ में प्रति मिलियन यूनिट कर्मचारियों की संख्या का राज्यवार/विद्युत विभागवार ब्यौरा संलग्न-विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1989-90 से 1991-92 और अप्रैल, 1992, नवम्बर, 1992 के दौरान राज्यवार/प्रणालीवार कुल विद्युत उत्पादन

राज्य/प्रणाली	विद्युत उत्पादन (मि० यू०)			
	1989-90	1990-91	1991-92	अप्रैल, 92 नवम्बर,92
1	2	3	4	5
बी०बी०एम०बी०	11450	13052	12527	9244
दिल्ली	5905	6515	6729	4910
जम्मू व कश्मीर	3291	3265	3074	2200
हिमाचल प्रदेश	1574	2000	1859	1600
हरियाणा	2641	2607	3547	2489
राजस्थान	6483	6828	8628	5060
पंजाब	9173	8503	8777	6793
उत्तर प्रदेश	34534	382 8	43916	30003
गुजरात	19733	19877	20779	15569
महाराष्ट्र	36020	38222	40737	26381
मध्य प्रदेश	26227	29540	32865	20967
आन्ध्र प्रदेश	23363	26632	30207	18949
कर्नाटक	11067	12430	12884	8057
केरल	5068	5494	5322	4254
तमिलनाडु	20584	22748	23995	18076
बिहार	3913	2974	2586	1852
उड़ीसा	4672	5527	6076	3449
पश्चिम बंगाल	11225	11826	13827	9896
डी० वी० सी०	5454	4954	5333	3296
सिक्किम	36	29	36	24

1	2	3	4	5
असम	1154	1217	1083	680
मेघालय	1046	1093	1244	941
त्रिपुरा	78	137	136	109
मणिपुर	450	473	544	319

विवरण-II

1988-89 से 1990-91 के दौरान विक्रय की गई बिजली के सन्दर्भ में प्रति यूनिट कर्मचारियों की राज्यवार/विद्युत विभागवार संख्या

क्र० सं०	एजेंसी	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.7	4.4	4.0
2.	असम	16.2	14.9	15.0
3.	बिहार	8.5	7.5	7.6
4.	गुजरात	3.1	2.8	2.5
5.	हरियाणा	7.0	7.1	6.7
6.	हिमाचल प्रदेश	9.3	9.7	7.1
7.	जम्मू व कश्मीर	12.9	11.6	13.5
8.	कर्नाटक बोर्ड	5.8	3.9	3.5
9.	केरल	6.8	6.2	5.6
10.	मध्य प्रदेश	7.3	7.0	6.0
11.	महाराष्ट्र	4.3	3.9	3.8
12.	मेघालय	10.8	12.4	15.4
13.	उड़ीसा	8.0	7.9	7.2
14.	पंजाब	6.5	5.6	5.4
15.	राजस्थान	8.4	7.6	7.2
16.	तमिलनाडु	6.6	6.4	5.8

1	2	3	4	5
17.	उत्तर प्रदेश	6.3	5.6	5.1
18.	पश्चिम बंगाल	8.5	8.1	7.9
	सभी बोर्डों का औसत	5.8	5.7	5.2
1.	गोवा	8.2	8.9	7.0
2.	मणिपुर	45.6	41.6	30.9
3.	मिजोरम	34.7	31.0	24.0
4.	नागालैंड	39.1	39.4	34.9
5.	त्रिपुरा	46.7	46.7	38.0
6.	डेसू	5.1	4.4	4.0
7.	पांडिचेरी	6.1	6.1	3.5
	ई० बी० एस० औसत	8.1	7.3	5.7

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कलाकार

2244. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में कलाकारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने कलाकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कलाकारों की अलग सूची नहीं रखी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) जाति-वार ब्यौरा सिर्फ नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही रखा जाता है। तथापि, कलाकारों को नियत कार्य पर (असाइन्मेन्ट) पर तभी रखा जाता है यदि वे अपेक्षित क्षेत्र में प्रतिभा के न्यूनतम स्तर पर खरे उतरते हैं तथा उनको आकाशवाणी के स्वर परीक्षा बोर्ड द्वारा ग्रेड दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार स्वर परीक्षा दे सकता है।

डाक टिकटें जारी करना

2245. **श्री विलासराव नाग नाथ राव गूंडेवार :**

श्री संदीपान भगवान थोरात :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री ललित उरांव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान महान व्यक्तियों के नाम पर विशेष डाक टिकटें जारी करने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान अब तक जारी की गई ऐसी डाक टिकटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन महान व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके नाम पर वर्ष 1993-94 के दौरान स्मारक टिकटें जारी करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) 1993-94 के दौरान अब तक जिन विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक टिकट जारी किए जाने के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1. सत्यजीत राय,
2. दादा भाई नारौजी,
3. फकीर मोहन सेनापति,
4. विलियम कैरे,
5. खान अब्दुल गफ्फार खान,
6. राहुल साकृत्यायन,
7. पी० सी० महालानोबिस,
8. रानी रासमणि,
9. द्वारम वेंकटस्वामी नायडू,
10. दीनानाथ मंगेशकर ।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान 2 दिसम्बर, 1992 तक जारी किए गए
स्मारक/विशेष डाक टिकट

क्र० सं०	विषय	जारी करने की तारीख	मूल्यवर्ग (पैसे)	डाक टिकट की संख्या
1.	कृष्णचन्द्र गजपति	25-4-92	100	1
2.	विजय सिंह पथिक	29-4-92	100	1
3.	हेनरी गिडने	9-5-92	100	1
4	ऊधम सिंह	31-7-92	100	1
5.	डा० एस० आर० रंगनाथन	30-8-92	100	1
6.	हनुमान प्रसाट पोद्दार	19-9-92	100	1
7.	योगी जी महाराज	2-12-92	100	1

असम में करीमगंज में हवाई अड्डा

[अनुवाद]

2246. **श्री द्वारका नाथ दास :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के करीमगंज जिले में एक हवाई अड्डा बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित एयरलाइन्स प्रचालकों से करीमगंज से होकर प्रचालन करने की कोई मांग नहीं आई है।

बिहार में मुख्य डाकघर

[हिन्दी]

2247. **श्री साईमन मरान्डी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मुख्य डाकघरों सहित मुख्यालयों के नाम क्या हैं;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां मुख्य डाकघर स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) शेष जिलों में उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क)

1. औरंगाबाद
2. बांका
3. बेगूसराय
4. बेतिया (पश्चिमी चम्पारण जिला)
5. भागलपुर
6. आरा (भोजपुर जिला)
7. बिहार शरीफ (नालन्दा जिला)
8. बोकारो
9. बक्सर
10. चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम जिला)
11. डालटनगंज
12. दरभंगा
13. बैद्यनाथ देवघर (देवघर जिला)
14. धनबाद
15. दुमका
16. गया
17. गिरिडीह
18. गोपालगंज
19. गुमला
20. हाजीपुर (वैशाली जिला)
21. हजारीबाग
22. जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम जिला)
23. कटिहार
24. मधुबनी
25. मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण जिला)
26. मुंगेर
27. मुजफ्फरपुर
28. नवादा
29. पटना
30. पूर्णिया
31. रांची
32. सासाराम (रोहतास जिला)
33. छपरा (सारण जिला)
34. सहरसा
35. समस्तीपुर
36. सीतामढ़ी
37. सिवान

(ख) बिहार के शेष जिलों में कोई प्रधान डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त "ख" के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नई संचार नीति

[अनुवाद]

2248. श्री प्रफुल पटेल :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री वी० कृष्णा राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री धर्मभिक्षम :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह नीति कब तक तैयार तथा घोषित की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) नीति अभी तैयार की जा रही है।

(ग) इस नीति को अन्तिम रूप देने के बाद इसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

जल के मामलों पर भारत-नेपाल समझौता

[हिन्दी]

2249. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच जल संबंधी सभी बकाया मुद्दों पर समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो भारत निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने में किस सीमा तक सहायता देने पर सहमत हुआ है;

(घ) क्या कारूआली और जल कुंडा परियोजना तथा अन्य बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को

पूरा करने पर भी कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) भारत के प्रधानमंत्री की अक्तूबर, 1992 की नेपाल यात्रा के समय दोनों पक्ष करनाली, पंचेश्वर, सप्त कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला और बागमती परियोजनाओं पर तथा बाढ़ पूर्वानुमान व चेतावनी प्रणाली की स्थापना, बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के निर्माण एवं विद्युत विनिमय पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने व उनकी जांच करने के वास्ते एक समय सीमा पर सहमत हुए। जलकुंडी परियोजना पर कोई करार नहीं हुआ है।

पीलीभीत दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता

2250. **डा० परशुराम गंगवार** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में पीलीभीत दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बरेली में हाल ही में शुरू किए गए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से पीलीभीत जिले के अधिकांश भाग में टी० वी० सेवा प्राप्त करते हैं।

बिहार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2251. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान शेष जिलों में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 525

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 1992-93 के दौरान सभी 50 जिलों में नए एक्सचेंज संस्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार क्षमता

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षमता	क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षमता
1.	औरंगाबाद	1056	27.	खगड़िया	640
2.	भागलपुर	5321	28.	दरभंगा	4334
3.	पटना	41500	29.	मधुबनी	1935
4.	बोकारो स्टील सिटी	4932	30.	मुजफ्फरपुर	6587
5.	धनबाद	11496	31.	समस्तीपुर	979
6.	हजारीबाग	4285	32.	सहरसा	1568
7.	चतरा	248	33.	चंपारन (पू०)	1332
8.	पालामऊ (डाल्टनगंज)	1829	34.	चंपारन (प०)	2034
9.	गरवा	328	35.	मुंगेर	1943
10.	रांची	20918	36.	जमुई	645
11.	गुमला	315	37.	सीतामढ़ी	1616
12.	लोहारदगा	376	38.	पूर्णिया	1684
13.	भबुआ	320	39.	कटिहार	1320
14.	रोहतास	428	40.	अरारिया	1147
15.	बी० देवघर	2268	41.	किशनगंज	769
16.	गुड्डा	2366	42.	सुबौल	888
17.	साहेबगंज	970	43.	मधेपुरा	640
18.	दुमका	2083	44.	सिवान	1478
19.	सिंहभूम (पू०)	12800	45.	गोपालगंज	987
20.	सिंहभूम (प०)	5016	46.	वैशाली	2459
21.	गया	6248	47.	नालंदा	2177
22.	बांका	463	48.	भोजपुर	1409
23.	गिरिडीह	1776	49.	बक्सर	697
24.	जहानाबाद	448	50.	छपरा	2490
25.	नवादा	1600			
26.	बेगूसराय	2880			
	जोड़	13,3269		जोड़	17·4027

विवरण-II

(1992-93 के दौरान खोले जा रहे नए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार सूची

क्रम सं०	जिला	स्थान
1	2	3
1.	पटना	घनरुआ, इस्लामपुर
2.	बिहारशरीफ	सिवाल
3.	जारीबाग	चुरचू, केरेदारी, बहरैंटनगर, गिद्दी, पांडु, बरकोठा, मरकाचो, सतगामा
4.	चतरा	तांडवा, सुलताना, इतकोरी
5.	गिरिडीह	जमुआ, दियरी, गावन, बिरनी, गांदे, पिरटांड
6.	बोकारो स्टीलसिटी	नवादीह, तेनूघाट
7.	गुमला	कोलेबीरा, बानो, चैनपुर, किशनपुर, बसिया, रायडीह, घोघरा
8.	लोहारदगा	तंतनगर
9.	भागलपुर	नरायनपुर, बिहपुर
10.	जमुई	चकई
11.	धनबाद	मुहुदा, इचागढ़
12.	जहानाबाद	घोसी, कुरथा
13.	सीतामढ़ी	मेजरगंज, बथनाहा, ढोंग, बाजपट्टी
14.	गोपालगंज	दिघवा, दिघौली
15.	बट्टिया	बाल्कीकि नगर
16.	मोतीहारी	सिकरहाना
17.	हुमका	नूनीहाट
18.	देवघर	थोरम
19.	गोड्डा	महागामा
20.	साहेबगंज	महाराजपुर
21.	सिवान	जीरादेई
22.	छपरा	मेलदी

1	2	3
23.	बांका	महेशमुंडा
24.	मधुबनी	लदाया
25.	दरभंगा	सिमरी, जलाई, नेहरा
26.	समस्तीपुर	कापन
27.	खगड़िया	मरैया
28.	बेगूसराय	साहेबपुर करमाल
29.	सुपाल	पिपरा
30.	हाजीपुर	चापराकुने
31.	रांची	तंतनगर
32.	जमशेदपुर	पोटका
33.	चाईबासा	जालीडीह
34.	डाल्टनगंज	माहवादरनर गारु
35.	भारवा	बादाम
36.	सासाराम	दिनारा
37.	भभुआ	दौयूवट्टी
38.	बक्सर	राजपुर
39.	आरा	संदेश
40.	औरंगाबाद	बरून
41.	गया	इमामगंज
42.	नवादा	कहवाकोल
43.	पूर्णिया	समौली
44.	अररिया	नरपतगंज
45.	किशनगंज	तुलसिया
46.	मधेपुरा	चौमा
47.	सहरसा	जलखुआ
48.	मुजफ्फरपुर	प्रतापगढ़
49.	मुंगेर	धरहारा
50.	कटिहार	आजम नगर

राजनैतिक दलों द्वारा मैट्रो चैनल का उपयोग

[अनुवाद]

2252. **श्री चित्त बसु :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दलों को प्रस्तावित मैट्रो चैनल का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के बिचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार और गुजरात में राज्य की राजधानियों को एस० टी० डी० सुविधा के साथ जोड़ना

2253. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और गुजरात में ऐसे कौन-कौन से शहर है जिन्हें अब तक एस० टी० डी० सुविधा द्वारा राज्य की राजधानियों से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान यह सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) (i) बिहार में फसरी (बेरमो) और पतरातू

तथा

(ii) गुजरात में नवसारी को अभी तक एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जाना है।

(ख) जी हां।

(ग) (i) संस्थापनाधीन विश्वसनीय माध्यम के चालू होने के बाद, फसरो और पतरातू को 92-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा दिये जाने की सम्भावना है।

(ii) नवसारी के लिए एस० टी० डी० सुविधायुक्त 5000 लाइनों के स्थानीय इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज को मार्च, 1993 तक चालू करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल्को, नाल्को और हिन्डालको का विस्तार

2254. **श्री के० प्रधानी :**

श्री के० पी० सिंह देव :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल्को, नाल्को और हिन्डालको का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संयंत्र पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) इन कार्यक्रमों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इनके विस्तार के बाद प्रत्येक संयंत्र के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) बाल्को और हिन्डालको का विस्तार करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नाल्को का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव पर सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और उसने 970 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर (मई, 1992 के मूल्य स्तर पर) बाक्साइट खान (2·4 मिलियन टन से 4·8 मिलियन टन वार्षिक) और एल्यूमिना रिफाइनरी) 6 लाख टन से 13·5 लाख टन वार्षिक) का विस्तार करने की सिफारिश की है। इस परियोजना के आरम्भ होने की तारीख से 51 महीनो में पूरा होने का अनुमान है।

बिहार में टेलीफोन उपकरणों की कमी

[हिन्दी]

2255. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दूरसंचार केन्द्रों के विभिन्न गोदामों में टेलीफोन उपकरणों और अन्य मदों की कमी पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कमी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित उत्तर को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

225. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :**

श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

डा० कृपासिन्धु भोई :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इस्पात संयंत्र लगाने के लिए कुछ स्थानों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इन स्थानों के नाम क्या हैं और इनको शामिल करने के लिए क्या मान-दण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उनके सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकार द्वारा जारी "लोहा तथा इस्पात उद्योग से सम्बन्धित उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत" से अभिज्ञात हुआ है कि देश में नई लोहा तथा इस्पात परियोजनाएं तथा कोक निर्माण के संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए 25 स्थल उपयुक्त पाए गए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में कहा गया है कि यह केवल एक संकेतात्मक सूची है।

(ख) उन स्थानों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उपर्युक्त स्थानों का पता लगाने में इन प्रमुख कारकों को ध्यान में रखा गया है कच्चे माल की उपलब्धता और स्रोतों से उनकी समीपता, पर्याप्त तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता तथा बिजली, पानी और रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से सम्बद्धता जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता। स्थलों का चयन उद्यमियों के वाणिज्यिक/आर्थिक निर्णय पर छोड़ दिया गया है जिन्हें अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व विस्तृत शक्यता अध्ययन करना पड़ेगा।

विद्युत चाप भट्टी ईकाइयों के लिए किन्ही विशिष्ट स्थानों का पता नहीं लगाया गया है क्योंकि स्क्रैप, स्पंज लोहे, विद्युत और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए इन संयंत्रों के स्थानों के लिए पर्याप्त लोच है।

(ग) से (ङ) इस्पात मंत्रालय ने विभिन्न इस्पात से सम्बन्धित कच्ची सामग्री की उपलब्धता तथा स्रोतों, बिजली की लागत तथा उपलब्धता, कार्यकुशल श्रमिक-शक्ति की उपलब्धता तथा उपयुक्त स्थान-स्थिति, यदि कोई हो, तो इन स्थलों पर बड़े तथा मध्यम इस्पात संयंत्रों के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हों, के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों

से अनुरोध किया था।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडू तथा पंजाब की राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये थे। दिल्ली, अण्डमान और निकोबार तथा चण्डीगढ़ संघ राज्यों ने कहा है कि इन संघ राज्यों में इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते समय उपर्युक्त जानकारी को ध्यान में रखा गया था।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्रा प्रदेश	1. काकीनाडा 2. कोठागुडम
2.	बिहार	1. मनोहरपुर 2. रामगढ़
3.	गोआ	1. गोआ
4.	गुजरात	1. भावनगर 2. दहेज 3. पिपावव
5.	कर्नाटक	1. हासपेट 2. मंगलौर
6.	महाराष्ट्र	1. अलीबाग 2. कुदल 3. सुर्जागढ़
7.	मध्य प्रदेश	1. दैलाडीला 2. विलासपुर 3. दुर्ग 4. गुना 5 रायगढ़ 6. रायपुर
8.	उड़ीसा	1. दैयतारी 2. पारादीप 3. तलचर
9.	उत्तर प्रदेश	1. जगदीशपुर
10.	पश्चिम बंगाल	1. हल्दीया 2. पुरूलिया

नई सिंचाई नीति

[हिन्दी]

2257. श्री नीतीश कुमार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश की सिंचाई के पानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में 113 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए एक नई सिंचाई नीति की घोषणा की है;

(ख) क्या नई नीति के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपने पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई परियोजनाओं को तैयार करने के बाद पानी का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अनेक राज्यों से गुजरने वाली नदियों के पानी को मिलकर उपयोग करने के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि कमान क्षेत्र में उपयुक्त जल प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय जल नीति से भिन्न सिंचाई प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाने के लिए उपाय किए गए हैं। नीति का दबाव जल के इष्टतम प्रयोग के लिए सिंचाई प्रणाली के उपयुक्त प्रबन्ध पर और प्रचालन व अनुरक्षण, संयुक्त प्रयोग, जलनिकास, किसानों की भागीदारी, अनुरक्षण अनुदान जल दरें, प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों पर होगा।

आपात स्थिति में एयर इंडिया के विमानों को उतारना

2258. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एयर इंडिया के विमानों को कितनी बार आपात स्थिति में उतारा गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण एयर इंडिया को कितना नुकसान हुआ; और

(घ) आपात स्थिति में विमानों को उतारने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क)	1989-90	7
	1990-91	3
	1991-92	3

(ख) से (घ) सुरक्षा संबंधी कारणों से दो बार आपात अवतरण करना पड़ गया था। शेष बम्ब की धमकी के कारण किये गए थे।

आपात अवतरण के स्थान पर, यात्रियों और कर्मीदल के जबरदस्ती रुकने के कारण अवतरण और हैंडलिंग प्रभार, भोजन और होटल आवास आदि के कारण एयर इंडिया को राजस्व की कुछ हानि हुई थी। जबकि जांच रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुरक्षा उपायों को उठाकर इन घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते है; यथापि बम्ब रखने की सूचना प्राप्त होने पर आपात अवतरण अनिवार्य और अपरिहार्य हो जाते हैं।

गुजरात को सिंचाई परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

2259. **श्री काशीराम राणा :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने लघु, मध्यम और बृहत् सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए, कितनी वित्तीय सहायता राशि दिए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गुजरात में लघु, मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सहायता हेतु गुजरात सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध, वाह्य सहायता के वास्ते चार लघु सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर, प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं की क्षेत्रवार लागत इस प्रकार है :

		(करोड़ रुपए)
1.	कच्छ	35.76
2.	उत्तर गुजरात	31.44
3.	सौराष्ट्र	145.96
4.	गुजरात	27.35

(ग) इन प्रस्तावों की जांच की गई है तथा आर्थिक कार्य विभाग से और वाह्य सहायता देने की सिफारिश की गयी है।

पिग स्पंज, आयरन और इस्पात का उत्पादन

[अनुवाद]

2260. **प्रो० रीता वर्मा :**

श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में पिग आयरन, स्पंज आयरन और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र में इन संयंत्रों को किन-किन राज्यों में स्थापित करने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) देश में कच्चा लोहा तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और लोहा तथा इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं :—

(i) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से "लोहा और इस्पात" को निकाल दिया गया है और इसे उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता से भी छूट दे दी गयी है। औद्योगिक लाइसेंस केवल तभी प्राप्त करना अपेक्षित होता है जबकि प्रस्तावित संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की 25 कि० मी० की सीमा के भीतर हो।

(ii) लोहा और इस्पात क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार के उद्योगों को साम्य में 51% तक की विदेशी निवेश की स्वतः मंजूरी मिलने की सुविधा है, बशर्ते कि विदेशी साम्य में पूंजीगत माल के आयात की लागत शामिल हो।

(iii) गौण क्षेत्र में लघु इस्पात संयंत्रों के लिए आयातित इस्पात प्रगलन स्क्रैप, प्रमुख कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क 35% से घटा कर 10% कर दिया गया है।

(iv) लोहे और इस्पात के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।

(v) "लोहा और इस्पात उद्योग के उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों" का एक सेट अक्तूबर, 1992 में जारी किया गया था। मार्गदर्शी सिद्धांतों में नीतिगत रूपरेखा, मांग प्रक्षेपण, आवश्यक कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता, संरचनात्मक सुविधाएं, सम्भव स्थानों, देश में विद्यमान प्रौद्योगिकी क्षमताओं, लोह और इस्पात परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति की आवश्यकता आदि के बारे में भावी उद्यमियों के लिए विस्तृत जानकारी दी गयी है।

(ग) और (घ) "लोहा तथा इस्पात उद्योग से संबंधित उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत" से अभिज्ञात हुआ है कि देश में नई लोहा तथा इस्पात परियोजनाएं तथा कोक निर्माण के संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए 25 स्थल उपयुक्त पाए गए हैं। इनमें आन्ध्र प्रदेश में 2, बिहार में 2, गोवा में 1, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 3, मध्य प्रदेश में 6, उड़ीसा में 3, उत्तर प्रदेश में 1 और पश्चिमी बंगाल में 2 शामिल हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में कहा गया है कि यह केवल एक संकेतात्मक सूची है। स्थलों का चयन उद्यमियों के उत्तम वाणिज्यिक/आर्थिक निर्णय पर छोड़ दिया गया है जिन्हें अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व विस्तृत शक्यता अध्ययन कराना पड़ेगा।

विद्युत चाप भट्टी इकाइयों की स्थापना के लिए किन्हीं विशिष्ट स्थानों का पता नहीं लगाया गया है क्योंकि स्क्रैप स्पंज लोहे, विद्युत और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन संयंत्रों के स्थानों के लिए पर्याप्त लोच है ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

2261. **श्री योगानन्द सरस्वती :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की, श्रेणी-वार, इस समय कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 30-9-92 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची के जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) दूर संचार विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) तैयार की है जिसमें निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया है :

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना

—बड़ी टेलीफोन प्रणालियो में प्रतीक्षारत आवेदकों की अधिकतम दो वर्ष तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना

तदनुसार विस्तार योजनाएं बनाई गई हैं ।

विवरण

30-2-92 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची के जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरे

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रतीक्षा सूची		
		ओवाईटी	गैर-ओवाईटी-विशेष	गैर ओवाईटी सामान्य
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	42	24	369
2.	बस्तर	54	30	365

1 2	3	4	5
3. बेतूल	19	7	465
4. भिण्ड	95	76	570
5. भापरी	147	208	7365
6. बिलासपुर	59	294	1834
7. छत्तरपुर	36	45	421
8. छिंदवाड़ा	55	89	977
9. दकोह	8	28	257
10. दतिया	15	10	336
11. देवास	14	79	969
12. धार	50	24	551
13. दुर्ग	442	357	4112
14. गुना	16	51	692
15. ग्वालियर	15	190	6791
16. होशंगाबाद	31	13	1036
17. इन्दौर	1157	1176	28420
18. जबलपुर	131	342	1125
19. झबुआ	4	6	170
20. खण्डुआ	37	56	1327
21. खरगौन	3	28	378
22. काण्डला	4	4	124
23. मंदसौर	5	28	1042
24. मोरेना	2	10	595
25. नरसिंहपुर	5	10	235
26. पन्ना	0		183
27. रायगढ़	0	1	47

1	2	3	4	5
28.	रायपरे	7	76	5252
29.	राजदान	6	2	294
30.	राजगढ़	0	0	107
31.	राजनन्दगांव	70	59	645
32.	रतलाम	6	67	861
33.	वरीवा	82	149	1027
34.	सागर	40	185	1621
35.	सरगुजा	7	47	639
36.	सतना	81	86	1457
37.	सिहोर	0	0	258
38.	सिवनी	19	58	340
39.	शहडोल	10	4	223
40.	शाजापुर	0	0	302
41.	शिवपुरी	15	73	746
42.	सिधी	0	0	130
43.	टिकमगढ़	5	3	128
44.	उज्जैन	54	110	3249
45.	विदिशा	11	43	645

उत्तर प्रदेश में डाक और तार घर

2262. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री राम बदन :

श्री राम सागर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने डाक और तारघर स्थापित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है

और वे कहां-कहां पर स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान खोले गए डाकघरों और तारघरों की संख्या निम्नानुसार है—

	1990-91	1991-92
डाकघर	421	489
तारघर	124	283

(ख) 1992-93 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या 85 है। डाकघरों के स्थान का निर्धारण सर्किल अध्यक्षों द्वारा मांग और औचित्य के आधार पर किया जाता है।

तारघर

1992-93 के दौरान खोले जाने वाले तारघरों की संख्या 50 है और उनके स्थानों का निर्धारण मांग के आधार पर किया जाता है।

बिजली की कमी

[अनुवाद]

2263. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :

श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

श्री गिरधारीलाल भार्गव :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री हाराधन राय :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में बिजली की कमी का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाएंगे; और

(घ) बिजली की उत्पादन लागत तथा पारेषण और वितरण में होने वाले घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्युत की वर्तमान

कमी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्याशित कमी का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) बिजली की मांग तथा पूर्ति के बीच के अन्तराल को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करना, पुरानी यूनिटों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना, प्रचालन तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना तथा ऊर्जा के संवर्धन सम्बन्धी उपाय करना।

(घ) विद्युत उत्पादन लागत तथा पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में ये शामिल हैं—

—बिजली की आनुषांगिक खपत को कम किए जाने के लिए प्रोत्साहन स्कीम

—ईंधन तेल की खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम

—ताप विद्युत केन्द्रों के कुशल कार्य निष्पादन के लिए एक उत्कृष्ट उत्पादकता स्कीम

—बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाए जाने के लिए बिजली अधिनियम, 1910 में संशोधन।

विवरण-I

अप्रैल, 92-अक्तूबर, 92 के दौरान संचयी विद्युत सप्लाई स्थिति

(आंकड़े मि० यू० में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 92—अक्तूबर, 92			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	380	380	0	0.0
दिल्ली	6168	6124	44	0.7
हरियाणा	6770	6608	162	2.4
हिमाचल प्रदेश	869	869	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	1940	1661	279	14.4
पंजाब	11870	11261	609	5.1
राजस्थान	7527	7368	159	2.1

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	18830	16648	2182	11.6
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	54354	50919	3435	6.3
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	14655	14277	378	2.6
मध्य प्रदेश	11759	10692	1067	9.1
महाराष्ट्र	24925	23387	1538	6.2
गोवा	438	438	0	0.0
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	51777	48794	2983	5.8
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	14455	13289	11 6	8.1
कर्नाटक	11660	8850	2810	24.1
केरल	4390	4195	195	4.4
तमिलनाडु	14285	14052	233	1.6
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	44790	40386	4404	9.8
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	4705	2881	1824	38.8
डी० वी० सी०	4395	3323	1072	24.4
उड़ीसा	4790	4102	687	14.3
पश्चिम बंगाल	7065	6551	514	7.3
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	20955	16858	4897	9.5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	95.2	66.5	28.7	30.1
असम	1432.8	1197.7	235.1	16.4
मणिपुर	159.4	128.2	31.1	19.5
मेघालय	153.4	147.6	5.8	3.8
मिजोरम	60.2	46.7	13.5	22.4
नागालैंड	83.8	67.3	16.5	19.7
त्रिपुरा	168.3	131.0	37.3	22.2
जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	2153.0	1785.0	368.0	17.1
अखिल भारत	174029	158742	15287	8.8

विवरण-II

1996-97 के दौरान प्रत्याशित विद्युत सप्लाई स्थिति (8वीं योजना के दौरान 30537.7 मे०वा० का समाकलन कार्यक्रम

क्षेत्र/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	व्यस्ततम-कालीन मांग (मे०वा०)	व्यस्ततम-कालीन मांग (मे०वा०)	अधिशेष/ कमी (मि०यू०)	अधिशेष/ कमी %	ऊर्जा की आवश्यकता (मि०यू०)	ऊर्जा की उपलब्धता (मि०यू०)	अधिशेष/ कमी (मि०यू०)	अधिशेष/ कमी %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	3058	1657	—1401	—45.8	15183	11254	— 929	—25 9
हिमाचल प्रदेश	683	508	—175	—25.7	3254	2831	—423	—13.0
जम्मू व कश्मीर	1202	817	—385	—32.0	5836	7317	1481	25.4
पंजाब	4482	3168	—1314	—29.3	23851	21488	—2363	—9.9
राजस्थान	3851	1980	—1871	—48.6	22232	12463	—9769	—43.9
उत्तर प्रदेश	8263	5793	—2471	—29.9	43957	38712	—5245	—11.9
चंडीगढ़	162	63	—99	—61.2	859	436	—423	—49.2
दिल्ली	2532	2148	—384	—15.2	14416	16275	1859	12.9
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	24234	16968	—7266	—30.0	129587	114188	—15399	—11.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	5487	3802	—1685	—30.7	33645	27645	—6000	—17.8
मध्य प्रदेश	4634	4278	—356	—7.7	28104	26251	—1853	—6.8
महाराष्ट्र	9202	8322	—880	—9.6	58036	52613	—5423	—9.3
गोवा	185	236	51	27.3	932	1960	1028	—110.3
दादर और नगर हवेली	48	7	—42	—86.5	313	54	—259	—82.6
दमन और दीव	31	6	—25	—80.6	130	50	—80	—61.2
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	19587	17111	—2477	—12.6	121159	112417	—8742	—7.2
आन्ध्र प्रदेश	6001	4162	—1839	—30.6	35062	24275	—10687	—30.5
कर्नाटक	4201	3459	—742	—17.7	24188	20228	—3961	—16.4
केरल	2330	1768	—562	—24.1	11293	8322	—3572	—30.0
तमिलनाडु	5351	4071	—1280	—23.9	30528	27786	—2743	—9.0
पांडिचेरी	267	94	—173	—64.9	1519	770	—749	—49.3
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	18150	13892	—4259	—23.5	103191	84173	—19018	—18.4
बिहार	2388	1488	—908	—38.8	12190	10767	—1423	—11.7
उड़ीसा	2495	2359	—136	— 5.5	14919	11856	—3063	—20.5
पश्चिम बंगाल	3229	2473	—756	—23.4	17159	18605	1446	8.4
डी० वी० सी०	2106	2215	109	5.2	11670	15446	3776	32.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	36	51	15	41.0	72	390	318	442.2
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	10254	8828	—1426	—13.9	56011	59125	3114	5.6
अरुणाचल प्रदेश	64	69	5	7.6	199	340	141	71.1
असम	875	913	38	4.3	4264	5619	1355	31.8
मणिपुर	120	72	—48	—39.7	426	391	—35	—8.1
मेघालय	92	222	130	141.0	454	659	205	45.1
मिजोरम	76	38	—38	—50.4	193	198	5	2.4
नागालैंड	53	70	17	31.1	200	372	172	85.9
त्रिपुरा	108	101	—7	—6.7	432	492	60	13.8
जोड़ (उत्तर-पूर्वी	1388	1587	199	14.3	6169	8601	2432	39.4
क्षेत्र) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	39	15	—24	—61.9	140	105	—35	—24.9
लक्षद्वीप	4	3	—1	—22.4	17	18	1	6.8
अखिल भारत	73656	58403	—15253	—20.7	416274	378626	—37648	—9.0

टिप्पणी : आवश्यकताएं, 14वीं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हैं।

विद्युत उत्पादन

2264. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

डा० लाल बहादुर रावल :

श्री नीतीश कुमार :

श्री सुकदेव पासवान :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में विद्युत उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक महीने कितना कम हुआ और इसके क्या कारण थे; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल—सितम्बर, 92 के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों के सन्दर्भ में बिजली की कमी/अतिरेक उत्पादन की मात्रा का महीनेवार विवरण नीचे दिया गया है—

	कमी (—) विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों के संदर्भ में (मिलियन यूनिट)
अप्रैल, 92	*338
मई, 92	—935
जून, 92	—1171
जुलाई, 92	—1005
अगस्त, 92	—876
सितम्बर, 92	+78
अप्रैल, 92—सितम्बर, 92	—3571

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का ईष्टतम समुपयोजन किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—(1) पुरानी यूनिटों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना (2) संयंत्र

*देश में बिजली का कम उत्पादन होने का मुख्य कारण ताप विद्युत केन्द्रों को विशेषतौर पर वर्ष की पहली तिमाही में कोयले की कम सप्लाई होना है ।

सुधार कार्यक्रम चलाए जाने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना (3) अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना (4) प्रचालन तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (5) पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना।

लौह अयस्क की खरीद

2265. **डा० कृपासिंधु भोई :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० एम० डी० सी० ने अनारक्षित खानों से लौह अयस्क की खरीद में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान एन० एम० डी० सी० द्वारा उड़ीसा में इसकी अनारक्षित खानों से कुल कितने लौह अयस्क का उत्पादन करने का प्रस्ताव है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 1992-93 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन० एम० डी० सी०) देश में अनारक्षित खानों से लौह अयस्क नहीं खरीदता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन निगम की बिल प्रणाली

2266. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से यह पाया गया है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बिल प्रणाली (बिलिंग सिस्टम) "मनमानी और स्वैच्छिक" है और इस क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है;

(ख) क्या इस अध्ययन के अनुसार छूट सम्बन्धित अधिकारी की पक्षपातपूर्ण दृष्टि के अनुसार उसकी अटकलबाजी के आधार पर दी जाती है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बिल प्रणाली में कई अन्य त्रुटियां भी दर्शायी गई हैं;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के कार्यक्षेत्र में बिलिंग प्रणाली शामिल नहीं थी बल्कि अधिक

राशि के बिलों को ठीक करने की प्रक्रिया तक ही उसका कार्य क्षेत्र सीमित था। इस अध्ययन रिपोर्ट में इस प्रक्रिया पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ कई सुझाव भी दिए गए हैं। अधिक बिलिंग की शिकायतों को निपटाने के लिए निर्धारित विभिन्न कार्य विधियों को अपनाने और जांच करने के बाद, जहां कहीं उचित पाया जाता है वहां अलग-अलग मामलों में रियायतें दी जाती हैं।

(ग) क्योंकि यह अध्ययन बिलिंग प्रणाली से सम्बन्धित नहीं है, अत: बिलिंग प्रणाली के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में किसी प्रकार की कमियां नहीं बताई गई हैं।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

मुम्बई में एलीफेन्टा गुफाओं में बारहमासी जैटी

2267. **श्री अनन्तराव देशमुख** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मुम्बई में एलीफेन्टा गुफाओं में एक नई बारहमासी जैटी के निर्माण के लिए सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई में एलीफेन्टा गुफाओं के लिए सभी मौसमों के लिए जैटी के निर्माण हेतु पहले 1.54 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्त सहायता के लिए अनुरोध किया था। तथापि, केन्द्र सरकार वित्तीय दिक्कतों के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकी।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विलय

2268. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) सरकार ने सिद्धांत रूप में, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करने का निर्णय लिया है। विलय की कार्यविधि तैयार की जा रही है। कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—

(1) एकल प्राधिकरण द्वारा बेहतर समन्वय।

(2) हवाई यातायात नियन्त्रण और संचार प्रणाली सहित सभी पहलुओं की दृष्टि से हवाई अड्डे की आधारभूत सुविधाओं के एकीकृत विकास के संवर्धन के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग ।

(3) एकल प्राधिकरण के दक्ष प्रबन्ध द्वारा अधिक राजस्व का अर्जन ।

(4) हवाई अड्डे के डिजाइन में विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग और सुधरी हुई कार्य-कुशलता के लिए प्रबंधन के संसाधनों को सुनियोजित करना ।

"इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम" का आयात

2269. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख हवाई अड्डों पर "इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम" लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान "इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम" कतिपय विमानों के लिए सहायक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या आधुनिक "इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम" आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जेट विमानों द्वारा उपयोग किए गए हवाई अड्डों पर उपस्कर अवतरण प्रणाली की व्यवस्था की जाती है यदि मौसम या भू-भाग की स्थिति को उसकी आवश्यकता होती है ।

(ख) मौजूदा उपस्कर अवतरण प्रणाली सभी विमानों के लिए उपयोगी होती है बशर्ते कि ये अनुकूल उडानगत उपकरणों से सुसज्जित हों ।

(ग) तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हो जाता है ।

(घ) आयात किए जा रहे उपस्कर अवतरण प्रणाली के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

योजना	हवाई अड्डे का नाम	अनुमानित लागत
8 आई०एल०एस०	(क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और नागपुर में प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित किया जाना है।	15.021 करोड़ रु०
	(ख) औरंगाबाद, इन्दौर, कोयम्बतूर, और कालीकट हवाई अड्डों पर नई सुविधा के रूप में स्थापित किया जाना है ।	

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा
टेलीफोन डायरेक्टरियों हेतु ठेके

2270. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री धर्मण्णा मोंड्या सावुल :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री मनोरंजन भक्त :

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन हेतु ठेके देने के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने पिछले चार वर्षों के दौरान टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन हेतु ठेके देने में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक बार इनका पालन न करने के क्या कारण हैं;

(घ) इन दिशा निर्देशों का पालन न करने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसके फलस्वरूप निगम को पिछले चार वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और न्यायाधीन है।

महाराष्ट्र में बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

2271. **श्री विजय एन० पाटिल :**

श्री कमल चौधरी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय चल रही बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक से कितनी परियोजनाओं को सहायता मिल रही है और आठवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) लागत अधिक होने तथा अधिक समय लगने को रोकने के लिए उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं और महाराष्ट्र में आठवीं योजना के अन्त तक कितनी सिंचाई क्षमता के बढ़ जाने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आठवीं योजना (1992—97) तथा वार्षिक योजना (1992-93) प्रस्तावों के अनुसार, 7162.45 करोड़ रुपये की नवीनतम अनुमानित लागत की 38 वृहद सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें 21.55 लाख हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गई है तथा 1053.46 करोड़ रुपये की नवीनतम लागत की 73 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें 3.37 लाख हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गई है, पर कार्य पूर्ण होने के विभिन्न स्तरों पर है।

(ख) देवगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसमें 8347 हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है, को नवम्बर, 1992 में 24.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई है।

(ग) महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई-III परियोजना के रूप में महाराष्ट्र में जायकवाड़ी और माजलगांव सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र विकास कार्यों के लिए स्पेशल ऋण ड्राईंग राईट्स के अन्तर्गत 164.2 मिलियन की विश्व बैंक सहायता प्राप्त की जा रही है। ऋण जो मार्च, 1986 से जून, 1991 तक प्रभावी था, 31-12-1992 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) विश्व बैंक ने हाल ही में सिद्धान्ततः पुनर्निर्मित महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई-III परियोजना के अन्तर्गत, पहले महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई-II परियोजना के तहत शामिल कुकाडी, भीमा, कृष्णा और अपर पेनगंगा परियोजनाओं के शेष कार्यों को शामिल करने के वास्ते अनुमोदन प्रदान कर दिया है ताकि निधियों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। योजना आयोग के कार्यदल ने आठवीं योजना के दौरान 12 बृहद और 50 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त परिव्यय की सिफारिश की है। आठवीं योजना में महाराष्ट्र के लिए 4.00 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य नियत किया गया है।

दिल्ली में आवश्यक टेलीफोन सेवा

2272. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक उपयोग के टेलीफोन नम्बर 197, 198 और 199 सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी सेवाओं को सन्तोषजनक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। डायरेक्टरी पूछताछ (197) तथा दोष मरम्मत सेवा (198) पर उपलब्ध सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक हैं।

(ख) डायरेक्टरी पूछताछ (.97) तथा स्थानीय सहायता (199) सेवाएं दिनांक 5 मई,

92 को किदवई भवन में लगी भीषण आग के परिणामस्वरूप पूर्ण रूपेण अस्त-व्यस्त हो गई थी।

वैसे डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा (197) को सामान्य स्तर तक बहाल कर दिया गया है परन्तु स्थानीय सहायता सेवा (199) की 80 पोजीशनों में से केवल 30 पोजीशनें ही अब तक चालू की जा सकी हैं और इस सेवा को आंशिक रूप से पुनः बहाल किया गया है।

(ग) सेवाओं में आगे और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा (197)

प्रत्युत्तर समय कम करने के लिए कम्प्यूटर तथा सम्बन्ध साफ्टवेयर का उन्नयन।

दोष मरम्मत सेवा (198)

सभी मुख्य एक्सचेंज केन्द्रों के लिए सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

स्थानीय सहायता (199)

आग लगने से पूर्व लेवल से अधिक पोजीशनों की संख्या में वृद्धि करना। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय नेटवर्क में अत्यन्त उच्च सफल काल दरों को देखते हुए इस सेवा की आवश्यकता अपेक्षाकृत घटी है।

मनीआर्डर भेजने के लिए फैक्स योजनाएं

2273. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीआर्डर भेजने के लिए फैक्स योजनाओं का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को विद्युत आपूर्ति

2274. **डा० सुधीर राव** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा विभिन्न राज्यों को बिजली किस दर पर दी जा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकारें ली गई बिजली के लिए पूरा भुगतान करती हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में डाक और तार सेवा

[हिन्दी]

2275. **श्री राम कापसे :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के थाणे जिले में डाक और तार सेवा संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेवा में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डाक और तार सेवाएं संतोषजनक हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ठाणे जिले में डाक और तार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

डाक सेवाएं

(i) इस क्षेत्र में सेवा का स्तर सुधारने के लिए डाक वितरण व पारेषण की निरंतर मानीटरिंग की जाती है।

तार सेवाएं

(ii) ठाणे जिले के सभी तारघर नेशनल स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग नेटवर्क से जोड़ दिए गए हैं। कल्याण के तारघर में एक लघु कम्प्यूटर पर आधारित टेलीग्राफ मैसेज स्विच सुलभ कराया गया है।

किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय :

(iii) डांडेकरवाड़ी में एक स्वतंत्र तारघर खोलना : भयंदर, विरार, डांडेकरवाड़ी, पालघर, दहानू रोड तथा बोइसार में प्रत्येक एक-एक अर्थात 6 दूरसंचार केन्द्र खोलना, भयंदर, पालघर, दहानु रोड तथा बोइसार के संयुक्त डाक-तारघर में टेलीप्रिंटर कार्यप्रणाली आरम्भ करना तथा मोर्स प्रणाणी को चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रानिक की बोर्ड में बदलना।

महाराष्ट्र में टंगस्टन का खनन

2276. **श्री तेजसिंह राव भोंसले :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पता लगाए गए टंगस्टन के विशाल भंडारों के खनन

हेतु तकनीकी/आर्थिक सम्भाव्यता का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम० ई० सी० एल०) द्वारा खोबना, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) में किए गए पूर्व साध्यता अध्ययन से 313% डब्ल्यू० ओ० युक्त टंगस्टन अयस्क के 3,362 मिलियन टन भंडार की पुष्टि की गई है। हिन्दुस्तान जिंक लि० (एच० जेड० एल०) जो इसका विदोहन करने में रुचि रखता है, उसने इस क्षेत्र के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है।

कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन बिल

[अनुवाद]

2277. **श्री जी० माडे गौडा** :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पब्लिक टेलीफोन बूथों में एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/स्थानीय टेलीफोन कालों के लिए कम्प्यूटरीकृत बिल शुरू करने के लिए संचार विभाग को कोई मार्ग निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन राज्यों में अब तक कम्प्यूटरीकृत बिल प्रणाली शुरू नहीं की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सरकार द्वारा पब्लिक टेलीफोन बूथों में एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/स्थानीय कालों के लिए कम्प्यूटरीकृत बिल शुरू करने के सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग को कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरीय जिलों को छोड़कर, बूथ होल्डरों के पब्लिक टेलीफोन बूथों के एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/स्थानीय कालों के लिए मैनुअल रूप से तैयार किए जाते हैं।

सिंचाई क्षमता तथा इसके उपयोग में अन्तर

2278. **श्री बापू हरि चौरे** :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई क्षमता तथा इसके उपयोग में बहुत अधिक अन्तर है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस अन्तर पर निगरानी रखने तथा उसको कम करने के लिए किसी एजेंसी की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद तथा संसाधन प्रबन्ध एवं आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली जैसे संस्थानों द्वारा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करके सिंचाई क्षमता के सृजन और इसके उपयोग पर ध्यान देते हुए कुछ अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से पता चला है कि सिंचाई क्षमता के उपयोग में धीमी प्रगति के मुख्य कारण के रूप में सिंचाई जल की आपूर्ति में निश्चितता की कमी है। अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कारणों में ये शामिल हैं (I) आन फार्म विकास कार्य-कलापों का धीमा प्रसार (II) प्रत्येक वर्ष सृजित की गई क्षमता को शामिल करना तथा (III) परियोजना तैयारी के समय विद्यमान फसल पद्धतियां और प्रोजेक्टिड फसल पद्धतियों के बीच अन्तर।

(घ) और (ङ) कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के समक्ष नियंत्रण और निर्देशन में एक बहु-विषयक दल द्वारा महत्वपूर्ण विकास के लिए जल, फसल और भूमि सामंजस्य के डायनेमिक तरीके का प्रबन्ध किया जाना था। इस समय इस कार्यक्रम के संचालन के लिए ऐसे 54 प्राधिकरण हैं। कुछ राज्यों में जहां ये प्राधिकरण स्थापित नहीं किए गए हैं, सरकारी विभागों द्वारा सीधे ही इन कार्य-कलापों को शुरू किया गया है।

केरल में "शार्ट वेव" का आकाशवाणी केन्द्र

2279. **श्री पी० सी० थामस** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में "शार्ट वेव" आकाशवाणी केन्द्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रस्तावित केन्द्र से केरल से प्रसारित होने वाले मलयालम कार्यक्रम को देश के सभी भागों में सुना जा सकेगा;

(ग) क्या इस प्रकार के "शार्ट वेव" केन्द्र अन्य राज्यों से भी क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम में 50 कि० वा० शा० वे० क्षेत्रीय शा० वे० ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना है। इसके शुरू हो जाने पर यह स्टेशन समस्त केरल राज्य में और कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में सेवा प्रदान

करेगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जहां क्षेत्रीय शार्ट वेव ट्रांसमीटर चालू हैं उन स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

क्र० सं०	नाम
1.	ऐजवाल
2.	भोपाल
3.	बम्बई
4.	कलकत्ता
5.	दिल्ली
6.	गुवाहाटी-1
7.	गुवाहाटी-2
8.	हैदराबाद
9.	जम्मू
10.	कोहिमा
11.	कुर्सियांग
12.	लेह
13.	लखनऊ
14.	मद्रास
15.	पोर्ट ब्लेअर
16.	रांची
17.	शिलांग
18.	शिमला
19.	श्रीनगर

पेंच परियोजना

2281. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेंच डायवरशन परियोजना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निर्माण लागत और इसे पूरा करने में लगने वाले समय का ब्यौरा दें; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता की राशि क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इस परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा इसे लगभग 184 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अक्तूबर, 1988 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है, बशर्ते कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की जाए। परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना के बाद, इस परियोजना को निवेश स्वीकृति के लिए फरवरी, 1991 में योजना आयोग को भेजा गया है। निवेश स्वीकृति राज्य के पास समग्र संसाधन उपलब्धता और उसके द्वारा निश्चित की गई क्षेत्र संबंधी प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इस स्कीम को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है।

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

5282. **श्री संदीपन भगवान थौरात** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत संयंत्रों के आमूल नवीकरण और आधुनिकीकरण पर प्रत्येक राज्य में संयंत्र-वार अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि खर्च दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन के उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मार्च, 1992 तक चरण-1 तथा चरण-2 कार्यक्रमों के अन्तर्गत ताप विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण करने पर क्रमशः 852·93 करोड़ रुपये एवं 27·61 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। राज्यवार/संयंत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, चरण-1 तथा चरण-2 कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि क्रमशः 9·96 करोड़ रु० तथा 94·23 करोड़

रुपये हैं ।

(ग) से (ङ) चरण-1 कार्यक्रम की केन्द्रीय ऋण सहायता निधि के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों के आधुनिकीकरण कार्य संतोषजनक रहे हैं। चरण-1 तथा चरण-2 कार्यक्रमों के अपने संसाधनों/राज्य आयोजना के अंतर्गत आने वाले नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों की प्रगति अपेक्षित स्तर की नहीं रही है। धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं—राज्य सरकारों द्वारा बिजली बोर्डों को पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध न कराया जाना, दीर्घकालिक कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु दीर्घकालिक शट-डाउन अपेक्षित होना, सामग्री की देर से उपलब्धता आदि। पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के फेज-I के अन्तर्गत राज्य योजना/स्वयं के संसाधनों के तहत कुछ प्रमुख नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यकलापों और द्वितीय चरण नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख भाग हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है।

विवरण

चरण-1 तथा चरण-2 कार्यक्रमों के अन्तर्गत ताप विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर मार्च 1992 तक संयंत्रवार व्यय की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/ताप विद्युत केन्द्र का नाम	मार्च 1992 तक व्यय की गई कुल राशि	
		चरण-1 कार्यक्रम के अन्तर्गत	चरण-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9433·78	220·00
	1. कोठागुडम	8993·68	210·00
	2. नेलोर	*	10·00
	3. रामागुण्डम	440·10	**
2.	असम	799·68	63·00
	4. नामरूप	799·68	शून्य
	5. बोंगाईगांव	*	63·00
3.	बिहार	6408·09	शून्य
	6. पतरातू	4297·14	शून्य
	7. बरानी	1644·15	शून्य

1	2	3	4
	8. करबीगाहिया	466·89	**
4.	**गुजरात**	**4755·16**	**126·89**
	9. गांधी नगर	1685·59	16·20
	10. घबरन	1557·68	44·51
	11. उकाई	1511·89	61·38
	12. वानकबोरी	*	4·80
5.	**हरियाणा**	**3304·38**	**7·31**
	13. फरीदाबाद	2217·32	7·31
	14. पानीपत	1087·06	शून्य
6.	**मध्यप्रदेश**	**5661·85**	**91·70**
	15. अमरकंटक	952·90	15·00
	16. कोरबा (पूर्वी)	1608·61	71·00
	17. सतपूड़ा	3100·34	5·70
7.	**महाराष्ट्र**	**3476·66**	**232·20**
	18. कोरडी	2745·81	14·71
	19. नाशिक	573·66	45·47
	20. भूसवाल	70·35	23·31
	21. पारस	86·84	शून्य
	22. चन्द्रापुरा	*	139·65
	23. पारली	*	9·06
8.	**उड़ीसा**	**2966·06**	**28·00**
	24. तलचर	2966·06	28·00
9.	**पंजाब**	**4232·86**	**शून्य**
	25. भटिण्डा	4232·86	शून्य
10.	**राजस्थान**	—	**799·25**
	26. कोटा	*	799·25

1	2	3	4
11.	**तमिलनाडु**	**14460·56**	**267·00**
	27. एन्नोर	13608·52	105·00
	28. तूटिकोरिन	852·04	162·00
12.	**उत्तर प्रदेश**	**9651·88**	**11·73**
	29. ओबरा	3036·34	10·00
	30. पाकी	3050·66	1·73
	31. हरदऊगंज	3564·88	शून्य
13.	**पश्चिम बंगाल**	**4727.81**	**38·00**
	32. सांयालडीह	1639·61	शून्य
	33. बाडेल	1313·32	शून्य
	34. दुर्गापुर (डी पी एल)	1774·88	16·06
	35. कालाघाट (डब्ल्यू बी पी डी सी)	*	21·94
14.	**डेसू**	**4676·73**	**83·19**
	36. इन्द्रप्रस्थ स्टेशन	4676·73	83·19
15.	**डी० वी० सी०**	**4503·92**	**793·15**
	37. चन्द्रापुर	3321·46	517·90
	38. बोकारो	653·54	शून्य
	39. दुर्गापुर	528·92	275·25
16.	**एन० एल० सी०**	**3188·91**	शून्य
	40 नेवेली	3188·81	शून्य
17.	**एन० टी० पी० सी०**	**3045·09**	शून्य
	41. बदरपुर	3045·09	शून्य
	योग	85293.32	2761·42

* चरण-1 के अन्तर्गत शामिल नहीं है .

** चरण-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं है ।

उड़ीसा में पत्रों का वितरण

2283. **श्री के० पी० सिंह देव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** उड़ीसा में, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में पत्रों के वितरण में काफी समय लग रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अनियमितताओं को रोकने तथा पत्रों का वितरण शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) दूर-दराज के पहाड़ी और जनजातिय-क्षेत्रों में डाक-वितरण में यदा-कदा विलम्ब की कुछ घटनायें ध्यान में आई हैं।

(ख) यह विलम्ब सीमित रेल नेटवर्क, प्राइवेट और राज्य सड़क परिवहन की बसों के न चलने या फिर उनके चलने न चलने की अनिश्चितता के कारण परिगमन में होता है।

(ग) पश्चिमी क्षेत्र में विलम्ब को 3 दिन से घटाकर 2 दिन करके और प्राइवेट मेल कैरियर्स से अनुबंध करने में परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में कुल मिलाकर सुधार करके डाक वितरण में तेजी लाई गई है। बेहतर परिवहन सेवाएं प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के उच्चतम स्तर के अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

टेली फिल्मों के स्तर में गिरावट

[हिन्दी]

2284. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा निर्मित टेली-फिल्मों के स्तर में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो टेली-फिल्मों के स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि दूरदर्शन का सतत यह प्रयास रहता है कि वह टेलीफिल्में सहित अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखे और उनमें सुधार भी करता रहे।

पर्वतीय क्षेत्रों में कुल सिंचित भूमि

2285. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई जाएगी; और

(ख) पर्वतीय राज्यों के लिए आठवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्रों में कोई वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है । पहाड़ी क्षेत्रों में केवल लघु सिंचाई स्कीमें शुरू की जाती हैं, जिनकी आयोजना, वित्तपोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इसलिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

तथापि, इन क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मुक्त की गई राशि वास्तविक व्यय पर निर्भर करती है जिसका पता आठवीं योजना बनने के बाद ही चल पायेगा ।

महाराष्ट्र में जलगांव हवाई अड्डे का निर्माण

2286. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जलगांव हवाई अड्डे के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जलगांव हवाई अड्डे, जो कि महाराष्ट्र सरकार का है, के उन्नयन की कोई योजना नहीं है ।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब होना/उनका रद्द होना

2287. **श्री मदन लाल खुराना** :

प्रो० के० वी० थामस :

डा० राजगोपालन श्रीधरण :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 से अक्तूबर, 1992 तक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत के डिवीजन-वार विमानों की कितनी उड़ानें विलम्बित हुईं/रद्द हुईं और इन विमानों की उड़ानों को न्यूनतम एवं अधिकतम कितने समय तक विलम्बित किया गया/रद्द किया गया तथा उक्त स्थिति के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या जून, 1992 में दिल्ली में कई विमानों की उड़ानें रद्द हुईं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क)	कुल उड़ानों की संख्या	विलम्बित उड़ानें	रद्द की गई उड़ानें
एयर इंडिया	22958	2666	356
इंडियन एयरलाइन्स	129616	33928	7703
वायुदूत	9602	1992	788

एयर इंडिया के मामले में विलम्ब 30 मिनट से 3 घंटे के बीच हुआ। रात्रि ठहराव, कर्मीदल ड्यूटी समय-सीमाएं इंजिन को बदलने आदि जैसे आपवादिक मामलों में विलम्ब का समय 12 घण्टे से भी अधिक रहा।

इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत के मामले में आंकड़े 14/15 मिनट से अधिक विलम्ब पर आधारित है। ये विलम्ब मुख्य रूप से तकनीकी, प्रचालनात्मक एवं इंजीनियरी कारणों, खराब मौसम बम की धमकी, पक्षियों के टकराने, धावन-पथ की मरम्मत आदि जैसे कारणों से हुये।

(ख) दिल्ली में जून, 1992 के दौरान विलम्बित उड़ानों की संख्या निम्न प्रकार है—

	कुल	विलम्बित
एयर इण्डिया	251	72
इंडियन एयरलाइन्स	897	286
वायुदूत	205	28

(ग) उड़ानों में विलम्ब/रद्द करने की घटनाओं से बचने के लिए समय पर उड़ानों की कड़ी निगरानी रखने, बार-बार होने वाली खराबियों को ठीक करने, समयावलियों को युक्तिसंगत बनाने, पर्याप्त कल-पुर्जों के रख-रखाव आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

बंगलौर से मालवाहक जहाजों की उड़ानें

[अनुवाद]

2288. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे से मालवाहक जहाजों की अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयर इंडिया पहले से ही बंगलौर से मालवाहक की सीधी उड़ानों का परिचालन करता है। इसके अतिरिक्त,

इंडियन एयरलाइंस, लुफ्थान्सा कुवैत एयरलाइन आदि बंगलौर से भी सामान उठाती हैं। कार्गो परिचालन के लिए "ओपन स्काई नीति" का पालन किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रचालक मांग के अनुसार सेवा बढ़ाते हैं।

समुद्र-दीवार के निर्माण के लिए केरल को सहायता

2289. **श्री थाइल जान अंजलोज :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से समुद्री कटाव को रोकने हेतु समुद्र-दीवार का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) और (ख) केरल सरकार ने समुद्री कटाव को रोकने के लिए लगभग 193.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 123.6 कि० मी० लम्बी नई समुद्री दीवारें और पुरानी समुद्री दीवारों के 73.72 कि० मी० लम्बे सुधारात्मक कार्यों के निर्माण हेतु केन्द्रीय ऋण सहायता देने के वास्ते नवम्बर, 1992 में अनुरोध किया है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिसम्बर, 1991 में आयोजित की गई बैठक के निर्णय के अनुसार वर्ष 1991-92 से समुद्रवर्ती राज्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता बन्द कर दी गई है।

[हिन्दी]

डेहरी पन बिजली परियोजना

2290. **श्री रामलखन सिंह यादव :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में डेहरी पन बिजली परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बिहार में देहरी के समीप दो जल विद्युत परियोजनाएं नामशः सोन पश्चिमी नहर (4×1.65 मेगावाट) तथा सोन पूर्वी नहर (2×1.65 मेगावाट) इस समय निर्माणाधीन हैं। सोन पश्चिमी नहर जल-विद्युत परियोजना की यूनिट I, II व III तथा IV को क्रमशः दिसम्बर, 1992 तथा जनवरी, 1993 के अन्त तक रोटेट किए जाने की प्रत्याशा है। सोन पूर्वी नहर की दो यूनिटों को 1993-94 के दौरान चालू कर दिए जाने की सम्भावना है।

परियोजना प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श तथा परियोजना स्थलों का भ्रमण करके परियोजना के क्रियान्वयन की सघन रूप से मानीटरिंग की जाती है।

डाक एवं तार पेंशनभोगियों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा

[अनुवाद]

2291. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक एवं तार के पेंशन भोगियों को राज्य/केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों द्वारा वहीं अन्तरंग चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, जो नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों को दी जाती हैं और जिसमें आन्तरिक चिकित्सा सुविधा के मामले में चिकित्सा शुल्क की वापसी भी शामिल है;

(ख) क्या पुणे की अखिल भारतीय डाक एवं तार पेंशन भोगी एसोसिएशन ने उन्हें इस संबंध में कोई अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) उन्हें यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) डाक-तार पेंशनर्स को डाक-तार डिस्पेंसरी में बहिरंग चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं लेकिन उन्हें अन्तरंग चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं। दूसरी ओर डाक-तार पेंशनर्स सहित केन्द्रीय सरकार के ऐसे सभी पेंशनर्स जो उन शहरों में रह रहे हैं जहां सी०जी०एच०एस० की सुविधाएं हैं, अन्तरंग/बहिरंग/परामर्श संबंधी (रैफरल) चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) डाक-तार पेंशनर्स को अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सी० एस० (एस० ए०) (सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेन्डेंस) नियमावली में संशोधन अपेक्षित है और माननीय संचार राज्य मंत्री ने यह मामला पहले ही माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ उठाया हुआ है। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने अपने उत्तर में यह बताया है कि पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने जो अन्तर-विभागीय समिति गठित की है, उसने सी० जी० एच० एस० का पूरे देश में और अधिक शहरों/क्षेत्रों तक विस्तार करने की पहले ही सिफारिश की है तथा यह मामला पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच अभी भी विचाराधीन है। चूंकि, इस सम्बन्ध में अनेक सरकारी विभागों के साथ परामर्श करके कुछ कार्य-प्रणालियां तय की जानी हैं और इसमें काफी अधिक वित्तीय खर्च भी शामिल है, इसलिए इस मसले को निपटाने में कुछ और समय लगने की संभावना है। इस प्रकार, कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

[हिन्दी]

2292. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की टेलीफोन लाईनों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक एक्सचेंज की कितनी क्षमता बढ़ाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31 अक्तूबर, 1992 तक की स्थिति इस प्रकार है :

संस्थापित क्षमता—	364355 लाइनें
इस्तेमाल की जा रही क्षमता	2,92545 लाइनें

(ख) इनमें से कई एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1992-93 के दौरान जिन छोटे और मध्यम आकार वाले एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है उनकी सूची

एक्सचेंजों का नाम	जिला	वर्तमान क्षमता	प्रस्तावित विस्तार	लाइनों की संख्या (निवलम्बित)
1	2	3	4	5
बालाघाट	बालाघाट	1160	1000 लाइनें सी-डाट	1000
जगदलपुर	बस्तर	1188	1000 लाइनें सी-डाट	1000
कोंडागांव	बस्तर	200	512 आई०एल०टी०	184
कांकेर	बस्तर	320	512 आई०एल०टी०	64
बेतुल	बेतूल	806	1000 लाइनें सी-डाट	1000
तुलताज	बेतूल	256	512 आई०एल०टी०	128
भिंड	भिंड	752	1000 लाइनें सी-डाट	1000
मालनपुर	भिंड	176	512 आई०एल०टी०	208
देरसिया	भोपाल	176	512 आई०एस०टी०	208
कोरबा (+बाल्को)	बिलासपुर	1208	1.4 के० सी-डाट	192

1	2	3	4	5
दरीं	बिलासपुर	240	512 सी-डाट	160
चम्पा	बिलासपुर	300	512 आई०एल०टी०	84
पेन्डारा रोड	बिलासपुर	200	512 आई०एल०टी०	184
शक्ति	बिलासपुर	220	512 आई०एल०टी०	164
मुंगेली	बिलासपुर	240	512 आई०एल०टी०	144
नाजला	बिलासपुर	256	512 आई०एल०टी०	128
बिलासपुर	बिलासपुर	5488	0.4 के० सी-डाटा	400
नौगांव	छतरपुर	200	512 आई०एल०टी०	184
खजुराहो	—वही—	192	512 आई०एल०टी०	192
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	1132	1 हजार लाइनेंसी-डाटा	1000
पांठरना	—वही—	600	1000 लाइनें सी-डाटा	400
परसिया	—वही—	600	1000 लाइनें सी-डाटा	400
सोसार	—वही—	250	512 सी-डाट	150
दत्ता	दमोह	216	512 आई०एल०टी०	168
दत्ता	दतिया	488	512 आई०एल०टी०	400
सोनकूच	दतिया	256	512 आई०एल०टी०	128
कन्नोड	दतिया	256	512 आई०एल०टी०	128
खातेगांव	दतिया	256	512 आई०एल०टी०	128
धार	धार	856	1000 लाइनें सी-डाट	1000
धामनोड	धार	472	512 आई०एल०टी०	384
कुकशी	धार	256	512 आई०एल०टी०	128
राजगढ़	धार	256	512 आई०एल०टी०	128
घटाबिल्लोत	धार	256	512 आई०एल०टी०	128
महावर	धार	256	512 आई०एल०टी०	128
दुर्ग+भिलाई	दुर्ग	3764	5. के० ई-10बी	1236
डल्लीजारा	दुर्ग	176	512 आई०एल०टी०	208

1	2	3	4	5
गुना	गुना	1276	1.4 के०सी-डाट	1400
अशोकनगर	गुना	600	512 आई०एल०टी०	384
विजयपुर	गुना	192	512 आई०एल०टी०	192
डबरा	ग्वालियर	700	512 सी-डाट	400
ग्वालियर	ग्वालियर	17000	2के०ई-10	2000
पिपरिया	होसंगाबाद	640	1.4 के० सी-डाट	760
होसंगाबाद	—वही—	936	1.4 के० सी-डाट	464
पचमढ़ी	—वही—	192	512 सी-डाट	208
तिमारंज	—वही—	192	512 आई०एल०टी०	192
बाणपुरा	—वही	256	512 आई०एल०टी०	128
खिरकिया	—वही—	256	512 सी-डाट	144
बम्बई	—वही—	176	512 सी-डाट	224
इंदौर	इंदौर	47800	20 के० नई प्रो०	20000
मऊ	इंदौर	900	1.4 के सी-डाट	1400
मंगलिया	इंदौर	90	1 कैसी-डाट	910
बेटमा	इंदौर	176	512 के०सी०-डाट	224
सांवर	इंदौर	88	512 आई०एल०टी०	296
सिमराल	इंदौर	88	512 आई०एल०टी०	296
गांधीनगर	इंदौर	88	512 आई०एल०टी०	296
राऊ	इंदौर	400	512 आई०एल०टी०	384
सिहौरा	जबलपुर	256	512 आई०एल०टी०	128
कटनी	जबलपुर	1700	512 सी-डाट	400
अलीराजपुर	जबुआ	384	512 आई०एल०टी० (ई)	384
तेलताबाड़	जबुंआ	256	512 आई०एल०टी०	128
जबुआ	जबुआ	576	512 सीडाट	400
हरसुद	खंडवा	256	512 सी-डाट	144

1	2	3	4	5
बुरहानपुर	खंडवा	2076	512 आई०एल०टी०	384
खंडवा	खंडवा	1928	512 आई०एल०टी०	384
बरवाह	खरगोन	576	1के० सी-डाट	824
खरगोन	खरगोन	856	1के०सी-डाट	744
सानावाड़	खरगोन	500	512 आई०एल०टी०	384
अन्जाब	खरगोन	256	512 सी-डाट	144
महेश्वर	खरगोन	176	512 आई०एल०टी०	208
मांडला	मांडला	592	512 सी-डाट	400
निमच	मंदसौर	236	3.5 केसी-डाट	1132
मनाशा	मंदसौर	472	512 आई०एल०टी०	384
जावद	मंदसौर	256	512 आई०एल०टी०	128
भानपुरा	मंदसौर	256	512 आई०एल०टी०	128
दालदामंडी	मंदसौर	256	512 आई०एल०टी०	128
केरट	मंदसौर	256	512 सी-डाट	144
सिंघाली	मंदसौर	256	512 आई०एल०टी०	128
सीतामऊ	मंदसौर	256	512 सी-डाट	144
सेवपुरकला	मुरेना	300	1के०सी०-डाट	700
खम्बा	मुरेना	300	512 आई०एल०टी०	84
केलारक्ष	मुरेना	300	512 आई०एल०टी०	84
पोरस	मुरेना	300	512 आई०एल०टी०	84
मुरेना	मुरेना	1472	512 आई०एल०टी० (ई)	384
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	800	1.4 के० सी०-डाट	600
करेली	—वही—	384	512 आई०एल०टी० (ई)	384
गोटेगांव	—वही—	384	512 आई०एल०टी० (ई)	184
पायलगांव	रायगढ़	200	512 आई०एल०टी०	184
सारंगगढ़	रायगढ़	200	512 आई०एल० टी०	184

1	2	3	4	5
खरसिया	रायगढ़	800	512 आई०एल०टी०	384
राजगढ़	रायगढ़	1672	512 आंई०एल०टी०	384
धमतरी	रांयपुर	876	1.4 के०सी०-डाट	524
नदापाड़ाराजम	रायपुर	240	512 आई०एल०टी०	144
माहसगंड	रायपुर	384	512 आई०एल०टी०	384
नैवरा	रायपुर	3 0	512 आई०एल०टी०	64
बलोदाबाजार	रायपुर	256	512 आई०एल०टी०	128
सरायपल्ली	—वही—	256	512 सी-डाट	144
रायसैन	रायसैन	472	512 आई०एल०टी०	3 4
बरैली	—वही- -	256	512 आई०एल०टी०	128
मंडीदीप	—वही—	428	512 सी-डाट	312
ओबेदुल्लागंज	—वही—	192	512 सी-डाट	208
राजगढ़	राजगढ़	288	512 आई०एल०टी०	96
पछौर	—वही—	256	512 आई०एल०टी०	128
नरसिंहगढ़	राजगढ़	256	512 आई०एल०टी०	128
राजनन्दगांव	राजनन्दगांव	1288	512 सी-डाट	400
अलोट	रतलाम	256	512 आई०एल०टी०	188
रीवां	रीवां	1388	1.4 के० सी-डाट	1312
दीना	सागर	480	1के०सी०-डाट	520
खुरई	—वही—	384	512 आई०एल०टी०	384
बांदा	—वही—	232	522 आई०एल०टी०	152
चिरीमिरी	सरगुजा	256	512 सी-डाट	150
अम्बिकापुर	—वही—	1028	512 सी-डाट	400
महेंन्द्रगढ़	सरगुजा	384	512 आई०एल०टी०	384
सूरजपुर	—वही—	176	512 आई०एल०टी०	208
बैंकठपुर	—वही—	176	512 आई०एल०टी०	208
सतना	सतना	2552	513 आई०एल०टी०	384

1	2	3	4	5
मैहर	मतना	192	512 सी-डाट	208
आस्ता	सिहौर	384	512 आई०एल०टी०	384
सिहौर	—वही—	1200	512 आई०एल०टी०	384
सिवनी	सिवनी	800	1.4 के०सी०-डाट	600
बुरहार	शहडोल	425	1.के सी-डाट	574
शहडौल	वही—	1200	512 सी-डाट	400
कटमा	—वही—	176	522 आई०एल०टी०	208
सुजालपुर	सुजालपुर	560	512 आई०एल०टी० (ई)	384
अगरमालवा	—वही—	384	512 आई०एल०टी० (ई)	384
शाजापुर	—वही—	656	512 सी-डाट	400
मक्शी	—वही—	255	512 आई०एल०टी०	128
अकोदिया	सुजालपुर	176	512 आई०एल०टी०	208
शिवपुरी	शिवपुरी	1048	1 के०सी०-डाट	1000
करेरा	शिवपुरी	300	512 आई०एल०टी०	84
टिकमगढ़	टिकमगढ़	560	512 सी-डाट	400
उज्जैन	कनौज	7968	2 के०सी०-डाट	2000
बारनगर	—वही—	472	1 के०सी०-डाट	528
खचरोल	—वही—	384	512 आई०एल०टी०	384
तराना	—वही—	256	512 आई०एल०टी०	128
गजबसौदा	विदिशा	472	1 के सी-डाट	528
विदिशा	विदिशा	1372	512 आई०एल०टी०	384

समुद्री तट का कटाव

[अनुवाद]

2293. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री तट के कटाव को रोकने के लिए धनराशि के आबंटन को स्थगित

करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशाल समुद्र तट वाले राज्यों पर इस निरन्तर समुद्र तट के कटाव का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आठवीं योजना में समुद्री कटाव-रोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता बन्द कर दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 199! में आयोजित की गई बैठक में जैसा कि अनुमोदन प्रदान किया गया है, केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए संशोधित फार्मूले के तहत विशेष समस्याओं के वास्ते 7.5% वल (वेट) दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए समुद्री कटाव-रोधी कार्यों की अनुमोदित स्कीमों को प्रस्तुत कर सकती हैं।

आधुनिक सुविधाओं वाले हवाई अड्डे

[हिन्दी]

2294. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने आधुनिक सुविधाओं के साथ हवाई अड्डों के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन हवाई अड्डों का निर्माण कब तक होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय ने हाल में महाराष्ट्र के यावतमल नामक स्थान पर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए निरीक्षण किया है। यह हवाई अड्डा राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने की योजना है, अतः कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में खीरी में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज

2295. **डा० जां० एल० कनोजिया** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खीरी में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है, योजना की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। स्थान का नाम

"लखीमपुर खीरी" है।

(ख) इस एक्सचेंज की संस्थापना का कार्य 1993-94 की प्रथम तिमाही में शुरू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4 करोड़ रुपये है।

जयपुर में टेलीफोन कनेक्शन

2296. **श्री गिरधारीलाल भार्गव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर में टेलीफोन कनेक्शनों को विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई योजना बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-10-92 की स्थिति के अनुसार जयपुर में प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है—

ओ० वाई० टी०	= 2636
गैर—ओ० वाई० टी० (विशेष)	= 3543
गैर—ओ० वाई० टी० (सामान्य)	= 53077
कुल	= 59256

(ख) जी, हां।

(ग) जयपुर शहर में 19 नए एक्सचेंज खोलने और इनके सदृश केबिल स्कीमों के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है।

(घ) 31-3-92 तक पंजीकृत सभी उपभोक्ताओं को मार्च, 1995 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। मौजूदा प्रतीक्षा सूची के शेष आवेदकों को मार्च, 1996 तक कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों की प्रसारण-अवधि

[अनुवाद]

2297. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री रामसिंह काशवां :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों की प्रसारण अवधि बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) यद्यपि आकाशवाणी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने पर कोई प्रस्ताव नहीं है, अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ दूरदर्शन के दोपहर के कार्यक्रमों की अवधि को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। इस पर अतिरिक्त व्यय लगभग 35 लाख रुपये होगा।

विभिन्न हवाई अड्डों का प्रबन्ध

2298. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर अत्यन्त उपेक्षा बरते जाने एवं कुप्रबन्ध की विभिन्न घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) देश में हवाई अड्डों के प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) (1) हवाई अड्डों के बेहतर प्रबन्ध और उपकरणों के कुशल संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) हवाई अड्डे की व्यवस्था को सुधारने के लिए हवाई अड्डों पर प्राप्त सुझावों/शिकायतों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और प्रणाली को कारगर बनाया जाता है।

(3) हवाई अड्डों पर नियमित एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें की जाती हैं।

(4) हवाई अड्डों के निदेशकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा सुविधाओं और सेवाओं का निरीक्षण किया जाता है।

त्रिवेन्द्रम से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

2299. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

श्री ए० चार्ल्स :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम् विमानपत्तन से संचालित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम् से कोई नई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम् से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ करने के लिए विदेशी एयर-लाइनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय त्रिवेन्द्रम् से प्रति सप्ताह निम्नलिखित 30 अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का प्रचालन किया जाता है—

एयर इंडिया		14 सेवाएं
इंडियन एयरलाइन्स		6 सेवाएं
एयर लंका		6 सेवाएं
गल्फ एयर	:	4 सेवाएं

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) अमीरात एयरलाइन्स ने प्रति सप्ताह 4 सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन के लिए यू० ए० ई० सरकार के साथ द्विपक्षीय हवाई वार्ताएं हुई थी। तथापि, अन्तिम समझौता नहीं हो सका।

मैथन ताप विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

2300. **डा० लाल बहादुर रावल :**

श्री नीतीश कुमार :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सहायता से 840 मेगावाट की मैथन ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । वित्त पोषण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी है ।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में आकाशवाणी केन्द्र

[अनुवाद]

2301. **प्रो० प्रेम धूमल** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमीरपुर (हिमांचल प्रदेश) में आकाशवाणी केन्द्र उद्घाटन के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका उद्घाटन कब तक किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) हमीरपुर स्थित रेडियो स्टेशन तकनीकी रूप से तैयार है परन्तु इसे तभी चालू किया जा सकता है, जब वहां पर इसके परिचालन एवं रखरखाव के लिए न्यूनतम आवश्यक स्टाफ की तैनाती हो जाएगी ।

गुजरात के लिए विमान सेवा

2302. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत-जामनगर, सूरत-भावनगर, राजकोट-दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने तथा सौराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न भागों के बीच वायुदूत सेवा भी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) ये प्रस्ताव इस समय किन चरणों में हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी एजेंसियों से आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए समाचार खरीदना

[हिन्दी]

2303. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विदेशी, एजेंसियों से समाचार खरीदती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के किन-किन देशों को ऐसी कितनी एजेंसियों के साथ समझौते हैं; और

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे समाचारों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन केवल दो विदेशी समाचार एजेंसियों अर्थात् विसन्यूज आफ यू० के० और एशिया वीजन, मलेशिया से समाचार खरीदती है ।

(ग) दूरदर्शन मै० विसन्यूज, लंदन को 1,27,000 यू० एस० डालर का वार्षिक अंशदान का और मै० एशिया वीजन, मलेशिया को 1,48,800 यू० एस० डालर का वार्षिक भुगतान करता है ।

भारत और बंगलादेश के बीच पानी का बंटवारा

[अनुवाद]

2304. श्री बारे लाल जाटव :

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और बंगलादेश के बीच पानी के बंटवारे के मामलों पर चर्चा की गई है; और

(ख) इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत और बंगला देश के बीच नदी जल बंटवारे के मुद्दों पर भारत-बंगलादेश संयुक्त विशेषज्ञ समिति (जे०सी०ई०) की नवम्बर, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित पहली बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया । गंगा, तीस्ता और अन्य वृहद नदियों के प्रवाहों के बंटवारे के लिए न्यायसंगत, दीर्घावधिक और व्यापक व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य पर दोनों पक्षों ने गहराई से विचार-विमर्श किया ।

नर्मदा सागर की सिंचाई और पनबिजली क्षमता

2305. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सागर परियोजना की सिंचाई क्षमता और पनबिजली क्षमता कितनी है;

(ख) इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तारीख क्या है; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नर्मदा सागर परियोजना की सिंचाई क्षमता तथा जल-विद्युत क्षमता क्रमशः 1.68 लाख हेक्टेयर और 1000 मेगावाट है।

(ख) 100%।

(ग) स्पिलवे द्वारों सहित पूरा होने का संभावित वर्ष 2000 ई० है।

(घ) मुख्य बांध की नींव की खुदाई तथा विद्युत घर की खुदाई का कार्य शुरू हो गया है तथा काफर बांध और दिक्परिवर्तन सुरंग पर कार्य चल रहा है। हेड रेस और टेल रेस चैनलों के लिए भी कार्य को आबंटित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में सरदार सरोवर परियोजना के कारण प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

[हिन्दी]

2306. **श्री गोविन्द राव निकाम** :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु 1500 हेक्टेयर भूमि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरदार सरोवर से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धूले जिले में अतिरिक्त 1500 हेक्टेयर वन भूमि का दिक्परिवर्तन करने का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रस्ताव की जांच के बाद पायी गयी कमियों के बारे में 24-11-92 को महाराष्ट्र राज्य सरकार से कुछ आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं।

चन्द्रपुर में एच० वी० डी० सी० सम्पर्क

[अनुवाद]

2307. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में चन्द्रपुर में तथा पूर्व एवं दक्षिणी क्षेत्रों में जयपुर-गाजूवाकू में एच० वी० डी० सी० सम्पर्क (लिंक) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्पर्कों के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) चन्द्रपुर एच० वी० डी० सी० बैक-टू-बैक लिंक की क्षमता 2 × 500 मे०वा० होगी और जयपोर लिंक की क्षमता 2 × 250 मेगावाट होगी। इन दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा किया जाना है।

(ग) ठेका दिए जाने की तारीख से 48 महीने की अवधि के पश्चात् इन दोनों परियोजनाओं को चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

दिल्ली और बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

2308. **श्री मंजय लाल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बिहार में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं और उक्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उन्होंने कितने आवेदकों को बारी से पहले टेलीफोन कनैक्शन स्वीकृत किए हैं;

(ग) उनके विवेकाधिकार के अंतर्गत किन मानदंडों के आधार पर बारी से पहले टेलीफोन कनैक्शन स्वीकृत किये जाते हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता को वरीयता कोटे से टेलीफोन कनैक्शन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या टेलीफोन कनैक्शन स्वीकृत करते समय मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता को किसी विशेष श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) दिल्ली और बिहार में 30·10·1992 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनैक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 378854 और 32596 है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों के अनुसार देश में छोटी टेलीफोन प्रणालियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन वास्तविक रूप में मांग होने पर, योजना अवधि मार्च, 1997 के अन्त तक दे दिए जाने की आशा है। बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा समय आठवीं योजना अवधि के अन्त तक 2 वर्षों की अवधि तक सीमित कर दिए जाने की सम्भावना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विस्तार योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(ख) संचार मंत्रियों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान बिना बारी के मंजूरशुदा टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

1989	1990	1991
12685	14898	29932

(ग) संचार मंत्रियों द्वारा बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी आवेदक की वास्तविक और तत्कालित जरूरतों का तटस्थ मूल्यांकन करने के बाद दी जाती है।

(घ) और (ङ) फिलहाल मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के अभिभावक लागू नियमों के अनुसार गैर-ओ वाई टी/विशेष श्रेणी के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन के लिए पंजीकरण के पात्र नहीं हैं।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

2309. **श्री सत्यनारायण जटिया** :

श्री अरविन्द नेताम :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार से 1992-93 और 1993-94 के लिए प्राप्त सिंचाई योजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) विचाराधीन योजनाओं को अब तक स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई नई वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा और उनके मूल्यांकन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्राप्त हुई मध्य प्रदेश की नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा और उनके मूल्यांकन की स्थिति

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लाख (हेक्टेयर)	प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन स्थिति
1	2	3	4	5	6
	वृहद				
1.	कोलार	139·14	60870	10/91	तकनीकी-आर्थिक जांच पूरी हो गयी है और परामर्शदात्री समिति की 4/92 में आयोजित की गयी बैठक में उसके द्वारा स्वीकार्य पायी गयी, बशर्ते कि राज्य अपने वित्त विभाग की सहमति तथा सतही एवं भूजल के संयुक्त प्रयोग का प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करें।
2.	कुनु	190·00	66000	2/92	इस परियोजना को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए राज्य को 3/92 में वापस कर दी गयी है।
3.	बीना कम्प्लेक्स फेस-1	202·90	66500	3/92	जांच के बाद पाया गया कि इस संबंधित परियोजना रिपोर्ट में मूल आयोजना में कमी थी। राज्य सरकार को

1	2	3	4	5	6
					संशोधित जल विज्ञान अध्याय प्रस्तुत करना है, वैकल्पिक बांध स्थल की जांच करनी है, पर्यावरण एवं वन पहलुओं पर अध्याय तैयार करना है और अन्य मामलों को अन्तिम रूप देना अपेक्षित है ।
4.	पारवती (रिम्सी)	351·00	110930	4/92	इस परियोजना को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए 6/92 में राज्य को लौटा दी गयी है ।
5.	लोअर गोई	98·09	.7890	5/92	इस स्कीम को, जांच के बाद, परियोजना आयोजना में मूल कमियां होने के कारण, 7/92 में राज्य को लौटा दिया गया ।
6.	गोपद मायर	31·74	23460	8/92	इस परियोजना को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है अत: इसे 9/92 में राज्य को लौटा दिया गया ।
7.	अरपा	265·71	1438'0	9/92	संशोधित परियोजना रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है ।
	मध्यम				
8.	अपर बेड़ा सिंचाई परियोजना	89·17	13360	7/92	यह स्कीम हाल ही में प्राप्त हुई है ।

रेलवे सुरक्षा संबंधी आयोग

[अनुवाद]

2310. डा० वसन्त पवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी आयोग द्वारा गठित आयोग से रेल दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने में किसी प्रकार की सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक आयोग पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अलग से किसी आयोग की नियुक्ति नहीं की जाती है लेकिन रेल संरक्षा आयोग स्वयं ही गम्भीर रेलवे दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच करता है । इन जांचों के फलस्वरूप दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायता मिली है ।

(ख) वर्ष 1991-92 में, 11 सांविधिक जांच किए गए जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) आयुक्तों द्वारा सांविधिक जांच करने के लिए अलग से कोई खर्च नहीं किया जाता क्योंकि इसकी व्यवस्था संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जाती है ।

विवरण

क्र०सं०	दुर्घटना	हताहत	कारण
1	2	3	4
1.	दिनांक 28·6·91 को पूर्वोत्तर रेलवे के टिनिच स्टेशन पर गोरखपुर बम्बई एक्सप्रैस की लोहित एक्सप्रैस के साथ टक्कर	मारे गए 0 गंभीर चोट 5	खतरे के प्वाइंट पर सिगनल पार करना ।
2.	दिनांक 4·8·91 को उत्तर रेलवे के सोनिक स्टेशन पर छपरा-ग्वालियर मेल और मिलीटरी स्पेशल के बीच टक्कर	मारे गए 11 गहरी चोट 21	—तदैव—
3.	दिनांक 30·9·91 को दक्षिण-मध्य रेलवे के विपारथी स्टेशन के निकट 352 अप यात्री गाड़ी और डिब्बों के बीच टक्कर	मारे गए 4 गहरी चोट 5	स्टेशन यार्ड से डिब्बों का खिसक जाना

1	2	3	4
4.	दिनांक 19·10·91 को दक्षिण-मध्य रेलवे के पोंडूगला स्टेशन पर 7055 अप एक्सप्रेस गाड़ी और मालगाड़ी के बीच टक्कर।	मारे गए 13 गहरी चोट 39	पटरी की खराबी, तेज गति और इंजिन की खराबी
5.	दिनांक 30·10·91 को दक्षिण रेलवे के माकाली दुर्गा और घोनडेभावी स्टेशनों के बीच 2627 अप एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना	मारे गए 29 गहरी चोट 18	भीषण वर्षा के कारण पटरी पर भारी पत्थर का गिर जाना।
6.	दिनांक 8·11·91 को मध्य रेलवे के निवार स्टेशन के निकट 1389 डाउन यात्री गाड़ी के साथ मालगाड़ी की टक्कर	मारे गए 2 गहरी चोट 8	ब्लाक खंड में मालगाड़ी का गलती से चला जाना।
7.	दिनांक 7·12·91 को उत्तर रेलवे के हरसर देहरी स्टेशन के निकट 3 अप यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना।	मारे गए 27 गहरी चोट 22	भारी भीड़ और तेज गति के कारण मोड़ पर डिब्बे का उलट जाना।
8.	दिनांक 30·1·92 को दक्षिण-मध्य रेलवे के मौरीग्राम स्टेशन के निकट लेवल क्रासिंग पर ई० एम० यू० लोकल की ट्रक के साथ टक्कर।	मारे गए 2 गहरी चोट 5	मोटरमैन द्वारा रेड गेट सिग्नल पार करना।
9.	दिनांक 3·2·92 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के ससान स्टेशन पर वर्कमैन गाड़ी की डिब्बे के साथ टक्कर।	मारे गए 2 गहरी चोट 1	रि-रेलिंग प्रचालन के दौरान अन्तिम डिब्बे को पटरी पर लाने में असफल होना।
10.	दिनांक 25·2·92 को पूर्वी रेलवे के पिछकुरीर ढाल स्टेशन पर 335 अप यात्री गाड़ी की मालगाड़ी के साथ टक्कर।	मारे गए 5 गहरी चोट 4	यात्री गाड़ी के सही प्वाइंट सेट करने में असफलता
11.	दिनांक 22·3·92 को दक्षिण-मध्य रेलवे के टेटू स्टेशन के निकट 7488 अप एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना।	मारे गए 5 गहरी चोट 12	पटरी का टूट जाना।

"लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट" का निर्माण

2311. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही देश में कुछ उद्योगों से "लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टो" (हल्के परिवहन विमान) का निर्माण करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या शर्तें नियत की गई हैं और इसके लिए किस तरह केन्द्रीय सहायता दी जाएगी; और

(ग) इस प्रस्ताव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन में कोयला घोटाला

[हिन्दी]

2312. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के विद्युत नगर में हाल ही में हुए कथित कोयला घोटाले की जांच करवाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन० टी० पी० सी०) द्वारा गठित की गई विभागीय समिति ने पता लगाया है कि कोयले की कमी नहीं थी।

प्रताप नगर पेयजल परियोजना

[अनुवाद]

2313. **श्री मानवेन्द्र सिंह :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले में टेहरी जल विकास निगम द्वारा हम्साली-टेहरी-प्रताप नगर रोड, चम्बा-धरांसु रोड प्रताप नगर पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य राज्य/लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया गया और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) घनसाली-टिहरी-प्रताप नगर सड़क तथा चम्बा-धरांसू सड़क का निर्माण कार्य टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन की स्थापना किए जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा मूलतः राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को डिपोजिट कार्य के रूप में दिया गया था। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन उसे कार्यों का हस्तांतरण किए जाने के पश्चात् इन्हीं प्रबन्धों के साथ कार्य करता रहा। प्रताप नगर पेयजल परियोजना का कार्य टी० एच० डी० सी० द्वारा राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा गया। तथापि, उससे अनुरोध किये जाने तथा परियोजना के कारण प्रभावित हुए लोगों के कल्याणार्थ टी०एच०डी०सी० ने प्रताप नगर के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम का क्रियान्वयन किए जाने हेतु जिलाधिकारी टिहरी-गढ़वाल को निधियां उपलब्ध कराई हैं।

(ख) घनसाली-टिहरी-प्रताप नगर सड़क तथा चम्बा-धरांसू सड़क का निर्माण कार्य का ठेका 1978 में दिया गया था तथा इसके 1994-95 तक पूरा होने की प्रत्याशा की गई है।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

2314. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई कुल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और जनवरी से अक्तूबर, 1992 तक इन दुर्घटनाओं से कितना नुकसान हुआ; और

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या निवारक उपाय किये गए हैं अथवा किये जाएंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जनवरी से अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई प्रतिवेद्य दुर्घटनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	गैर-घातक	घातक	कुल
(1) नियमित कर्मचारी	216	5	221
(2) ठेका कर्मचारी	4	9	13
कुल :	220	14	234

उपर्युक्त दुर्घटनाओं से संयंत्र की सम्पत्ति को कोई भारी क्षति नहीं पहुंची।

(ख) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ने अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाई है जिससे औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता मिली है। प्रचालन के प्रथम वर्ष में ही विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को वर्ष 1990 के दौरान सर्वोत्तम सुरक्षा निष्पादन के लिए भारत के सभी एकीकृत संयंत्रों में से इसे गौरवशाली इस्पात मंत्री ट्राफी प्रदान की गई। विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना ने इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति द्वारा गठित (1991) इस्पात सुरक्षा पुरस्कार भी जो प्रति 1000 कामगार पर दुर्घटना दर में उच्चतम कमी करने के लिए है, प्राप्त किया है। तथापि, इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम से कम करने के लिए संयंत्र में एक सुसज्जित सुरक्षा विभाग बनाया गया है जिसमें एक सलाहकार (सुरक्षा), सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा निरीक्षक और अन्य कर्मचारी हैं। हेलमेट,

जूते, सेफ्टी बेल्ट इत्यादि जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नियमत: बाध्यकर है। इसके अतिरिक्त, असुरक्षित कार्य दशाओं को समाप्त करने के लिए गहन स्थल निरीक्षण किए जाते हैं। छोटी अथवा बड़ी सभी प्रकार की दुर्घटनाओं की जांच की जाती रही है और उपचारात्मक कारंवाई की जाती रही है। सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा प्रतियोगिताएं, गृह-व्यवस्था प्रतिस्पर्धाओं जैसी सुरक्षा संवर्द्धनात्मक कार्यविधियों का विभाग-वार तथा सम्पूर्ण संयंत्र आधार पर भी आयोजिन किया जाता है। दुर्घटनाओं तथा सुरक्षा कार्यविधियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। ठेका कर्मचारियों को भी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुरक्षा के बारे में प्रेरित किया जाता है तथा ऊंचाई पर कार्य करने के लिए कुछ परीक्षा लेने के पश्चात हाइट-पास जारी लिए जाते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र

[हिन्दी]

2315. **श्री मोहन लाल झिकराम :**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह और इस्पात के उत्पादन हेतु उनके स्रोतों पर आवश्यक विभिन्न खनिजों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी इष्टतम क्षमता से कार्य कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इसकी स्थापित क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए अपेक्षित विभिन्न मुख्य खनिजों और उनके स्रोतों को नीचे दर्शाया गया है :—

नाम	स्रोत
कोककर कोयला	कोल इंडिया लि० और आयात द्वारा
लौह अयस्क	दल्ली-राजहरा खान
चूना-पत्थर	नन्दनी, कटनी, राजस्थान, जुकेही
डोलोमाइट	हिरि, कुडवा, चन्दिया, बेल्हा, बारादौर
मैंगनीज अयस्क	मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
बोक्साइट	कटनी और मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम (एम० पी० एस० एम० सी०)

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोजिकोड विमानपत्तन

[अनुवाद]

2316. **श्री रमेश चेन्नितला :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कारगो काम्पलैक्स" के निर्माण सहित कोजिकोड विमानपत्तन को विकसित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके विकास पर होने वाले खर्च की राशि किस प्रकार जुटाई जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोजीकोड (कालीकट) हवाई अड्डे के मौजूदा टर्मिनल के निकट नवीनतम सुविधाओं से युक्त एक नया टर्मिनल बनाने की योजना है। इस टर्मिनल में कार्गो परिसर की कोई व्यवस्था नहीं है। इस परियोजना की लागत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाएगी।

अहमदाबाद हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

2317. **श्री हरिन पाठक :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में जनवरी, 1991 में एक नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल से ब्रिटेन/अमरीका अथवा नैरोबी आदि के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल ब्लाक का उद्घाटन 14-12-1991 को किया गया था।

(ख) और (ग) एअर इंडिया दिल्ली और बम्बई से होकर अहमदाबाद से विदेश के लिए संयोजी उड़ानों का प्रचालन कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में विमान सेवाएं

[हिन्दी]

2318. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में नागर विमानन सुविधाओं के निर्माण, विकास और तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि और खर्च की गई, धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं; जहां यह धनराशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों के विकास पर राजस्थान में 5.27 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश में 16.10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपये में)

	स्वीकृत लागत	खर्च की गई राशि
राजस्थान		
जयपुर		
धावनपथ का पुनः सतहलेपन, मिट्टी का परीक्षण, धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि का अर्जन, सौर शक्ति प्रतिबन्ध, चेतावनी प्रकाश प्रणाली, आरक्षित लांज की मरम्मत, वैमानिकी संचार सेवाओं के विभिन्न उपकरण और ग्राउंड और सुरक्षा सेवाओं के लिए उपकरण ।	420.00	408.78
कोटा		
परिचालनात्मक दीवार का निर्माण (भूमि के अतिक्रमण के कारण 5/91 को 2650 मीटर में से 1855 मीटर तक की दीवार के पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य बन्द कर दिय गया) वैमानिकी संचार सेवाओं के विभिन्न उपकरण और ग्राउंड और सुरक्षा सेवाओं के लिए उपकरण ।	38.00	21.75
उदयपुर		
परिचालनात्मक दीवार का निर्माण, वैमानिकी संचार सेवाओं के विभिन्न उपकरण और ग्राउंड और सुरक्षा सेवाओं के लिए उपकरण ।	98.00	98.16
		526.20

(लाख रुपये में)

	स्वीकृत लागत	खर्च की गई राशि
मध्य प्रदेश		
भोपाल		
धावनपथ का विस्तार और नये टर्मिनल काम्पलैक्स का निर्माण, ग्राउंड सुरक्षा उपकरण और वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण ।	680.00	582.00
ग्वालियर		
टर्मिनल काम्पलैक्स, एप्रैन, टैक्सीपथ, एप्रोच रोड आदि, टैक्सीपथ प्रकाश प्रणाली और ग्राउंड तथा सुरक्षा उपकरण ।	575.00	310.00
इन्दौर		
चारदीवारी, कनवेयर बेल्ट, धावनपथ का पुनः सतह लेपन, साधारण एप्रोच प्रकाश और ग्राउंड तथा सुरक्षा उपकरण ।	295.00	267.00
खजराहो		
धावनपथ, टैक्सीपथ और एप्रेन का बिस्तार, ग्राउंड और सुरक्षा उपकरण, वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण और डी० बी० ओ० आर० की स्थापना ।	250.00	216.00
रायपुर		
परिचालनात्मक दीवार, दोनों पर धावनपथ का सुदृढ़ीकरण, एच० आई० आर० एल० प्रणाली, टैक्सीपथ एप्रेन बाढ़ प्रकाश, साधारण एप्रोच प्रकाश प्रणाणी, ग्राउंड और सुरक्षा उपकरण और वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण ।	225.00	207.00
सतना		
हवाई अड्डे का विकास ।	30.00	28.00
	जोड़ :	1610.00

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

2319. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विस्तार और अधिक क्षेत्र में करने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसे विस्तार कार्य के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) राष्ट्रीय स्तर की तुलना में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण की औसत स्थिति क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस औसत को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के क्रियान्वयन हेतु आठवीं योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें राज्य आयोजन भी शामिल है। आठवीं योजना अर्थात 1992-93 के प्रथम वर्ष के लिए योजना आयोग में आर० ई० सी० वित्तपोषित स्कीम के अन्तर्गत 480 गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 11500 पम्पसेटों का ऊर्जन करने के लिए 72 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इसके अलावा, 500 गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 700 पम्पसेटों का ऊर्जन करने के लिए राज्य आयोजना के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार, 84% राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य में 74% गांवों को विद्युतीकृत किया गया। यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो राज्य में इस कार्यक्रम को अनवरत गतिशील बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे।

लोह अयस्क का निर्यात

[अनुवाद]

2320. **श्री वसुदेव आचार्य :**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल के आयात के बदले लौह अयस्क गुटिकाओं (पेल्लेटों) का निर्यात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्यात देश में इस्पात उत्पादन की कीमत पर किया जा रहा है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, मैसर्स वी० एच० पी०, आस्ट्रेलिया के कुछ कोककर कोयले का आयात कर रही है। करार की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि कोयले का आपूर्तिकर्त्ता (मैसर्स बी० एच० पी०) स्टील

अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को कोयले की की गई आपूर्ति की कीमत की कुछ प्रतिशतता का लौह अयस्क पैलेड कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के० आई० ओ० सी० एल०) से खरीदेगा। बशर्ते कि कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा न्यूनतम 3 लाख टन वार्षिक पैलेटों की आपूर्ति हो। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, आस्ट्रेलिया को पैलेट की सप्लाई कर रही है।

(ख) लौह अयस्क पैलेटों का इस्तेमाल देश में एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, उपयुक्त ग्रेड के पैलेटों का इस्तेमाल गैस पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से पंज लोहे के उत्पादन के लिए भरण-सामग्री के रूप में किया जाता है। स्पंज लोहा उद्योग में पैलेटों की कमी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

11.02 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.00 म० प०

लोक सभा 2 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अयोध्या की घटनाओं के बारे में—जारी

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे ढांचे की रक्षा करने में असफल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : प्रधान मंत्री को त्यागपत्र देकर चले जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : प्रधान मंत्री एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

2.01 म० प०

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, श्री श्रीकान्त जेना, श्री नितीश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के विरुद्ध कार्य किया है। वे यहां नहीं बैठ सकते। भारतीय जनता पार्टी को इस सभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अन्ततः सिद्ध कर दिया है कि वह एक साम्प्रदायिक संगठन है। उन्होंने इस

देश के साथ धोखा किया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कम से कम पहले मेरी बात तो सुनें।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस हाउस में आप जो चाहें कर सकते हैं। बोलिए आप। आपकी भावनाओं को सब लोग जानते हैं। आप सुनिए तो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया है। उन्हें इस देश में एक राजनैतिक दल के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे देश की उच्चतम न्यायिक संस्था को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया है, प्रधान मंत्री को गुमराह किया है, देश को गुमराह किया है। विश्व हिन्दू परिषद पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया पहले मुझे सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मुझे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मुझे सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे वह रिकार्ड पर भी आ जाएगा, अभी तो रिकार्ड पर कुछ नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे सुनना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप मेरी बात सुनने के बाद रिएक्ट कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनने के बाद रिएक्ट कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना ठीक नहीं है, यह पार्लियामेंट में बात करने का तरीका नहीं है । जो कुछ भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में यह बात करने का तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे समय में आपको और भी ज्यादा संजीदगी से काम लेना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनने के बाद आप रिएक्ट कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन लीजिए, यह तरीका ठीक नहीं है । आप यहां पर चर्चा करने के लिए आए हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, यदि आप यहां पर चर्चा नहीं करेंगे तो इस तरह करने से कोई लाभ नहीं होगा । इस तरह से बात करने से किसी का भी भला नहीं होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरी बात सुनकर आप रिएक्ट कीजिए । पहले मेरी बात सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनने के बाद आप रिएक्ट कीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको मेरी बात पसंद न आए तो उस बात को छोड़ दीजिए, पर मेरी बात तो सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे सुनना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में मैं आपको सुनूंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये पार्लियामेंट में स्टेटमेन्ट भी दे सकते हैं, रिकार्ड पर भी आ सकता है, बाहर भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, मगर पहले आप मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे सकती है, टेबल पर रख सकती है, बाहर भी दे सकती है। मेरी बात आप सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनने के बाद। मेरी बात सुनिए, आपको पसन्द नहीं आए तो छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको एक्सपैल करके सदन नहीं चलाना है, आपको यहां रखकर सदन चलाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप मेरी बात सुनिए। आपको पसन्द नहीं आए तो छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। पसन्द नहीं आए तो छोड़ दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पार्लियामेंट में इस काम को कन्डेम नहीं करना चाहते। जो हुआ है उसको कन्डेम नहीं करना चाहते। सारा हाउस उसके लिए तैयार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जो बात हमारे मुंह को कलंक लगाने वाली हुई है, हमारे देश में मुंह पर

कलंक लगाने वाली बात हुई है, उसको आप कन्डेम नहीं करना चाहते। आप रैंगूलेशन की बात नहीं करना चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, ऐसे नहीं। पासवान जी, ऐसे नहीं, जहां दर्द है वहां ही दवा दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए। इतनी बड़ी बात हुई है और इस सदन के अन्दर उसके खिलाफ आप अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं तो ठीक बात नहीं होगी। आपको यह करना पड़ेगा। आपको इतनी बड़ी घटना के बारे में बात यहां पर उठानी होगी। आप नहीं बोलने देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जो बात हुई है उसके खिलाफ अगर सदन में कोई रैज्योलूशन आप लाना चाहते हैं तो आप जरूर ला सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो यह भी अच्छा नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका प्रस्ताव करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइए। मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मूव करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : हम इसका समर्थन करते हैं। हम अध्यक्षपीठ से इस कार्यवाही की निन्दा करने के लिए एक प्रस्ताव चाहते हैं। (व्यवधान)···हम अध्यक्षपीठ से एक संकल्प चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका आभारी हूं। आपने स्थिति की गम्भीरता को समझा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका प्रस्ताव करने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

आप सब लोगों को यहां से निकली हुई आवाज की बहुत कीमत है सदन में और बाहर भी। हमारा सदन बैठा हुआ है। यह घटना हुई है, उसके ऊपर आप कंडम नहीं कर रहे हैं, यह बात अच्छी नहीं होगी। उसके बाद प्रधान मंत्री जी वक्तव्य करना चाहें तो सदन में करें या बाहर करें। आपको ताकत बड़ी है, उसको आप छोटा मत समझें। यह घटना होने के बाद भी आपने सदन में इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, आप उसको कंडम कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : क्या आपके कहने के लिए कोई नैतिकता बची है? आप हमें शिक्षा दे रहे हैं कि विश्व क्या कहेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी, सदन में वक्तव्य करें या बाहर करें, मगर इस घटना को आपको कंडम करना पड़ेगा। आप कंडम भी नहीं करेंगे, यह बात नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरा सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय सदस्यों का बहुत आदर करते हैं, इनकी भावनाओं का भी आदर करते हैं। ये केवल इनकी सेंटीमेंट्स नहीं हैं, पूरे सदन की हैं। जो हुआ है उससे देश का हर नागरिक बहुत मायूस है। यहां शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। देश की हालत अगर कंट्रोल करनी है तो मेरे खयाल में प्रधानमंत्री जी को सुनें, प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट दे दें उसके बाद जो आपका विरोध है वह चर्चा में प्रकट करें और हम सब पूरी कोशिश से इसका मुकाबला करें जिससे देश में अमन और शान्ति हो। मेरी अपील है कि आप हाउस में शन्ति बनाये रखें और प्रधान मंत्री जी को बोलने दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 4.30 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

2.34 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.50 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

4.30 म० प०

लोक सभा 4.30 पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

इस समय श्री श्रीकान्त जेना, श्री नीतीश कुमार और कुछ माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

4.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1992/17 अग्रहायण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिज्स. न्यू सीलमपुर, दिल्ली—110053